



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2019/कार्तिक 14, 1941

No. 349]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2019/KARTIKA 14, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से कांतिनुअस कास्ट कॉपर वायर राइस के आयातों से संबंधित सब्सिडी रोधी जाँच के अंतिम जाँच परिणाम

सं. 6/17/2018-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और मै. वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाइट कापर) (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट

प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से कांतिनुअस कास्ट कापर वायर राइस (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर, अधिसूचना संख्या 6/17/2018 - डीजीएडी दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें नियम 6 के अनुसार संबद्ध जाँच की शुरुआत की गई ताकि कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

- क) प्राधिकारी के संबंधित नियम 6 के उप-नियम 5 के अनुसार जाँच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान सब्सिडीरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया।
- ख) प्राधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुसार इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम की सरकारों को आमंत्रित किया और एक पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंचने के लिए विचार-विमर्श किया। यह विचार-विमर्श 12 जुलाई, 2018 और 13 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम की सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- ग) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक प्रकाशित 10 सितम्बर, 2018 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- घ) प्राधिकारी ने 10 सितम्बर, 2018 की जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना संबद्ध देशों के दूतावासों, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादक/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजीं और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- ङ) प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 7(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई थी।
- च) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ भेजी गई थी।
- छ) प्राधिकारी ने ऐसी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जिनसे प्रतिसंतुलनकारी लाभ संबद्ध देशों की सरकार द्वारा दिया गया हो के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देशों सरकारों को प्रश्नावलियां भेजीं। थाइलैंड, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया ने प्रश्नावली का उत्तर दिया जिस पर विचार भी किया गया है।
- ज) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7 (4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी:—
 - i. मै. क्रोनटोंग स्क्रैप कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

- ii. मै. कॉस्को यू मेटल लिमिटेड, थाईलैंड
- iii. मै. सियाम पैसिफिक इलेक्ट्रिक वायर एंड केबलको, थाईलैंड
- iv. मै. सेई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कं लिमिटेड, थाईलैंड
- v. मै. अल्फा इंडस्ट्रीज, मलेशिया
- vi. मै. मेट्रोड, मलेशिया
- vii. मै. मेट्टूइम एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
- viii. मै. पीएम कॉपर वायर एंड केबल्स एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
- ix. मै. लुवाटा मलाशिया एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
- x. मै. पीटी. स्नोलिक्टोन टेकनालिका, इंडोनेशिया
- xi. मै. पीटी कार्या सुमिडेन, इंडोनेशिया
- xii. मै. वियतनाम ट्रि्यू वेल्लिंग सामग्री उद्योग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
- xiii. मै. मुओन एएनएच ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- xiv. मै. एसएनसी वियतनाम जेएससी, वियतनाम
- xv. मै. एसएनसी ज्वाइंट स्टॉक कं, वियतनाम
- xvi. मै. डोंग वियत नॉन फेरस मेटल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
- xvii. मै. नगोहन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम

झ) प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने विहित प्रारूप में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया:

- i. मै. सीएफटी वीना कॉपर कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- ii. मै. डोंग वियत नॉन फेरस मेटल एंड प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
- iii. मै. अल्फा इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी. मलेशिया
- iv. मै. एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- v. मै. पीटी तेमबागा मुलिया सेमानन टीबीके, इंडोनेशिया
- vi. मै. पीटी कार्या सुमिडेन, इंडोनेशिया
- vii. मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी
- viii. मेट्रोड (ओएचएफसी) एसडीएन बीएचडी
- ix. मेट्रोड कॉपर उत्पाद एसडीएन बीएचडी

- x. पैनासोनिक प्रोक्यूरमेंट मलेशिया एसडीएन बीएचडी
- अ) जॉच शुरूआत अधिसूचना के अनुपालन में, संबद्ध देशों से उपरोक्त उत्पादकों/निर्यातकों, मलेशिया, थाइलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया की सरकार ने भी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।
- ट) नियमावली के नियम 7 (4) के अनुसार प्राधिकारी ने आयातक प्रश्नावली को भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/वस्तु संबद्ध के प्रयोक्ताओं को आवश्यक जानकारी के लिए भेजा:
- i. मै. पॉलीकैब वायर्स
 - ii. मै. ट्रेफिगुरा इंडिया प्रा. लिमिटेड
 - iii. मै. हैवेल्ल्स
 - iv. मै. प्रीसीजन
 - v. मै. एएसटीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. मै. क्रॉम्पटन ग्रीन्स
 - vii. मै. केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड
 - viii. मै. मदरसंस
 - ix. मै. डुप्लेक्स वायर
- ठ) प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
- i. मै. अपार इंडस्ट्रीज लि.
 - ii. मै. जीके वाइंडिंग वायर्स लि.
 - iii. मै. ग्रेट वाइट ग्लोबल प्रा. लि.
 - iv. मै. सावली कॉपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
 - v. मै. एंकर इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.
- ड) ऊपर उल्लिखित प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के अलावा, इस जॉच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पक्षों की ओर से कुछ विधिक अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं।
- (i) थाइलैंड की सरकार
 - (ii) वाइंडिंग वायर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
- ढ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों/किए गए अनुरोधों को हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया था।
- ण) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जॉच अवधि समेत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्योरे की जानकारी देने का अनुरोध किया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जॉच के बाद आयातों की मात्रा और अपेक्षित विश्लेषण की गणना के लिए

डीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

- त) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) ज्ञात की गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि सब्सिडी मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- थ) आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन वास्तविक सत्यापन के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा किया गया था। वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम के प्रयोजनार्थ जहां आवश्यक हो वहां आवश्यक सुधार सहित केवल इस तरह की सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया गया है।
- द) उत्पादकों/निर्यातकों और वियतनाम, थाइलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया की सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया था और वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम के प्रयोजनार्थ ऐसी सत्यापित सूचना उस पर भरोसा किया गया है।
- ध) वर्तमान सब्सिडीरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 (12 महीने) है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 की अवधि तथा जांच की अवधि पर विचार किया गया है।
- न) नियमावली के नियम 7 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने 29 मार्च, 2019 को हुई मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पक्षों से विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और अपने खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
- प) हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/खंडनों में दिए गए तर्कों पर वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम में विचार किया गया है।
- फ) इस जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोधों पर इस अंतिम जाँच परिणाम में ध्यान दिया गया है।
- ब) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- भ) प्राधिकारी ने दिनांक 5 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना द्वारा उचित तुलना करने के लिए घरेलू उद्योग समेत हितबद्ध पक्षों से प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां मंगाई गई थी। तत्पश्चात, दिनांक 13 मई, 2019 की अधिसूचना द्वारा पीसीएन-वार सूचना मंगाई गई थी।
- म) आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षों से अतिरिक्त सूचना आवश्यक समझी गई सीमा तक मांगी गई थी।
- य) जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया या जांच में अत्यधिक बाधा डाली तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अंतिम जांच परिणाम को दर्ज किया है।
- र) दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को हितबद्ध पक्षों के लिए एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्य दिए गए थे, और प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए 29 अक्टूबर, 2019 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों से प्राप्त प्रकटन विवरण के बाद की

टिप्पणियों पर वर्तमान जाँच परिणामों पर उचित रूप से ध्यान दिया है।

- ल) पीओआई के लिए विनियम दर प्राधिकारी द्वारा 1 अमरीकी डॉलर = 65.33 रुपये के रूप में लिया गया है।
- व) अंतिम जाँच परिणाम में *** चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है : वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद कांटीनुअस कापर वायर रॉड है जिसे सीमा शुल्क उपशेष 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11, 7409.19 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सका है।

ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं—

- वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद कांटीनुअस कास्ट कापर वायर राड है उत्पाद के दायरे में विशिष्ट रूप से निम्नलिखित शामिल हैं।
- कान्टीनुअस कास्ट कापर वायर रॉड
- कापर वायर
- कापर रॉड
- कापर वायर रॉड
- कान्टीनुअस कास्ट कापर रॉड
- कापर स्ट्रिप
- वेल्डिंग वायर्स

ख) पीयूसी के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :—

- कापर जिक बेस अलाय (पीतल) या कांसे (और इसी प्रकार अलाय से बनी रॉड);
- कापर वेल्ड वायर
- तांबा, जिक आधारित अलाय (पीतल) या तांबा-निकिल आधारित अलाय (कुप्रो निकेल) या तांबा-जिक निकेल आधारित अलाय (निकेल सिल्वर) या कांसा (और समान अलाय) के बने वायर्स;
- सिल्वर प्लेटेड कापर वायर्स;
- टिनसेल वायर्स;
- इनेमेलड कापर वायर्स;
- मेटल कोटेड कापर वायर्स;
- इन्सुलेटेड कापर वायर्स केबल्स

- ग) पी यू सी अपनी पूरी लंबाई के साथ एक ठोस एक समान क्रास सेक्शन होता है। क्रास सेक्शन गोल, अंडाकार, वर्गाकार, हेक्टागोनल, आयताकार और अन्य आकार में हो सकता है। पी यू सी आमतौर कोइल के रूप में होता है। कॉपर वायर और रॉड लाल और संतरे रंग की होती हैं और उसे मूल रासायनिक तत्व एक धातु तांबे से बनाया जाता है।
- घ) पी यू सी भारतीय घरेलू बाजार 1.6 एमएम, 1.8 एमएम, 2 एमएम, 2.6 एमएम, 8 एमएम, 10 एमएम, 12 एमएम, 14 एमएम और 20 एमएम. सहित विभिन्न आयामों में प्रवेश कर रहा है।
- ङ) विभिन्न व्यास कांटीनूअस कापर वायर रॉड वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ एक वस्तु है, क्योंकि इनमें समान तकनीकी एवं भौतिक विशेषताएं हैं।
- च) वायर बनाने के लिए ड्राइंग रॉड के लिए अपेक्षित निवेश नगण्य है और उसे अलग वस्तु नहीं माना जा सकता है।
- छ) कापर वायर रॉड और कापर वायर में समान भौतिक और तकनीकी विशेषताएं होती हैं।
- ज) दोनों उत्पाद निरंतर कास्टिंग प्रक्रिया का परिणाम हैं। आयातित कापर वायर भी एक मध्यवर्ती उत्पाद है और अंततः उसे वांछित आकारों में ढाला जाता है। रॉड या राड वायर के स्तर तक मूल प्रक्रिया रॉड और वायर दोनों के उत्पादन समान होती है।
- झ) कापर वायर रॉड और वायर की कीमत निर्धारण वर्ष भर में समान स्तर पर ही रहता है।
- ञ) पी यू सी को बनाने में शामिल प्राथमिक कच्ची सामग्री कापर कैथोड है। तांबा अयस्क (जिसमें दो प्रतिशत से कम तांबा होता है) को सांद्रण (25-30 प्रतिशत तक तांबे वाले) से निकाला जाता है।
- ट) जैसा कि चीन जन. गण. से ग्लास फाइबर और उसकी वस्तुओं से संबंधित जांच में देखा गया है, चीन जन. गण. और जापान से पैरोक्स सल्फेट को परसल्फेट के नाम से भी जाता है और प्लास्टिक सोडा के रूप में थोड़े से बदलाव से आवश्यक रूप से अलग वस्तु नहीं बनती है।
- ठ) सभी वायर राड और वायर विद्युत के ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं और अंततः उनका प्रयोग केबल, हाउसिंग वायर, वाइडिंग वायर, स्ट्रिप्स और ट्रांसफार्मर तथा आटो उद्योग में होता है।
- ड) 8 एमएम या उससे अधिक के कापर वायर राड या 1.6-5.7 एमएम के कापर वायर को सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उन्हें 0.04 एमएम के वायर के रूप में ढाला जाता है।
- ढ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रियाओं प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण और वितरण तथा वस्तुओं के वर्गीकरण के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के समान है। ये दोनों वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।
- ण) इसके अलावा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम का अध्याय 74 केवल (क) बार, (ख) राड (ग) प्रोफाइल (घ) वायर को मान्यता देता है यह वायर राड को नहीं मानता है। याचिकाकर्ता अपने उत्पादन को 7408 के अधीन स्वीकृत कराकर उसकी बिक्री कर रहे हैं।
- त) वायर/राड इनकोइल रूप जो 7408 का उत्पाद तथा 7407 के राड इनकोइल रूप में बीच में भारी अंतर है याचिकाकर्ताओं ने बाद वाले के संबंध में सीवीडी की मांग नहीं की है।
- थ) अल्फा इंडस्ट्रीज ने एक उत्पाद कैटालॉग दिया है जिसमें उन्होंने स्वयं को राड/वायर विनिर्माता बताया है। उन्होंने राड और वायर के लिए कोई अंतर नहीं किया है। यह भी स्पष्ट है कि वह ड्राइंग वायर के प्रयोजनार्थ राड उत्पादन की अपनी 2/3 क्षमता का उपयोग करता है। यह दर्शाता है कि 6 एमएम से कम या अधिक का कापर वायर एक वस्तु है और एक मात्र अंतर यह है कि राड को पतले व्यास में आगे और ढाला जाता है और वाणिज्यिक रूप से वायर कहा जाता है।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :—

- क) वर्तमान याचिका जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार कांटीनुअस कास्ट कापर राड उत्पाद के लिए दायर की गई है। जांच शुरूआत अधिसूचना में उत्पाद के अन्य रूपों को नहीं दर्शाया गया है।
- ख) कांटीनुअस कास्ट कापर राड, कांटीनुअस कास्ट कापर राड और कापर राड समान उत्पाद हैं और इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, परंतु कापर वायर एक अलग उत्पाद और वह राड से भिन्न है।
- ग) संघ सरकार के 2017 की रिपोर्ट संख्या 1 (अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क) के अध्याय VI के पैरा 6.5 के अनुसार कापर वायर और कापर राड को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है :—

“6.5 कापर वायर को कापर बार/राड के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया है। अध्याय 74 के 1 (घ) और (च) के अनुसार बार और राड को रोलड एक्सट्रूडेड के रूप में परिवर्तित किया जाता है ड्रान और फोर्ज्ड उत्पाद कोइल में नहीं होते हैं, जबकि वायर को कोइल में ड्रान उत्पादों के रोलड एक्सट्रूडेड के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुसार वायर राड का अर्थ 6 एमएम से अधिक एक समान क्रॉस सेक्शन आयाम के राड उत्पाद होता है। इनका प्रयोग ठंडे रूप में निर्माण के लिए मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में होता है। 6 एमएम से अधिक क्रॉस सेक्शन आयाम वाले कापर वायर सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 74081190 के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं और उन पर 5 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगता है।”

- घ) कापर वायर और कापर राड दो अलग अलग उत्पाद हैं और उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोनों की विनिर्माण प्रक्रिया भी अलग अलग है। कापर राड का उत्पादन कास्टिंग से होता है जबकि कापर वायर को कापर राड से निकाला जाता है। कापर वायर कापर राड का निम्नवर्ती उत्पाद है।
- ङ) उत्पादों के अंतिम प्रयोग भी अलग अलग हैं। राड को वायर में बदला जाता है और उसके बाद उनका प्रयोग विद्युत और संचार तारों, ट्रांसफार्मर और मैग्नेट वायर के रूप में होता है। कापर वायर कापर राड से बने होते हैं कापर राड वायर से नहीं बनायी जा सकती हैं। कापर राड से कापर वायर बनाने के लिए अलग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। राडों की मोटाई 6 एमएम से अधिक होती है और वायर की 6 एमएम से कम होती है।
- च) वर्तमान जांच की शुरूआत के बाद प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक सूचना जारी की और जांच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित पी यू सी के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसके उत्तर में याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी को पी यू सी तथा गैर पी यू सी के समावेशी आंकड़े प्रस्तुत करके धोखा दिया है।
- छ) इसके अलावा मौखिक सुनवाई के बाद प्राधिकारी ने पी यू सी और समान वस्तु के बीच में उचित तुलना के लिए निम्नलिखित पी सी एन को अपनाकर पी सी एन पद्धति को अपनाने के लिए 5 अप्रैल, 2019 को एक पत्र जारी किया (क) कांटीनुअस कास्ट वायर और (ख) कापर वायर। जैसा ऊपर सिद्ध हुआ ये दोनों अलग अलग उत्पाद हैं।
- ज) प्राधिकारी ने पी यू सी और समान वस्तु का स्वयं विश्लेषण किए बिना याचिकाकर्ता के दावों पर विश्वास कर लिया है और इस समय पी यू सी के दायरे को बढ़ाने के लिए पी सी एन अपना कर पी सी एन पद्धति का प्रस्ताव किया है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने पी यू सी का दायरा निर्धारित करने से पहले आवश्यक परिश्रम नहीं किया है।
- झ) पी सी एन पद्धति को अपनाकर प्राधिकारी ने पी यू सी के दायरे को बढ़ाने / व्यापक करने का प्रयास किया है, जो डीजीटीआर द्वारा जारी व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचालन प्रथाओं की नियम पुस्तिका 3.4 और 3.5 के अनुसार अनुमति नहीं है।

- ज) प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पी सी एन पत्र प्राधिकारी की प्रचालन प्रथाओं का उल्लंघन है।
- ट) डीजीटीआर द्वारा जारी व्यापार उपचार की प्रचालन प्रक्रिया संबंधित नियम पुस्तिका के पैरा 3.23 के अनुसार पी सी एन के लिए पत्र जांच शुरुआत के 60 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
- ठ) वर्तमान पी सी एन पत्र 200 से अधिक दिनों बाद जारी किया गया है जो व्यापार उपचार महानिदेशक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रचालन प्रथाओं के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार पी यू सी का दायरा इस स्तर पर नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- ड) सब्सिडीरोधी जांच का उद्देश्य विशिष्ट रूप से सरकार की वित्तीय सहायता द्वारा प्रदत्त लाभ की मौजूदगी सिद्ध करना होता है और तत्पश्चात ऐसे लाभ की राशि की गणना करना होता है ताकि सब्सिडी का स्तर ज्ञात किया जा सके। इस प्रकार, सब्सिडी दर की गणना के लिए घरेलू कीमत (सामान्य मूल्य) की तुलना निर्यात कीमत से करना अपेक्षित नहीं है। इस स्थिति में, पीसीएन की आवश्यकता नहीं है।
- ढ) सीमाशुल्क शीर्ष केवल सांकेतिक हैं और निर्विवाद नहीं हैं। उत्पाद को विभिन्न सीमाशुल्क शीर्षों के अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है जब तक प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से बताया न जाए उन सभी पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- ण) यह प्राधिकारी द्वारा संकेत दिया गया है कि उत्पाद विभिन्न एचएस कोड के तहत वर्गीकृत है। उक्त एचएस कोड में विभिन्न उत्पाद जैसे कि कॉपर रॉड, कॉपर वायर, कॉपर प्लेट, शीट, स्ट्रिप्स और अन्य शामिल हैं। प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए जो पीयूसी या एचएसएन कोड में वर्णित विवरण से अधिक प्रासंगिक है।
- त) अध्याय शीर्षकों का संदर्भ केवल यह बताने के उद्देश्य से है कि पीयूसी (उनके द्वारा परिभाषित) का विभिन्न शीर्षकों के तहत आयात किया जा रहा है। पीयूसी को इन उद्धरणों के भीतर स्पष्ट रूप से उल्लिखित के अनुसार सीमित किया जाएगा अर्थात् आवेदन में और साथ ही जांच शुरुआत अधिसूचना में दोनों में "निरंतर कास्ट कॉपर वायर रॉड्स"।
- थ) संबद्ध देशों से आयात किया जा रहा उत्पाद केवल तांबे का तार है, न कि तांबे की छड़ या अन्य रूप।
- द) तांबे के तारों का उपयोग अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें विद्युत उत्पादन, विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण, रेलवे और रक्षा, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, प्रशीतन और एयर कंडीशनर, पंखे, वाशिंग मशीन, उपकरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं।
- ध) इंडोनेशिया का भारत को निर्यात केवल 2.6 मिमी से 1.6 मिमी (अधिकांश 1.6 मिमी) के व्यास के साथ तांबे के तार को कवर करता है, जो कि 8 मिमी और उससे अधिक के व्यास के साथ याचिकाकर्ताओं के तांबा रॉड उत्पादन से काफी कम है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा उत्पाद के दायरे के संबंध में प्रस्तुत किए गए अनुरोधों को नोट किया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- क) जांच में बिल्कुल पहला चरण विचाराधीन उत्पाद को पहचानना है। विचाराधीन उत्पाद आयातित उत्पाद है जो कथित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण और आयात के आंकड़ों की जांच के आधार पर, प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान जांच में उत्पाद "सीमा शुल्क टैरिफ 7408 के टैरिफ शीर्ष के अधीन आने वाले कंटीनुअस कास्ट वायर" है। विचाराधीन उत्पाद में कॉपर वायर शामिल है जिसमें अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल आयाम 6 मिमी से अधिक 6 मिमी और उससे कम है। अध्याय 74 के अनुसार अध्याय नोट (च) के अनुसार, वायर का अर्थ है "कॉइल में रोलड, निकाला हुआ या खींचा हुआ उत्पाद, जिसमें एक समान ठोस क्रॉस-सेक्शन होता है जो सर्कल, अंडाकार, आयताकार (वर्ग सहित) के आकार में पूरी लंबाई के साथ होता है, समबाहु त्रिभुज या नियमित उत्तल

बहुभुज ("चपटे सर्कल" और "संशोधित आयत", जिनमें से दो विपरीत पक्ष उत्तल चाप हैं, अन्य दो भुजाएं समान लंबाई और समानांतर की सीधी हैं)। एक आयताकार (वर्ग सहित), त्रिकोणीय या बहुभुज क्रॉस-सेक्शन वाले उत्पादों को उनकी पूरी लंबाई के साथ गोल कोने हो सकते हैं। ऐसे उत्पादों की मोटाई जिसमें एक आयताकार ("संशोधित आयताकार" सहित) क्रॉस-सेक्शन चौड़ाई का दसवां हिस्सा होता है। निम्नलिखित को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

- i. कापर ज़िंक बेस अलाय (पीतल) या कांसे (और इसी प्रकार अलॉय से बनी रॉड);
- ii. कापर वेल्ड वायर
- iii. तांबा, जिंक आधारित अलॉय (पीतल) या तांबा-निकिल आधारित अलॉय (कुप्रो निकेल) या तांबा-जिंक निकेल आधारित अलॉय (निकेल सिल्वर) या कांसा (और समान अलाय) के बने वायर्स;
- iv. सिल्वर प्लेटेड कापर वायर्स;
- v. टिनसेल वायर्स;
- vi. इनेमेलड कापर वायर्स;
- vii. मेटल कोटेड कापर वायर्स;
- viii. इन्सुलेटेड कापर वायर्स केबल्स

ख) सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर संबद्ध देशों से आयात किए गए कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर के समान वस्तु है। प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में सामूहिक और संचयी रूप से तुलनीय हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि सब्सिडीरोधी नियमों के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु हैं।

घ) काफी देरी से पीसीएन पद्धति को अपनाये जाने संबंधी अनुरोधों के बारे में, प्राधिकारी पीयूसी के दायरे को बढ़ा/विस्तृत कर रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के विभिन्न प्रकारों/रूपों के बीच उचित तुलना करने के लिए प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है।

ड.) कुछ हितबद्ध पक्षों द्वारा दी गई इस दलील के संबंध में कि पहली बार पीसीएन पद्धति टैरिफ कोड के आधार पर विकसित की गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कुछ हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया था कि आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद से अलग हैं। इसलिए टैरिफ कोड के आधार पर एक पीसीएन पद्धति विकसित करना उचित माना गया।

घ. घरेलू उद्योग के का दायरा और स्थिति

घ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में जाँच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

क) हिंडाल्को का उत्पादन समान वस्तु के भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। हिंडाल्को को घरेलू उद्योग माना जाता है और हिंडाल्को के आंकड़ों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी सभी मापदंडों का विश्लेषण किया गया है।

- ख) वेदांता सरकार के आदेशों के कारण कंपनी द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के कारण प्रासंगिक जानकारी के संकलन में कठिनाइयों के मद्देनजर निर्धारित रूप और तरीके से अपनी क्षति की जानकारी नहीं दे सका। वेदांता प्रासंगिक जानकारी देने को तैयार है, लेकिन असमर्थ था।
- ग) हिंडालको ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

9. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क) आवेदन के अनुसार, संबद्ध वस्तु के तीन प्रमुख उत्पादक हैं अर्थात् (क) मै० हिंडालको इंडस्ट्रीज; (ख) मै० वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाईट कॉपर); और (ग) हिंदुस्तान कॉपर लि० तीन उत्पादकों में से अग्रणी उत्पादकों अर्थात् हिंडालको इंडस्ट्रीज और मै० वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाईट कॉपर) ने आवेदन दायर किया है और उसका समर्थन किया है। तीसरे उत्पादक अर्थात् हिंदुस्तान कॉपर लि. ने न तो सब्सिडी/क्षति का दावा किया है और न ही आवेदन का समर्थन किया है।
- ख) वेदांता सरकार के आदेशों के कारण उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण क्षति की जानकारी नहीं दे सकती थी इसलिए, हिंडालको को घरेलू उद्योग माना जाता है क्योंकि इसका समान वस्तु का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ताओं को हुई क्षति के कुछ अन्य कारक होने चाहिए जिनकी वजह से वे प्राधिकारी को क्षति की जानकारी भी नहीं दे पा रहे हैं।
- ग) इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने हिंडालको को घरेलू उद्योग के रूप में माना है और लिखित अनुरोधों में कहा है कि हिंडालको "घरेलू उद्योग" का गठन करता है क्योंकि समान वस्तु का इसका उत्पादन कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।
- घ) घरेलू उद्योग के संघटन को जाँच की शुरुआत से पहले परिभाषित किया जाना चाहिए और यह कि याचिकाकर्ता स्वयं घरेलू उद्योग की स्थिति को पुनः परिभाषित नहीं कर सकते हैं। माननीय महानिदेशक का यह स्वविवेक है कि वे अनुरोध पर विचार करें या नहीं।
- ङ) सब्सिडीरोधी नियमों के नियम 6 के संदर्भ में, आवेदकों का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का कम से कम 25% होना चाहिए। आवश्यक और अनिवार्य शर्त पूरी नहीं होने की स्थिति में, "कॉपर वायर" के संबंध में इस जांच को जारी रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आवेदक स्पष्ट रूप से "कॉपर वायर" के नियम 6 के संदर्भ में स्थिति संबंधी परीक्षण में असफल होंगे।
- च) आवेदक "घरेलू उद्योग" का गठन भी नहीं करते हैं क्योंकि देश में कुल घरेलू उत्पादन में "कॉपर तारों" के उत्पादन के शामिल होने के बाद उनका कुल घरेलू उत्पादन के "एक प्रमुख हिस्सा" नहीं बनता है। जैसा कि ऊपर अनुरोध किया गया है, आवेदकों का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन के 2% से भी कम है। यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने "कॉपर वायर" को "कॉपर वायर रॉड्स" और "कॉपर वायर" जैसे दो अलग-अलग उत्पादों को बाधित करके "कॉपर वायर" में शामिल करने का प्रयास किया है।
- छ) इसके अलावा, डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए व्यापार उपचार के लिए मैनुअल ऑफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के पैरा 4.9.16 के अनुसार, यदि कंपनियां संबंधित जानकारी प्रदान नहीं करती हैं, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान जांच में, चूंकि वेदांता ने क्षति संबंधी प्रासंगिक और अनिवार्य जानकारी नहीं दी है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और वर्तमान जांच को समाप्त कर देना चाहिए।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा इस प्रकार है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

11. यह याचिका मै० हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और मै० वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाईट कॉपर) द्वारा दायर की गई है।
12. भारत में संबद्ध वस्तु के तीन उत्पादक हैं अर्थात् मै० हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि०, मै० वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाईट कॉपर) और मै० हिंदुस्तान कॉपर लि०. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक याचिकाकर्ता कंपनी मै० वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाईट कॉपर) ने जॉच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया है और इस प्रकार वह घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने से अपात्र हो गई है। मै० वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाईट कॉपर) ने उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने के संबंध में प्राधिकारी को कोई अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
13. भारत में तांबे के तार के कुछ उत्पादक हैं जो उच्च व्यास के तांबे के तार का आयात करते हैं और इसे निचले आवश्यक व्यास के तांबे के तार में परिवर्तित करते हैं। प्राधिकारी ने भारत में तांबे के तार के ऐसे उत्पादकों के उत्पादन पर विचार नहीं किया है क्योंकि वे पीयूसी के एक रूप को आयात कर रहे हैं और इसे पीयूसी के अन्य रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। उन उत्पादकों के संबंध में, जो उच्च व्यास के तांबे के तार का आयात नहीं करते हैं बल्कि घरेलू उत्पादकों से उसे खरीदते हैं, उनके उत्पादन को ध्यान में रखने पर दोहरी गणना की स्थिति पैदा हो जाएगी।
14. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मै० हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि० ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्धवस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि मै० हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि० भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। तदनुसार, इस जॉच के प्रयोजनार्थ, मै० हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि० नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 6(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग हैं।

ड.. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. गोपनीयता संबंधी मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क) निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
- ख) मै० सेयी थाई इलेक्ट्रिक कन्डक्टर कंपनी लि० (एसटीईसी) थाइलैंड की मूल कंपनी ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- ग) एसटीईसी यह साबित करने में विफल रहा है कि निर्यात योजना पर वेट ब्रूट पर निर्यात 'सब्सिडी क्यों नहीं है और इसने योजना से संबंधित जानकारी के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- घ) अल्फा इंडस्ट्रीज ने यह नहीं बताया है कि वे पीयूसी के उत्पादन या बिक्री में लगी किसी कंपनी से संबंधित हैं या नहीं। हालांकि, इंडोनेशिया से जवाब देने वाली कंपनियों में से एक, अर्थात्, पीटी टेम्बागा मुलिया सेमनान टीबीके ने मौजूदा जांच में स्वयं ही अपने प्रश्नावली के उत्तर में कहा है कि अल्फा इंडस्ट्रीज उनकी संबद्ध कंपनियों में से एक है।
- ड) निर्यातकों द्वारा दिए गए प्रश्नावली के उत्तर में कमी है और सूचना को छिपाया गया है, या अन्यथा जानकारी अपूर्ण है क्योंकि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार उत्तर नहीं दिए गए हैं।

- च) पैनासोनिक प्रोक्योरमेंट मलेशिया ने कहा है कि मेट्रोड मलेशिया कॉपर प्रोडक्ट्स एसडीएन. बीएचडी. उत्पाद के उत्पादन में शामिल कारखानों में से एक है। हालांकि, मेट्रोड मलेशिया कॉपर प्रोडक्ट्स एसडीएन. बीएचडी.ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में कहा है कि वे पूरी तरह से एक व्यापारी हैं। इसलिए, एक स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे दोनों उत्तर अविश्वसनीय हो जाते हैं।
- छ) इंडोनेशिया ने गोपनीयता कानून के दुरुपयोग की हद तक “बैंक मंदिरी” की वार्षिक रिपोर्ट प्रदान नहीं करके अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है।
- ज) केवल इसलिए कि घरेलू उद्योग योजनाओं के संचालन, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में ठीक से अवगत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसी पर गोपनीय दावा किया जा सकता है।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) याचिका का अगोपनीय अंश सीवीडी नियमावली के नियम 7 और 8 तथा डीजीटीआर द्वारा जारी व्यापार सूचना संख्या 1/2013 दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 में निर्धारित अपेक्षाओं और मानकों का उल्लंघन करता है।
- ख) याचिका व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018, जो जांच प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों गोपनीय संस्करण/अगोपनीय संस्करण में जानकारी के प्रकटीकरण के लिए मानक निर्धारित करती है, का अनुपालन नहीं करती है।
- ग) याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक गोपनीयताका दावा किया है और अधूरी याचिका प्रस्तुत की है।
- घ) याचिकाकर्ता उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा और मूल्य, लाभप्रदता, रोजगार और मजदूरी और निवेश पर आय के संदर्भ में क्षति के दावों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत देने में विफल रहे हैं।
- ङ) याचिकाकर्ताओं ने अगोपनीय सारांश में न्यूनतम सूचना या कीमत कटौती अथवा स्टॉक के लिए संकेतकों संबंधी न्यूनतम सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिससे प्रभावित पक्ष उचित बचाव जुटाने के लिए एक सार्थक समझ तैयार कर सकें।
- झ) याचिकाकर्ताओं ने भारत में अन्य उत्पादकों की मौजूदा और संभावित क्षमताओं की संख्या प्रस्तुत की है। तथापि यह उनके स्वयं के लिए नहीं दी गई है।
- ञ) याचिकाकर्ता द्वारा उसके आवेदन में प्रदत्त सूचना से सब्सिडी मार्जिन और स्थानीय उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति की मात्रा की तर्कसंगत समझ नहीं मिल पाती है।
- ट) याचिका में दोनों आवेदकों की क्षति संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई है। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत वैध नहीं है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. सूचना की गोपनीयता के संबंध में सब्सिडी-रोधी नियमावली के नियम-8 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

गोपनीय सूचना. (1) नियम 7 के उपनियमों (1), (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 14 के उपनियम (2) और नियम 17 के उपनियम (4) और नियम 19 के उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 6 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

18. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा सार्वजनिक फाइल के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अगोपनीय संस्करण को निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय संस्करण वाले अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराए।
19. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध को संगत समझी गई सीमा तक गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उन पर ध्यान दिया गया। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी वांछित है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षों को इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी के पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि सभी हितबद्ध पक्षों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय माना है।

च. सब्सिडी का निर्धारण और सब्सिडी मार्जिन

20. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में जांच की शुरुआत से पहले तत्काल जांच शुरू करने के लिए संबद्ध देश में प्रतिसंतुलनयोग्य सब्सिडी के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किया गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड सरकार को परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था, जो 12 और 13 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी और उन्हें इस तरह की सब्सिडी, यदि कोई हो की मौजूदगी और मात्रा के उचित निर्धारण के लिए कथित सब्सिडी कार्यक्रम के मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव पर सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। ।
21. इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड की सरकारों सहित इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :
 - i. मै० सी एफ टी बीना कॉपर कंपनी लि०, वियतनाम
 - ii. मै० डंग वियत नान फेरस मेटल एंड प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
 - iii. मै० अल्फा इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया
 - iv. सेई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लि०, थाईलैंड
 - v. मै० पी टी टेमबागा मुलिया सेमानन टीबीसे, इंडोनेशिया

- vi. मै० पी टी कार्या सुमीडेन, इंडोनेशिया
- vii. मेट्रॉड, मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.
- viii. मेट्रॉड (ओएफएचसी) एसडीएन. बीएचडी.
- ix. मेट्रॉड कॉपर प्रोडक्ट्स एसडीएन. बीएचडी.
- x. पैनासोनिक प्रोक्योरमेंट मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.

निर्दिष्ट सब्सिडी कार्यक्रम का सामान्य अवलोकन

च. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. निर्यातकों ने इस आधार पर सभी योजनाओं पर "लागू नहीं" कहा है कि कंपनी ने निर्दिष्ट कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठाया है। हालांकि, जब कोई कंपनी किसी कार्यक्रम के लिए योग्य होती है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उसे कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं मिला होगा। इस प्रकार, या तो कंपनी को पात्रता की अनुपस्थिति दिखानी चाहिए या यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उसने कार्यक्रम के तहत मिलने वाले लाभ का लाभ क्यों नहीं उठाया है।
- ii. अल्फा इंडस्ट्रीज ने केवल चार कार्यक्रमों के संबंध में उत्तर दिया है, और याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित 30+ कार्यक्रमों के बाकी हिस्सों के लिए एक भी अनुरोध नहीं किया है।
- iii. मलेशिया सरकार द्वारा दायर किया गया उत्तर अल्फा द्वारा दायर की गई प्रतिक्रिया के विपरीत है। मलेशिया सरकार ने कहा है कि अल्फा कार्यक्रम 23 : मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर, के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। तथापि अल्फा इंडस्ट्रीज ने इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
- iv. इसके अलावा, कार्यक्रम सं. 19 - आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्राबैक पर मलेशिया सरकार ने कहा कि यह जांच के अधीन किसी भी कंपनी पर लागू नहीं है; तथापि, अल्फा इंडस्ट्रीज ने अपनी विशिष्ट प्रतिक्रिया में लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है।
- v. वियतनाम सरकार ने आरंभिक योजनाओं के अलावा अन्य सब्सिडी जानकारी के संबंध में सूचना प्रदान की है।
- vi. कार्यक्रम सं. 5 और 9 अधिमान्य और रियायती दरों के संबंध में नहीं हैं परंतु वियतनाम सरकार ने ब्याज दर और रियायती दर के संबंध में विवरण प्रदान नहीं किया है।
- vii. पी -8 एक्सपोर्ट सपोर्ट क्रेडिट को समाप्त करने के संबंध में जानकारी को दबा दिया गया है। डिक्री 151/2006 / एनडी-सीपी -2006 के बारे में, प्रतिवादी निर्यातकों में से किसी ने भी नहीं कहा कि उक्त योजना समाप्त हो गई है। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने उक्त लाभ नहीं उठाया है।
- viii. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि वियतनाम सरकार ने प्रश्नावली की पूर्ण प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की है।
- ix. वियतनाम सरकार (जीओवी) ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया में कहा कि "अचल संपत्ति बनाने के लिए उपकरण और मशीनरी के लिए उपकरण के लिए आयात शुल्क में छूट" कार्यक्रम है। उक्त कार्यक्रम वियतनाम सीमा शुल्क विभाग (जीडीवीसी) के वित्त विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। जीओवी ने कहा कि सीएफटी वीना कॉपर 1996 में कुछ निश्चित परिसंपत्तियों के लिए आयातित उपकरणों और मशीनरी के लिए आयात शुल्क से छूट का हकदार था, जो पीओआई से पहले हुआ था। तथापि, निर्यातक ने उक्त तथ्य को दबा दिया है।

- x. उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर पर छूट के संबंध में वियतनाम की सरकार ने कहा कि कॉपर छूट के लिए हकदार है। तथापि प्रतिवादी निर्यातकों सीएफटी वीना कॉपर और डोंग वायट नॉनवेरस और प्लास्टिक जेएससी ने इस तरह के किसी भी लाभ को प्राप्त करने के संबंध में जानकारी को दबा दिया है।
- xi. वियतनाम सरकार ने कहा कि कार्यक्रम 1 समाप्त हो गया है। डोंग वायट नॉन-फेरस मेटल एंड प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के विरोधाभास में कहा गया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान उक्त लाभ का प्राप्त किया है।
- xii. कार्यक्रम सं. 3 के तहत जिन कंपनियों ने आवेदन किया है, दावा किया है, प्राप्त किया है या उपयोग किया है और पात्रता मानदंड पूरा किया है, इसकी जानकारी कंपनियों को दी गई है। इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कंपनियों ने इस योजना के तहत कोई लाभ लिया है या नहीं।
- xiii. कंपनी जो लाभ के लिए पात्र हैं और उसने कार्यक्रम संख्या के तहत लाभ के लिए आवेदन किया है। 6, 7, 17 ने कथित रूप से कोई लाभ प्राप्त/उपयोग नहीं किया है। यह उचित समझ से परे है कि किसी कंपनी ने लाभ के लिए आवेदन किया है लेकिन उसे लाभ नहीं मिला है।
- xiv. कंपनी को कार्यक्रम सं. 8 की धारा 31 के तहत दी गई सामान्य कर दर कॉर्पोरेट आयकर छूट की अवधि की 50% कटौती प्राप्त हुई। थाईलैंड सरकार द्वारा केवल इस तथ्य का खुलासा किया जाना चाहिए कि कंपनी पात्र है और योजना के संबंध में अधिक जानकारी और पात्रता के आधार पर सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
- xv. कंपनी को कार्यक्रम 9 के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए मूल्यांकन योग्य आय से परिवहन, बिजली और पानी की आपूर्ति की लागत में दोगुनी कटौती प्राप्त हुई। थाईलैंड सरकार ने प्रश्नावली में इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न की उपेक्षा की है।
- xvi. कार्यक्रम की धारा 35 (3) के तहत संवर्धन गतिविधि में उपयोग की जाने वाली स्थापना और सुविधाओं की लागत का 25% से अधिक नहीं होने पर कंपनी को शुद्ध लाभ से कटौती करने की अनुमति मिली। थाईलैंड सरकार ने प्रश्नावली में इस से संबंधित प्रश्न की उपेक्षा कर दी।
- xvii. कार्यक्रम 18 और 19 का उल्लेख किया गया है लेकिन आगे कोई जानकारी नहीं दी गई है।
- xviii. ऋण बेंचमार्क योजनाओं के लिए, यह कहा गया है कि कंपनी ने जांच में सूचीबद्ध कार्यक्रम का उपयोग नहीं किया है और न ही किसी राज्य के स्वामित्व वाले बैंक से ऋण लिया है। यह नहीं माना जा सकता है कि किसी निजी बैंक से ऋण में कोई सब्सिडी नहीं मिली है।
- xix. कर कार्यक्रम के लिए, कंपनी ने कहा है कि उसने किसी भी योजना के तहत कोई लाभ नहीं लिया है, लेकिन कार्यक्रम सं. 7 के अधीन प्रकटन किए हैं। स्पष्ट विरोधाभास और तथ्यों को छिपाया गया है।
- xx. एलटीएआर के लिए, कंपनी ने कहा है कि कंपनी में वस्तुओं या सेवाओं का कोई प्रावधान लागू नहीं है। निर्यातक खनन सब्सिडी के बारे में पूरी तरह से मौन है।
- xxi. 'अन्य सब्सिडी' के संबंध में ईक्यूआर में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। निर्यातक को या तो अन्य सब्सिडी 'की जानकारी दे या यह बताए कि कोई अन्य सब्सिडी नहीं है।
- xxii. कार्यक्रम संख्या 11- पुनर्निवेश भत्ता: इस कार्यक्रम के तहत लाभ विनिर्माण गतिविधियों में लगी मौजूदा कंपनियों को दिया जाता है जो एक ही उद्योग के साथ किसी भी संबंधित उत्पादों में विस्तार, स्वचालन, आधुनिकीकरण या अपने मौजूदा व्यवसायों के विविधीकरण के उद्देश्यों के लिए पुनर्निवेश करती हैं यह कि ऐसी कंपनियां 2009 के आकलन के वर्ष से कम से कम 36 महीनों के लिए परिचालन में हैं। पात्रता वास्तविक विशिष्टता पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- xxiii. कार्यक्रम संख्या 12: त्वरित कैपिटल अलाउंस (एसीए): याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि त्वरित कैपिटल अलाउंस (एसीए) संवर्धनप्राप्त उत्पादों के निर्माण में सुदृढीकरण करने वाले उद्यमों के लिए उपलब्ध है। पात्रता मानदंड इस प्रकार विशिष्ट हो जाता है कि केवल उद्यम जो उत्पादों को बढ़ावा देते हैं और इस तरह पुनर्निवेश केवल वही हैं जो इस कार्यक्रम के तहत प्रदान किए गए विशेष भत्ते से निर्माण से लाभान्वित हो सकते हैं।
- xxiv. कार्यक्रम सं. 13: समूह राहत: याचिकाकर्ताओं ने कहा कि समूह राहत कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, पात्रता मानदंड में से एक में उद्यम को किसी स्वचालन उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जो सीधे निर्माण गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, और उद्यम के पास मूल्यांकन के उस वर्ष के लिए आधार अवधि की शुरुआत में आरएम 2.5 मिलियन से अधिक के सामान्य शेयरों के संबंध में प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए। ऐसा मापदंड जो विनिर्माण गतिविधियों में लगे मौजूदा उद्यमों के अनुकूल है, उसके तटस्थ होने का तर्क नहीं दिया जा सकता है, और यह कार्यक्रम प्रथम दृष्टया कुछ उद्यमों को दूसरों की तुलना में वरीयता देता है। इसलिए, संबंधित कार्यक्रम को एससीएम और भारतीय नियमों के अनुसार प्रतिसंतुलनयोग्य माना जाता है।
- xxv. कार्यक्रम संख्या 15: उद्योग भवन भत्ता/औद्योगिक भवन भत्ता: औद्योगिक भवन भत्ता कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, उद्यम को किसी ऐसे भवन के निर्माण या खरीद पर पूंजीगत व्यय करना चाहिए जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें शामिल हैं विनिर्माण, कृषि, खनन, बुनियादी सुविधाओं, अनुसंधान, स्वीकृत सेवा परियोजनाएं और होटल जो पर्यटन मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं। चूंकि भवन के उपयोग के पीछे के उद्देश्यों को एक सूची में सीमित कर दिया गया है, यह स्पष्ट है कि यह योजना केवल कुछ प्रकार के उद्यमों तक सीमित है जो इस तरह की गतिविधियों में संलग्न हैं; इसलिए, यह कार्यक्रम विशिष्ट है। इसलिए, संबंधित कार्यक्रम एससीएम समझौते और भारतीय नियमों के अनुसार प्रतिसंतुलनयोग्य माना जा सकता है।
- xxvi. कार्यक्रम संख्या 16: संयंत्रों और मशीनरी के लिए भत्ता/पूंजी भत्ता (सीए): एक वैकल्पिक मानदंड जो एक निश्चित मात्रा में योग्यता व्यय के साथ एक वाणिज्यिक गतिविधि करने वाले उद्यमों के लिए अनुकूल है, जो तब संयंत्रों और मशीनरी में उपयोग नहीं किया जा सकता है के तटस्थ होने का तर्क नहीं दिया जा सकता है, और यह कार्यक्रम प्रथम दृष्टया कुछ उद्यमों को दूसरों से वरीयता देता है। इसलिए, संबंधित कार्यक्रम को एससीएम समझौते और भारतीय नियमों के अनुसार प्रतिसंतुलनयोग्य माना जा सकता है।
- xxvii. कार्यक्रम संख्या 19: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्राबैक, कार्यक्रम संख्या 21: आउटसोर्सिंग निर्माण गतिविधियों के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट, कार्यक्रम संख्या 23: मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट, , कार्यक्रम संख्या 14: टैरिफ संबंधित प्रोत्साहन / कच्चे माल से आयात शुल्क पर छूट और कार्यक्रम संख्या 24: कच्चे माल / उपकरण पर आयात शुल्क से छूट :: इस बात की जाँच करना महत्वपूर्ण है कि क्या इनपुट के वास्तविक उपयोग के संबंध में ऋण की राशि की गणना की गई है। इसके अलावा, निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के उत्पादन प्रक्रिया में कौन से इनपुट (उनकी मात्रा और मूल सहित) की पुष्टि करने के लिए एक प्रणाली या प्रक्रिया होनी चाहिए या क्या मद (एल) के मूल विनियमन के अनुबंध I और अनुबंध III के अर्थ के भीतर आयात शुल्क का अधिक भुगतान हुआ है।
- xxviii. कार्यक्रम संख्या 5 (क): निवेश ऋण और कार्यक्रम 5 (ख): उद्यमी के लिए ऋण: मंडिरी बैंक एक राज्य का स्वामित्व वाला बैंक है जिसे 1998 में बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए सरकारों के कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है। यद्यपि बैंक के अधिकांश हिस्से का स्वामित्व इंडोनेशिया सरकार के पास है, 7.01% हिस्सा राष्ट्रीय निवेशकों का है और शेष 32.99% का स्वामित्व विदेशी निवेशकों के पास है। यह एसओई बैंक प्रशासनिक निकाय है जो सार्वजनिक निकाय के रूप में कार्य करता है और रियायती दर पर मध्यम और दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान करता है। कार्यक्रम 5 (क) निवेश ऋण विशिष्ट है क्योंकि यह केवल सीमित संख्या में व्यापार उद्यमों और व्यक्तियों

- के लिए उपलब्ध है, कार्यक्रम 5 (ख) उद्यमी के लिए ऋण है क्योंकि यह केवल उन उद्यमों की सीमित संख्या के लिए उपलब्ध है जो 100 मिलियन रूपए से ऊपर की जरूरत है और 5 बिलियन रूपिया तक के वित्तपोषण के साथ नए व्यक्तिगत उद्यमी और एसएमई व्यवसाय हैं। कार्यक्रम इस सीमा तक लाभ प्रदान करता है कि गारंटीकृत ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि उस ब्याज की राशि से कम है जो फर्म एक तुलनीय ऋण के लिए भुगतान करेगा।
- xxix. कार्यक्रम संख्या 2: निर्यातक (एसटीईसी) ने दावा किया है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2002 के तहत लाभ मिला है, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को दबा दिया है कि 2017 में उक्त अधिनियम को अद्यतन किया गया है। पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क से छूट प्राप्त की, लेकिन एयूएल अवधि के संबंध में सूचना को दबा दिया। छूट के संबंध में इस कार्यक्रम के तहत मिलने वाले लाभों के लिए दिए गए लेखांकन उपचार इस कार्यक्रम के तहत लाभ की जानकारी नहीं देते हैं। निर्यातक ने इस तथ्य को पूरी तरह से दबा दिया है कि किस प्रणाली के तहत लाभ परिलक्षित होता है।
- xxx. कार्यक्रम सं. 5: निर्यातकों ने कहा कि यह लागू नहीं है क्योंकि प्राथमिक कच्चे माल यानी तांबा कैथोड पर आयात शुल्क 1 जनवरी 2017 से शून्य है।
- xxxi. कार्यक्रम संख्या 9: निर्यातकों ने योजना और विवरण की प्रकृति के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया।
- xxxii. थाईलैंड सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि एसटीईसी ने तीन कार्यक्रमों अर्थात् कार्यक्रम संख्या 13, 14, 15, के तहत लाभ लिया है। एसटीईसी ने उपर्युक्त कार्यक्रमों में से किसी के तहत लाभ लेने पर सहमति व्यक्त नहीं की है।

च. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

एससीएम करार के अनुच्छेद 11.3 में जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए किसी याचिका में प्रदान किए गए साक्ष्यों की सटीकता और पर्याप्तता की समीक्षा करना अपेक्षित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह एक जांच की शुरुआत को सही ठहराने के लिए "पर्याप्त" है।

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के पैरा 8 का पाठ निम्नानुसार है :

'8. प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादन या निर्यात पर प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और इस तरह के सब्सिडीप्राप्त आयात घरेलू उद्योग को उसकी मात्रा और मूल्य प्रभाव के माध्यम से वास्तविक क्षति का कारण बन रहे हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी निर्धारित करते हैं कि प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि यदि कथित सब्सिडीप्राप्त आयातों के मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है।'

यह अवश्य नोट किया जाए कि प्रथम दृष्टया और पर्याप्त दो पूरीतरह से अलग-अलग शब्द हैं, इनके मानक भिन्न-भिन्न हैं और यह प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

याचिकाकर्ता तीन तत्वों की मौजूदगी को सिद्ध नहीं कर सका, जिसमें एक प्रतिसंतुलनयोग्य सब्सिडी अर्थात् किसी सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान; लाभ; और वरीयता।

भारत सरकार के मूल्यांकन के निचले स्तर का लगातार उपयोग और इसकी पहले यह निर्धारित करने की विफलता कि याचिका में निर्यातक उत्पादकों द्वारा कंटिनुअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स के सब्सिडीकरण और परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग को क्षति के "पर्याप्त साक्ष्य" प्रदान करती है, एक घातक त्रुटि है।

भारत सरकार को उचित ठहराना चाहिए:

क्या इसने याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सब्सिडी से संबंधित साक्ष्य की पर्याप्तता और सटीकता का आकलन किया है; तथा

जिस आधार पर यह विचार करती है कि याचिका में उत्पाद के निर्यातक उत्पादकों के संबंध में प्रत्येक सब्सिडी योजना के संबंध में पर्याप्त और सटीक जानकारी है।

"पर्याप्त साक्ष्य" प्रदान करने में विफलता को इस दावे से परिरक्षित नहीं किया जा सकता है कि याचिका में ऐसी जानकारी है जो याचिकाकर्ता को "यथोचित रूप से उपलब्ध है"।

गणना का कोई विवरण नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता निर्यातक सदस्यों से सब्सिडी का मूल्यांकन को गोपनीय रूप में नहीं रख सकते हैं।

याचिका में सूचीबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ पहुंचाने का दावा करने वाला कोई भी कार्यक्रम पर्याप्त साक्ष्य के साथ प्रमाणित नहीं किया गया है।

अपनी याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने कोई समर्थक उल्लेख उपलब्ध कराए बिना यह कहा कि "वियतनाम सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि प्रतिवादी विनिर्माता/निर्यातक सीएफटी वीना कॉपर कंपनी लिमिटेड ने कार्यक्रम नंबर 2 : कच्चे माल के लिए आयात शुल्क में छूट या प्रतिपूर्ति" के तहत लाभ लिया है।

वियतनाम की सरकार ने कार्यक्रम नंबर 2 पर प्राधिकारी के प्रश्नों का उत्तर अगोपनीय उत्तर के पृष्ठ 25-32 पर दिया है और इस तरह की चर्चा में कहीं भी यह संकेत नहीं दिया गया कि सीएफटी ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाया था।

सीएफटी यह भी नोट करता है कि अपने उत्तर में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे कार्यक्रम 2 के तहत कोई लाभ नहीं मिला है और कोई लाभ नहीं दिखाने के लिए सहायक आकड़े प्रदान किए हैं क्योंकि सीएफटी द्वारा आयातित कच्चे माल के लिए मानक आयात शुल्क दर 0% है।

कोई भी सब्सिडी आरोप किसी भी समर्थित उल्लेख साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, जो वियतनाम के कानून के बारे में उनकी सतही समझ और कॉपर वायर राड के उत्पादकों पर लागू होने वाली प्रक्रिया या निराधार आरोप का उपयोग करके प्राधिकारी को गुमराह करने के उनके इरादे को प्रदर्शित करता है। कार्यक्रम 11 में, छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों की स्थापना में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर निवेश समर्थन, यह दावा किया गया है कि यह "विदेशी निवेशकों के लिए विशिष्ट सब्सिडी" है।

सीएफटी ने अपने प्रारंभिक उत्तर के 34-35 पृष्ठों पर "एसबीवी द्वारा ब्याज दर समर्थन" कार्यक्रम पर चर्चा की। तदनुसार, 1 फरवरी और 31 दिसंबर, 2009 के बीच क्रेडिट संस्थानों द्वारा वितरित 8-महीने की अवधि तक के अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज भुगतान पर 4% समर्थन, जबकि 1 अप्रैल, 2009 और 31 दिसंबर, 2011.10 के बीच क्रेडिट संस्थानों द्वारा वितरित 24-महीने की अवधि तक मध्यम से दीर्घकालिक ऋणों के लिए ब्याज भुगतान पर 4% समर्थन। इस प्रकार, इस कार्यक्रम के तहत समर्थन पीओआई से बहुत पहले बंद हो गया। चर्चा बार-बार प्रदर्शित करती है कि पीओआई के दौरान एसबीवी द्वारा ब्याज दर समर्थन उपलब्ध नहीं था और सीएफटी को इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं मिला। इस कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले कानूनी नियमों को प्रदान करने वाले सीएफटी की प्रारंभिक उत्तर के एक्जीबिट 32 सार्वजनिक और स्पष्ट सबूत है कि पीओआई के दौरान कोई ब्याज दर सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

यद्यपि आवेदकों ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड सरकार कथित 20 कार्यक्रमों के तहत सब्सिडी प्रदान कर रही है, तथापि यह अनुरोध किया जाता है कि अधिकांश कार्यक्रम दोहराए हुए हैं और थाईलैंड से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं पर कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

थाईलैंड सरकार द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार, कथित कार्यक्रमों को तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) पहले कार्यक्रम जो समाप्त हो गए हैं; (ii) दूसरे कार्यक्रम जो डब्ल्यूटीओ-एएससीएम के अनुरूप हैं; (iii) तीसरे कार्यक्रम जो लाभ प्रदान नहीं करते हैं।

आवेदकों द्वारा आरोपित कार्यक्रमों को कथित तौर पर पहले से ही समाप्त कर दिया गया है: सीवीडी नियमों के नियम 5 (3) (ख) के संदर्भ में, कोई भी जांच तब तक शुरू नहीं की जानी चाहिए जब तक कि (क) सन्सिडी, (ख) क्षति और (ग) कारणात्मक संबंध के साक्ष्य मौजूद न हों। तथापि, वर्तमान आवेदन पुराने आकड़ों के आधार पर दायर किया गया है और यह सन्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति के समक्ष थाईलैंड सरकार द्वारा दायर किए गए आकड़ों/सूचनाओं के विपरीत है।

जब तक आवेदक सन्सिडी की मौजूदगी को प्रमाणित नहीं करते, तब तक ऐसे कथित कार्यक्रम के विरुद्ध जांच शुरू नहीं की जा सकती।

यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदकों द्वारा कथित कार्यक्रम या तो गैर-प्रतिसंतुलनकारी हैं या बंद हैं या बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। उदाहरण के रूप में, प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि 'गोल्ड कार्ड योजना' नामक कार्यक्रम थाईलैंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है।

जब तक आवेदक "ऐसे शुल्कों या करों जिनपर व्यय हुआ है से अतिरिक्त उपार्जन" को दर्शाने के लिए रिकार्ड में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक शुल्क छूट और माफी कार्यक्रमों को प्रथमदृष्टया प्रतिसंतुलनकारी नहीं माना जा सकता है। थाईलैंड में शुल्क छूट या शुल्क माफी कार्यक्रम डब्ल्यूटीओ के अनुरूप हैं।

यूनाइटेड स्टेट के वाणिज्य विभाग ने वर्तमान जांच अर्थात् निर्यात के लिए उत्पादन में प्रयोग हेतु आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क में छूट संबंधी कार्यक्रम सं. 5 की जांच की थी और इस कथित कार्यक्रम को गैर-प्रतिसंतुलन योग्य निर्धारित किया था।

कथित कार्यक्रम प्राप्तकर्ताओं को कोई लाभ नहीं प्रदान करते हैं।

आर टी जी ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि यूएसडीओसी ने हाल में वर्तमान जांच अर्थात् मशीनरी पर आयात शुल्कों की छूट/कटौती – निवेश संवर्धन अधिनियम (आईपीए) की धारा 28 के कार्यक्रम सं.2 की जांच की है। कार्यक्रम की जांच करते समय यू एस डी ओ सी ने नोट किया कि धारा 28 के अनुसार, चीन से पूंजीगत सामान के आयात पर वैट में छूट प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है क्योंकि चीन से पूंजीगत सामान का आयात आशियान चीन मुक्त व्यापार क्षेत्र के अधीन शून्य वैट के अंतर्गत है। तदनुसार यूएसडीओसी ने माना है कि चीन से पूंजीगत सामान के आयातक को वैट छूट के रूप में लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा लाभ की अनुपस्थिति में यूएसडीओसी ने माना कि आईपीए की धारा 28 के अधीन कर छूट प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है।

किंगडम ऑफ थाईलैंड और भारत गणराज्य अधिक सहयोग और व्यापार अवरोधों में उत्तरोत्तर कटौती के लिए एफटीए में शामिल हुए थे। आवेदकों को शुल्क लगाने जाने की मांग द्वारा एफटीए के अधीन लाभ को बेकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एफटीए के अनुच्छेद 15 के अनुसार यदि कथित क्षति एफटीए के अधीन रियायत के कारण हुई है तो आवेदक एफटीए कार्यवाहक के अंतर्गत उचित राहत की मांग कर सकता है।

34 कथित मलेशियाई कार्यक्रमों की सूची केवल डाउनलोड की गई है और किसी औचित्य के बिना सूचीबद्ध कार्यक्रमों को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) से जोड़ दिया गया है।

- इस याचिका में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मलेशिया के उत्पादकों ने सूचीबद्ध कार्यक्रमों का लाभ कैसे लिया। जी ओ एम की चिंताओं को हमारे दिनांक 2 नवंबर, 2018 की प्रश्नावली के उत्तर के माध्यम से सही ठहराया गया है, जिसमें

यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ है कि जांच के अधीन किसी भी कंपनी ने 6 कार्यक्रमों को छोड़कर किसी कथित कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है या उससे लाभ प्राप्त किया है। वास्तव में 6 कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी वाले नहीं हैं क्योंकि वह निर्यात शर्तों से स्पष्टतः जुड़े नहीं हैं और वह आम तौर पर मलेशिया में सभी कंपनियों को उपलब्ध हैं।

- इन तर्कों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि याचिका में सब्सिडीरोधी कार्रवाई की शुरुआत को भी उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सिद्ध करने की सत्यता और सटीकता नहीं है। .
 - मलेशिया सरकार (जीओएम) ने अनुरोध किया है कि की गई आपत्तियों पर सब्सिडीरोधी जांच संबंधी निर्णय में गंभीरता से विचार किया जाए। जी ओ एम इन मुद्दों और इस जांच से संबंधित किसी अन्य मुद्दे को बाद में उठाने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।
 - इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि निर्यात कर व्यवस्था से संबंधित सब्सिडी का आरोप अब वर्तमान जांच के अधीन नहीं है।
 - निर्यात कर व्यवस्था संबंधी हमारे तर्क का सार तत्व यह है कि यह सब्सिडी नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कोई वित्तीय अंशदान नहीं है जिससे लाभ प्राप्त हो सकता हो।
 - इसके अलावा, ऐसे प्रतिबंध से किसी भी तरह से इंडोनेशिया में इस तथ्य की वजह से तांबा, अयस्क या सांद्रणों की कीमत में विकृति नहीं आ सकती है कि तांबे वाले उत्पादों को लंदन मैटल एक्सचेंज (एलएमई) द्वारा निर्धारित स्पाट कीमत के तहत निर्धारित किया जाता है। घरेलू बिक्रियों के लिए इंडोनेशिया की स्मेल्टर कंपनियां एल एम ई की कीमत का प्रयोग करके सामग्री (सांद्रण) की खरीद करती हैं। इसके अलावा, इंडोनेशिया के कॉपर वायर रॉड उत्पादन इसी मानक का प्रयोग करके कैथोड की खरीद करते हैं। निर्यात बिक्री के लिए इंडोनेशिया की स्मेल्टर कंपनियां एल एम ई कीमत जमा प्रीमियम का प्रयोग करके अपने उत्पादों की बिक्री करती हैं। फिर भी घरेलू बाजार में कीमत के कारण एल एम ई कीमत के प्रयोग से निर्यात कर व्यवस्था से घरेलू कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
 - याचिकाकर्ताओं ने कोयले के लिए निर्यात प्रतिबंध पर अपने अनुरोधों का उल्लेख भी किया है। यह फिर से अप्रासंगिक है और कोयले को ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है और इसलिए यह प्रतिबंध उद्योग के सभी क्षेत्रों के लिए है। इस प्रकार, कोयले के लिए निर्यात प्रतिबंध में बिल्कुल भी विशिष्टता नहीं है।
 - यह बिल्कुल अस्वीकार्य है कि याचिकाकर्ताओं ने आशियन देशों के बीच कथित एफटीए में सब्सिडी का आरोप लगाया है जोकि देशों को लाभ का "हस्तांतरण" है। यह बिल्कुल अप्रासंगिक है क्योंकि एफटीए को डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत उचित माना गया है और आजकल ऐसे अनेक एफटीए मौजूद हैं जिनमें भारत भी सक्रिय भागीदारी कर रहा है।
 - याचिकाकर्ता के अनुरोध में उन्होंने दावा किया है कि इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशियाई उत्पादकों के बीच सब्सिडी कार्यक्रम सं. 12 का उत्तर देते समय विरोधाभास हुआ है। कार्यक्रम सं. 12 विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) के अंतर्गत सुविधा से संबंधित है। चूंकि दोनों उत्पादक इंडोनेशिया में किसी एसईजैड के भीतर प्रचालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे किसी सुविधा के हकदार नहीं हैं। तथापि, न तो इंडोनेशिया सरकार और न ही इंडोनेशियाई उत्पादकों ने इस संबंध में कोई गलती की है।
24. एसीसीएम के अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 1 के पैराग्राफ 1 के अनुपालन में प्राप्तकर्ता को मिले लाभ की गणना के लिए दिशानिर्देशों और पद्धति का प्रावधान है और इसमें यह भी उपबंध है कि प्राप्तकर्ता को मिले लाभ की गणना के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई पद्धति पारदर्शी और पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगी। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता को प्राप्त लाभ की गणना के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त पद्धति उनके राष्ट्रीय विधान या संबंधित सदस्य के कार्यान्वयन विनियमों और प्रत्येक मामला विशेष में उनके अनुप्रयोग को पारदर्शी और पर्याप्त रूप से स्पष्ट करके दर्शाया जाएगा। इस अपेक्षा के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियमावली, 1995 में सब्सिडीकरण की राशि निर्धारित करने की पद्धति दी गई है। इस जांच में निर्धारण इन दिशानिर्देशों के अनुसार हुआ है।

च.4 याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच**थाइलैंड****च.5 याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच****(i) कार्यक्रम सं. 1: गोल्ड कार्ड स्कीम****क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध**

25. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत आयातों और निर्यातों को ग्रीन लाइन के जरिए प्रसंस्कृत किया जाता है। इन आयातों और निर्यातों को जांच से छूट प्राप्त है। कर दावों तथा ड्रॉ बैक दावों का अनुमोदन फाइलिंग के समय किया जाता है। गोल्ड कार्ड स्कीम थाइलैंड सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित और प्रदत्त की जाती है जो 25 जनवरी, बी.ई.2542 (2000) की सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक डॉट इंटरचेंज (ईडीआई) के अधीन सीमाशुल्क निकासी के लिए आयातों, निर्यातों की सहायता हेतु समर्थकारी उपाय उपलब्ध कराती है।

ख. थाइलैंड की सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. गोल्ड कार्ड के दर्जे वाले आयातकों और निर्यातकों के लाभ 1 अक्टूबर, 2013 को समाप्त हो गए। प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) दर्जे वाले आयातक और निर्यातक दिनांक 5 फरवरी, 2013 बी ई. 2556 (2013). द्वारा प्रवृत्त थे। विशेषाधिकार त्वरित कर वापसी और क्षति पूर्ति, आयात और निर्यात के लिए सीमाशुल्क प्रक्रिया, विशिष्ट शर्तों के अधीन विधिक मामले आदि के रूप में प्रदान किए जाते थे।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोल्ड कार्ड स्कीम 1 अक्टूबर, 2013 को समाप्त हो गई और जांच अवधि के दौरान वह लागू नहीं थी। सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 12/2556 के द्वारा गोल्ड कार्ड स्कीम को प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) दर्जे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ए ई ओ का दर्जे के अधीन कतिपय विशेषाधिकार दिए जाते हैं। लाभभोगी को ए ई ओ दर्जे के अधीन प्रदत्त विशेषाधिकार व्यापार सुगमकारी उपायों के रूप में होते हैं जो प्रशासनिक प्रवृत्ति के होते हैं और वित्तीय अंशदान के रूप में नहीं होते हैं। अतः एईओ दर्जाधारक द्वारा प्राप्त लाभ सब्सिडी नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलन योग्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(ii) कार्यक्रम सं. 2: मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट/कटौती**क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध**

29. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उक्त कार्यक्रम ऑफिस ऑफ दि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (बीओआई) और निवेश संवर्धन अधिनियम (आई पी ए) द्वारा चलाया जाता है। निवेश संवर्धन अधिनियम, 2002 (आईपीए) की धारा 28 अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए मशीनरी/उपकरण के आयातों हेतु आयात शुल्क में छूट/कटौती प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में आयात शुल्कों की वापसी का प्रावधान है जो कि स्पष्ट है क्योंकि वह इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत सीमित संख्या में उद्यमों को ही उपलब्ध रहता है, मशीनरी के आयातों पर आयात शुल्क को 90% तक कम किया गया है।

ख. थाइलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

30. इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन कंपनियों को सुविधा पहुंचाना है जो ऐसी कतिपय आयातित मशीनरी के आयात शुल्क में छूट द्वारा निवेश संवर्धन अधिनियम (आईपीए) की धारा 28 के अधीन लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिनकी जरूरत निवेश बोर्ड (बीओआई)- संवर्धित परियोजनाओं में होती है।
31. बीओआई निवेश संवर्धन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को प्रत्येक परियोजना के लिए एक आवेदन प्रपत्र जमा करना होता है। यदि परियोजना अनुमोदन मापदंड को पूरा करती है तो बीओआई पैकेज के रूप में अधिकार और लाभ प्रदान करेगा। बीओआई निवेश संवर्धन प्रोत्साहन कार्यक्रम आधार पर प्रदान नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में बीओआई कार्यक्रम वार लाभ प्रदान नहीं करता है बल्कि कंपनियों की हकदारी वाले आईपीए लाभों का एक पैकज प्रदान करता है। तथापि, जब (या यदि) कोई बीओआई संवर्धित कंपनी आईपीए पैकेज के अधीन प्रदत्त विशेष लाभ का वास्तव में प्रयोग करने का निर्णय लेती है तो कंपनी को प्रत्येक लाभ के उपयोग हेतु अलग से एक अनुरोध प्रस्तुत करना होता है। जीओटी ने बताया है कि एसईआई थाई इलैक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड ने कॉपर वायर रॉड के उत्पादन हेतु बीओआई निवेश संवर्धन के लिए आवेदन किया था, जो बीओआई घोषणा सं. 10/2552 (2009). के अधीन निवेश संवर्धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। एसईआई थाई इलैक्ट्रिक कंडक्टर लिमिटेड ने बताया कि उन्होंने निवेश संवर्धन अधिनियम, 2002 की धारा 28 के अंतर्गत उक्त लाभ प्राप्त किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) में संवर्धित कंपनियों/ परियोजनाओं/ कार्यकलापों को कतिपय अधिकार और लाभ देने की व्यवस्था है। (निवेश संवर्धन पैकेज स्कीम)। अधिनियम की धारा 16 में विहित है कि निवेश बोर्ड (बीओआई) अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लाभ हेतु निवेश कार्यकलाप पात्रता के प्रकारों और आकारों को निर्धारित करते हुए एक घोषणा करेगा।
33. अधिनियम की धारा 28 अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के अंतर्गत मशीनरी पर आयात शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान करती है और मशीनरी पर आयात शुल्क में कटौती प्रदान नहीं करती है। अधिनियम की धारा 30 कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क में कटौती (90 प्रतिशत से अधिक नहीं) प्रदान करती है और मशीनरी पर आयात शुल्क में छूट/कटौती प्रदान नहीं करती है।
34. थाइलैंड से एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक एसटीईसी ने प्रश्नावली के उत्तर में बताया है कि उसने निवेश संवर्धन पैकेज स्कीम के अंतर्गत मशीनरी के आयात पर आयात शुल्क से छूट का लाभ लिया है और पीओआई के दौरान उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी की राशि के संबंध में सूचना प्रदान की है।
35. यह कार्यक्रम छोड़े गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ मिला है। सब्सिडी भी स्पष्ट है क्योंकि यह संबंधित कार्यकलाप करने वाले संवर्धित उद्यमों तक सीमित है। यह तथ्य कि एस टी ई सी को कार्यक्रम से लाभ मिला है, दर्शाता है कि वास्तव में इस कार्यक्रम का उपयोग थाइलैंड में जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद के निर्यात में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किया गया है।

(iii) कार्यक्रम सं. 3: आयकर छूट**क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध:**

36. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र कंपनियों को आयकर से छूट प्रदान की गई है।

ख. थाइलैंड की सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

37. यह छूट बीओआई स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाती है। बी ओ आई केवल बीओआई-संवर्धित परियोजनाओं के लिए कार्पोरेट आयकर छूट पर लाभ प्रदान करता है। यह लाभ निवेश संवर्धन अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्धन पैकेज स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त एक लाभ है। अधिनियम की धारा 31 पात्र कंपनियों को कार्पोरेट आयकर से छूट प्रदान करती है।
39. यह कार्यक्रम छोड़े गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ मिला है। सब्सिडी भी स्पष्ट है क्योंकि यह संबंधित कार्यक्रमलाप करने वाले संवर्धित उद्यमों तक सीमित है। थाइलैंड से एकमात्र प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में अनुरोध किया है कि वह यह सब्सिडी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें जांच अवधि सहित अपने व्यवसाय की शुरुआत से कोई लाभ अर्जित नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि एस टी ई सी के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए।
40. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत थाइलैंड में संबद्ध उत्पाद के उन उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ उपलब्ध था जिन्होंने पी ओ आई के दौरान निवल लाभ अर्जित किया था। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि थाइलैंड से इस उत्पाद के सभी अन्य उत्पादक/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(iv) कार्यक्रम सं. 4 : निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के संबंध में छूट**क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध**

41. याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि संस्थाओं को अनधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहित गतिविधि से प्राप्त लाभ पर निर्गमित आयकर की सामान्य दर में 50 प्रतिशत कमी प्रदान की गई है।

ख. थाइलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

42. निवेश प्रोत्साहन अधिनियम बी.ई.2520(1977) के अंतर्गत, छूटें, जो बी ओ आई संवर्धित कंपनियों को प्रदान करती हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (1) धारा 28: मशीनरी पर आयात शुल्कों की छूट
- (2) धारा 31: निगमित आयकर की छूट
- (3) धारा 36: कच्ची और अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्कों की छूट

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मशीनरी और कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्कों की छूट और निगमित आयकर की छूट का अन्य कार्यक्रमों में प्राधिकारी द्वारा पहले ही प्रतिकारी बनाया किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के प्रति कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(v) कार्यक्रम सं. 5: निर्यात हेतु उत्पादन में प्रयोग के लिए आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की छूट**क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध**

44. याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कच्ची सामग्री पर आयात शुल्कों से छूट प्रदान की गई है जो निर्यात हेतु वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। प्रोत्साहित व्यक्तियों के उत्पादों और संयोजन प्रचालनों के लिए आयात शुल्कों और निर्यात शुल्कों से छूट प्रदान की जाती है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

45. निवेश प्रोत्साहन अधिनियम में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम को सृजित किया और बी ओ आई को निदेश संवर्द्धन प्रोत्साहनों को प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया, जिसमें धारा 36 के अंतर्गत बी ओ आई – संवर्द्धित परियोजनाओं में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों अथवा आवश्यक सामग्रियों पर आयात शुल्क छूट शामिल है।

46. निवेश परियोजनाएं जो धारा 36 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार हैं, को निम्नलिखित विशेष लाभों में से एक या अधिक लाभ प्रदान किए गए हैं:

(1) निर्यात के लिए वस्तुओं या उत्पादों के उत्पादन, मिश्रण या संयोजन में विशेष रूप से प्रयोग हेतु आयातित कच्ची और अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्कों की छूट; और

(2) ऐसी मदों पर आयात शुल्कों की छूट जिन्हें प्रोत्साहित व्यक्ति पुनः निर्यात हेतु आयात करते हैं। पूर्वोक्तलिखित बी ओ आई द्वारा यथा निर्धारित शर्तों, कार्य-विधियों और विशेष समयावधि के अनुसरण में होगा। इसके अतिरिक्त, कच्ची सामग्री और अनिवार्य सामग्रियों का केवल प्रोत्साहित परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

47. इस कार्यक्रम का प्रयोजन बी ओ आई – प्रोत्साहित परियोजनाओं में प्रयुक्त कच्ची अथवा अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्क की छूट द्वारा धारा 36 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार कंपनियों को मदद करना है। बी ओ आई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों की आयात गुणवत्ता परिक्रामी अधिकतम स्टॉक से अधिक नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनियां तैयार वस्तुओं के रूप में उन आयातित कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों का निर्यात करें, एक प्रभावी प्रणाली स्थापित की है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 36 में बी ओ आई – प्रोत्साहित परियोजनाओं में प्रयुक्त कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्क से छूट के लिए व्यवस्था की गई है। इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत, शुल्क मुक्त इनपुट का प्रयोग करते हुए उत्पादित उत्पादों के मिश्रण, संयोजन और उत्पादक गतिविधियों से गुजरने के पश्चात पुनः निर्यातित अथवा पुनः निर्यातित करने की जरूरत है। यह सब्सिडी कार्यक्रम निवेश प्रोत्साहन पैकेज योजना का भाग है।

49. थाईलैंड की सरकार ने अनुरोध किया है कि बी ओ आई के पास यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रणाली मौजूद है कि कंपनियां तैयार वस्तुओं के रूप में आयातित कच्ची सामग्री का निर्यात करें और प्रोत्साहित गतिविधि को लागू करने वाले उत्पादक/निर्यातकों को कोई अतिरिक्त लाभ न हो। थाईलैंड सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया है और कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए बी ओ आई योजना के अंतर्गत तंत्र कैसे प्रचालन करता है कि कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ है और यह कि कच्ची सामग्री जो कि शुल्क मुक्त आयातित की गई है, निर्यातित उत्पाद में प्रयोग की गई है। यह दर्शाने के लिए किसी साक्ष्य के अभाव में कि कार्यक्रम में अनुमेय कर छूट कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, यह निर्धारित किया गया है कि सब्सिडी कार्यक्रम में पूर्व निर्धारित राजस्व के रूप में

वित्तीय अंशदान की व्यवस्था की गई है जो अन्यथा रूप से देय है और इसके संबंध में एक लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर प्रासांगिक है और प्रोत्साहित गतिविधियों को लागू करने वाले प्रोत्साहित उद्यम तक सीमित भी है।

50. एस टी ई सी, थाईलैंड से एकमात्र उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक ने अपने प्रश्नावली उत्तर में अनुरोध किया है कि उन्होंने यह सब्सिडी प्राप्त नहीं की थी क्योंकि एस टी ई सी द्वारा अयातित कच्ची सामग्री कॉपर कैथोड पर आयात शुल्क पहले ही शून्य था। प्राधिकारी ने एस टी ई सी के दावे की सत्यापित किया है। अतः, प्राधिकारी धारित करते हैं कि एस टी ई सी के लिए इस कार्यक्रम के प्रति कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
51. जबकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री, उसकी अधिप्राप्ति के स्रोत और प्रयोज्य आयात शुल्क विवरण के अभाव में थाईलैंड में संबद्ध उत्पाद के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि थाईलैंड से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(vi) कार्यक्रम सं. 6: कच्ची सामग्री अथवा अनिवार्य सामग्रियों के लिए आयात शुल्कों की कमी

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

52. याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि उत्पादन, संयोजन अथवा मिश्रण प्रचालनों को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्कों से छूट दी गई है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

53. निवेश प्रोत्साहन अधिनियम ने निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम सृजित किया और बी ओ आई को निवेश प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जिसमें कच्ची सामग्रियों या अनिवार्य सामग्रियों पर सामान्य दर की अनधिक 90 प्रतिशत आयात शुल्कों की कमी शामिल है, जो प्रोत्साहित परियोजनाओं में उत्पादन, मिश्रण अथवा संयोजन के प्रयोजन के लिए किंगडम में आयातित की गई हैं।
54. जो कंपनियां बी ओ आई प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की इच्छा रखती हैं उन्हें प्रत्येक परियोजना के लिए एक पृथक आवेदन फार्म प्रस्तुत करना चाहिए। यदि परियोजना अनुमोदन संबंधी मानदंड को पूरा करती है तो निवेश बोर्ड पैकेज के रूप में अधिकार और लाभ प्रदान करेगा। बी ओ आई प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग से प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता बल्कि ऐसे लाभों को पैकेज के रूप में प्रदान करता है जिन्हें कंपनियां प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। तथापि, यदि पैकेज के अंतर्गत प्रदत्त विशिष्ट लाभों का उपयोग करने के लिए एक पृथक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश प्रोत्साहन अधिनियम की धारा 30 में कच्ची सामग्रियों या अनिवार्य सामग्रियों पर सामान्य दर की अनधिक 90 प्रतिशत आयात शुल्कों की कमी के लिए व्यवस्था की गई जो प्रत्येक समय बी ओ आई द्वारा निर्धारित तारीख से अनधिक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहित परियोजनाओं में उत्पादन, मिश्रण अथवा संयोजन के प्रयोजनार्थ किंगडम में आयातित की गई हैं, बशर्ते कि गुणवत्ता में तुलनीय ऐसी कच्ची सामग्री अथवा अनिवार्य सामग्रियां ऐसी परियोजना में उपयोग किए जाने के लिए अधिग्रहित किए जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में किंगडम के भीतर उत्पादन नहीं की जाती रही हैं अथवा उसके मूल की नहीं हैं। सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संबद्ध प्रोत्साहन पैकेज का भाग है।

56. सब्सिडी कार्यक्रम में निर्धारित राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान की व्यवस्था की गई है जो अन्यथा रूप से देय है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। सब्सिडी भी विशिष्ट है क्योंकि यह प्रोत्साहन गतिविधि को जारी रखने वाले उपक्रम को प्रोत्साहन देने तक सीमित है।
57. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करने वाला सब्सिडी कार्यक्रम पहले ही प्रतिकारी शुल्क लगाया गया है। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि थाईलैंड से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(vii) कार्यक्रम सं. 7: बी ओ आई प्रोत्साहित गतिविधियों के लिए निगमित आय कर की छूट

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

58. याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि प्रोत्साहन गतिविधि से व्युत्पन्न निवल लाभ को बी ओ आई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आयकर से छूट प्रदान की गई है किंतु आय प्राप्त करने की तारीख से 8 वर्षों से अधिक के लिए नहीं। यदि जहां पात्र छूट के दौरान हानि उपगत की गई है वहां बी ओ आई ऐसी अवधि की समाप्ति की तारीख से अनधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए पात्र छूट अवधि के समाप्त होने के पश्चात प्राप्त निवल लाभों से ऐसी वार्षिक हानि की कटौती करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। प्रोत्साहित व्यक्ति ऐसी हानि को किसी एक वर्ष अथवा कई वर्षों के लिए निवल लाभ संकटौती को चुन सकता है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

59. निवेश प्रोत्साहन अधिनियम ने निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम को सृजित किया और निवेश संबर्द्धन प्रोत्साहनों को प्रदान करने के लिए निवेश बोर्ड के लिए प्राधिकारी को सूचित किया जिसमें धारा 31 के तहत प्रोत्साहित परियोजनाओं से व्युत्पन्न निवल लाभ पर निगमित आय कर की छूट शामिल है।
60. यदि, जहां गतिविधियां विशेष महत्वपूर्ण हैं और देश को लाभ पहुंचाने वाली हैं, जैसा कि बी ओ आई की एक घोषणा द्वारा निर्धारित किया गया है तो ऐसी गतिविधियों में किसी प्रोत्साहित व्यक्ति को बी ओ आई द्वारा यथा निर्धारित अवधि के लिए प्रोत्साहित गतिविधि से व्युत्पन्न निवल लाभ पर निगमित आय कर छूट प्रदान की जाएगी किंतु ऐसी गतिविधि से प्रथम बार प्राप्त आय की तारीख से आठ वर्षों से अधिक प्रदान नहीं की जाएगी।
61. आय, जिस पर निवल लाभ की संगणना गतिविधि से प्राप्त की जाती है, में ऐसे गौण उत्पाद और अर्ध उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय शामिल होगी जैसा भी बी ओ आई उचित समझे।
62. जहां पैराग्राफ एक अथवा पैराग्राफ दो के तहत संदर्भित निगमित आयकर की छूट को प्राप्त करने की अवधि के दौरान हानि उपगत की जाती है, बी ओ आई प्रोत्साहित व्यक्ति को ऐसी अवधि की समाप्ति की तारीख से अनधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए निगमित आयकर की छूट की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रोदभूत निवल लाभों से ऐसी हानि की कटौती को अनुमति प्रदान कर सकता है। प्रोत्साहित व्यक्ति किसी एक वर्ष या कई वर्षों के निवल लाभों से ऐसी हानि की कटौती किए जाने को चुन सकता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रोत्साहित गतिविधि से व्युत्पन्न निवल लाभों पर निगमित आय कर से छूट के लिए निवेश प्रोत्साहन अधिनियम की धारा 31 में व्यवस्था की गई है जैसा कि बी ओ आई की एक घोषणा द्वारा निर्धारित किया गया है। आयकर से छूट ऐसी गतिविधि से पहली बार आय प्राप्त करने की तारीख से आठ वर्षों से अनधिक के लिए उपलब्ध नहीं है।

64. यदि किसी मामले में पात्र अवधि के दौरान, जिस में निगमित आयकर की छूट उपलब्ध थी, हानि उपगत की गई है, बी ओ आई को ऐसी अवधि की समाप्ति की तारीख से अनधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए निगमित आयकर से छूट की पात्र अवधि की समाप्ति के बाद प्रोदभूत निवल लाभों से ऐसी वार्षिक हानि की कटौती के लिए प्रोत्साहित व्यक्ति को अनुमति प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। प्रोत्साहित व्यक्ति ऐसी हानि को किसी वर्ष या कई वर्षों के निवल लाभ से ऐसी हानि की कटौती किए जाने को चुन सकता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम निवेश प्रोत्साहन पैकेज योजना का भाग है।
65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम में पूर्वविदित राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान की व्यवस्था की गई है, जो अन्यथा रूप से देय है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह प्रोत्साहित गतिविधि को लागू करने वाले प्रोत्साहित उपक्रम तक सीमित है।
66. एस टी ई सी, थाईलैंड से उत्तर देने वाले एकमात्र निर्यातक, ने इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं किया क्योंकि इसने पी ओ आई सहित इसकी स्थापना के बाद से कोई लाभ अर्जित नहीं किया। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयकर से छूट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम पर पहले ही प्रतिकारी शुल्क लागू हैं। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि थाईलैंड से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(viii) कार्यक्रम सं. 8: निवेश प्रोत्साहन क्षेत्रों में निगमित आयकर की 50% कटौती

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

67. याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम में प्रोत्साहित गतिविधि से प्रथम बार आय प्राप्त करने की तारीख से अनधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहित गतिविधि से प्राप्त निवल लाभ के लिए आयकर दर की सामान्य दर से 50% कटौती के लिए व्यवस्था की गई है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

68. निवेश प्रोत्साहन अधिनियम ने निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम का सृजन किया और निवेश संवर्धन प्रोत्साहनों को प्रदान करने के लिए बी ओ आई के लिए प्राधिकार की घोषणा की जिसमें धारा 35(1) के अंतर्गत प्रोत्साहित गतिविधि से प्राप्त निवल लाभ पर निगमित आयकर की 50 प्रतिशत कटौती शामिल है।
69. निवेश परियोजनाओं, जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार हैं, को प्रोत्साहित गतिविधि से प्रथम बार प्राप्त आय की तारीख से आरंभ कर अनधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहित गतिविधि से प्राप्त निवल आय पर निगमित आयकर की सामान्य दर की 50% कटौती प्रदान की गई।
70. जो कंपनियां बी ओ आई प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की इच्छा रखती हैं उन्हें प्रत्येक परियोजना के लिए एक पृथक आवेदन फार्म प्रस्तुत करना चाहिए। यदि परियोजना अनुमोदन संबंधी मानदंड को पूरा करती है तो निवेश बोर्ड पैकेज के रूप में अधिकार और लाभ प्रदान करेगा। बी ओ आई प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग से प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता बल्कि ऐसे लाभों को पैकेज के रूप में प्रदान करता है जिन्हें कंपनियां प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। तथापि, यदि पैकेज के अंतर्गत प्रदत्त विशिष्ट लाभों का उपयोग करने का अलग से एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रोत्साहन गतिविधि से प्राप्त निवल लाभ पर निगमित आयकर की सामान्य दर की तुलना में 50% कमी उपलब्ध है। यह सब्सिडी कार्यक्रम निवेश प्रोत्साहन पैकेज स्कीम का भाग है।

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम में पूर्वविदित राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान की व्यवस्था की गई है, जो अन्यथा रूप से देय है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह प्रोत्साहित गतिविधि को लागू करने वाले प्रोत्साहित उपक्रम तक सीमित है।
73. प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि आयकर से छूट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(ix) कार्यक्रम सं. 9: आयकर की दुगुनी कटौती परिवहन, बिजली और पानी की लागत को दुगुना करती है।

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

74. याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रोत्साहित गतिविधि से प्राप्त आय से दस वर्षों के लिए परिवहन, जल और बिजली की लागत से दुगुनी कटौती करने की अनुमति दी जाएगी।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

75. निवेश प्रोत्साहन अधिनियम ने निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम का सृजन किया और निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहनों को प्रदान करने के लिए निवेश बोर्ड के लिए प्राधिकार की घोषणा की जिसमें निगमित आय कर के आकलन के प्रयोजन हेतु परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति की लागतों के दुगुने की कटौती करने की अनुमति शामिल है।
76. निवेश परियोजनाएं, जो निवेश प्रोत्साहन अधिनियम की धारा 35 (2) के अंतर्गत इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं, को प्रोत्साहन गतिविधि के प्रचालन में प्रोत्साहित व्यक्ति द्वारा उपगत परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति की लागतों की दुगुनी राशि की निगमित आयकर के आकलन के प्रयोजन हेतु कटौती करने की अनुमति प्रदान की गई है। निवेश बोर्ड द्वारा इस लाभ को प्राप्त करने के लिए शर्तें, कार्यविधियों, और समायावधि निर्धारित की गई हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत, आयकर के प्रयोजन हेतु कुल आय को परिकलित करने के लिए परिवहन, बिजली और जल व्ययों की दुगुनी कटौती के रूप में लाभ उपलब्ध कराया गया है। यह सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहन पैकेज का भाग है। इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उन कर राशियों के बीच अंतर के समकक्ष है जो दुगुनी कटौती और वास्तव में अदा की गई आयकर की राशि के अभाव में अदायगी योग्य होता।
78. एस टी ई सी, थाईलैंड से उत्तर देने वाले एकमात्र उत्पादक/निर्यातक, ने इस कार्यक्रम के तहत व्ययों की दुगुनी कटौती का दावा किया है। तथापि, एस ई टी सी ने निवल लाभ उपगत नहीं किया और दुगुनी कटौती के अभाव में भी निवल लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार, एस टी ई सी द्वारा पी ओ आई के दौरान कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम पूर्वोक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान उपलब्ध कराता है, जो अन्यथा रूप से देय है और उस के द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। सब्सिडी भी विशिष्ट है क्योंकि यह प्रोत्साहित गतिविधि को लागू करने के लिए प्रोत्साहित उपक्रमों तक सीमित है। प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया था कि आयकर से छूट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के प्रति प्रतिकारी शुल्क लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के प्रति कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(x) कार्यक्रम सं. 10: सुविधाओं की स्थापना अथवा निर्माण की लागत के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की कटौती

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

80. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रोत्साहित फर्मों को उनके कर विवरणी पर प्रोत्साहन गतिविधियों में प्रयुक्त सुविधाओं की स्थापना अथवा निर्माण की लागत के 25% की कटौती की अनुमति दी गई है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

81. निवेश परियोजनाएं जो निवेश प्रोत्साहन अधिनियम की धारा 35(3) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार हैं, को निवेशबोर्ड द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार, प्रोत्साहित गतिविधि में प्रयुक्त सुविधाओं की स्थापना या निर्माण लागत की अनधिक 25 प्रतिशत राशि को निवल लाभ से काटने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके तहत प्रोत्साहित व्यक्ति, सामान्य मूल्य ह्रास के अतिरिक्त, प्रोत्साहित गतिविधि से पहली बार आय प्राप्त करने की तारीख से दस वर्षों के भीतर किसी एक वर्ष या कई वर्षों के लिए निवल लाभ से ऐसी कटौती किए जाने को चुन सकता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

82. अधिनियम की धारा 35(3) में प्रोत्साहित गतिविधि में प्रयुक्त सुविधाओं की स्थापना या निर्माण की लागत की अनधिक 25 प्रतिशत राशि को निवल लाभ से काटने के जरिए घटे आयकर की व्यवस्था की गई है। इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ कर की ऐसी राशि जो ऐसी कटौती के अभाव में अदायगी योग्य होती और वास्तव में अदा की गई आयकर की राशि के बीच के अंतर के समकक्ष है। सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहन पैकेज का भाग है।
83. सब्सिडी कार्यक्रम में निर्धारित राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान की व्यवस्था की गई है जो अन्यथा रूप से देय है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह प्रोत्साहन गतिविधि को जारी रखने वाले उद्यम को प्रोत्साहन देने तक सीमित है। प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि आयकर से छूट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रातिकारी शुल्क नहीं लागू किया जाना चाहिए।

(xi) कार्यक्रम सं. 11: कर और शुल्क प्रतिभूति/कर कूपन

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

84. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम में आयातित इनपुट पर शुल्क वापसी के लिए व्यवस्था की गई है जो निर्यातित उत्पाद के उत्पाद में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस शुल्क वापसी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ इस सीमा तक मौजूद है कि शुल्क व्यापारी की राशि आयातित ऐसे इनपुट पर प्रभारित आयात की राशि से अधिक हो जाती है जो अपशिष्ट के लिए सामान्य भत्तों को बनाते हुए निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त किए जाते हैं।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

85. वित्त मंत्रालय ("एम ओ एफ") और थाई सीमा शुल्क विभाग निर्यातकों के लिए एक कर कूपन प्रणाली संचालित करते हैं। कर कूपन प्रणाली किंगडम में उत्पादित निर्यातित वस्तुओं की कर और शुल्क प्रतिभूति अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्राधिकृत है। कर कूपन का मूल्य किसी कंपनी की निर्यातित वस्तुओं के एफ ओ बी मूल्य द्वारा एक उत्पाद विशिष्ट कूपन दर को गुणा करने के द्वारा परिकलित किया जाता है। किसी विशिष्ट निर्यातित वस्तु की कूपन दर को प्राप्त करने के लिए, एम ओ एफ निर्यातित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों और अन्य इनपुट के लिए अदा किए गए आयात शुल्कों और अप्रत्यक्ष करों की जांच करता है। कर कूपन प्रणाली निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और अन्य इनपुट के लिए अदा किए गए आयात शुल्कों और अप्रत्यक्ष करों को रिफंड करती है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

86. यह कार्यक्रम किंगडम अधिनियम बी ई 2524 (1981) में उत्पादित निर्यातित वस्तुओं की कर और शुल्क प्रतिपूर्ति के अनुसरण में स्थापित किया गया है और 15 अगस्त, 1951 को प्रभावी हुआ था। इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत, निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और अन्य इनपुट के लिए अदा किए गए आयात शुल्कों और अप्रत्यक्ष करों को रिफंड किया जाता है।
87. इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, वित्त मंत्रालय और थाई सीमा शुल्क विभाग निर्यातकों के लिए एक कर कूपन प्रणाली संचालित करते हैं। किसी कर कूपन के मूल्य को किसी कंपनी की निर्यातित वस्तुओं के एफ ओ बी मूल्य द्वारा एक उत्पाद-विशिष्ट कूपन दर को गुणा कर परिकलित किया जाता है। किसी विशिष्ट निर्यातित वस्तु के लिए कूपन दर को आयात शुल्कों कच्ची सामग्री के लिए अदा किए गए अप्रत्यक्ष करों एवं निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त अन्य इनपुट द्वारा निर्धारित किया जाता है। निर्यातित कंपनियां निगमित आयकरों के विरुद्ध कर कूपन का क्रेडिट के रूप में भी प्रयोग कर सकती है।
88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है या किसी तंत्र की विद्यमानता को स्थापित नहीं किया है कि कर कूपन का मूल्य आयात शुल्कों और निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर अदा किए गए अन्य करों की राशि से अधिक नहीं है। इसलिए, कार्यक्रम पूर्वोक्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है, जो अन्यथा रूप से देय है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी भी विशिष्ट है क्योंकि यह कर कूपनों को धारित करने वाले विशिष्ट उपक्रम तक सीमित है।
89. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य सब्सिडी कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के जरिए प्रतिकार किए जाने के लिए कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की छूट के रूप में लाभ पहले ही प्रस्तावित किया गया है। इसलिए प्राधिकारी धारित करते हैं कि कच्ची सामग्रियों / इनपुट पर अदा किए गए आयात शुल्क के रिफंड के जरिए कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान नहीं किया जाता है बशर्ते कि इनपुट पर शुल्क छूट के लाभ प्राप्त किए गए हों।

(xii) कार्यक्रम सं. 12: बंधक माल गोदामों के लिए आयात/निर्यात शुल्क की छूट

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

90. याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि इस बंधक माल गोदाम योजना के अंतर्गत, पुनः निर्यात के प्रयोजन हेतु किसी बंधक माल गोदाम में भंडार की गई आयातित वस्तुएं आयात/निर्यात करें और शुल्कों की अदायगी से छूट प्राप्त होगी, आयात किए जाने या अन्य वस्तुओं के समान मिश्रित या संग्रहित किए जाने के रूप में एक ही स्वरूप में निर्यात किए जाने की परवाह किए बिना।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

91. विनिर्माण प्रकार के बंधक माल गोदाम को प्रचालित करने के लिए कारोबार प्रचालकों को आयात करें और शुल्कों की अदायगी से छूट प्रदान की गई है बशर्ते कि ऐसे बंधक माल गोदामों में भंडार की गई और आयातित वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन, मिश्रण अथवा संयोजन किए जाने और तब निर्यातित किए जाने की प्रक्रिया में प्रयोग किया गया है, इस बात का विचार किए बिना कि उन्हें समान में निर्यात किया जा रहा है जैसा कि आयातित किया गया था अथवा स्वरूप में अन्य वस्तुओं के समान उत्पादित, मिश्रित, संयोजित किया जा रहा है या अन्य बंधक माल गोदामों को स्थानांतरित किया जा रहा है अथवा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत, ड्राँ बैक योजना के अंतर्गत आयातकों को विक्रय किया जा रहा है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिकारी शुल्क को पहलेही कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करते हुए सब्सिडी कार्यक्रम के प्रति निर्धारित किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि थाइलैंड से सभी अन्य उत्पादक / निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के प्रति कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(xiii) कार्यक्रम सं. 13: थाईलैंड में बिना निवेशों अथवा विद्यमान बहुत कम निवेशों के साथ मूल्य वर्धित लाभ सृजित करने के लिए अग्रिम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली गतिविधियों, देश की विकास के लिए बुनियादी ढांचे में गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन।

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

93. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत विशिष्ट निवेश गतिविधियों के लिए निर्यातों के उत्पादन में प्रयुक्त मशीनरी और कच्ची सामग्री पर आयात शुल्कों से छूट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

94. बी ओ आई ने जनवरी, 2015 से नई निवेश प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। नई योजना के अंतर्गत बोर्ड निवेश क्षेत्र के बजाय निवेश गतिविधि के अनुसार प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करता है। इसका उद्देश्य देश के नए आर्थिक मॉडल के अनुरूप सृजन और उच्च प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना है।

95. निदेशक बोर्ड की घोषणा सं. 2/2557 (2014)2 प्रकारके प्रोत्साहन निर्धारित करती है: गतिविधि आधारित प्रोत्साहन और मेरिट आधारित प्रोत्साहन। गतिविधि आधारित प्रोत्साहनों के लिए, निवेश बोर्ड ने इस प्रोत्साहन को 2 समूहों में वर्गीकृत किया है जो समूह क (क1-क4) और समूह ख (ख1-ख2)। प्रत्येक समूह के लिए, बी ओ आई ने प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्पष्ट और उद्देश्यात्मक मानदंड निर्धारित किए हैं।

96. देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे में गतिविधियां, थाईलैंड में बिना निवेशों या मौजूद बहुत कम निवेशों के साथ मूल्य वर्धित लाभ सृजित करने के लिए अग्रिम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली गतिविधि को समूह क2 के तहत गतिविधियों का वर्णन करने के लिए निर्धारित किया गया मानदंड है। निवेश परियोजनाएं जो समूह क2 के रूप में वर्गीकृत की गई हैं निम्नानुसार लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होंगी: (1) 100% निवेश के लिए, परिकलित 8 वर्षीय निगमित आयकर छूट (भूमि की लागत और 22 कार्यशील पूंजी रहित) (2) मशीनरी पर आयात शुल्क की छूट (3) 1 वर्ष के लिए निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्क की छूट, जिसे बढ़ाया जा सकता है जैसा भी बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए और (4) निवेशकों को मदद करने के लिए अन्य कर – भिन्न प्रोत्साहन।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

97. इस सब्सिडी कार्यक्रम की निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के तहत यथा प्राधिकृत बी ओ आई द्वारा घोषणा की गई है। इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत, विनिर्दिष्ट निवेश परियोजनाएं आयकर से छूट, मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट, निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के आयात शुल्क पर छूट और निवेशकों को मदद करने के उद्देश्य से कर भिन्न अन्य प्रोत्साहनों को प्राप्त करने की हकदार है। सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्धन प्रोत्साहन पैकेज का भाग है।

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर भिन्न प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रत्येक प्रोत्साहन की पहले ही जांच कर ली गई है प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारी शुल्क लागू किया गया है। इसलिए,

प्राधिकारी धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के प्रति कर-भिन्न प्रोत्साहनों की सीमा तक अतिरिक्त प्रतिकारीता शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(xiv) कार्यक्रम सं. 14: उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन, जो थाईलैंड में पहले से मौजूद कुछ निवेशों के साथ, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं.

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

99. याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मशीनरी और कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क और निगमित आयकर से छूट प्रदान की गई है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

100. बी ओ आई ने जनवरी, 2015 से नई निवेश प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। नई योजना के अंतर्गत, बोर्ड निवेश क्षेत्र के बजाय निवेश गतिविधि के अनुसार प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करता है। इसका उद्देश्य देश के नए आर्थिक मॉडल के अनुरूप मूल्य सृजन और उच्च प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना है।

101. निदेशक बोर्ड की घोषणा सं. 2/2557 (2014)2 प्रकार के प्रोत्साहन निर्धारित करती है: गतिविधि आधारित प्रोत्साहन और मेरिट आधारित प्रोत्साहन। गतिविधि आधारित प्रोत्साहनों के लिए, निवेश बोर्ड ने इस प्रोत्साहन को 2 समूहों में वर्गीकृत किया है जो समूह क (क1-क4) और समूह ख (ख1-ख2)। प्रत्येक समूह के लिए, बी ओ आई ने प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्पष्ट और उद्देश्यात्मक मानदंड निर्धारित किए हैं।

102. समूह क 3 के अंतर्गत गतिविधियों को वर्णित करने के लिए निर्धारित मानदंड है “उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियां, जो थाईलैंड में पहले से विद्यमान कुछ निवेशों के साथ देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियां” हैं। निवेश परियोजनाएं जो समूह क-3 के रूप में वर्गीकृत की गई हैं, निम्नानुसार लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होंगी: (1) 100% निवेश के लिए परिकलित 5 वर्षीय निगमित आयकर छूट (भूमि की लागत और कार्यशील पूंजी के बिना) (2) मशीनरी पर आयात शुल्क की छूट (3) 1 वर्ष के लिए निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्क की छूट जिसे बढ़ाया जा सकता है जैसा भी बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए और (4) निवेशकों की मदद करने के उद्देश्य से अन्य कर-भिन्न प्रोत्साहन।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

103. इस सब्सिडी कार्यक्रम की निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के तहत यथा प्राधिकृत बी ओ आई द्वारा घोषणा की गई है। विनिर्दिष्ट निवेश परियोजनाएं आयकर से छूट, मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट, निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के आयात शुल्क पर छूट और निवेशकों की मदद करने के उद्देश्य से कर - भिन्न अन्य प्रोत्साहनों को प्राप्त करने की हकदार है। सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्धन प्रोत्साहन पैकेज का भाग है।

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रत्येक प्रोत्साहन की पहले ही जांच कर ली गई है और प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारी शुल्क लिया गया है। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के प्रति कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xv) कार्यक्रम सं. 15: प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि में बढ़ोतरी के लिए मेरिट आधारित प्रोत्साहन

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

105. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे परियोजनाओं, जिन्होंने निवेश किया है अथवा गतिविधियों पर व्यय को निर्धारित किया है, वो एक, दो या तीन वर्षों के लिए निगमित आयकर से अतिरिक्त छूट प्राप्त करेंगी।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

106. निवेश बोर्ड ने जनवरी, 2015 के बाद से एक नई निवेश प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। नई योजना के तहत, बोर्ड निवेश जोन के स्थान पर निवेश गतिविधि के अनुसार प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करता है। इसका उद्देश्य देश के नए आर्थिक मॉडल के अनुसार मूल्य सृजन और उच्च प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना है।

107. निदेशक बोर्ड की घोषणा सं. 2/2557 (2014)2 प्रकार के प्रोत्साहन निर्धारित करती है: गतिविधि आधारित प्रोत्साहन और मेरिट आधारित प्रोत्साहन। मेरिट आधारित प्रोत्साहनों का उद्देश्य अधिक निवेश को आकर्षित करना और बढ़ावा देना या मेरिट आधारित गतिविधियों पर व्यय करना है जो कुल मिलाकर देश या उद्योग को लाभ पहुंचाती हैं। इसलिए, परियोजनाएं जिनमें निवेश किया गया है या निर्धारित मेरिट गतिविधियों पर व्यय किया गया है, प्रदत्त प्रोत्साहन के रूप में एक अतिरिक्त मेरिट आधारित प्रोत्साहन की पात्र है जो परियोजनाएं गतिविधि आधारित प्रोत्साहनों के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए हकदार हैं।

108. मेरिट आधारित प्रोत्साहनों को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं (1) प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि पर मेरिट (2) विकेंद्रीकरण पर मेरिट और (3) औद्योगिक क्षेत्र विकास पर मेरिट। इसलिए, प्रतिस्पर्धी वृद्धि पर मेरिट आधारित प्रोत्साहन तीन प्रकार के मेरिट आधारित प्रोत्साहनों में से एक है जो बी ओ आई ऐसी परियोजनाओं को प्रदान करता है जो ऐसी गतिविधियों पर निवेश करती हैं या व्यय करती हैं जैसा कि बी ओ आई की घोषणा सं. 2/2557(2014) में निर्धारित किया गया है। बी ओ आई ने प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि पर मेरिट आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्पष्ट और उद्देश्य परक मानदंड निर्धारित किया है। ये मानदंड जनता को भी सूचित किए गए हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

109. इस सब्सिडी कार्यक्रम की निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के तहत यथा प्राधिकृत बी ओ आई द्वारा घोषणा की गई है। सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहन पैकेज का भाग है।

110. वित्तीय योगदान आयकर से छूट के रूप में उपलब्ध कराया गया है और इसके द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि आयकर से छूट के विरुद्ध प्रतिकारीता शुल्क लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, इस सब्सिडी कार्यक्रम के प्रति कोई अतिरिक्त प्रतिकारीता शुल्क लागू किए जाने की जरूरत नहीं है।

(xvi) कार्यक्रम सं. 16: निर्यातों पर वैट छूट**क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध**

111. याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वस्तुओं के निर्यात पर वैट से छूट प्रदान की गई है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

112. कोई व्यापारी, जो थाईलैंड में वस्तुओं के विक्रय या सेवाओं के प्रावधानों में अपना व्यापार करता है और ऐसा व्यापार की कर आधार का निर्धारित मूल्य है, तो ऐसा व्यापारी मूल्य वर्धित कर के लिए उत्तरदायी है जैसा कि राजस्व कोड की धारा 80/2 में निर्धारित किया गया है।

113. राजस्व कोड की धारा 80/1 के अनुसार, जिन वस्तुओं का व्यापार धारा 81(3) के अंतर्गत मूल्य वर्धित कर से छूट प्राप्त है, मूल्य वर्धित कर संगणना की शून्य दर का प्रयोग करेगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

114. थाईलैंड के राजस्व कोड की धारा 82/16 में वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री में संलग्न व्यापारी द्वारा मूल्य वर्धित कर की अदायगी के लिए व्यवस्था की गई है। तथापि, यह मूल्य वर्धित कर दर कुछ विनिर्दिष्ट उद्यमों के लिए शून्य है।

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम में वस्तुओं के निर्यात पर मूल्य वर्धित कर से छूट की व्यवस्था की गई है जो अन्य व्यापारों पर प्रयोज्य है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम में निर्यातित वस्तुओं पर कर की माफी के लिए व्यवस्था की गई है, जो अन्यथा समान उत्पादन द्वारा वहन की जाती है जब वह एस सी एम करार की पाद टिप्पणी (फुटनोट) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (ख)(i) के अनुसरण में घरेलू खपत के लिए बनाई गई हो। इसलिए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति कोई प्रतिकारीता शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(xvii) कार्यक्रम सं. 17: समर्थनकारी विशेषाधिकार

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

116. याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत मशीनरी आयात शुल्क की अदायगी से पर और आयकर से छूट प्रदान की गई है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

117. निवेश प्रोत्साहन अधिनियम बी ई 2520 (1977) के अंतर्गत, जो बी ओ आई द्वारा उपलब्ध कराता है, कराए गए प्रोत्साहनों में निम्न शामिल हैं:

1. धारा 28: मशीनरी पर आयात शुल्कों में छूट
2. धारा 30: कच्ची सामग्री या अनिवार्य सामग्रियों के लिए आयात शुल्कों की कटौती
3. धारा 31: निगमित आयकर की छूट
4. धारा 35(1): निगमित आयकर की 50 प्रतिशत कमी
5. धारा 35(2): परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति की लागतों से दुगुनी कमी
6. धारा 35(3): सुविधाओं की स्थापना या निर्माण की लागत से अतिरिक्त 25 प्रतिशत कमी।
7. धारा 36: कच्ची और अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्कों की छूट

118. बी ओ आई विदेशी निवेशकों की सुगमता के लिए कर-भिन्न प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराता है जैसे विदेशियों को निवेश अवसरों का अध्ययन करने के लिए किंगडम में प्रवेश करने, भूमि को क्रय करने, विदेशी मुद्रामें विदेश में धन को ले जाने अथवा प्रेषण करने की अनुमति।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

119. प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया है कि निवेश कर प्रोत्साहन अधिनियम बी ई 2520 (1977) के अंतर्गत, कर प्रोत्साहन जो बी ओ आई उपलब्ध कराता है जैसे कि (1) धारा 28: मशीनरी पर आयात शुल्कों में छूट (2) धारा 30:

कच्ची सामग्री या अनिवार्य सामग्रियों के लिए आयात शुल्कों में कटौती (3) धारा 31: निगमित आयकर की छूट (4) धारा 35(1) निगमित आयकर की 50 प्रतिशत कटौती (5) धारा 35(2): परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति की लागतों से दुगुनी कटौती (6) धारा 35(3): सुविधाओं की स्थापना या निर्माण की लागत से अतिरिक्त 25 प्रतिशत कटौती (7) धारा 36: कच्ची और अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्कों की छूट पहले ही अन्य योजनाओं के अंतर्गत शामिल है। इसलिए प्राधिकारी ने इस योजना को अलग से मात्रा में निर्धारित करना उचित नहीं समझा, इससे लाभ की दोहरी गणना हो जाएगी।

120. इसलिए, इस सब्सिडी कार्यक्रम के प्रति कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लागू किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xviii) कार्यक्रम सं. 18: सीमा शुल्क कानूनों की धारा 19 के तहत शुल्क वापसी

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

121. याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, निर्यातक कंपनियां आयातित वस्तुओं पर अदा किए गए सीमा शुल्क का रिफंड प्राप्त करती हैं जहां ऐसी वस्तुओं का उत्पादन, मिश्रण, संयोजन अथवा पैकिंग की जाती है और तत्पश्चात निर्यात किया जाता है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

122. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 29 के तहत शुल्क वापसी से तात्पर्य पहले से अदा किए गए आयात शुल्क का रिफंड या आयातों पर निर्धारित गारंटी की वापसी से है जिनका उत्पादन, मिश्रण, संयोजन या पैकिंग और तत्पश्चात निर्यात किया गया है।

123. शुल्क वापसी के लिए पात्र वस्तुएं इस प्रकार हैं:

1. कच्ची सामग्रियां जो निश्चित रूप से निर्यातों में देखी जाती है। जैसे- सिले कपड़ों में फैब्रिक, बटन, जिपर और धागा, प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक शीटिंग आदि।
2. विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे रूप से प्रयुक्त और निर्यातों में अंतर्निहित किंतु निश्चित रूप से न देखी गई कच्ची सामग्री जैसे – डब्बाबंद भोजन में संरक्षक (प्रिजरवेटिव), सिले हुए कपड़ों में स्टिफनिंग एजेंट, सेलोफोन में ग्लू के लिए सोल्वेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जंगरोधी एजेंट आदि।
3. विनिर्माण प्रक्रिया में जरूरी कच्ची सामग्री जैसे – उत्पादों में प्रयुक्त परिमाण संबंधी सामग्री और ब्लीचिंग एजेंट्स, सैंड पेपर, मंजाई पाउडर, वार्निश, वेलवेट, मंजाई एजेंट्स, चॉक, कार्बन पेपर और पैटर्न।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

124. शुल्क वापसी के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 29 में व्यवस्था की गई है। सब्सिडी कार्यक्रम में कच्ची सामग्रियों पर अदा किए गए आयात शुल्क के रिफंड के लिए व्यवस्था की गई है जिसे उत्पादन, मिश्रण, संयोजन या पैकिंग और तत्पश्चात निर्यात किया गया है। रचना तंत्र के बारे में प्राधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं है जो सुनिश्चित करता है कि आयात शुल्क की अधिक माफी नहीं दी गई है और यह कि शुल्क वापसी की राशि निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर अदा की गई शुल्क की राशि से अधिक नहीं होगी।

125. अतः, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम में राजस्व की सीमा के रूप में वित्तीय अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। सब्सिडी कार्यक्रम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि यह निर्यात के लिए प्रासांगिक है। इसलिए प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम प्रतिकारीता शुल्क के योग्य है। तथापि, प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया था कि कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क की छूट के प्रति प्रतिकारी शुल्क लागू किया जाना चाहिए और इसलिए इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xix) कार्यक्रम सं. 19: सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्र

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

126. याचिकाकर्ता ने इस सब्सिडी कार्यक्रम की विद्यमानता के बारे में कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

127. मुक्त क्षेत्र योजना थाईलैंड में विनिर्माण के साथ संबद्ध कुछ विशिष्ट निरुत्साहनों को हटा कर थाईलैंड आधारित प्रचालनों को प्रोत्साहित करती है। क्षेत्र में उत्पादित किए गए उत्पादों को टैरिफ आकलन के प्रयोजन हेतु प्रतिपादित किया गया है जैसे कि वे विदेश में विनिर्मित किए गए हों। मुक्त व्यापार क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क से राहत, निर्यातित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र में आयातित माल के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अनिवार्यताओं से राहत, आदि।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मुक्त व्यापार क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रचालन अथवा किन्हीं अन्य गतिविधियों के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 136 के तहत सीमा शुल्क महानिदेशक द्वारा नामित क्षेत्र है।

129. ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं के टैरिफ आकलन के प्रयोजन हेतु मुक्त व्यापार क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र के रूप में माना गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को बहुत से प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है। कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क से छूट और मशीनरी पर आयात शुल्क पर छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए, प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि इन प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xx) कार्यक्रम सं. 20: औद्योगिक संपदा प्राधिकरण विधि के तहत निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई पी जेड)

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

130. याचिकाकर्ता ने इस सब्सिडी कार्यक्रम की विद्यमानता के बारे में कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

131. निर्यात संसाधन क्षेत्र में स्थित कारोबार प्रचालक भवन के निर्माण/प्रमाणन, कारोबार प्रचालन के प्रकार में अतिरिक्त व्यापार/परिवर्तन, कर-विशेषाधिकार (केवल आई - ई ए - टी मुक्त क्षेत्र में स्थापित) अथवा गैर-कर विशेषाधिकार (सामान्य औद्योगिक क्षेत्र और आई - ई ए - टी मुक्त क्षेत्र में स्थापित) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

132. विशेषाधिकार स्थापित प्रचालनों के स्थान/क्षेत्र पर आधारित हैं। प्रोत्साहन सभी औद्योगिक प्रचालनों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हें औद्योगिक संपदाओं में विशेषाधिकार क्षेत्रों में औद्योगिक प्रचालनों में संलग्न होने की अनुमति

प्रदान की गई है। पी ओ आई के दौरान थाईलैंड में सत्तावन सामान्य औद्योगिक क्षेत्र और तेरह आई- ई ए- टी मुक्त (निर्यात संसाधन) क्षेत्र स्थित थे।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

133. निर्यात संसाधन क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को कर प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क से छूट के रूप में से और मशीनरी पर आयात शुल्क पर छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए प्राधिकारी ने पहले ही जांच की है और लाभ के बराबर माना है। इसलिए, इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

थाईलैंड से उत्पादक/निर्यातक

एस ई आई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कं. लिमि.

(उत्पादक/निर्यातक)

134. एस ई आई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कं. लि. ("एस टी ई सी") थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक हैं। एस टी ई सी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं एस टी ई सी द्वारा भारत को सीधे निर्यात की जाती हैं। एस टी ई सी ने प्रश्नावली उत्तर दायर किया और उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई।

135. प्राधिकारी ने एस टी ई सी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया है और उन कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है जिसके लिए पी ओ आई के दौरान लाभ प्राप्त अथवा प्रोदभूत किए गए थे। प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि सब्सिडी कार्यक्रमों का परिणाम पूर्वोक्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान के प्रावधान में हुआ जो अन्यथा रूप से देय था। परिणामस्वरूप, इस अनुदान के प्राप्तिकर्ता के रूप में एस टी ई सी को लाभ प्रदान किया गया। सब्सिडी कार्यक्रम भी विनिर्दिष्ट था क्योंकि वे एस टी ई सी सहित कुछ विशेष उपक्रमों तक सीमित थे।

136. नीचे दी गई सारणी सब्सिडी कार्यक्रमों के नाम और तदनुसारी सब्सिडी मार्जिन उपलब्ध कराती है।

कार्यक्रम सं.	अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/टिप्पणियां	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 2	निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित मशीनरी पर आयात शुल्क की छूट	एस टी ई सी द्वारा विशिष्ट मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट प्राप्त की गई है और इसके विवरण इस ई क्यू आर के खंड -II के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। मशीनरी के आयात पर आयात शुल्क से छूट के विवरणों के लिए कृपया इसके साथ संलग्न प्रदर्श13 देखें।	***	0-1%

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एस ई आई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कं. लि. के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम है।

थाईलैंड के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों का सारांश

138. थाईलैंड से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। थाईलैंड से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिकारी शुल्क को संबंधित कार्यक्रमों के प्रतिकारीता और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
कार्यक्रम सं. 2	निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के तहत मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट	***	0-1
कार्यक्रम सं. 3/4/7/8/9/10/15	निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के अंतर्गत आय कर से छूट	***	0-5
कार्यक्रम सं. 4/5/6/11/12/18/19/20	निर्यात के लिए उत्पादन में प्रयोग के लिए आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट	***	0-1
कार्यक्रम सं. 13/14	थाईलैंड में किसी निवेश या बहुत कम निवेश के साथ मूल्य वर्धित को सृजित करने के लिए अग्रिम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए देश के विकास गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे में गतिविधियों को प्रोत्साहन	***	0-1
योग		***	0-5%

मलेशिया

च. 6. याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

(i) कार्यक्रम सं. 1: बाजार विकास अनुदान (एम डी जी)

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

139. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि यह योजना निर्यात संबर्द्धन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एस एम ई के लिए मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण (एम आई डी ए) द्वारा आरंभ की गई है। एम डी जी कार्यक्रम के अंतर्गत किसी एस एम ई के लिए अधिकतम अनुदान आकार एम 200,000। एस एम ई को कम से कम 60% मलेशियाई इक्विटी स्वामित्व के साथ कंपनी अधिनियम, 1965 के अंतर्गतन समविष्ट किया जाना चाहिए। बाजार विकास अनुदान (एमडीजी) – 2016 के लिए साक्ष्य और कानूनी आधार सामान्य नीतियां, सुविधाएं और दिशा-निर्देश हैं।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

140. यह निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों में एस एम ई को बढ़ाने के लिए 11वें मलेशिया योजना (2016-2020) के अंतर्गत संरचनाबद्ध एक सतत कार्यक्रम है।

141. एम डी जी निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों अर्थात् अंतराष्ट्रीय व्यापार मेलों, व्यापार एवं निवेश मिशन/निर्यात त्वरण मिशन, अंतराष्ट्रीय विदेशी सम्मेलनों और सुपर मार्केटों, हायपर मार्केट अथवा विदेशी खुदरा केंद्रों में मेड-इन-मलेशिया

उत्पादों के लिए सूचीकरण शुल्क में प्रतिभागिता के लिए 200,000 आर एम तक एक प्रतिपूर्ति अनुदान के आवेदन करने हेतु मलेशियाई एस एम ई के लिए अवसर प्रदान करता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार विकास योजना (एम डी पी) को 2002 में आरंभ किया गया था। यह 11वीं मलेशियाई योजना (2016-2020) का भाग है। यह निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों में एस एम ई की प्रतिभागिता में वृद्धि करने के लिए अभिप्रेरित है। एम डी पी निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों अर्थात् अंतराष्ट्रीय व्यापार मेलों, व्यापार एवं निवेश मिशन/निर्यात त्वरण मिशन, अंतराष्ट्रीय विदेशी सम्मेलन और सुपर मार्केटों, हायपर मार्केट अथवा विदेशी खुदरा केंद्रों में मेड-इन-मलेशिया उत्पादों के लिए सूचीकरण शुल्क में प्रतिभागिता के लिए 200,000 आर एम तक एक प्रतिपूर्ति अनुदान के आवेदन करने हेतु मलेशियाई एस एम ई के लिए अवसर प्रदान करता है।

143. सब्सिडी कार्यक्रम में निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में वित्तीय योगदान के लिए व्यवस्था की गई है और इस प्रकार लाभ प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह निर्यात पर प्रासांगिक है। अतः, प्राधिकारी धारित करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के प्रति प्रतिकारी शुल्क लागू किया जाना चाहिए।

(ii) कार्यक्रम सं. 2: विज्ञान निधि

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

144. याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि यह अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुदान है जो अनुप्रयुक्त विज्ञान में जानकारी की उन्नति और नए विचारों के आविष्कार में योगदान कर सकता है। निधि सभी अनुसंधान वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के लिए उपलब्ध है जो सरकारी अनुसंधान संस्थान (जी आर आई), सरकारी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीकरण (एस टी आई) एजेंसियों और पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायरलर्निंग (आई एच एल) में संविदात्मक/स्थायी आधार पर नियोजित हैं।

ख. थाईलैंड की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

145. विज्ञान निधि 1 जनवरी, 2017 से प्रस्तावित नहीं की गई है। इसके लिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीकरण मंत्रालय (एम ओ एस टी आई) द्वारा आधिकारिक घोषणा की गई है। रिकार्डों के आधार पर, जाचांधीन कंपनियों में से कोई भी विज्ञान निधि की प्राप्तकर्ता नहीं हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम ई एस टी ई सी सी) द्वारा संचालित किया जाता है।

147. अधिक प्रभाव और नवीन अनुसंधान पर बल देते हुए अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विज्ञान निधि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुदान है। राजसहायता कार्यक्रम को 01 जनवरी 2017 से समाप्त कर दिया है। राजसहायता कार्यक्रम 31 दिसम्बर 2016 तक प्रचालन में था तथा इसके प्रचालन की अवधि के दौरान राजसहायता कार्यक्रम में निधियों को प्रत्यक्ष तौर पर अन्तरण करने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया गया तथा उसके द्वारा लाभ प्रदान किया गया था। राजसहायता कार्यक्रम विशिष्ट भी था क्योंकि यह आर. एण्ड. डी. परियोजनाओं में लगे उद्यम को उपलब्ध कराया गया था। तथापि, राजसहायता कार्यक्रम केवल अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के लिए ही उपलब्ध था और इसलिए यह मलेशिया में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के लिए उपलब्ध नहीं

था। अतः प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम के लिए कोई समतुल्य शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

(iii) कार्यक्रम संख्या 3: टेक्नो निधि

क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन

148. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि यह एक अनुदान योजना है जिसका उद्देश्य मलेशिया के उद्यमियों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों (आई. एच. एल.) और अनुसंधान संस्थानों के विकास एवं सफलता पूर्वक नवीनता कार्यों को प्रोत्साहन देना होता है। इसके द्वारा नए-नए कारोबारों का सृजन करने तथा आर्थिक धन-सम्पत्ति पैदा करने के लिए वाणिज्यिक क्षमता सहित पूर्व - व्यापारीकरण चरण तक प्रौद्योगिकी विकास हेतु निधियों की व्यवस्था की जाती है। परियोजना में नवीनतम उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं के व्यापारीकरण को प्रेरित करने के प्रौद्योगिकीय नवीनता के तत्व निहित होने चाहिए। आवेदक अनुसंधानकर्ता एवं एस. एम. ई., आई. एच. एल., अनुसंधान संस्थानों एवं एस. टी. आई. एजेंसियों के अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। सभी श्रेणियों की कंपनियों के पास मलेशियाईयों के द्वारा धारित न्यूनतम 5 प्रतिशत इक्विटी होने चाहिए। एस. एम. ई. के अधीन आवेदक के पास न्यूनतम आर. एम. 10,000 नकद प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए, तथापि स्टार्ट-अप्स को उचित स्पष्टीकरण के साथ इससे छूट होती है। कुछ मंत्रालय/विभाग/एजेंसी के स्कोप/पोर्ट फोलियों के अधीन परियोजनाएं के अधीन परियोजनाएं तथा सी. ई. एस. एस. निधि जैसे आन्तरिक अनुसंधान निधियन वाले अनुसंधान संस्थान टेक्नो निधि के अधीन पात्र नहीं होते हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

149. एम. ई. एस. टी. ई. सी. सी. यह मानती है कि इनमें से कुछ बाधाओं पर काबू पाने के लिए अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं उद्योग के अनुसंधानकर्ता एक साथ इसमें कार्य कर सकते हैं; अतः इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि ज्यादा आर. एण्ड. डी. उत्पादों को बाजार में लाया जाता है। इस प्रकार देश के लिए आर्थिक लाभों में बढ़ावा होता है। अतः पूर्व - व्यापारीकरण निधियों अर्थात् टेक्नो निधि कही गई इस श्रेणी की निधियां शुरू की गई थीं।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

150. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम एम. ई. एस. टी. ई. सी. सी. के द्वारा लागू किया है। मलेशिया में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए शासित कोई कानून, विनियमन अथवा डिक्री नहीं है। एम. ई. एस. टी. ई. सी. सी. ने अनुसंधान और विकास पहलों में अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं उद्योग की सहायता करने के लिए पूर्व - व्यापारीकरण निधि अथवा टेक्नो निधि का सृजन किया है।
151. राजसहायता कार्यक्रम के द्वारा निधियों में प्रत्यक्ष अन्तरण के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। राजसहायता, कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उच्चतर शिक्षण संस्थानों एवं अन्य अनुसंधान संस्थाओं के अलावा एस. एम. ई. के लिए उपलब्ध है। प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम पर समतुल्य शुल्क लगाना चाहिए।

(iv) कार्यक्रम संख्या 4: इन्नो निधि

क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन :

152. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि इस अनुदान स्कीम के अन्तर्गत नए अथवा मौजूद उत्पादों, प्रक्रिया अथवा सेवाओं के विकास/सुधार करने के लिए नवीनता के संघटकों सहित वित्तीय - व्यवस्था की जाती है। परियोजना का उत्पादो, प्रक्रियाओं और सेवाओं का विकास करने के लिए आर्थिक महत्व होना चाहिए जिससे समाज के कल्याण में सुधार हो। निधियों को उद्यम नवीनता निधि और समुदाय नवीनता निधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्ववर्ती निधि व्यक्ति, अकेले प्रोपराइटर, माइक्रो कंपनियों तथा लघु कंपनियों के लिए लागू होती है, जबकि उत्तरवर्ती निधि पंजीकृत

एसोसिएशनों/एन. जी. ओ., पंजीकृत कम्पनियों और समुदाय समूहों के लिए लागू होती है। एस. एम. ई. के अधीन आवेदक के पास आर.एम. 10,000 नकद न्यूनतम प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए, जबकि स्टार्ट-अप को इससे छूट होती है। यह राशि परियोजना के अनुसार अलग-अलग होती है, लेकिन यह आर. एम. 500,000 से अधिक नहीं हो सकती है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

153. इस कार्यक्रम में नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सिस्टमों की नवीनता के लिए सहायता प्रदान करनी होता है जिसके द्वारा ग्राहकों, कारोबारों और समाज के लिए महत्व का सृजन किया जा सकता है। धन के सृजन एवं समाज कल्याण के लिए नवीनता के महत्व को महसूस करते हुए इन्नों निधि शुरू की गई थी।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

154. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम एम. ई. एस. टी. ई. सी. सी. से शासित होता है। यह कार्यक्रम को शासित करने के लिए कोई कानून अथवा कानूनी विनियमन नहीं है। उद्यमियों के द्वारा नवीनता को बढ़ावा देने के लिए एम. ई. एस. टी. ई. सी. सी. ने नवीनता निधि का सृजन किया।
155. इस कार्यक्रम के द्वारा निधियों में प्रत्यक्ष अन्तरण के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। राजसहायता, कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह नवीनता कार्यक्रमलाप को पूरा करने के लिए उद्यम के लिए विशेष है। इसलिए प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम पर समतुल्य शुल्क लगाना चाहिए।

(v) कार्यक्रम संख्या 5: सहारा (क्रेडल) निवेश कार्यक्रम

क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन :

156. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि यह अनुदान योजना मलेशिया को प्रथम विकास एवं प्रौद्योगिकी व्यापारीकरण निधि कार्यक्रम है, जिसमें मलेशिया के प्रवर्तक और महत्वाकांक्षी उद्यमी, व्यापारीकरण की प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अपने अनुचित विचारों को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य उद्यमों अथवा स्थानीय स्टार्ट-अप के लिए बदलते हैं। दो प्रकार के सशर्त अनुदान हैं – प्रारंभ-पूर्व (प्री-सीड) विकास (सी. आई. पी. प्रेरक, यू- सी. आई. पी. प्रेरक) और प्रारम्भ (सीड) व्यापारीकरण (सी. आई. पी.- 500) सी. आई. पी. प्रेरक और यू- सी. आई. पी. प्रेरक के अन्तर्गत आवेदक 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के मलेशिया वाले, मलेशिया के स्थायी निवासी होने चाहिए। इस टीम में कम से कम 2 और अधिकतम 5 आवेदक होने चाहिए। सी. आई. पी. प्रेरक और यू-सी. आई. पी. प्रेरक के अधीन अधिकतम वित्तीय व्यवस्था आर. एम. – 1,50,000 तथा सी. आई. पी. 500 में आर. एम. 5,00,00 होती है।

ख. मलेशिया सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

157. क्रेडल निवेश कार्यक्रम में यह सुनिश्चित होता है कि महत्वाकांक्षी उद्यमी क्रेडल के द्वारा उपलब्ध करायी गई आवश्यक सहायता से प्रमुख स्टार्ट अप बनते हैं। क्रेडल के दो (2) किस्म के उत्पाद होते हैं जो अनुदान वित्तीय सहायता और इक्विटी निवेश वाले होते हैं। अनुदान उत्पाद, सी. आई. पी. 300 एक प्री-सीड कार्यक्रम है जो आर. एम. 300,000 तक अनुदान एवं मूल्य संबंधित सहायता उपलब्ध कराता है। अन्य उत्पाद डी. ई. क्यू. 800 है जिसमें आर. एम. 300,000 तथा आर. एम. 800,000 के बीच उन क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश का प्रावधान होता है जिनके पास विकास की अच्छी संभावना होती है। ऐसे सभी व्यक्तियों/फर्मों ने आवेदन किया है और पात्रता संबंधी सभी मानदण्डों को पूरा करती हैं, ऐसे सभी को फण्डिंग प्राप्त करने पर लाभ नहीं मिलेगा।
158. छंटनी किए गए आवेदकों को भी इस योजना से लाभ उठाने से पूर्व अनुमोदन समितियों (अनुदान) अथवा निवेश समितियों (इक्विटी) से सहमति लेनी होती है। इस कार्यक्रम के लाभ से पारम्परिक कारोबारों को विशेष तौर पर अलग-अलग रखा जाता है।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

159. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्रेडल की वर्ष 2003 में वित्त मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी के रूप में स्थापना की गई थी। स्टार्ट - अप कम्पनियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रेडल प्रभावी अनुदान, इक्विटी, व्यापारीकरण सहायता, कोचिंग आदि उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम को शासित करने के लिए कोई कानून अथवा विधिक विनियमन नहीं है। डिजीटल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगी कम्पनियों के द्वारा इस कार्यक्रम को उपयोग में लाया जाता था।
160. इस कार्यक्रम के द्वारा निधियों के प्रत्यक्ष अन्तरण के रूप में वित्तीय अंशदान उपलब्ध कराया जाता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह न्यूनतम 5 प्रतिशत मलेशिया इक्विटी से स्टार्ट - अप उद्यमी (कम से कम 3 वर्षों) तक सीमित होता है। तदनुसार, राजसहायता कार्यक्रम समतुल्य योग्य है। तथापि, इस कार्यक्रम का मलेशिया में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक के द्वारा उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जांचाधीन उत्पाद के लिए कोई स्टार्ट-अप उद्यम नहीं रहा है। अतः प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम के प्रति समतुल्य शुल्य नहीं लगाया जाना चाहिए।

(v) कार्यक्रम संख्या 6 : निर्यात उत्कृष्ट पुरस्कार**क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन**

161. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि यह एक भत्ता होता है जो निर्धारित उत्पाद के निर्यातों को बढ़ाने के लिए दिया है। दिया गया भत्ता बढ़े हुए निर्यातों के मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर होता है जो 70 प्रतिशत सांविधिक आय से कटौती करने योग्य होता है। इसकी पात्रता यह होती है कि कम्पनी के द्वारा निर्धारित उत्पाद का निर्यात करना चाहिए।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

162. यह पुरस्कार निर्यात निष्पादन, बाजार में प्रभाव तथा बाजार प्रचालन (कार्य) में उत्कृष्ट कम्पनियों को मान्यता एवं स्वीकार करने के लिए होता है। यह कार्यक्रम वर्ष 2012 से बन्द कर दिया गया है।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

163. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एम. आई. टी. आई.) के द्वारा शासित किया जाता है। यह पुरस्कार निर्यात निष्पादन, व्यापार में प्रभाव, बाजार प्रचालन तथा समुदाय एवं उद्योग में सहयोग देने के लिए कम्पनियों को दिया जाता है। वर्ष 2012 में एम. आई. टी. आई. ने इस पुरस्कार को बन्द कर दिया है और व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार को बदलकर निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार कर दिया है।
164. इस कार्यक्रम में पूर्ववर्ती राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान अंशदान के लिए प्रावधान होता है, जो अन्यथा देय है तथा उसके द्वारा लाभ प्रदान किए जाते हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी होता है क्योंकि यह निर्यात पर आश्रित होता है तथा यह ऐसे उद्यम तक सीमित होता है जो बाजार में प्रभाव, समुदाय के लिए सहयोग देने आदि से संबंधित अन्य मानदण्डों को पूरा करते हैं। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारित किया है कि आयकर से छूट प्रदान करते हुए राजसहायता कार्यक्रम पर समतुल्य शुल्क लगाना चाहिए। प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त समतुल्य कर नहीं लगाना चाहिए।

(vi) कार्यक्रम संख्या 7 : निर्यात क्रेडिट और निर्यात संबंधी वित्त व्यवस्था**(क) याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन**

165. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि यह योजना निर्यात क्रेडिट के रूप में है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यातकों के लिए अल्पकालिक और लदान के बाद वित्त व्यवस्था होती है। निर्यातक अपने निर्यात आर्डर की 95 प्रतिशत कीमत तक वित्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

166. लदान पूर्व तथा लदान के बाद वित्त व्यवस्था के रूप में मलेशिया के निर्यातों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात क्रेडिट रिफाइनंसिंग (ई. सी. आर.) योजना का उपयोग किया जाता है। मलेशिया में निगमित तथा निर्यात कार्यकलाप में शामिल सभी कंपनियों के लिए ई. सी. आर. उपलब्ध होता है।
167. ई. सी. आर. योजना की प्रचालन प्रक्रिया ई. सी. आर. दिशा-निर्देश से शासित होती है जो एग्जिम बैंक के द्वारा जारी की जाती है।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

168. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम मलेशिया के निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) के द्वारा प्रशासित होता है। निर्यात क्रेडिट रिफाइनंसिंग कार्यक्रम में उत्पादों का निर्यात करने हेतु वित्त व्यवस्था हेतु उद्यम को ऋण दिया जाता है। यह कार्यक्रम बैंक के द्वारा जारी किए गए निर्यात – क्रेडिट रिफाइनंसिंग संबंधी दिशा-निर्देश से शासित होता है जिसमें कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ उत्पाद की पात्रता सहित (उत्पादों की निषेध सूची, जो बैंक द्वारा बनायी जाती है) पात्रता संबंधी मानदण्ड के लिए प्रावधान होता है। राजसहायता कार्यक्रम किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है तथा मलेशिया में निगमित सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है।
169. एग्जिम बैंक सरकार के स्वामित्व वाला विकास वित्तीय संस्थान है। यह मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन्कारपोरेटिड (इन्क) का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक एजेंसी के रूप में एग्जिम बैंक की अधिदेशाधीन भूमिका सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट की है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा विदेशी परियोजनाओं के निर्यात तथा आयातों के लिए वित्त एवं सहायता देने के लिए क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है जिसमें गैर-पारम्परिक बाजारों पर बल दिया जाता है, निर्यात क्रेडिट बीमा सेवाओं, निर्यात वित्त व्यवस्था बीमा, विदेशी निवेश बीमा तथा गारंटी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है।
170. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि एग्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है क्योंकि इस पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए सरकारी प्राधिकारी के पास इसके बारे में अधिकारी होता है। तदनुसार, किसी सार्वजनिक निकाय के द्वारा निधियों के प्रत्यक्ष अन्तरण के रूप में एग्जिम बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण वित्तीय अंशदान होता है। प्राप्तकर्ता से प्रदत्त लाभ एग्जिम बैंक के द्वारा ली गई ब्याज की राशि तथा तुलनीय वाणिज्यिक ऋण के लिए ली गई ब्याज की राशि के बीच में आए अन्तर के रूप में होती है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर आश्रित होता है। प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम पर समतुल्य शुल्क लगाना चाहिए।

(viii) कार्यक्रम संख्या 8 : क्रेता क्रेडिट गारंटी

क. याचिकाकर्ता के द्वारा निवेदन

171. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि इस कार्यक्रम के तहत विदेशी क्रेताओं की एग्जिम बैंक की बिना किसी शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी से सहायता की जाती है जिसमें उधारकर्ता बैंक को देय और ब्याज राशि को लौटाने की गारंटी दी जाती है। मलेशिया के निर्यातक बी. सी. जी. का उपयोग करते हुए किसी ऋणदाता से दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए विदेशी क्रेता की सहायता कर सकता है। मलेशिया के निर्यातक को ऐसे भुगतान किया जाता है कि मानो उसने कोई नकद संविदा ऐसे की है, जबकि विदेशी क्रेता के पास ऋणदाता से प्राप्त ऐसे ऋण के माध्यम से एग्जिम बैंक की गारंटी से समर्थन होता है। दिया हुआ प्रमाण एग्जिम बैंक के द्वारा क्रेता क्रेडिट बीमा होता है। इस कार्यक्रम के तहत ऋण राशि किसी नकद संविदा के समर्थन में आर. एम. जेड एम एन का न्यूनतम मूल्य होना चाहिए तथा ऋण लौटाने की अवधि कम से कम दो वर्ष और अधिकतम 15 वर्षों की होनी चाहिए।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

172. बैंकर्स ट्रेड क्रेडिट टकाफुल (बी. टी. सी. टी) विदेशी क्रेताओं की चूक के कारण उनके निर्यातकों के द्वारा भुगतान न करने के जोखिम के प्रति इस्लामिक वित्तीय संस्थान (आई एफ आई) को सुरक्षा प्रदान के लिए निर्मित एक क्रेडिट टकाफुल है। यह

खाता खोलने, टस्तावेजी संग्रह और/अथवा साख पत्र जैसी व्यापार शर्तों पर व्यापार वित्त सुविधा के लिए उपलब्ध होता है।

ख. प्राधिकारी के द्वारा जांच

173. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम एग्जिम बैंक से प्रशासित होता है। इस कार्यक्रम को शासित करने के लिए कोई कानून अथवा विधिक विनियमन नहीं है।
174. प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारण किया है कि एग्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी क्रेताओं की ओर से हुई चूक की वजह से अपने निर्यातकों (ग्राहकों) के द्वारा भुगतान न करने के जोखिम के प्रति वित्तीय संस्थानों को एग्जिम बैंक गारंटी देता है। इस कार्यक्रम के द्वारा निधियों के संभावित प्रत्यक्ष अन्तरण के रूप में वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ता पर प्रदत्त लाभ (i) एग्जिम बैंक से गारंटी लेने के लिए प्राप्तकर्ता के भुगतान किए गए शुल्क और ऐसी गारंटी के लिए किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को भुगतान किए शुल्क के बीच में अन्तर तथा (ii) विचाराधीन ऋणदाता बैंक को ऋण लौटाने (एग्जिम बैंक गारंटी की वजह से सामान्य वाणिज्यिक व्याज दर से कम होने के कारण) तथा ऐसी गारंटी के न होने की स्थिति में भुगतान की जाने योग्य राशि (सामान्य वाणिज्यिक व्याज दर के आधार पर) के बीच अन्तर के बराबर हो। यह राजसहायता कार्यक्रम विशिष्ट भी होता है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर होता है।
175. प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम पर समतुल्य शुल्क लगाना चाहिए।

(ix) कार्यक्रम संख्या 9 पायनीर – स्टेट्स

क. याचिकाकर्ता के द्वारा निवेदन

176. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पायनीर स्टेट्स प्राप्त कम्पनी को कारपोरेट आयकर से कर छूट मिलेगी। जो निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में योगदान दे सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में संबर्धित कार्यकलापों/उत्पादों में निवेशको को इस कार्यक्रम में प्रोत्साहन दिया जाता है। यह विनिर्माण क्षेत्र में अनुमोदित संबर्धित उत्पादों/कार्यकलापों के लिए स्थानीय और विदेशी निवेशकों के लिए लागू होता है। आयकर का भुगतान करने के लिए पांच वर्ष की आंशिक छूट दी जाती है। कंपनी अपना उत्पादन करने के दिन से शुरू हुई अवधि से अपनी 3 प्रतिशत सांविधिक आय पर कम्पनी कर देती है। अग्रगामी अवधि के दौरान लिए गए पूंजीगत छूट तथा संचित हानियों को आगे ले जाया जा सकता है तथा कंपनी बाद की अग्रगामी आय से कटौती की जा सकती है। कार्यक्रम से अस्तित्व के प्रमाण के रूप में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है :-

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- गैट, 1994 के अनुच्छेद xvi:1 तथा सब्सिडीज एण्ड काउण्टरवेलिंग मेजर्स पर करार- मलेशिया, दिनांक 5 अक्टूबर के अनुच्छेद 25 के अनुसरण में नई और पूरी अधिसूचना।
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- ऐसे संबर्धित कार्यकलापों और उत्पादों की सूची जो पायनीर स्टेट्स के विचाराधीन होने के पात्र हैं तथा निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के तहत निवेश कर भत्ता है।
- निवेश संवर्धन अधिनियम 1986 का लॉज ऑफ मलेशिया एक्ट, 327, भाग-II पायनीर स्टेट्स संबंधी धारा 5, 6, 7,
- वेब रिपोर्ट : एग्जिम बैंक की एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंसिंग
- मलेशिया के माध्यम से यू. एस. एक्सट्रयूडिड

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

177. एक संबर्धित कार्यकलाप में लागू लेने के लिए अथवा संबर्धित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए आशयित किसी कंपनी को पायनीर स्टेट्स प्रदान किया जा सकता है। संबर्धित कार्यकलापों तथा संबर्धित उत्पादों का वित्त मंत्री और मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री के द्वारा निर्धारण किया जाता है। संबर्धित उत्पादों तथा कार्यकलापों में सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। पायनीर स्टेट्स विशिष्ट उद्योगों में शामिल कंपनियों तक सीमित होता है। आवेदकों को अनुमोदन समिति के माध्यम से भी जाना होगा। चूंकि मलेशिया ओ ई सी डी के तहत फोरम ऑन हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसिज प्रोग्राम को अपनाने के लिए बचनबद्ध है, इसलिए कार्यक्रम में परिवर्तन किए जाएंगे।
178. कृषीय और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश कर रही कंपनियों के लिए बड़े - बड़े कर प्रोत्साहन पायनीर स्टेट्स तथा निवेश कर छूट होती हैं। ये प्रोत्साहन परस्पर विशिष्ट होते हैं। निवेश संबर्धन अधिनियम 1986 की धारा 5 - 25 इनका प्रमाण हैं। लाभ पर देय करों से छूट होती है। इसके अलावा, हानियों को भी आगे ले जाया जा सकता है।
179. पायनीर स्टेट्स के लिए पात्रता संबंधी मानदण्ड प्रबंधकीय, तकनीकी और पर्यवेक्षी (एम टी एस) सूचकांक के द्वारा मापे गए अनुसार मूल्य - संबर्धित (वी ए) प्रतिशतता का स्तर तथा प्रौद्योगिकी का स्तर होते हैं।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

180. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निवेश संबर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 5 से 25 में पायनीर स्टेट्स कार्यक्रम के लिए प्रावधान होता है। इस कार्यक्रम में आयकर से छूट के रूप में कर प्रोत्साहनों के लिए प्रावधान होता है। छूट अवधि के दौरान हुई हानियों को कर योग्य आय/निवल लाभ की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आगे ले जाया जा सकता है। यह कार्यक्रम संबर्धित उत्पादों/कार्यकलापों की पूर्व - विनिर्दिष्ट सूची के लिए उपलब्ध होता है।
181. इस कार्यक्रम में पूर्ववर्ती राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान के लिए प्रावधान होता है जो अन्यथा देय होता है तथा उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह सूची में बताए गए संबर्धित कार्यकलाप/उत्पाद के लिए उपलब्ध होता है। सूची की जांच यह दर्शाती है कि उत्पाद सूची में विचाराधीन उत्पाद शामिल होता है। एल्फा इण्डस्ट्रीज एस डी एन बी एच डी के द्वारा दायर प्रश्नावली प्रयुक्त यह दर्शाता है कि संबर्धित उत्पाद सूची के आधार पर राजसहायता कार्यक्रमों के लिए जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों के द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है। प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम के लिए समतुल्य शुल्क लगाना चाहिए।

(x) कार्यक्रम संख्या 10 : निवेश कर नीतियां/छूट**क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन**

182. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि जिस कंपनी के लिए निवेश कर छूट (आई टी ए) स्वीकृत किया है, वह कंपनी प्रत्येक आकलन वर्ष की सांविधिक आय के प्रति इस भत्ते की क्षतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम में विनिर्माण क्षेत्र में संबर्धित ऐसे कार्यकलापों/उत्पादों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है जो अर्थव्यवस्था के विकास और संबर्धन में सहयोग कर सकते हैं। यह विनिर्माण क्षेत्र में अनुमोदित संबर्धित उत्पादों/कार्यकलापों के लिए स्थानीय और विदेशी निवेशकों के लिए लागू होता है। किए गए प्रथम अर्हक पूंजीगत व्यय की तारीख से 5 वर्षों के भीतर किए गए अपने अर्हक पूंजीगत व्यय पर 60 प्रतिशत छूट दी जाती है। कंपनी प्रत्येक आकलन वर्ष की अपनी सांविधिक आय के 70 प्रतिशत पर इस छूट की क्षतिपूर्ति कर सकती है। अपनी शेष 30 प्रतिशत सांविधिक आय पर कंपनी की प्रचलित कर दर से कर लगया जाएगा। कार्यक्रम से अस्तित्व के प्रमाण के रूप में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है :-

- निवेश संबर्धन अधिनियम, 1986
- गैट, 1994 के अनुच्छेद xvi:1 तथा सन्सिडीज एण्ड काउण्टरवेलिंग मेजर्स पर करार- मलेशिया, दिनांक 5 अक्टूबर के अनुच्छेद 25 के अनुसरण में नई और पूरी अधिसूचना।

- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- ऐसे संबर्धित कार्यकलापों और उत्पादों की सूची जो पायनीर स्टेट्स के विचाराधीन होने के पात्र हैं तथा निवेश संबर्धन अधिनियम, 1986 के तहत निवेश कर भत्ता है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

183. ऐसी किसी भी कम्पनी को निवेश कर छूट (आई टी ए) दी जा सकती है जिसका किसी संबर्धित कार्यकलाप में भाग लेने अथवा संबर्धित उत्पाद का उत्पादन करने का इरादा हो। इनमें ऐसे कार्यकलाप/उत्पाद शामिल होते हैं जो मलेशिया के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक महत्व के हों। संबर्धित कार्यकलापों तथा संबर्धित उत्पादों को मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री के द्वारा निर्धारित और गजेटिड किया जाता है। निवेश संबर्धन अधिनियम 1986 (अधिनियम 327)) की धारा 26 – 29 इसके प्रमाण हैं।
184. संबर्धित कार्यकलापों अथवा संबर्धित उत्पादों के उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लाए गए औद्योगिक भवनों संयंत्र और मशीनरी पर किए गए पूंजीगत व्यय पर ही छूट दी जाती है। कम्पनियों के द्वारा एम आई टी आई के तहत एक एजेंसी एम आई डी ए के पास आई टी ए कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होता है। फिर कम्पनी आई टी ए अवधि शुरू करनी सुनिश्चित करनी होगी, जो एम आई डी ए के द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रथम पूंजीगत व्यय के होने पर होती है। बाद में, अनुमोदित कार्यक्रम वाली कम्पनियां कर कटौती करने के लिए दावा की गणना करने वाली वार्षिक कर रिटर्न के साथ - साथ आन्तरिक राजस्व बोर्ड (आई आर बी) के पास अपने- अपने दावे प्रस्तुत करती है।
185. आई टी ए की पात्रता का मानदण्ड मूल्य संबर्धित (वी ए) प्रतिशतता और एम टी एस सूचकांक के द्वारा मापे गए अनुसार प्रौद्योगिकी का स्तर होते हैं।
186. जिन व्यक्तियों/फर्मों ने आवेदन किया और पात्रता के सभी मानदण्डों को पूरा करती है, उन सभी को अनुमोदित नहीं किया जाता है। आवेदकों को अनुमोदन समिति के समक्ष जाना होगा। यह सहायता कर योग्य आय से कटौती है। छूट का जब तक पूर्ण तक उपयोग न हो जाए, तब तक छूट को आगे ले जाया जा सकता है।
187. कम्पनी पायनर स्टेट्स प्राप्त लेकिन निवेश कर छूट न लेने का चयन कर सकती है अथवा निवेश कर छूट लेने लेकिन पायनर स्टेट्स न लेने का चयन कर सकती है।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

188. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निवेश संबर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 26 से 29 में निवेश कर छूट कार्यक्रम का प्रावधान होता है। संबर्धित कार्यकलापों और संबर्धित उत्पादों पर पूंजीगत छूट प्रदान की जाती है। मूल्य संबर्धन एवं प्रौद्योगिकीय अपेक्षाओं को भी पूरा करना होगा। कुल पूंजीगत व्यय में से 60 प्रतिशत के प्रति इसकी कटौती की जा सकती है। शेष आय पर सामान्य आय कर छूट दर से कर लगाया जा सकता है। यहां तक कि जो कम्पनियां संबर्धित कार्यकलाप, मूल्य संबर्धन और प्रौद्योगिकी का स्तर के सूचीबद्ध मानदण्डों को पूरा करती हैं, उनके बारे में भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राधिकारी लाभ लेते हुए आवेदन पत्र को निरस्त करने का स्वनिर्णय रखता है।
189. इस कार्यक्रम में पूर्ववर्ती राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान के लिए प्रावधान होता है जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यद्यपि राजसहायता कार्यक्रम संबर्धित कार्यकलाप तक सीमित नहीं होता है, परन्तु राजसहायता कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह ऐसे उद्यम के लिए उपलब्ध होता है जो कम से कम 3 वर्षों से प्रचालन कार्य कर रहे हैं तथा अर्हक परियोजना कार्य (विनिर्माण के संबंध में अपने मौजूदा कारोबार का विस्तार, आधुनिकीकरण अथवा आटोमेटिंग) कर रही हैं। प्राधिकारी ने बाद में कार्यक्रम संख्य 12 के बारे में यह निर्धारण किया है पूंजीगत निवेश और छूट के माध्यम से सांविधिक आय से कटौती समतुल्यनी हो। इसलिए प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम पर कोई अतिरिक्त समतुल्य शुल्क लगाना अपेक्षित नहीं है।

(xi) कार्यक्रम संख्या 10 : पूर्वनिवेश पर छूट

क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन

190. आयकर का निर्धारण करने के सांविधिक आय के निर्धारण हेतु कंपनी के द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय करने के लिए कटौती मंजूर की जाती है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

191. मलेशिया से कुछ कपड़ा मिल उत्पादों और परिधानों (1985) और मलेशिया से स्टील वायर नेल्स (1989) (यू एस सी वी डी निर्धारणों) में यू एस डी ओ सी ने यह निर्धारण किया कि पुनर्निवेश पर छूट समतुल्य योग्य नहीं है। मलेशिया से स्टेनलैस स्टील फासनरों (ई यू सी वी डी निर्धारण) (2000) में पुनर्निवेश पर छूट समतुल्य योग्य नहीं है।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

192. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मलेशिया में किसी कम्पनी अथवा व्यक्ति को पुनर्निवेश पर छूट प्रदान की जाती है यदि कम्पनी 3 वर्ष के लिए प्रचालन में हो और परिवर्तित परियोजना के लिए फैक्टरी, संयंत्र और मशीनरी पर पूंजीगत व्यय किया हो। ऐसे 60 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए सांविधिक व्यय की 70 प्रतिशत राशि से कटौती के लिए स्वीकृति दी जाती है। जिस आकलन वर्ष में दावा किया जाता है उस वर्ष के प्रारम्भ से 15 वर्षों के लिए पुनर्निवेश पर छूट के लिए दावा किया जा सकता है। आन्तरिक राजस्व बोर्ड इस कार्यक्रम को शासित करने के लिए जिम्मेदार होता है।
193. इस कार्यक्रम में पूर्ववर्ती राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान के लिए प्रावधान होता है जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदत्त होता है। यद्यपि राजसहायता कार्यक्रम संबंधित परन्तु राजसहायता कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह ऐसे उद्यम के लिए उपलब्ध होता है जो कम से कम 3 वर्षों के लिए प्रचालन है और परिवर्तित परियोजना का (विनिर्माण के संबंध में विस्तार आधुनिकीकरण अथवा अपने मौजूदा कारोबार का आटोमैटिंग) का कार्य कर रहे हैं। प्राधिकारी ने बाद में कार्यक्रम संख्या 12 में यह निर्णय किया है कि पूंजीगत निवेश और छूट के द्वारा सांविधिक आय से कटौती समतुल्य योग्य होती है। इसलिए, प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि किसी भी अतिरिक्त समतुल्य शुल्क इस राजसहायता कार्यक्रम पर लगाना अपेक्षित नहीं है।

(xii) कार्यक्रम संख्या 12 : त्वरित पूंजीगत छूट**क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन**

194. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशेष छूट, जहां पूंजीगत व्यय को 3 वर्षों के भीतर बट्टे खाते डाला जाता है, अर्थात् 40 प्रतिशत की प्रारम्भिक छूट और 20 प्रतिशत की वार्षिक छूट दी जाती है। पुनर्निवेश छूट की पात्रता की 15 वर्ष की अवधि के बाद जो कम्पनियां संबंधित उत्पादों का विनिर्माण करने में पुनः निवेश करती हैं, वे त्वरित पूंजीगत छूट लेने के लिए आवेदन करने की पात्र होती हैं। आवेदन पत्रों के साथ एम आई डी ए का पत्र लगाकर आई आर बी के पास यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करने होंगे कि कम्पनियां संबंधित कार्यकलाप / उत्पादों का विनिर्माण कर रही हैं।

- निवेश सवर्धन अधिनियम, 1986
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- ऐसे संबंधित कार्यकलापों और उत्पादों की सूची जो पायनीर स्टेट्स के विचाराधीन होने के पात्र हैं तथा निवेश सवर्धन अधिनियम, 1986 के तहत निवेश कर भत्ता है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

195. त्वरित पूंजीगत छूट (ए सी ए) में 3 वर्षों के भीतर पूंजीगत व्यय को बट्टे खाते डालने के लिए छूट अर्थात् पहले वर्ष में 20 प्रतिशत की प्रारम्भिक छूट और 40 प्रतिशत की वार्षिक छूट का प्रावधान होता है। यह कार्यक्रम सभी कम्पनियों के लिए

उपलब्ध है तथा ए सी ए देने आई आर बी के वस्तुपरक मानदण्ड लागू होते हैं। कार्यक्रम में समतुल्यनीय राजसहायता नहीं बनती है क्योंकि यह निर्यात की शर्तों से जुड़ी नहीं है, यह विशिष्ट नहीं है और यह सामान्य तौर पर उपलब्ध होती है। यह सहायता एक त्वरित पूंजीगत छूट होती है जिसकी कर योग्य आय से कटौती करनी होगी। छूट को आगे ले जाया जा सकता है। सामान्य तौर, त्वरित पूंजीगत छूट (ए सी ए) के लिए पात्र बनने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :-

- आधार अवधि के दौरान वह कारोबार कर रहा था।
- उसने आधार अवधि में अर्हक व्यय किया है।
- परिसंपत्ति का कारोबार के लिए उपयोग किया था।
- आधार अवधि के अन्त में वह परिसम्पत्ति का मालिक था और परिसम्पत्ति उपयोग में थी।

196. जांचाधीन कम्पनियां ए सी ए का दावा करने के लिए पात्र होंगी यदि वे मानदण्डों को पूरा करती हो और कौन - सी फर्म लाभ लेने के लिए पात्र हैं, इस बारे में सरकार विवेक का प्रयोग नहीं करती है।
197. वर्ष 2017 के लिए एल्फा इण्डस्ट्रीज एस. डी. एन बी. एच. डी और मैट्रोड (मलेशिया) एस. डी. एन बी. एच. डी. ने इस कार्यक्रम का उपयोग किया।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

198. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में पुनर्निवेश छूट अवधि के 15 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित कार्यकलाप के बारे में पूंजीगत छूट अर्थात् सांविधिक आय से पूंजीगत छूट की कटौती करने का प्रावधान है। कार्यक्रम में 3 वर्षों के भीतर कुल पूंजीगत व्यय अर्थात् पहले वर्ष में 20 प्रतिशत की प्रारम्भिक छूट और अगले 2 वर्षों में 40 प्रतिशत की वार्षिक छूट को बट्टे खाते में डालने की अनुमति होती है।
199. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम में पूर्ववर्ती राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ प्रदत्त होता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह ऐसे संबंधित कार्यकलाप को पूरा करने के लिए कुछ उद्यम के लिए उपलब्ध हो जो इस छूट का उपयोग करने के लिए अर्हक हो तथा पात्रता की 15 वर्षों की अवधि के समाप्त होने के कारण पुनर्निवेश करने के लिए अर्हक नहीं होता है। मलेशिया सरकार ने सूचित किया है कि प्रत्युत्तर देने वाला निर्यातकों एल्फा इण्डस्ट्रीज और मैट्रोड मलेशिया ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ लिया। इसलिए, प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए समतुल्य शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

(xiii) कार्यक्रम संख्या 13 : समूह राहत

क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन

200. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समूह राहत को एक ही समूह के भीतर एक दूसरी कम्पनी की आय के प्रति क्षतिपूर्ति की जाने वाली वर्तमान वर्ष की समाहित न हुई हानियों को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया है। यह स्थानीय रूप से निगमित सभी रेजीडेंट कम्पनियों के लिए आयकर अधिनियम, 1976 के तहत उपलब्ध कराया जाता है। दावेदार और अभ्यर्पण करने वाली कम्पनी के पास आर एम 2.5 एम एन से अधिक साधारण शेयरों की प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए।

- निवेश संबंधन अधिनियम, 1986
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- ऐसे संबंधित कार्यकलापों और उत्पादों की सूची जो पायनीर स्टेट्स के विचाराधीन होने के पात्र हैं तथा निवेश संबंधन अधिनियम, 1986 के तहत निवेश कर भत्ता है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

201. समूह राहत आयकर अधिनियम, 1976 की धारा 44 क के तहत यथा उपलब्ध निबंधन और शर्तों के अधीन स्थानीय रूप से निगमित सभी रेजीडेंट कम्पनियों के लिए उपलब्ध है। यह एक ही समूह के भीतर एक अथवा अधिक संबद्ध कम्पनियों की (दावेदार कम्पनी के रूप में कहा है) आय की क्षतिपूर्ति करने हेतु एक आकलन वर्ष की आधार अवधि में उसकी अधिकतम 70 प्रतिशत हानि का अभ्यर्पण करने के लिए (अभ्यर्पण कम्पनी के रूप में कहा है) एक समूह में एक कम्पनी को अनुमति देता है। इस सहायता की निश्चित कुल आय से कटौती होती है। किसी भी कटौती को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।
202. यह कार्यक्रम सभी कम्पनियों के लिए उपलब्ध है तथा समूह राहत देने में आई. आर. बी. वस्तुपरक मानदण्डों को लागू करता है। इस कार्यक्रम में समतुल्य राजसहायता बनती है क्योंकि यह निर्यात संबंधी शर्तों से जुड़ा हुआ नहीं है, विशिष्ट नहीं है और यह सामान्य तौर पर उपलब्ध है। कार्यक्रम में कोई प्रत्याशित परिवर्तन नहीं होते हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

203. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम आयकर अधिनियम की धारा 44क के द्वारा शासित होता है। राजसहायता कार्यक्रम में एक ही समूह के भीतर एक या अधिक संबद्ध कम्पनियों के लाभ के प्रति एक समूह में एक कम्पनी को उसकी अधिकतम 70 प्रतिशत हानियों की क्षतिपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। जो कंपनियां समूह राहत के लिए दावा कर सकती हैं। यह कार्यक्रम सभी कम्पनियों के लिए उपलब्ध है।
204. इस कार्यक्रम में पूर्ववर्ती राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान के लिए प्रावधान होता है, जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदत्त होता है। यह कार्य विशिष्ट होता है क्योंकि यह संबद्ध कम्पनियों वाले उद्यम तक सीमित होता है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्णय लिया है कि आयकर से छूट देते हुए राजसहायता कार्यक्रम के प्रति समतुल्य शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त समतुल्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xiv) कार्यक्रम संख्या 14 : टैरिफ से संबंधित प्रोत्साहन

क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन

205. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्चे माल/ उपकरणों पर आयात शुल्क से पूरी छूट सामान्य तौर दी जाती है बशर्ते कच्चा माल/ उपकरणों का स्थानीय रूप से उत्पादन न होता हो अथवा यदि स्थानीय उत्पादन होता हो, तो वे स्वीकार्य गुणवत्ता और कीमत के नहीं होती हैं। क्या तैयार उत्पाद निर्यात के लिए हैं अथवा घरेलू बाजार के लिए हैं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पात्रता यह होती है कि कम्पनियां विनिर्माण के कार्यकलापों में लगी हुई होती चाहिए।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

206. राजसहायता कार्यक्रम वैसा ही है जैसा कार्यक्रम संख्या 24 है।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

207. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क महानिदेशक द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम में योग्य विनिर्माता के लिए कच्चे माल/ उपकरणों पर आयात शुल्क में छूट का प्रावधान है। छूट उस स्थिति में दी जाती है जब कच्चा माल / उपकरण स्थानीय तौर पर उपलब्ध न हों और अनुमोदित विनिर्माता के परिसर(रों) में तैयार उत्पादन करने में सीधे ही प्रयोग में लाया जाता हो।
208. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में पूर्ववर्ती राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान के लिए प्रावधान होता है जो अन्यथा देय होता है। यह कार्यक्रम अनुज्ञेय शुल्क छूट कार्यक्रम बनने लायक नहीं होता है क्योंकि इसमें सभी किस्म के विनिर्माण कार्यकलापों में प्रयुक्त कच्चे माल के लिए और निर्यात किए उत्पादों में प्रयुक्त न केवल कच्चे माल के लिए आयात शुल्क से छूट का प्रावधान होता है, जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ख (ख) और एस सी एन

करार की पाद टिप्पणी 1 में प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट हैं क्योंकि यह उस उद्यम तक सीमित होता है जो ऐसे कच्चे माल का उपयोग करते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होता है। प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम के लिए समतुल्य कर लगाना चाहिए।

(xv) कार्यक्रम संख्या 15 : औद्योगिक भवन छूट

क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन

209. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि जिन भवनों का उपयोग विनिर्माण, कृषि, खनन, अवसंरचना सुविधाओं अनुसंधान, अनुमोदित सेवा परियोजनाओं तथा होटलों सहित, जो पर्यटन मंत्रालय के पास पंजीकृत हैं, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे भवन का निर्माण अथवा खरीद करने पर पूंजीगत व्यय करने वाली कम्पनियों को 10 प्रतिशत प्रारम्भिक छूट और 3 प्रतिशत वार्षिक छूट दी जाती है। आयकर अधिनियम 1967 में प्रमाण दिया है।

ख. सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

210. औद्योगिक भवन छूट (आई बी ए) ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती है जिसने ऐसे किसी औद्योगिक भवन का निर्माण करने अथवा खरीदने पर व्यय किया है जिसका उस के कारोबार के लिए उपयोग में लाया जाता है। सांविधिक आय प्राप्त करने के लिए समायोजित आय के प्रति औद्योगिक भवन छूट की कटौती की जाती है। सहायता एक छूट होती है जिसकी कर योग्य आय से कटौती करनी होगी। छूट को आगे ले जाया जा सकता है। आयकर अधिनियम 1967 की अनुसूची 3 इसका प्रमाण है। इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का अनुमान नहीं है।
211. आई. बी. ए. सामान्य तौर पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कम्पनियों जैसी सभी कम्पनियों तथा एकमात्र स्वामित्व और साझेदारी जैसे अनिगमित कारोबारों के लिए उपलब्ध है। आई बी ए स्वीकृत करने के लिए निर्यात कोई मानदण्ड नहीं होता है। भवन के उपयोग को ध्यान में रखते हुए आई बी ए सभी भवनों के लिए दी जाती है। आई बी ए ऐसे भवनों के लिए भी उपलब्ध है जिनका निर्यात हेतु माल के भण्डारण के लिए अथवा आयातित वस्तुओं के भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता है, जिनको संसाधित और वितरित अथवा पुनः निर्यात किया जाना होता है।
212. जो कम्पनियां पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करती हैं, ऐसी सभी कम्पनियां कटौती का दावा कर सकती हैं। कार्यक्रम में समतुल्यनीय राजसहायता नहीं बनती है क्योंकि यह विशिष्ट नहीं है। योग्य व्यक्ति :-
- भवन पर पूंजीगत व्यय करता है।
 - भवन एक औद्योगिक भवन होना चाहिए।
 - व्यक्ति के द्वारा किए गए कारोबार के लिए भवन का उपयोग किया जाना चाहिए।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

213. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि औद्योगिक भवन छूट (आई बी ए) ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती है जिसने ऐसे किसी औद्योगिक भवन का निर्माण करने अथवा खरीदने पर व्यय किया है जिसका उस के कारोबार के लिए उपयोग में लाया जाता है। सांविधिक आय प्राप्त करने के लिए समायोजित आय के प्रति औद्योगिक भवन छूट की कटौती की जाती है।
214. प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारित किया है कि त्वरित पूंजीगत छूट पर समतुल्य शुल्क लगाना चाहिए। इसलिए प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त समतुल्य शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

(xvi) कार्यक्रम संख्या 16 : संयंत्र और मशीनरी के लिए छूट

क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन

215. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि इस कार्यक्रम के तहत कारोबार की स्थिर परिसंपत्तियों की छूट टूट - फूट के लिए राहत देने हेतु पूंजीगत छूट दी जाती है। व्यय का स्वरूप पूंजीगत होना चाहिए और कारोबार के प्रयोजनों के लिए

उपयोग किया जाना चाहिए। जब पूंजीगत व्यय किया हो, उस समय पर परिसंपत्ति की लागत के आधार पर प्रारम्भिक छूट 20 प्रतिशत नियत की जाती है। परिसंपत्ति की मूल लागत के आधार पर वार्षिक छूट हरेक वर्ष समान दर से दी जाती है और तदनुसार भिन्न – भिन्न होती है। कार्यक्रम के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है :-

- आयकर अधिनियम 1967 की अनुसूची – 3
- वेब रिसर्च – इंग्लैण्ड रेवैन्यू बोर्ड आफ मलेशिया क्वालीफाइंग एक्सपेंडीचर एण्ड कम्प्यूटेशन ऑफ़ केपीटल एलाउन्सिज पब्लिक रूलिंग नं. 6/2015

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

216. पूंजीगत छूट में मशीनरी अथवा संयंत्र पर प्रतिबंधक व्यय करने के लिए कटौतियों का प्रावधान होता है। सी. ए. की गणना आकलन के एक वर्ष के लिए की जाती है और सांविधिक आय प्राप्त करने में कारोबार से समायोजित की गई आय से इसकी कटौती की जाती है। इसकी छूट की निर्धारित दर पर आधारित सीधी पद्धति से गणना की जाती है। जांचाधीन कम्पनियां यदि मानदण्डों को पूरा करती हैं, तो वे सी. ए. का दावा करने की पात्र होंगी। छूट को आगे ले जाया जा सकता है। कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का अनुमान नहीं होता है।
217. जो कम्पनियां पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करती हैं, वे सी. ए. के लिए दावा कर सकती हैं। यह कार्यक्रम सभी कम्पनियों के लिए उपलब्ध होता है और सी. ए. की स्वीकृति देने में आई आर बी के लिए वस्तुपरक मानदण्ड लागू होते हैं।

योग्य व्यक्ति :-

- कारोबार करते हैं।
- संयंत्र और मशीनरी पर पूंजीगत व्यय करता है।
- उस कारोबार में संयंत्र और मशीनरी का उपयोग होना चाहिए।
- आधार अवधि के अन्त में संयंत्र और मशीनरी का स्वामी।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

218. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूंजीगत छूट में मशीनरी अथवा संयंत्र पर प्रतिबंधक व्यय करने के लिए कटौतियों का प्रावधान है। यह उस उद्यम के लिए दी जाती है जो प्रतिबंधक व्यय करता है। इसकी गणना आकलन के एक वर्ष के लिए की जाती है और सांविधिक आय प्राप्त करने में कारोबार से समायोजित की गई आय से इसकी कटौती की जाती है। इसकी छूट की निर्धारित दर पर आधारित सीधी पद्धति से गणना की जाती है।
219. प्रत्युत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक मैट्रोड मलेशिया, मैट्रो ओ एफ एच सी और एल्फा इण्डस्ट्रीज ने संयंत्र और मशीनरी पर छूट का दावा किया है।
220. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में किसी समतुल्यनीय लाभ के लिए प्रावधान नहीं होता है क्योंकि इसमें सभी उद्यमों के लिए सीधी पद्धति के अनुसार संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यहास की सामान्य कटौती करने का प्रावधान है। इसलिए प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए कोई समतुल्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xvii) कार्यक्रम संख्या 17 : मलेशिया के ब्राण्ड को बढ़ावा देने के लिए दुगुनी कटौती

क. याचिकाकर्ताओं के द्वारा निवेदन

221. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय ब्राण्ड के उत्पादों का घरेलू स्तर पर विज्ञापन करने पर किए गए व्यय पर दुगुनी कटौती करने की अनुमति दी जाती है। अर्थात् कुछ कार्यकलापों पर किए गए व्यय पर कर योग्य लाभों की दुगुनी राशि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। स्थानीय ब्राण्ड पर मलेशिया ब्राण्ड नाम के पंजीकृत स्वामी के द्वारा 50 प्रतिशत से ज्यादा ब्राण्डों पर स्वामित्व होना चाहिए, जिन पर स्वामित्व एक ऐसी कम्पनी का होना चाहिए जो कम से कम 70 प्रतिशत मलेशिया ब्राण्ड के स्वामित्व वाली स्थानीय रूप से निगमित हो और मलेशिया अथवा विदेशों में पंजीकृत हो। आकलन के एक वर्ष में एक कंपनी के द्वारा कटौती का दावा किया जा सकता है। कार्यक्रम के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है :-

- निवेश संवर्धन अधिनियम 1986
- निर्यात का आयकर संवर्धन नियम 1986
- इन्लैण्ड रैवेन्यू बोर्ड ऑफ मलेशिया पब्लिक रूलिंग संख्या 1/2013
- मलेशियन एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट कारपोरेशन

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

222. मलेशिया ब्राण्ड नाम की वस्तुओं का विज्ञापन करने में सीमित विज्ञापनों पर व्यय करने के लिए एक कारोबार से समायोजित आय से दुगुनी कटौती करने के लिए पात्र होते हैं। आयकर (मलेशिया ब्राण्ड नाम वस्तुओं पर विज्ञापन व्यय के लिए कटौती) नियमावली 2002 प्रमाण के रूप में दी है। आवेदक कम्पनियों के द्वारा मलेशिया ब्राण्ड की वस्तुओं का विज्ञापन देने के लिए मलेशिया के भीतर किए गए व्यय से संबंधित कारोबार की रसीदों की प्रतियों के साथ फार्मों को पूरा करके तथा दावों के बारे में सबूत देकर प्रोत्साहन के लिए दावा करना होता है। आई आर बी की लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए मूल समर्थन दस्तावेजों को कम्पनी के द्वारा रख लेना चाहिए। जिस वर्ष में व्यय किया है, उस वित्तीय वर्ष (आधार अवधि) की वार्षिक कर विवरणियों में दावा किया जा सकता है। जो कम्पनियां मानदण्डों को पूरा करती हैं, ऐसी जांचाधीन कम्पनियां कटौतियों के बारे में दावा करने की पात्र होंगी। यह सहायता कर योग्य आय से कटौती होती है। कटौती को आगे ले जाया जा सकता है।
223. कार्यक्रम में किसी कटौती का अनुमान नहीं है।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

224. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम आयकर (मलेशिया ब्राण्ड नाम की वस्तुओं पर विज्ञापन व्यय के लिए कटौती नियमावली 2002 से शासित होता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेशिया ब्राण्ड पर विज्ञापन में किए गए खर्च के लिए कारोबार आय से दुगुनी कटौती करने के पात्र होते हैं। इस दुगुनी कटौती करने लायक बनने के लिए कम्पनी के पास 70 प्रतिशत मलेशिया इक्विटी होनी चाहिए तथा ब्राण्ड नाम निर्यात गुणवत्ता की वस्तुओं के बारे में होना चाहिए।
225. कार्यक्रम में पूर्ववर्ती राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान होता है जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदत्त होता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह ऐसे उद्यम के लिए उपलब्ध होता है जो मलेशिया वाले ब्राण्ड विज्ञापन पर व्यय करते हैं। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्णय लिया है कि आयकर से छूट देते हुए राजसहायता कार्यक्रम के प्रति समतुल्य शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त समतुल्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xviii) कार्यक्रम संख्या 18 : ईस्ट कोस्ट इकनॉमिक कारिडोर में विनिर्माण और विनिर्माण संबंधी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन

क. याचिकाकर्ता के द्वारा निवेदन

226. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कर छूट – पूर्ववर्ती राजस्व ऐसे कम्पनी को दी जाती है जो ईस्ट कोस्ट इकनॉमिक कारिडोर में स्थित हो, चुनिन्दा और कृषि आधारित उत्पाद और विनिर्माण संबंधी सेवाओं के विनिर्माण में लगी हो। प्रत्येक मामले की गुणवत्ता के आधार पर सीमा शुल्क प्रोत्साहन कम्पनी का सांविधिक आय शुरू

होने के वर्ष से 10 वर्षों के लिए शत प्रतिशत आयकर छूट अथवा 5 वर्षों के प्रतिबंधक पूंजीगत व्यय पर 100 प्रतिशत आयकर छूट दी जाती है। विकास के लिए अधिग्रहण की गई भूमि अथवा भवन पर स्टाम्प शुल्क छूट और जो मशीनरी तथा टिकाऊ वस्तुएं स्थानीय रूप से उत्पादित की जाती है और कार्यकलाप में सीधे ही उपयोग में लायी जाती हैं, उन पर आयात शुल्क तथा बिक्री कर छूट भी उपलब्ध होती है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

227. कर छूट ऐसी किसी कम्पनी के लिए दी जा सकती है जो किसी संबंधित कार्यकलाप में भाग लेना अथवा किसी कार्यकलाप/उत्पाद सहित ऐसे किसी संबंधित उत्पाद का उत्पादन करना चाहती हो जो मलेशिया के राष्ट्रीय और सामरिक महत्व का हो।
228. कम्पनियों के द्वारा एम ओ एफ के तहत एक एजेंसी ईस्ट कोस्ट इकोनामिक रिजन डेवलपमेंट काउंसिल (ई सी ई आर डी सी) को कर छूट कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। फिर कम्पनी के द्वारा कर छूट के लिए प्रथम सांविधिक आय प्राप्त करने वाली कंपनी के बारे में ई सी ई आर डी सी से अनुपालन पत्र की जांच करानी होगी। यह उस कम्पनी के जारी किया जाएगा जो सभी शर्तों को पूरी करती हो। कम्पनी ने सभी शर्तों को पूरा कर लिया है, इस बारे में ई सी ई आर डी सी के सन्तुष्ट हो जाने पर यह उक्त पत्र को जारी करेगी, जिसके लिए कम्पनी 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन लाभ ले सकती है। बाद में, कार्यक्रम से अनुमोदित कम्पनियां कर छूट के लिए दावे की गणना करने वाली अपनी वार्षिक कर विवरणियों के साथ – साथ आई आर बी के लिए अपने दावे प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम में परिवर्तन किए जाएंगे क्योंकि मलेशिया ओ ई सी डी के तहत फोरम ऑन हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसिज (एफ एच टी पी) कार्यक्रम को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सहायता देय करों से एक छूट होती है। हानियों के लिए प्रावधान होता है और उन्हें आगे ले जाने की अनुमति होती है। जिन व्यक्तियों/फर्मों ने आवेदन किया था और पात्रता संबंधी मानदण्डों के पूरा किया था, ऐसे सभी व्यक्तियों/फर्मों को कार्यक्रम का अनुमोदन नहीं दिया जाएगा। आवेदकों को अनुमोदन समिति के माध्यम से आवेदन करना होगा।
229. कार्यक्रम के लिए पात्रता संबंधी मानदण्ड निम्नलिखित है :-
- परियोजना मलेशिया के ईस्ट कोस्ट में अवस्थित हो।
 - मूल्य संबंधित और
 - प्रौद्योगिकी स्तर प्रबंधकीय, तकनीकी और पर्यवेक्षी (एम टी एस) सूचकांक के द्वारा मापे गए अनुसार।
230. जांचाधीन कम्पनी ने स्थल, एम टी एस और मूल्य संबंधन के बारे में पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा किया।

ग. प्राधिकारी के द्वारा जांच

231. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण आयकर छूट उस कम्पनी को दी जाती है, जिसकी परियोजना ईस्ट कोस्ट इकोनामिक कॉरीडोर में अवस्थित हो और जिसका इरादा किसी संबंधित कार्यकलाप में भाग लेने अथवा किसी ऐसे कार्यकलाप/उत्पाद का उत्पादन करने का हो जो मलेशिया के राष्ट्रीय और सामरिक महत्व का हो।
232. कार्यक्रम में पूर्ववर्ती राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान होता है जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदत्त होता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह संबंधित उत्पाद तक सीमित होता है तथा क्षेत्र विशेष के लिए भी होता है अर्थात् ऐसे उद्यम के लिए सीमित होता है जिसकी परियोजना ईस्ट कोस्ट इकोनामिक कॉरीडोर में अवस्थित होती है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्णय लिया है कि आयकर से छूट देते हुए राजसहायता कार्यक्रम के प्रति समतुल्य शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस राजसहायता कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त समतुल्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xix) कार्यक्रम संख्या 19 : आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क वापस लेना

क. याचिकाकर्ता क द्वारा निवेदन

233. याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, उनको वापस लेने के लिए विनिर्माता के द्वारा इस स्थिति में किया जा सकता है, यदि पुर्जों, कच्चे माल अथवा पैकेजिंग सामग्री का अधिनियमों में निर्धारित शर्तों के आधार पर एक वर्ष के भीतर निर्यात हेतु वस्तुओं का विनिर्माण करने में उपयोग किया जाता है। कार्यक्रम के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है :-

- सीमा शुल्क अधिनियम 1976 की धारा 99
- बिक्री कर अधिनियम 1972 की धारा 29
- उत्पाद शुल्क अधिनियम 1976 की धारा 19

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

234. इस कार्यक्रम में ऐसी आयातित वस्तुओं पर शुल्क आयात वापसी का प्रावधान होता है जिनको बाद में पुनः निर्यात किया जाता है। यह कार्यक्रम समतुल्यनीय नहीं है क्योंकि यह एस सी एम करार (राजसहायता परिभाषा के छूट) के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों के अनुरूप है। कार्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तनों की प्रत्याशा नहीं होती है। कम्पनियों के द्वारा रॉयल मलेशियन कस्टम्स डिपार्टमेंट (आर एम सी डी) के पास सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 93, 95, 99 के तहत ड्रा बैक (वापस लेने) के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होता है। बाद में कम्पनियों के द्वारा आयात/ निर्यात संबंधी घोषणा का प्रमाण तथा प्रासंगिक आयात/ निर्यात दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं। रिफण्ड करने अथवा नामंजूर करने से पूर्व आर एम सी डी दस्तावेजों की जांच करेगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

235. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन रॉयल मलेशियन कस्टम्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में उन वस्तुओं पर आयात शुल्क की वापसी की जाती है जिन्हें बाद में पुनः निर्यात किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत निर्यातक अल्फा इण्डस्ट्रीज ने इसका लाभ लिया है।
236. प्राधिकारी पहले ही यह निर्धारित कर चुके हैं कि कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट प्रतिवाद है। प्राधिकारी का यह मानना है कि शेष श्रेणी के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना करते समय इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xx) कार्यक्रम सं. 21: आउटसोर्सिंग विनिर्माण कार्यकलाप हेतु आयात शुल्क और बिक्री शुल्क से छूट।

(क) याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

237. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि व्यापार करने की लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु उन मलेशियायी ब्रांडों को कम से कम 60 प्रतिशत मलेशियायी के साथ आयात शुल्क और बिक्री कर में छूट दी जाती है जो विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग करते हैं। स्थानीय रूप से/विदेशों में उनके अनुबंधित विनिर्माताओं द्वारा अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाली कच्ची सामग्रियों और घटकों पर आयात शुल्क और बिक्री कर की छूट तथा अंतिम उत्पादों के विनिर्माण हेतु उनके स्थानीय अनुबंधित विनिर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उनके विदेशी विनिर्माताओं से अर्ध-परिष्कृत वस्तुओं पर आयात शुल्क और बिक्री कर की छूट उपलब्ध है। कार्यक्रम की मौजूदगी के समय के रूप में याचिकाकर्ताओं ने मिडा के प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहनों पर विश्वास किया है।

(ख) मलेशिया की सरकार/अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा अनुरोध

238. कार्यक्रम के तहत विनिर्माण कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग के लिए कच्ची सामग्रियों और/अथवा अर्ध-तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क की छूट दी जाती है। शुल्क छूट संबंधी एक समिति गठित की जाती है जिसमें वित्त मंत्रालय, एमआईटीआई, आरएमसीडी, एमआईडीए और आईपीसी के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2) को साक्ष्य के रूप में दिया जाता है। वे सभी विनिर्माता इस स्कीम का लाभ उठाते हैं जो पात्रता संबंधी मापदण्ड पूरा करते हैं और प्राधिकारी विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार के फेरबदल की प्रत्याशा नहीं है।
239. यह कार्यक्रम जवाबी कार्रवाई के तौर पर नहीं है क्योंकि यह एससीएम एक करार (सब्सिडी परिभाषा का अपवाद) के अनुबंध I, II और III के उपबंधों के अनुरूप है।
240. छूट प्राप्त करने हेतु अर्हता
- उन कच्ची सामग्रियों और घटकों का आयात जिनका उपयोग शून्य आयात शुल्क के साथ अंतिम उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है।
 - अर्ध-तैयार उत्पाद जिनका आयात विदेशों में अनुबंधित विनिर्माताओं से किया जाता है और उनका इस्तेमाल स्थानीय अनुबंधित विनिर्माताओं द्वारा तैयार उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

241. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 14(2) इस कार्यक्रम के प्रशासन को शासित करती है। यह कार्यक्रम मलेशियाई इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम में विनिर्माण कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग के लिए कच्ची सामग्रियों और/अथवा अर्ध-तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क की छूट प्रदान की जाती है। कच्ची सामग्रियां जिनका उपयोग निर्यातित उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है और अर्ध-तैयार वस्तुएं जिनका आयात अनुबंधित विनिर्माताओं से स्थानीय विनिर्माताओं के उपयोग हेतु किया जाता है, यह छूट प्राप्त करने के अर्हक है।
242. प्राधिकारी यह पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क/करों की छूट देने वाले कार्यक्रम पर प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxi) कार्यक्रम सं. 23: मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क और बिक्री कर की छूट।

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

243. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि चूंकि सरकार की नीति विनिर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त और स्थानीय रूप से अविनिर्मित मशीनरी और उपकरणों पर कर लगाना नहीं है अतः कर छूट-राजस्व का त्याग किया जाता है जहां आयातित मशीनरी और उपकरण कर योग्य हैं किन्तु स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। आयात शुल्क और बिक्री कर पर पूरी छूट दी जाती है। स्थानीय रूप से खरीदी गयी मशीनरी और उपकरणों के लिए बिक्री कर पर पूरी छूट दी जाती है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के तौर पर याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए की प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहनों पर भरोसा जताया है।

ख. मलेशिया की सरकार/अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा अनुरोध

244. कार्यक्रम में पात्र अर्हक विनिर्माता को मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क की छूट प्रदान की जाती है। एमआईडीए विनिर्माता की स्थिति की पुष्टि हेतु एक पत्र जारी करता है। विनिर्माता तब छूट का दावा पेश करता है। छूट लेने की अर्हता हेतु मशीनरी और उपकरण नए, अप्रयुक्त और अनुमोदित विनिर्माता के परिसरों पर तैयार उत्पाद के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होने चाहिए। वे सभी विनिर्माता इस स्कीम का लाभ प्राप्त करेंगे जो पात्रता संबंधी मापदण्ड पूरा करते हैं और एमआईडीए विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है। वे सभी विनिर्माता इस स्कीम का लाभ उठाते हैं जो पात्रता संबंधी मापदण्ड पूरा करते हैं और प्राधिकारी विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार

के फेरबदल की प्रत्याशा नहीं है। यह कार्यक्रम जवाबी कार्रवाई के तौर पर नहीं है क्योंकि यह एससीएम एक करार (सब्सिडी परिभाषा का अपवाद) के अनुबंध I, II और III के उपबंधों के अनुरूप है। इस कार्यक्रम को शासित करने वाले कानून एवं विनियमन सीमा शुल्क (छूट) आदेश, 2017 में निहित हैं।

245. जांचाधीन कम्पनी पात्रता मानदण्ड के अनुरूप है और यह एमआईडीए के क्षेत्राधिकार में है। एमआईडीए में अल्फा इंडस्ट्रीज एसडीएन, बीएचडी को दिनांक 2 जनवरी, 2018 को एक पुष्टिकारी पत्र जारी किया है जिसके तहत कम्पनी 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2020 तक आयात शुल्क में छूट के लिए आवेदन कर सकती है।
246. जिस लाइसेंस से विनिर्माताओं को बिक्री कर अधिनियम, 1972 (अधिनियम 64) के तहत बिक्री कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी उसका 1 जुलाई, 2014 से लाभ एवं सेवा कर अधिनियम, 2014 के अधिनियम से निरसन हो गया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

247. प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क (छूट) आदेश, 2017 द्वारा शासित है। इसमें अर्हक विनिर्माताओं को नए, अप्रयुक्त मशीनरी एवं उपकरणों पर आयात शुल्क की छूट दिए जाने का प्रावधान है। जांच अवधि के दौरान बिक्री कर से छूट दिए जाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि बिक्री कर अधिनियम, 1972 (अधिनियम, 64) का माल एवं सेवा शुल्क अधिनियम, 2014 (अधिनियम, 762) में अधिनियम के 1 जुलाई, 2014 को प्रभावी होने से निरसन हो गया है। यह कार्यक्रम मलेशियन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रशासित होता है।
248. प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक अल्फा इण्डस्ट्रीज ने छूट प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और यह 1 जनवरी, 2018 से इस छूट का उपयोग करने हेतु पात्र है। इस कार्यक्रम में राजस्व त्याग के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और एतद् द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम एक विशिष्ट स्वरूप का भी है क्योंकि यह उन सीमित उद्यमों तक ही सीमित है जो विनिर्माण कार्यक्रम हेतु मशीनरी एवं उपकरणों का आयात करते हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(xxii) कार्यक्रम सं. 24: कच्ची सामग्रियों/घटकों पर आयात शुल्क से छूट

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

249. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत कच्ची सामग्रियों/घटकों के लिए आयात शुल्क से पूरी छूट नहीं दी जा सकती है, चाहे तैयार वस्तुएं निर्यात अथवा घरेलू बाजार के उपयोग के लिए बनी हों अथवा नहीं, प्रदत्त कच्ची सामग्रियां/घटकों का स्थानीय रूप से उत्पादन नहीं किया जाता अथवा यदि स्थानीय रूप से उत्पादन किया जाता है तो, वे स्वीकार्य गुणवत्ता और कीमत के नहीं हैं। जहां तैयार उत्पाद निर्यात बाजार के लिए हैं वहां आमतौर पर आयात शुल्क से पूरी छूट दी जाती है। जहां तैयार उत्पाद घरेलू बाजार के लिए हैं वहां स्थानीय रूप से अनिर्मित कच्ची सामग्री/घटकों पर आयात शुल्क से पूरी छूट देने पर विचार किया जा सकता है। यदि तैयार उत्पाद कच्ची सामग्रियों/घटकों से बनाया जाता है और वे आयात शुल्क के अध्याधीन नहीं हैं तो, पूरी छूट देने पर भी विचार किया जा सकता है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए के प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहनों पर भरोसा जताया है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा अनुरोध

250. इस कार्यक्रम में कच्ची सामग्री/घटकों पर अर्हक विनिर्माता को आयात शुल्क पर छूट का मूल्यांकन शामिल है। शुल्क छूट पर एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें वित्त मंत्रालय, एमआईटीआई, आरएमसीडी और एमआईडीए के प्रतिनिधि सदस्य आते हैं। इस छूट के लिए अर्हक होने हेतु कच्ची सामग्रियां /घटक स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं और इसका उपयोग अनुमोदित विनिर्माताओं के परिसरों पर तैयार उत्पाद के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस कार्यक्रम

को शासित करने वाले कानून एवं विनियमन सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 14(2) में निहित हैं। वे सभी विनिर्माता इस स्कीम का लाभ उठाते हैं जो पात्रता संबंधी मापदण्ड पूरा करते हैं और प्राधिकारी विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार के फेरबदल की प्रत्याशा नहीं है। यह कार्यक्रम जवाबी कार्रवाई के तौर पर नहीं है क्योंकि यह एससीएम एक करार (सब्सिडी परिभाषा का अपवाद) के अनुबंध I, II और III के उपबंधों के अनुरूप है।

251. जांचाधीन कम्पनी पात्रता मापदण्ड के अनुरूप है। कॉपर कैथोड (कच्ची सामग्री) विचाराधीन उत्पाद पर किसी तरह का आयात शुल्क नहीं लगता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

252. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 14(2) द्वारा शासित होती है। इस कार्यक्रम में उन कच्ची सामग्री/घटक पर अर्हक विनिर्माताओं को आयात शुल्क में छूट दी जाती है जो स्थानीय तौर पर उपलब्ध नहीं हैं।
253. इस कार्यक्रम में राजस्व परित्याग के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है जो अन्यथा देय होता और एतद् द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट स्वरूप का भी है क्योंकि यह उस उद्यम तक सीमित है जो स्थानीय रूप से अनुपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। प्राधिकारी पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि प्रतिकारी शुल्क कच्ची सामग्री पर आयकर से छूट देने वाले कार्यक्रम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxiii) कार्यक्रम सं. 25: निर्यातों के प्रोत्साहन हेतु दोहरी कटौती

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

254. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत उन खर्चों हेतु निर्यातकों को कर कटौती दी जाती है जिनका लक्ष्य निर्यातों को बढ़ाना और विदेशों में वस्तुओं की आपूर्ति करना, सेवाओं के निर्यात और निर्यात बाजार अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के लिए मलेशिया से बाहर किसी मीडिया में प्रचार और विज्ञापनों के प्रयोजन से विदेशों में कार्यालयों के रख-रखाव की लागत रखना है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा व्यक्त किया है:

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 41
- निर्यात आयकर संवर्धन नियमावली 1986
- डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/292
- डब्ल्यूटीओ अधिसूचना- जी/एससीएम/एन/3/एमवाईएस-1995
- मलेशिया से यूएस कार्बन स्टील वायर रॉड

ख. मलेशिया सरकार द्वारा अनुरोध

255. यह कार्यक्रम जो निवेश संवर्धन अधिनियम, (पीआईए) 1986 (एक्ट 327) की धारा 41 के तहत चल रहा है, आधार अवधि में प्राथमिक और सैद्धांतिक रूप से अवसरों की प्राप्ति के प्रयोजन से और अथवा मलेशियायी विनिर्मित वस्तुओं कृषि उत्पादों के निर्यातकों का सृजन करने अथवा बढ़ाने में हुए व्ययों के संबंध में रेजिडेंट व्यापार, विनिर्माण अथवा कृषि संबंधी कम्पनियों पर लागू है। इस कार्यक्रम का जोर पात्र निर्यात संवर्धनात्मक कार्यकलापों, न कि उनकी वस्तुओं के निर्यात निष्पादन पर अथवा घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर मलेशियायी कम्पनियों की भागीदारी के समर्थन पर है। वे सभी

फर्मों जो पात्रता मापदण्ड पूरा करती हैं, इस कार्यक्रम का लाभ ले सकती हैं। जांचाधीन कम्पनियां यदि इस मापदण्ड को पूरी करती हैं तो कटौती का दावा करने की पात्र होंगी। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन की प्रत्याशा नहीं है। कटौती को आगे ले जाया जा सकता है।

256. आवेदक कम्पनियों को विज्ञापन देने, यात्रा करने और संबंधित निर्यात संवर्धनात्मक व्यय हेतु विदेशों में किए गए खर्चों से संबंधित व्यवसाय संबंधी रसीदों की प्रतियों के साथ फार्मों को पूरा करते हुए और अपने दावे को सत्यापित कर प्रोत्साहन प्राप्त करने का दावा करने की जरूरत है।
257. किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने की स्थिति में कम्पनियों को मेट्रेड से अनुमोदन पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

258. प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम आयकर (निर्यातों का संवर्धन) नियमावली 1986 के नियम 4(2) और निवेश संवर्धन अधिनियम (पीआईए) 1986 की धारा 41 द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम के तहत निर्यातों के संवर्धन हेतु किए गए व्ययों के लिए विनिर्माण, व्यापार एवं कृषिजन्य कार्यकलापों में शामिल उद्यमों को आय से दोहरी कटौती उपलब्ध है। निर्यातों की मांग बढ़ाने के लिए किसी कम्पनी द्वारा किए गए व्यय हेतु दोहरी कटौती की अनुमति है।
259. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में राजस्व परित्याग के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय होता है और एतद् द्वारा लाभ प्रदान किए जाते हैं। लाभ दोहरी कटौती के पश्चात भुगतान किए गए आयकर की राशि और उस आयकर की राशि के बीच का अंतर है जो इस प्रकार की दोहरी कटौती के अभाव में देय होता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट स्वरूप का भी है क्योंकि यह निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक है और उन उद्यमों तक सीमित है जो निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में संलग्न हैं। प्राधिकारी पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि आयकर से छूट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxiv) कार्यक्रम सं. 26: कार्गो निर्यात के संवर्धन हेतु दोहरी कटौती

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

260. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत कार्गो के निर्यात पर कोई भी निर्यातक बीमा प्रीमियम की कर योग्य आय से कटौती और कर बीमा के लिए क्षेत्रीय कटौती का लाभ ले सकता है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्न पर भरोसा जताया है:

- निवेश संवर्धन अधिनियम 1986
- निर्यात आयकर संवर्धन नियमावली 1986
- कम्पनियां के लिए कर संबंधी प्रोत्साहन
- प्राधिकारी के अन्य निष्कर्ष

ख. मलेशिया सरकार/अन्य देशों द्वारा अनुरोध

261. उस व्यक्ति को दोहरी कटौती की अनुमति प्राप्त है जिसने मलेशिया से निर्यातित कार्गो के बीमा पर प्रीमियम का भुगतान किया है बशर्ते कि मलेशिया में निगमित किसी बीमा कम्पनी के पास जोखिम का बीमा किया गया है। भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1967 की धारा 33 के अनुसार किया गया होना चाहिए। यह सहायता की कटौती कर योग्य आय से की जाती है। कटौती अग्रणीत की जा सकती है।

262. यह कार्यक्रम 2016 से समाप्त कर दिया गया है। आयकर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौतियां) (निरसन) नियमावली 2012 साक्ष्य के रूप में नीचे दी गयी है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

263. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम आयकर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) नियमावली, 1995 द्वारा शासित था और इसे आयकर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम कटौती) (निरसन) नियमानली 2012 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यह कार्यक्रम स्वरूप का है और 1 जनवरी, 2017 से समाप्त हो गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी का यह मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ किसी प्रकार का प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxv) कार्यक्रम सं. 27: लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु प्रोत्साहन

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

264. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत एसएमई को 500,000 आरएम तक की प्रभार योग्य आय पर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक घटा हुआ निगम कर दिया जाता है। यह सुविधा केवल 2.5 एमएन आरएम प्रदत्त पूंजी वाली मलेशियायी एसएमई रेजिडेंट को अथवा ऐसी कम्पनी जिसका नियंत्रण 2.5 एमएन आरएम से अधिक प्रदत्त पूंजी वाली किसी अन्य कम्पनी द्वारा ही, दी जाती है।
265. प्रथम आरएम 500,000 प्रभार योग्य आय पर आरएम 2.5 मिलियन और उससे कम प्रदत्त पूंजी वाली रेजिडेंट कम्पनी के लिए 18 प्रतिशत की विशेष कर दर और आयकर अधिनियम, 1967 की अनुसूची 1 के अनुसार अनुवर्ती प्रभार योग्य आय पर 24 प्रतिशत लागू है। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन की प्रत्याशा नहीं है। यदि किसी कम्पनी को कर की हानि हुई हो तो, अधिमानी दर लागू नहीं है।
266. कोई भी कम्पनी निम्नलिखित शर्तों के पूरी करने पर अधिमानी कर के लिए दावा करने की हकदार है:
- मलेशिया में रेजिडेंट और निगमित
 - 2.5 मिलियन और कम के साधारण शेयरों के संबंध में प्रदत्त पूंजी
 - कम्पनी किसी समूह कम्पनियों का हिस्सा नहीं होनी चाहिए जहां उसकी किसी संबद्ध कम्पनी की 2.5 मिलियन आरएम से अधिक की प्रदत्त पूंजी हो।
267. यदि जांचाधीन इस मापदण्ड को पूरा करती हैं तो, वे अधिमानी कर दर का दावा करने की पात्र हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

268. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत, एसएमई अर्थात् आरएम 2.5 मिलियन और उससे कम प्रदत्त पूंजी वाला उद्यम के लिए अधिमानी आयकर दर प्रदान किया जाता है। आरएम 500,000 तक की आय पर प्रभार योग्य दर 18 प्रतिशत है। आरएम 500,000 से अधिक आय के लिए प्रभार योग्यकर 24 प्रतिशत है।
269. इस कार्यक्रम में राजस्व परित्याग के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है जो अन्यथा देय होता और एतद् द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट स्वरूप का भी है क्योंकि यह लघु एवं मध्यम उद्यम तक सीमित है जो स्थानीय रूप से अनुपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। प्राधिकारी पहले भी निर्धारित कर चुके हैं कि प्रतिकारी

शुल्क कच्ची सामग्री पर आयकर से छूट देने वाले कार्यक्रम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxvi) कार्यक्रम सं. 28: बढ़े हुए निर्यात हेतु भत्ता

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

270. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि यह कार्यक्रम आयकर अधिनियम 1967 की धारा 154(1) और आयकर के नियम 3 (बढ़े हुए आयातों के लिए भत्ता) नियमावली 1999 और आयकर (बढ़े हुए निर्यातों के लिए भत्ता) संशोधन नियमावली, 2003 के तहत कम्पनियों को प्रदत्त कर प्रोत्साहनों के रूप में है। कोई भी निर्यातक बढ़े हुए निर्यातों के लिए कर योग्य आय से 70 प्रतिशत कर कटौती का लाभ ले सकता है। यह भी कि यदि कथित भत्ते का उपयोग अर्जित वर्ष के दौरान नहीं किया जाता है तो, उसे अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकता है। कार्यक्रम की मौजूदगी के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्न पर भरोसा जताया है:

- निवेश संवर्धन एक्ट 1986
- आयकर अधिनियम 1967
- सीमा शुल्क अधिनियम 1967
- बिक्री कर अधिनियम 1972
- उत्पाद कर अधिनियम 1976
- मुक्त जोन अधिनियम 1990

ख. मलेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा अनुरोध

271. कोई भी रेजिडेंट विनिर्माता कम्पनी अथवा कृषिजन्य कम्पनी जो विनिर्मित उत्पादों अथवा कृषि उत्पादों का निर्यात करती है को बढ़े हुए निर्यातों हेतु भत्ता दिया जाता है। यह सहायता कर योग्य आय से छूट है। इसे भत्ते को आगे ले जाया जा सकता है।

272. निम्नानुसार भत्ता निर्धारित किया जाता है:

क. विनिर्मित उत्पाद

- कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बढ़े हुए निर्यात के मूल्य का 10% जहां निर्यात किए गए उत्पादों को कम से कम 30% वर्धित मूल्य मिला;
- कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बढ़े हुए निर्यात के मूल्य का 15% जहां निर्यात किए गए उत्पादों को कम से कम 50% वर्धित मूल्य मिला।

ख. कृषि उत्पाद

- कंपनी द्वारा कृषि उत्पाद के बढ़े हुए निर्यात के मूल्य का 10%

273. यह भत्ता कंपनी के सत्तर प्रतिशत सांविधिक व्यापार आय के लिए दिया जाएगा। निर्धारित नहीं किए गए किसी भी निर्यात भत्ते को भविष्य के वर्षों में निर्धारित किए जाने वाली सांविधिक आय के सत्तर प्रतिशत के लिए निर्धारित किया जाएगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

274. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक निवासी विनिर्माण कंपनी या कृषि कंपनी जो विनिर्मित उत्पादों या कृषि उत्पाद का निर्यात करती है, को बड़े हुए निर्यात के लिए भत्ता दिया जाना है। यह भत्ता कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बड़े हुए निर्यात के मूल्य के 10% या 15% के बराबर होता है। सांविधिक व्यापार आय के 70% के लिए भत्ता दिया जाएगा।
275. यह कार्यक्रम व्यय किए गए राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, जो अन्यथा देय है। प्राधिकारी पहले ही यह निर्धारित कर चुके हैं कि आयकर से छूट देने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxvii) कार्यक्रम संख्या 29: मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यातकों के लिए कर छूट**ग. याचिकाकर्तियों द्वारा अनुरोध**

276. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत, मुक्त व्यापार क्षेत्र अधिनियम 1990 की धारा 4 के अनुसार, निर्यातकों को सीमा शुल्क, बिक्री या सेवाकर और उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। मुक्त क्षेत्र जैसे पोर्ट ब्लेग फ्री ज़ोन, एक मुक्त वाणिज्यिक क्षेत्र है जहाँ कच्चे माल, घटकों, उपकरणों और कर मुक्त मशीनरी आयात करने की अनुमति है।

ख. मलेशिया सरकार / अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

277. न्यूनतम सीमा शुल्क हस्तक्षेप सहित किए जाने वाले विनिर्माण और वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए मलेशिया में मुक्त क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। मुक्त क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मुक्त क्षेत्र अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) के तहत वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया है। दो प्रकार के मुक्त क्षेत्र हैं, एक मुक्त औद्योगिक क्षेत्र जिसका अर्थ मुख्य रूप से विनिर्माण गतिविधियों के लिए है और दूसरा मुक्त वाणिज्यिक क्षेत्र जिसका अर्थ मुख्य रूप से वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए है। मुक्त क्षेत्र, सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 31 के तहत निर्यात और आयात पर प्रतिबंध के अतिरिक्त प्रधान सीमा शुल्क क्षेत्र (मलेशिया का कोई भी हिस्सा, मुक्त क्षेत्र लबुआन, लैंगकावी और तिओमन को छोड़कर) के बाहर के स्थान हैं। इस प्रकार, किसी भी विवरण की वस्तु और सेवाएँ, कानून द्वारा खासतौर पर और पूर्ण: निषिद्ध को छोड़कर, किसी भी शुल्क या कर के भुगतान के बिना मुक्त क्षेत्र में लायी जा सकती है, उनका उत्पादन, विनिर्माण, या प्रदान किया जा सकता है। कोई आवेदन पत्र नहीं है। नीतिगत अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है और वित्त मंत्री द्वारा मुक्त क्षेत्र अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) के तहत घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम में कोई अनुमानित परिवर्तन नहीं हैं।
278. कोई भी कंपनी मुक्त क्षेत्र अधिनियम 1990 के तहत किसी भी गजट मुक्त ज़ोन क्षेत्रों में स्थित नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

279. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम मुक्त क्षेत्र अधिनियम 1990 और मुक्त क्षेत्र विनियमन 1991 द्वारा प्रशासित है।
280. मुक्त ज़ोन का प्रबंधन मुक्त ज़ोन के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें वित्त मंत्री द्वारा मुक्त ज़ोन के प्रशासन, रखरखाव और संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है। न्यूनतम सीमा शुल्क हस्तक्षेप सहित किए जाने वाले विनिर्माण और वाणिज्यिक कार्यकलापों के उद्देश्य से मलेशिया में मुक्त क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। किसी भी विवरण की वस्तु और सेवाएँ, कानून द्वारा खासतौर पर और संपूर्ण रूप से निषिद्ध को छोड़कर, किसी भी शुल्क या कर के भुगतान के बिना मुक्त क्षेत्र में लायी जा सकती है, उनका उत्पादन, विनिर्माण, या उपलब्ध कराई जा सकती है।

281. यह कार्यक्रम व्यय किए गए राजस्व के वित्तीय योगदान के रूप में सब्सिडी प्रदान करता है, जो अन्यथा देय है और इस तरह से लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह मुक्त क्षेत्र में स्थित उद्यम के लिए उपलब्ध है। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि संबद्ध उत्पाद का कोई भी उत्पादक/निर्यातक मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित नहीं है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी पहले ही यह निर्धारित कर चुके हैं कि आयात शुल्क से छूट देने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxviii) कार्यक्रम संख्या 30: अनुसंधान और विकास कोष

कार्यक्रम संख्या 30(क): अनुसंधान और विकास कोष का व्यावसायीकरण (सीआरडीएफ-1)

कार्यक्रम संख्या 30(ख): अनुसंधान और विकास कोष का व्यावसायीकरण (सीआरडीएफ-2)

कार्यक्रम संख्या 30(ग): अनुसंधान और विकास कोष का व्यावसायीकरण (सीआरडीएफ-3)

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

282. याचिकाकर्ता ने कहा कि सीआरडीएफ-1 उपोत्पाद कंपनी सिरिकैट टेरेबिटैनयूनिवर्सिटी (एसटीयू) द्वारा सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय (पीपीयू)/सरकारी अनुसंधान संस्थान (जीआरआई) के अनुसंधान और विकास परिणामों के व्यावसायीकरण के लिए अनुदान है। अधिकतम 500000 आरएम या पात्र व्यय का 90% (जो भी कम हो) आंशिक अनुदान के रूप में निधि प्रदान की जाती है। स्थानीय स्तर पर किसी भी मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी केंद्र से अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए एसटीयू आवश्यक है। आउट सोर्सिंग मोड के माध्यम से अपने उत्पाद का उत्पादन करते समय कंपनी को व्यवसाय विकास संबंधी अपनी व्यावसायीकरण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता होती है। व्यवसायीकरण किए जाने वाले प्रस्तावित प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता वाले प्रौद्योगिकी क्लस्टर में से एक होना चाहिए, जो आईसीटी को छोड़कर एमओएसटीआई द्वारा अभिज्ञात हो और परियोजना मूर्त प्रकृति की होनी चाहिए। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए द्वारा तैयार अनुसंधान और विकास बुकलेट प्रस्तुत किया है।
283. याचिकाकर्ता ने कहा कि सीआरडीएफ-2 ऐसा वित्तपोषण है जो अधिकतम 500000 आरएम या पात्र व्यय का 70% (जो भी कम हो) सहित आंशिक अनुदान के रूप में स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय (पीपीयू)/सरकारी अनुसंधान संस्थान (जीआरआई) के अनुसंधान और विकास परिणामों के व्यावसायीकरण के लिए प्रदान किया जाता है। स्टार्ट-अप को किसी भी मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी केंद्र से अपने व्यवसाय को संचालित करने की आवश्यकता होती है। आउट सोर्सिंग मोड के माध्यम से अपने उत्पाद का उत्पादन करते समय कंपनी को व्यवसाय के विकास के संबंध में उनकी व्यावसायीकरण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए द्वारा तैयार अनुसंधान और विकास बुकलेट प्रस्तुत किया है।
284. याचिकाकर्ता ने कहा है कि सीआरडीईएफ 3 (क) एसएमई द्वारा किसी भी स्थानीय अनुसंधान और विकास के व्यावसायीकरण के लिए अनुदान है और सीआरडीएफ 3 (ख) एक गैर-एसएमई द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विकास के व्यावसायीकरण के लिए अनुदान है। सीआरएमएफएफ-3 (क) ऐसा वित्तपोषण है जिसमें आंशिक अनुदान के रूप में अधिकतम 400,000 आरएम या पात्र व्यय का 70% (जो भी कम हो) प्रदान किया जाता है और सीआरडीएफ-3 (ख) ऐसा वित्तपोषण है जिसमें आंशिक अनुदान के रूप में अधिकतम 400,000 आरएम या पात्र व्यय का 50% (जो भी कम हो) प्रदान किया जाता है। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1965 के तहत शुरू किया होना चाहिए, जिसमें कम से कम 51% मलेशियाई स्वामित्व और आरएम 25एमएम से कम वार्षिक टर्नओवर या 150 से कम कर्मचारी होने चाहिए। इसके अलावा, व्यावसायीकरण की जाने वाली प्रस्तावित प्रौद्योगिकी को आईसीटी को छोड़कर एमओएसटीआई द्वारा

अभिज्ञात प्राथमिकता वाले प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में से एक होना चाहिए, और अनुसंधान और विकास कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जाना चाहिए, तथा वाणिज्यिक रूप से तैयार प्रोटोटाइप उपलब्ध होना चाहिए। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए द्वारा तैयार अनुसंधान और विकास बुकलेट प्रस्तुत किया है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध

285. अनुसंधान और विकास निधि (सीआरडीएफ) का व्यावसायीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जो मलेशियाई स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा स्थानीय रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों की व्यावसायीकरण गतिविधियों की सहायता के लिए निधियन सहायता उपलब्ध कराता है। प्रौद्योगिकियों को सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विकसित किया जा सकता है या कंपनियों द्वारा इन-हाउस अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियों द्वारा विकसित किया जा सकता है। कार्यक्रम 1997 में स्थापित किया गया था। कार्यक्रम को सांविधिक, विनियमन, डिक्री या अन्य कानूनी उपाय के अनुसार उपलब्ध नहीं कराया गया था। कोई भी कंपनी जो सीआरडीएफ के लिए आवेदन करना चाहती है, उसे पहले एक पिचिंग सत्र में भाग लेना होगा जिसे एमटीडीसी द्वारा साप्ताहिक आधार पर आयोजित किया जाता है। पिचिंग सत्र से, संभावित आवेदक को सूचित किया जाएगा कि कंपनी सीआरडीएफ के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है या नहीं। यदि कंपनी को पात्र माना जाता है, तो उन्हें आवेदन, जिसका संसाधन और मूल्यांकन किया जाना है, प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। पात्रता प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों तक सीमित है। कार्यक्रम के लिए कोई अनुमानित परिवर्तन नहीं हैं।
286. सीआरडीएफ-1 की अवधि एक वर्ष है और आंशिक अनुदान के रूप में वित्तपोषण की अधिकतम राशि आरएम 500,000 है। सीआरडीएफ-2 और 3 की अवधि 6 वर्ष है और परिवर्तनीय हल्फनामा के आधार पर आंशिक अनुदान और आंशिक सुलभ ऋण के रूप में वित्तपोषण की अधिकतम राशि आरएम 4,000,000 है।
287. सीआरडीएफ 2 और 3 के लिए, परियोजना के पहले 2 वर्षों में निधि का संवितरण होता है और तीसरे से छठे वर्ष में सुलभ ऋण का पुनर्भुगतान होगा। परियोजना की अवधि के दौरान, कंपनियां अपनी प्रगति, उपलब्धियों, निधियन उपयोग और व्यावसायिक गतिविधियों की निगरानी करेंगी।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

288. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुसंधान और विकास निधि (सीआरडीएफ) का व्यावसायीकरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय (एमईएसटीईसीसी) के तहत एक कार्यक्रम है। यह मलेशियाई स्वामित्व वाली कंपनियों (51% शेयर) द्वारा शुरू की गई स्थानीय रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण गतिविधियों की सहायता के लिए निधियन सहायता उपलब्ध कराता है।
 - सीआरडीएफ-1 नई प्रौद्योगिकियों के लिए बाजार वैधिकरण और प्रौद्योगिकी वैधिकरण के लिए निधि उपलब्ध कराता है;
 - सीआरडीएफ-2 स्टार्ट-अप और छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए व्यावसायीकरण गतिविधियाँ हेतु निधि उपलब्ध कराता है;
 - सीआरडीएफ 3 बड़ी कंपनियों के लिए व्यावसायीकरण गतिविधियों हेतु निधि उपलब्ध कराता है।
289. सीआरडीएफ-1 के लिए वित्तपोषण की अधिकतम राशि आरएम 500,000 है और सीआरडीएफ-2 और 3 के लिए अधिकतम वित्तपोषण आरएम 4,000,000 है।

290. कार्यक्रम निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में वित्तीय योगदान के लिए प्रावधान करता है और इस तरह लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह मलेशियाई स्वामित्व वाले उद्यम तक ही सीमित है। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाई जानी चाहिए।

(xxix) कार्यक्रम संख्या 31: इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए कर प्रोत्साहन

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

291. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी कंपनी जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) का कार्य करती है, कर भत्ते के लिए आवेदन कर सकती है। 10 वर्ष के भीतर किए गए अर्हक पूंजीगत व्यय के 50% आईटीए के लिए आवेदन और आंकलन के प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैधानिक आय के 70% (प्रोत्साहित क्षेत्रों के लिए 100%) हेतु भत्ते का समायोजन उपलब्ध है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए द्वारा तैयार अनुसंधान और विकास वुकलेट उपलब्ध कराया है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

292. इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के लिए प्रोत्साहन 10 वर्षों के भीतर किए गए अर्हक पूंजीगत व्यय पर 50% का निवेश कर भत्ता (आईटीए) है। आंकलन के प्रत्येक वर्ष की 70% सांविधिक आय के लिए आईटीए समायोजित (ऑफसेट) की जा सकती है। इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन गतिविधियों में से एक है जिसे वित्त मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रोत्साहन का उद्देश्य अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए है। आवेदन करने वाली और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली सभी कंपनियों को कार्यक्रम की मंजूरी नहीं दी जाएगी। आवेदकों को अभी भी अनुमोदन समिति के समक्ष जाने की आवश्यकता होगी। निवेश प्रोत्साहन अधिनियम (प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्ट) 1986 की धारा 26ई, 27ई और 29एफ साक्ष्य में दिए गए हैं। कार्यक्रम में कोई अनुमानित परिवर्तन नहीं हैं। आंकलन वर्ष के लिए आधार अवधि में किए गए अर्हक पूंजीगत व्यय को सांविधिक आय से घटा दिया जाता है। घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है।
293. इन-हाउस अनुसंधान और विकास प्रोत्साहन के लिए पात्रता मानदंड:
- कंपनी को कंपनी अधिनियम 1965/कंपनी अधिनियम 2016 के तहत शुरू किया जाना और मलेशिया का निवासी होना चाहिए।
 - शुरू की गई निवेश विकास गतिविधियों को निवेश प्रोत्साहन अधिनियम (पीआईए), 1986 की धारा 2 के तहत अनुसंधान और विकास गतिविधियों की परिभाषा का अनुपालन करना चाहिए।
 - अनुसंधान और विकास गतिविधियां देश की जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए और मलेशिया की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना चाहिए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

294. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 1986 की धारा 26ई, 27ई और 29एफ द्वारा प्रशासित है। इस कार्यक्रम के तहत, पूंजीगत व्यय के 50% निवेश कर भत्ते के रूप में इन-हाउस अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाता है। मूल्यांकन के प्रत्येक वर्ष की 70% सांविधिक आय के लिए भत्ते का समायोजन किया जा सकता है। किसी भी कंपनी को मलेशिया में इन-हाउस अनुसंधान गतिविधि में भाग लेने या भाग लेने की इच्छा करने वाली कंपनी को अनुमति दी जा सकती है।
295. यह कार्यक्रम व्यय किए गए राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान करता है, जो अन्यथा देय है और इस तरह लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह अनुसंधान और विकास कार्य से जुड़े उद्यम तक सीमित है। प्राधिकारी पहले ही यह निर्धारित कर चुके हैं कि आयकर से छूट देने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क

लगाया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxx) कार्यक्रम संख्या 32: अनुसंधान और विकास के लिए दोगुनी कटौती

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

296. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत, कोई भी कंपनी जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इन-हाउस अनुसंधान और विकास का कार्य शुरू करती है, 10 वर्षों के भीतर किए गए 50% अर्हक पूंजीगत व्यय के आईटीए के लिए आवेदन कर सकती है और ऑकलन के प्रत्येक वर्ष के लिए इसकी सांविधिक आय के 70% (प्रोत्साहित क्षेत्रों के लिए 100%) हेतु भत्ते का समायोजन उपलब्ध है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए द्वारा तैयार अनुसंधान और विकास बुकलेट उपलब्ध कराया है।

ख. मलेशिया सरकार / अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

297. मलेशिया में रहने वाले व्यक्ति द्वारा अनुसंधान संबंधी किया गया प्रत्यक्ष राजस्व व्यय, दोगुनी कटौती के दावे के लिए पात्र होगा। ये खर्च विशेष रूप से उस व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में इन-हाउस अनुसंधान में किए जाने चाहिए। उक्त शोध को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालांकि, मंत्री ने यह शक्तियां डायरेक्टर जनरल ऑफ इनलैंड रेवेन्यू (डीजीआईआर) को सौंप दी हैं। साक्ष्य के रूप में धारा 34ए आयकर अधिनियम 1967 दी गई। सरकार विवेकाधिकार का प्रयोग करती है कि कौन-सा फर्म लाभ का पात्र है। कार्यक्रम में कोई अनुमानित परिवर्तन नहीं हैं। कटौती को आगे बढ़ाया जा सकता है।
298. कंपनियों को अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए आईआरबी, जो कि एमओएफ के तहत एक एजेंसी है, को आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात कंपनी को आईआरबी से अनुमोदन पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। आईआरबी द्वारा संतुष्ट होने पश्चात कि कंपनी ने शर्तों का अनुपालन किया है, आईआरबी अनुमोदन पत्र जारी करेगा। बाद में, कार्यक्रम के लिए अनुमोदित कंपनियां कर कटौती के लिए दावे की गणना युक्त अपनी वार्षिक कर विवरणी सहित एक साथ आईआरबी को अपना दावा प्रस्तुत करती हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

299. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम धारा 34ए आयकर अधिनियम 1967 (अनुलग्नक डी-32.1) और पब्लिक रूलिंग 5/2004 द्वारा प्रशासित है। मलेशिया में रहने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अनुसंधान संबंधी राजस्व प्रत्यक्ष व्यय निवल लाभ से दोगुनी कटौती का दावा करने हेतु पात्र होगा। विचाराधीन अनुसंधान गतिविधि को निर्धारित मानदंडों और परिभाषा को पूरा करना होगा तथा वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
300. कार्यक्रम व्यय किए गए राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान करता है, जो अन्यथा देय है और इस तरह लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह अनुसंधान और विकास कार्य से जुड़े उद्यम तक सीमित है। प्राधिकारी पहले ही यह निर्धारित कर चुके हैं कि आयकर से छूट देने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxxi) कार्यक्रम संख्या 34: लघु और मध्यम उद्यम को सुलभ ऋण

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

301. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत, परियोजना में एसएमई और नई स्टार्ट-अप कंपनियों को ऋण, अचल संपत्ति और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की सुविधा दी जाती है, ताकि वे अपने कार्यों को वैध औद्योगिक साइटों पर स्थानांतरित कर सकें और व्यवसाय प्रबंधन तथा प्रचालन में आईसीटी को अपनाने के माध्यम से अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकें। न्यूनतम आरएम 50000 और अधिकतम 3 मिलियन ऋण प्रदान किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1965 के तहत निगमित एसएमई में कम से कम 60% इक्विटी मलेशिया की होनी चाहिए, और सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों की हिस्सेदारी 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनके पास वैध आधार लाइसेंस होना चाहिए। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने मलेशिया के एसएमई निगम पर भरोसा किया है।

ख. मलेशिया सरकार / अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

302. मलेशिया में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2001 में एसएलएसएमई शुरू किया गया था। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मलेशिया सरकार द्वारा एसएलएसएमई के लिए निधि एसएमई निगम मलेशिया के माध्यम से एमआईडीएफ को प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में कोई अनुमानित परिवर्तन नहीं हैं। विधिक, विनियमन, डिक्री या अन्य कानूनी उपाय के अनुसार कार्यक्रम का प्रवधान नहीं किया गया था।
303. मलेशियाई कंपनी अधिनियम 2016 या व्यापार पंजीयन 1956 के तहत शामिल एसएमई कम से कम 60% इक्विटी मलेशियाई द्वारा या शेयरधारिता के साथ सार्वजनिक-सूचीबद्ध कंपनियों (यदि लागू हो) द्वारा आयोजित 20% से अधिक नहीं के साथ-साथ व्यवसाय संचालन के साथ शामिल है। विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण संबंधित क्षेत्र और सेवा क्षेत्र (बीमा और वित्तीय सेवाओं को छोड़कर) एसएलएसएमई के तहत वित्तपोषण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
304. आवेदक/एसएमई को निधियन आवेदन प्रपत्र (फाइनेंसिंग एप्लीकेशन फॉर्म) को पूरा करना होगा और एमआईडीएफ को जमा करना होगा। आवेदन पत्र एमआईडीएफ की आधिकारिक वेबसाइट या मुख्य कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में एमआईडीएफ अधिकारियों के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने हैं। इसके बाद, एमआईडीएफ के अधिकारी एसएमई की वित्तपोषण आवश्यकताओं पर आगे चर्चा के लिए आवेदक/एसएमई से संपर्क करेंगे। आवेदक/एसएमई एमआईडीएफ के अधिकारियों को पूर्ण दस्तावेज जमा करने के बाद एमआईडीएफ आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करेगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

305. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम दिसंबर 2001 में शुरू किया गया था और यह एसएमई को ऋण प्रदान करता है। यह कार्यक्रम मौजूदा, साथ ही परियोजना के लिए स्टार्ट-अप उद्यमों, अचल संपत्तियों और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।
306. कार्यक्रम निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। लाभ की राशि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अनुसार दिए गए ऋण पर किए जाने वाले भुगतान की राशि और किसी अन्य तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर किए जाने वाले राशि के भुगतान के बीच अंतर के बराबर है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह एसएमई तक सीमित है जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाई जानी चाहिए।

(xxxii) कार्यक्रम सं. 35: अंतर्राष्ट्रीय खरीद केंद्र

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

307. इस कार्यक्रम में मलेशियाई कंपनियों को आयकर में छूट का प्रावधान है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

308. कार्यक्रम आयकर छूट संख्या 42 आदेश 2005 द्वारा अभिशासित किया गया था। कार्यक्रम 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त हो गया है। इसलिए, 1 मई से शुरू होने वाले नए आवेदकों को आईपीसी का कोई नया दर्जा और वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। मौजूदा आईपीसी कंपनियाँ तथापि, उनके आईपीसी वित्तीय प्रोत्साहन के 10 साल पूरे हो गए हैं और इसके बाद आईपीसी स्थिति अनुमोदन की शर्तों को पूरा करने के अधीन उनकी आईपीसी स्थिति बरकरार रह सकती है। उन सभी कंपनियों को नहीं जिन्होंने आवेदन किया और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया, कार्यक्रम के लिए अनुमोदित किया गया।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

309. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम आयकर छूट संख्या 42 आदेश 2005 के द्वारा प्रशासित था। कार्यक्रम आयकर से पूरी छूट प्रदान करता है। कार्यक्रम 30 अप्रैल 2015 को समाप्त हो गया है, लेकिन मौजूदा स्थिति धारक को कार्यक्रम के तहत 10 वर्षों तक पूर्ण कर छूट का लाभ प्राप्त करना जारी रहेगा और उसके बाद भी वे मापदंड को पूरा करते रहेंगे।

310. कार्यक्रम उन संस्थाओं के संचालन में बना हुआ है, जिन्हें 30 अप्रैल 2015 से पहले ही आईपीसी का दर्जा मिल चुका था। ऐसे उद्यमों के लिए यह कार्यक्रम पीओआई के दौरान परिचालन में था। कार्यक्रम आयकर से पूरी छूट प्रदान करता है। कार्यक्रम राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह आईपीसी स्थिति के साथ उद्यम तक सीमित है। मेट्रोड ओएफएचसी ने कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है और प्राधिकारी ने इस तरह के लाभ के लिए प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) निर्धारित की है।

(xxxiii) मेट्रोड ग्रुप द्वारा प्रयुक्त अन्य कार्यक्रम: उस कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क पर छूट जिसका प्रयोग निर्यातित सामानों के उत्पादन में किया जाता है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेट्रोड मलेशिया ने निर्यात उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री के आयात पर छूट के रूप में लाभ प्राप्त किया है क्योंकि मेट्रोड मलेशिया ने विशेष रूप से प्रदर्श-14 में अपनी प्रश्नावली के उत्तर में स्वीकार किया कि "निर्यात सामानों के लिए बनी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क में छूट प्रदान करना (कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की) छूट के तहत शामिल है। उन सामानों के लिए इस योजना के तहत कोई शुल्क छूट उपलब्ध नहीं है जिनका आयात घरेलू बाजार के लिए लक्षित परिष्कृत उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में गलत नोट किया था कि मेट्रोड द्वारा प्राप्त यह लाभ कार्यक्रम सं. 24 के तहत लाभ है।"

311. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में उस छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान के लिए प्रावधान है जो अन्यथा कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट के माध्यम से देय है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात निष्पादन संबंधी घटक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातित सामानों के उत्पादन में प्रयोग के लिए कच्ची सामग्री का आयात केवल तभी प्रतिकार योग्य सब्सिडी के रूप में नहीं माना जा सकता यदि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हो कि यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन तंत्र है कि कोई अधिक प्रेषण नहीं है। मेट्रोड ग्रुप ने केवल तंत्र की मौजूदगी और उस सत्यापन तंत्र की एक-एक कर व्याख्या अथवा पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए बिना अधिक प्रेषण के अभाव का ही दावा किया है। मेट्रोड ग्रुप ने उस कंपनी पर सरकार द्वारा शुल्क लगाए जाने का कोई उदाहरण नहीं दिया है जहां वह निर्यात दायित्व को पूरा करने में असमर्थ थी।

मलेशिया से उत्पादक/निर्यातक

अल्फा इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी

312. अल्फा इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/ निर्यातक है। अल्फा इंडस्ट्रीज ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की और उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान की।

313. प्राधिकारी ने अल्फा इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी द्वारा दायर उत्तर की जांच की। और जांच के बाद उनसे और जानकारी मांगी और उत्तर में प्रदान की गई जानकारी के सत्यापन के लिए भी अनुरोध किया। तथापि, अल्फा इंडस्ट्रीज ने प्रश्नावली में पहले से दी गई जानकारी के सत्यापन और जानकारी के लिए प्राधिकारी के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि अल्फा इंडस्ट्रीज ने जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है और तदनुसार कोई भी अलग-अलग सब्सिडी मार्जिन दर अल्फा इंडस्ट्रीज के लिए निर्धारित नहीं की जा सकती है। मलेशिया से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन को अल्फा इंडस्ट्रीज के लिए लागू किया जा रहा है।

मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी (निर्माता), मेट्रॉड (ओएफएचसी) एसडीएन बीएचडी (ट्रेडर), मेट्रोड कॉपर उत्पाद एसडीएन बीएचडी ("एमसीपी") (ट्रेडर), पैनासोनिक प्रोक्योरमेंट मलेशिया एसडीएन बीएचडी, (ट्रेडर), सावलि कॉपर प्रोडक्ट्स प्रा.लि. भारत (आयातक)

314. मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी ("**मेट्रॉड मलेशिया**") मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं का निर्माता है। मेट्रोड ओएफएचसी एसडीएन बीएचडी ("**मेट्रोड ओएफएचसी**") और मेट्रॉड कॉपर उत्पाद एसडीएन बीएचडी ("**एमसीपी**") पूरी तरह से मेट्रोड मलेशिया के स्वामित्व वाले सहायक हैं। मेट्रोड ओएफएचसी और एमसीपी, मेट्रॉड मलेशिया के लिए विपणन गतिविधियों में लगे हुए हैं। मेट्रोड ओएफएचसी और एमसीपी भी मेट्रोड मलेशिया को संबद्ध सामग्री के निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। मेट्रॉड मलेशिया सीधे भारत को माल निर्यात नहीं करता है। मेट्रोड मलेशिया द्वारा उत्पादित माल मेट्रोड ओएफएचसी और एमसीपी को विक्रय किया गया था। मेट्रोड ओएफएचसी ने भारत से संबंधित सामान सीधे उपयोगकर्ता सावली कॉपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भारत ("**सावली**") और अन्य असंबंधित अंत उपयोगकर्ताओं को निर्यात किया। एमसीपी ने असंबंधित व्यापारी पैनासोनिक प्रोक्योरमेंट मलेशिया एसडीएन बीएचडी, ("**पैनासोनिक**") के माध्यम से भारत को माल निर्यात किया। पैनासोनिक द्वारा भारत को संबद्ध वस्तुओं का सभी निर्यात एंकर इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लिमिटेड को किया गया था जो पैनासोनिक की सहायक कंपनी है।
315. मेट्रोड मलेशिया, मेट्रोड ओएफएचसी, मेट्रो कॉपर और पैनासोनिक ने प्रश्नावली का उत्तर दिया। मेट्रोड मलेशिया और मेट्रोड ओएफएचसी मलेशिया सरकार के सब्सिडी कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए।
316. प्राधिकारी ने मेट्रोड मलेशिया, मेट्रोड ओएफएचसी, मेट्रोड कॉपर और पैनासोनिक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की पुष्टि की है और कार्यक्रम सं. 23, 24 और 35, के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है। जिनके लिए पीओआई के दौरान लाभ प्राप्त हुआ या अर्जित किया गया। प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान था जो अन्यथा था। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि कि कार्यक्रम सं. 12, के संबंध में मेट्रोड मलेशिया द्वारा यह दावा किया गया है कि कोई लाभ नहीं लिया गया है जबकि मलेशिया सरकार ने प्रस्तुत किया है कि मेट्रॉड मलेशिया को कार्यक्रम सं. 12 के तहत लाभ मिला है। तदनुसार, प्राधिकरण, मेट्रोड मलेशिया के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यक्रम सं. 12 के तहत लाभ का निर्धारण करता है। परिणामस्वरूप, इस कार्यक्रम के प्राप्तकर्ता के रूप में मेट्रोड समूह को लाभ प्रदान किया गया। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट था क्योंकि वे मेट्रोड समूह सहित कुछ उद्यम तक सीमित थे।
317. निम्नलिखित तालिका सब्सिडी कार्यक्रमों और संबंधित सब्सिडी मार्जिन का नाम प्रदान करती है।

कार्यक्रम सं.	अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम	त्वरित पूंजी भत्ता	कर योग्य आय से पूंजीगत व्यय की	***	0-1%

सं. 12		त्वरित कटौती		
कार्यक्रम सं. 23	मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट	कार्यक्रम में योग्य निर्माता को मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क में छूट शामिल है।	***	0-1%
कार्यक्रम सं. 35	अंतर्राष्ट्रीय खरीद केंद्र (आईपीसी दर्जा)	सांविधिक आय पर पूर्ण आयकर छूट	***	0-1%
अन्य कार्यक्रम	कच्ची सामग्री/संघटकों पर आयात शुल्क से छूट	इस कार्यक्रम में उस आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की छूट शामिल है जिसका प्रयोग निर्यात सामानों के उत्पादन में किया जाता है।		0-5%
कुल			***	0-5%

मलेशिया के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों का सार

318. मलेशिया से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) का निर्धारण सहयोगी पार्टी, उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी के लिए मेट्रोड ग्रुप के लिए सबसे अधिक सब्सिडी के आधार पर और अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
कार्यक्रम सं. 12	त्वरित पूंजी भत्ता	***	0-1%
कार्यक्रम सं. 23	मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट	***	0-1%
कार्यक्रम सं. 14/19/21/24	कच्चे माल/घटकों पर आयात शुल्क से छूट	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 9/10/11/12/13/15/17/18/25/27/28/31/32/35	अंतर्राष्ट्रीय खरीद केंद्र (आईपीसी स्थिति)/आयकर लाभ.	***	0-1%
कार्यक्रम सं. 1, 3, 4, 6 और 30	अनुदान कार्यक्रम	***	0-5
कार्यक्रम सं. 34	ऋण कार्यक्रम	***	0-5
कार्यक्रम सं. 7 और 8	ऋण कार्यक्रम	***	0-5
कुल		***	5-15

वियतनाम**च.1. याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच**

(i) कार्यक्रम सं. 1: डिक्री 24 के अध्याय V के तहत आयकर प्राथमिकताएं (उद्यम आयकर कानून का कार्यान्वयन)

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

319. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि अनुच्छेद 9 के तहत, वित्त मंत्रालय ने आयकर दर को विनिर्दिष्ट किया है-

1. व्यावसायिक प्रतिष्ठान 28% हैं।
2. व्यावसायिक प्रतिष्ठान तेल और गैस और / या किसी अन्य दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोहन की गतिविधियों में शामिल है, ऐसे उद्यम पर लागू कर 28% - 50% से लेकर होगा।

320. कार्यक्रम के तहत, ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए विशिष्ट आयकर दरें (प्रकार 2) वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री द्वारा तय की जाएंगी। कार्यक्रम की सीमा कुछ निर्दिष्ट उद्यमों तक ही सीमित है। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित डिक्री या सूचनाएं प्रदान की हैं जो उनके लिए यथोचित उपलब्ध थीं।

- डिक्री सं. 48/2009/एनडी-सीपी, 19 मई 2009
- सरकार को उद्यम आय कर से संबंधित कानून के कार्यान्वयन का विवरण देने वाला 22 दिसंबर, 2003 की डिक्री संख्या 164/2003/ एनडीसीपी
- सरकार के संगठन से संबंधित कानून 25 दिसंबर, 2001 के अनुसरण में
- उद्यम आय कर से संबंधित 17 जून, 2003, कानून संख्या 09/2003/ क्यूएच11 के अनुसरण में

क. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

321. उद्यम आय कर 2003 से संबंधित कानून को लागू करने वाली डिक्री 24/2007/एनडी-सीपी 1 जनवरी, 2009 से समाप्त हो गई क्योंकि इसे उद्यम आय कर से संबंधित कानून 2008 से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इस प्रकार, इस जांच की पीओआई के दौरान डिक्री 24 को लागू नहीं किया गया था।
322. अधिमान्य आयकर दर, कर छूट और कर में कमी सहित कॉर्पोरेट आयकर लाभ, का अभिशासन संशोधित कानून 2013 के अनुच्छेद 1.7 और संशोधन कानून 2014 के अनुच्छेद 1.7 द्वारा किया जाता है।
323. 1996 में वियतनाम में विदेशी निवेश के कानून को 2000 में संशोधित किया गया था। कारपोरेट आयकर लाभ जिनमें अधिमान्य आयकर दर, कर छूट और कर कटौती शामिल हैं, को डिक्री 24/2000/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 46 से 49 द्वारा अभिशासित किया जाता है।
324. यहां कोई आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया नहीं है। उद्यम लागू कर कानून और नियमों पर भरोसा करते हैं कि वे उन लाभों की पहचान करते हैं, जो कर रिटर्न में लाभ की घोषणा करते हैं, और घोषणा के अनुसार आयकर का भुगतान करते हैं। निर्यात प्रदर्शन या घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर पात्रता आकस्मिक नहीं है।
325. लाभ के आकार को नियंत्रित करने वाला कोई मानदंड नहीं है। आयकर लाभ की राशि मानक कर की दर और अधिमान्य कर की दर और/या छूट या कमी के अभाव में कर भुगतान की राशि के बीच अंतर की राशि है।

326. डोंग वियत नॉन-फेरस मेटल एंड प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी (डीओवीआईएनए) को इस कार्यक्रम के तहत कॉर्पोरेट आयकर लाभ प्राप्त हुए। जांच की अवधि के दौरान, डीओवीआईएनए ने 2017 की कर अवधि के लिए नई निवेश परियोजनाओं से आय पर सरकार को देय कर पर 50% की कटौती प्राप्त की। यह वरीयता इस तथ्य पर आधारित है कि डीओवीआईएनए ने लॉन्ग एन इकोनॉमिक ज़ोन में नई परियोजनाओं पर निवेश किया, जो कि डिक्री नंबर 218/2013/एनडी-सीपी के तहत प्रोत्साहित भौगोलिक क्षेत्रों की सूची में आता है। कार्यक्रम में शामिल करों का कोई आधान नहीं है।
327. कार्यक्रम में कोई प्रत्याशित परिवर्तन नहीं किया गया है।
328. सीएफटी कॉपर विना लिमिटेड को बियेन होआ इंडस्ट्रियल पार्क में विदेशी निवेशित उद्यम के रूप में कॉर्पोरेट आयकर लाभ प्राप्त हुआ, यह डिक्री 24/2000/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 46 के अनुसार है। यह अपने निवेश परियोजना की अवधि के लिए सरकार को देय कर पर 15% की अधिमान्य आयकर दर के अधीन है, जो स्थापना की तारीख से 30 वर्ष है। यह वरीयता इस तथ्य पर आधारित है कि सीएफटी कॉपर विना की स्थापना एक विदेशी-निवेश कंपनी के रूप में की गई थी।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

329. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयकर से छूट प्रदान करने वाला कार्यक्रम कॉर्पोरेट आयकर 2008 द्वारा और 2013 में संशोधित विदेशी निवेश कानून द्वारा अभिशासित है। वियतनाम में कॉर्पोरेट आयकर की मानक दर 20% है। डिक्री 218/2013/ एनडी-सीपी उन मामलों को प्रदान करता है जहां करदाता 50% की कर कटौती के हकदार हैं। कटौती निर्दिष्ट क्षेत्रों या प्रोत्साहित भौगोलिक क्षेत्र में की जाने वाली निवेश परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
330. विदेशी निवेशित उद्यम के लिए, डिक्री 24/2000/ एनडी-सीपी के अनुच्छेद 46 के अनुसार 15% और 10% की अधिमान्य दर विनिर्दिष्ट है।
331. कार्यक्रम राजस्व पूर्वगामी के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है, जो अन्यथा देय है और जिससे लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम सेक्टर विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट भी है क्योंकि यह प्रोत्साहित क्षेत्रों या प्रोत्साहित भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(ii) कार्यक्रम सं. 2 : कच्चे माल के लिए आयात शुल्क में छूट या प्रतिपूर्ति

क. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया

332. याचिकाकर्ता ने कहा कि "कच्चे माल और उपकरणों और मशीनरी के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली आपूर्ति" के लिए आयात शुल्क में छूट कानून संख्या 45, अध्याय IV के तहत प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 16.6 (घ) और 16.9 के तहत वित्त मंत्रालय ने उन डोमेन की सूची में निवेश परियोजनाओं की उत्पादन गतिविधियों के लिए आयातित कच्चे माल, आपूर्ति और सामान को विनिर्दिष्ट किया है जहां निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है या असाधारण सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों के साथ भौगोलिक क्षेत्रों की बैठक की सूची है।
333. कार्यक्रम के तहत, निर्यात माल के उत्पादन के लिए आयात किए गए कच्चे माल या आपूर्ति, जिसके लिए कर का भुगतान किया गया है, शुल्क-मुक्त आयात (यू/ए. 16.4) या प्रतिपूर्ति (यू / ए.19) के अधीन है। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित डिक्री या सूचनाएं प्रदान की हैं जो उनके लिए यथोचित उपलब्ध थीं।

- विधि सं. 45/2005/ क्यूएच-11 (विधि सं. 45)
- डिक्री सं. 87/2010 /एनडी-सीपी (डिक्री 87) विधि संख्या 45 अध्याय IV

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

334. यह नीति निर्यात और आयात शुल्क पर कानून द्वारा विनियमित है और पूरे देश में हर रूप और प्रकार के व्यवसाय पर लागू होती है।
335. छूट की राशि निर्यात किए गए माल के उत्पादन में वास्तव में उपयोग किए जाने वाले आयातित सामग्रियों के मूल्य के अनुरूप शुल्क की मात्रा के बराबर है। यह राशि सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार निर्यात किए गए माल के उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल के उपयोग पर सीमा शुल्क को रिपोर्ट करने के समय निर्धारित या घोषित की जाती है। लागू सीमा शुल्क विनियम डिक्री 08/2015/एन डी-सीपी, दिनांक 21 जनवरी, 2015 ("डिक्री 08") और परिपत्र 38/2015/टीटी-बीटीसी, 25 मार्च, 2015 वित्त मंत्रालय के तहत वियतनाम सीमा शुल्क सामान्य विभाग (जीडीवीसी) ट्रैक सिस्टम तैयार करने के प्रभारी हैं।
336. कोई आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया नहीं है। जब तक आयातित सामग्रियों का उपयोग निर्यात किए गए सामानों के उत्पादन में किया जाता है, तब तक ऐसी सामग्रियों को आयात करने वाले उत्पादकों के क्षेत्र, स्थान या आकार पर ध्यान दिए बिना आयात शुल्क से छूट दी जाती है। इस कार्यक्रम के लिए कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं हैं। करों पर कोई प्रतिफल नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

337. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम को आयात और निर्यात ड्यूटी 2016 और सीमा शुल्क विनियम 08/2015/ एनडी-सीपी दिनांक 21, 2015 और परिपत्र 38/2015/टीटी-बीटीसी से संबंधित कानून द्वारा प्रशासित किया गया है। कार्यक्रम निर्यात उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल कच्चे माल पर आयात शुल्क में छूट का प्रावधान करता है। जीडीवीसी द्वारा बनाए गए ट्रैक सिस्टम के बारे में कोई साक्ष्य और विवरण नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादन में पूरे कच्चे माल का आयात शुल्क मुक्त है।
338. कार्यक्रम में राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर है। प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाई जानी चाहिए।

(iii) कार्यक्रम सं. 3 : उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर पर छूट**क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध**

339. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम कपड़ा और वस्त्रों के उद्यमों, चमड़े और जूते; इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उत्पाद; कार और यांत्रिकी विनिर्माण पर लागू है; वियतनाम सरकार की योजना के अनुसार लाभान्वित होंगे, यदि, -

1. वर्ष 2014 की कर अवधि में 50% कर कटौती किए जाने वाले उद्यमों, इस कटौती का पालन 3 वित्तीय वर्षों की कर अवधि के लिए किया जाएगा।
2. छूट की अधिकतम अवधि 1 वर्ष है, अनुबंध के निष्पादन की तारीख से शुरू या वियतनाम में पहली बार लागू प्रौद्योगिकियों के साथ ट्रेल प्रोडक्शन या प्रोडक्शन शुरू करना।
3. उद्यमों की आय 10 वर्षों के लिए 20% की अधिमान्य कर दर, 02 वर्ष के लिए कर छूट और अगले 04 वर्षों के लिए 50% की कटौती के लिए पात्र है।

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

340. कार्यक्रम सं. 1 के उत्तर में आयकर कार्यक्रम और लाभ के बारे में सूचना प्रदान की गई है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

341. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पहले ही निर्धारित कर चुका है कि आयकर से छूट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के लिए प्रतिकर शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकर शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) कार्यक्रम सं. 5 : निर्यातकों को अधिमान्य ऋण देना**क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध**

342. याचिकाकर्ता ने कहा कि बैंकों के साथ वित्त मंत्रालय कार्यक्रम के तहत ऋण को विनियमित करता है। बैंकों ने विकास निवेश क्रेडिट और निर्यात क्रेडिट पर राज्य की नीतियों को लागू करने के लिए निवेश के बाद की ब्याज दर के लिए उद्यमों को ऋण प्रदान किया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि राज्य बैंकिंग उद्योग में एक प्रमुख नियामक है और इसलिए वियतनाम में प्रमुख बैंकों द्वारा 50% ऋण कम ब्याज वाले ऋण हैं। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित डिक्री या सूचनाएं प्रदान की हैं जो उनके लिए यथोचित उपलब्ध थीं।

- डिक्री सं. 75/2011/एनडी-सीपी, 30 अगस्त 2011
- डिक्री सं. 106/2008/एनडी-सीपी
- डिक्री सं. 106/2004/एनडी-सीपी
- संकल्प संख्या 02/एनक्यू-सीपी (सरकार 7 जनवरी 2013)
- आधिकारिक पत्र संख्या 2667/एनएचएनएन-वीपी (स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम 17 अप्रैल 2014)

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध

343. सरकार बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों का रिकॉर्ड नहीं रखती है। सभी वित्तीय संस्थान, शेयरहोल्डिंग संरचना पर ध्यान दिए बिना, वाणिज्यिक विचारों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने ऋण का परिचालन करते हैं।
344. ये कार्यक्रम वियतनाम विकास बैंक ("वी डीबी") द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो वियतनाम विकास बैंक की स्थापना पर निर्णय 108/2006/क्यूडी-टीटीजी 19 मई, 2006 द्वारा स्थापित एक राज्य नीति बैंक है। वीडीबी में तीन बुनियादी राज्य क्रेडिट उपकरण हैं: (i) निवेश ऋण ऋण; (ii) निर्यात ऋण ऋण; (iii) निवेश पश्चात ऋण सहायता।
345. पीओआई के दौरान, डिक्री 75/2011/एनडी-सीपी और डिक्री 32/2017 / एनडी-सीपी के साथ निवेश क्रेडिट ऋण, निर्यात क्रेडिट और पोस्ट-निवेश क्रेडिट सहायता का प्रावधान।
346. वित्त मंत्रालय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए परिपत्र जारी करता है। वियतनाम विकास बैंक उपर्युक्त विनियमों और क्रेडिट प्रावधान पर इसके स्वयं के नियमों के अनुसार पात्र संस्थाओं को निवेश क्रेडिट प्रदान करता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

347. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम डिक्री 75/2011/एनडी-सीपी द्वारा प्रशासित है। डिक्री 75 के अनुच्छेद 5 में पात्र परियोजनाओं की सूची में निवेश परियोजनाओं वाले निवेशकों को निवेश क्रेडिट प्रदान करने के लिए वियतनाम विकास बैंक को अधिकृत करता है। निवेश ऋण क्रेडिट ऋण, निर्यात ऋण, निवेश पश्चात ऋण सहायता आदि के रूप में होता है। कार्यक्रम को संचालित करने के लिए दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं।
348. वियतनाम विकास बैंक (वीडीबी) की स्थापना सरकार द्वारा यथा विनियमित राज्य विकास निवेश और निर्यात ऋण नीतियों को निष्पादित करने के लिए निर्णय संख्या 108/2006/ क्यूडी-टीटीजी दिनांक 19 मई 2006 के तहत की गई है।

वीडीबी के संगठनात्मक और संचालन विनियम, प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय संख्या 1515/ क्यूडी-टीटीजी दिनांक 3 सितंबर 2015 के अनुसार हैं।

349. वीडिबी के वित्तीय तंत्र को निर्णय संख्या 44/2007/क्यूडी-टीटीजी दिनांक 30 मार्च के अनुसार निष्पादित किया जाता है। वियतनाम विकास बैंक को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है। वीडिबी का संचालन लाभ उन्मुख उद्देश्यों के लिए नहीं है।

350. क्रेडिट के संबंध में वियतनाम विकास बैंक के मुख्य कर्तव्य हैं:

- राज्य के निवेश और विकास ऋण और निर्यात ऋण को लागू करने के लिए घरेलू और विदेशी संगठनों से पूंजी जुटाना और प्राप्त करना।
- निवेश और विकास ऋण की नीति, राज्य के निर्यात ऋण की नीति को निष्पादित करना।
- वाणिज्यिक बैंकों से एसएमई के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना।

351. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम में वीडिबी और अन्य राज्य के स्वामित्व वाले बैंक एक सार्वजनिक निकाय हैं क्योंकि यह वियतनाम सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है और सरकारी प्राधिकारी का उपयोग करता है। वीडिबी या किसी अन्य राज्य के स्वामित्व वाले बैंक द्वारा दी गई ऋण निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान की प्रकृति में हैं। वीडिबी द्वारा लगाए गए व्याज और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर लगाए गए व्याज दर के बीच अंतर के रूप में प्राप्तकर्ता को लाभ दिया जाता है। प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाई जानी चाहिए।

(v) कार्यक्रम संख्या 6 - निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

352. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि व्यापार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के नियमों के तहत, व्यापार संवर्धन के लिए निधियों का प्रावधान और आवंटन का निरीक्षण, मूल्यांकन परिषद द्वारा किया जाता है। निर्णय 279 का 9 अभिशासन अनुच्छेद है, जो व्यापार संवर्धन योजनाओं के प्रकार निर्दिष्ट करता है जो समर्थन के योग्य हैं और निम्नलिखित अनुच्छेद (10) प्रत्येक योजना के लिए उपलब्ध सहायता के स्तर को विनिर्दिष्ट करता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सरकार इस कार्यक्रम के तहत घरेलू और विदेशी विशेषज्ञों को काम पर रखने से जुड़े खर्च का 50% कवर करेगी। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित डिक्री या सूचनाएं प्रदान की हैं:

- राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन कार्यक्रम 279 द्वारा स्थापित किया गया था और निर्णय 90 द्वारा अभिशासित था

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध

353. सरकार का एक वार्षिक व्यापार संवर्धन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विदेशी बाजारों, पर्वतीय और सीमावर्ती (गरीब) क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने के लिए संबंधित कंपनियों की सहायता करना है।

354. राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार गतिविधियों का समर्थन करना है, विशेष रूप से पर्वतीय और गरीब क्षेत्रों में निर्यात और व्यापार के लिए, निवेश और पर्यटन के साथ व्यापार को जोड़ने वाली गतिविधियाँ। वार्षिक रूप से निर्धारित मानदंडों के आधार पर और स्थानीय अधिकारियों और संगठनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, एमओआईटी, वर्ष के लिए व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों को मंजूरी देता है। स्वीकृत कार्यक्रमों के आधार पर एसोसिएशन या

स्थानीय प्राधिकरण, अपनी संबंधित कंपनियों के लिए संवर्धन गतिविधियों का संचालन करते हैं। अध्यक्ष निकाय प्रस्ताव तैयार करते हैं और व्यापार संवर्धन विभाग (राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड) को निर्धारित समय सीमा के भीतर (समान्यतः परियोजना कार्यान्वयन वर्ष से पहले वर्ष की 15 मई) प्रस्ताव भेजते हैं।

355. पात्रता मानदंड यह है कि कार्यक्रम स्वामियों के पास एक व्यापार संवर्धन योजना है जो उद्देश्यों, आवश्यकताओं और मानदंडों को पूरा करती है जैसा कि निर्णय संख्या 72/2010 /क्यूडी-टीटीजी में प्रावधान है।
356. कार्यक्रम अभी भी कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में इस कार्यक्रम को किसी नए कार्यक्रम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

357. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम डिक्री सं. 72/2010/क्यूडी-टीटीजी द्वारा प्रशासित है। यह विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या भौगोलिक स्थानों के लिए उद्यमों की व्यापारिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है।
358. कार्यक्रम में निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और इस प्रकार से लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित सहायता गतिविधियों या उद्यम करने वाले उद्यम तक सीमित है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाई जानी चाहिए।

(vi) कार्यक्रम संख्या 7- वियतनाम विकास बैंक से निर्यात ऋण

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

359. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वित्त मंत्रालय ने कुछ उद्यमों को ऋण के लिए पात्र बताया है। वियतनाम विकास बैंक वियतनामी वस्तुओं के निर्यात/आयात पर निवेश परियोजनाओं और अनुबंधों के लिए ऋण प्रदान करता है जिसका पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। बैंक द्वारा पूर्व-आवश्यकता निर्धारित की गई है कि वित्तीय योजनाओं और चुकौती योजनाओं को पहले से ही उनके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित डिक्री या सूचनाएं प्रदान की हैं जो उनके लिए यथोचित उपलब्ध थीं।

- डिक्री सं. 75/2011/ एनडी-सीपी, 30 अगस्त 2011
- डिक्री सं. 108/200 / क्यूडी-टीटीजी
- सोशललिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम से कुछ स्टील नेल्स पर यूएस फाइनल खोज

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध

360. कार्यक्रम 5 के उत्तर में ऋण कार्यक्रम के बारे में सूचना प्रदान की गई है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

361. प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि वीडिबी और राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(vii) कार्यक्रम सं. 8- निर्यात सहायता क्रेडिट

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

362. कार्यक्रम के तहत वित्त मंत्रालय ने ऐसे उद्यमों के लिए ऋण का प्रावधान किया है जो निर्णय द्वारा स्थापित मानदंडों को पूरा करते हैं। यह ऋण के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 7 और 8 वियतनाम सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्त और ऋण राशि निर्धारित करता है। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित डिक्री या सूचनाएं प्रदान की हैं जो उनके लिए यथोचित उपलब्ध थीं।

➤ निर्णय संख्या 133/2001-क्यूडी-टीटीजी

363. इस निर्णय में, सरकार का कहना है कि निर्यात ऋण निम्नलिखित पर लागू होगा-

1. निवेशक जिनके पास ऋण चुकाने की वित्तीय क्षमता है;
2. परियोजना ने निवेश और निर्माण चरण को पूरा किया होना चाहिए;
3. निवेशक का मूल्यांकन वित्तीय सहायता और ऋण चुकौती योजना विकास सहायता निधि द्वारा किया गया है।

364. क. 8- के तहत मंत्रालय द्वारा ऋण पूंजी के स्तर को तीन समूहों में विभाजित किया गया है। समूह क प्रधान मंत्री के निर्णय का पालन करेगा और बाकी निवेश पूंजी के 90% से अधिक के लिए लागू नहीं होंगे।

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

365. निर्यात सहायता क्रेडिट कार्यक्रम 2001 में शुरू हुआ और 16 जनवरी 2007 को समाप्त कर दिया गया। इसलिए, यह कार्यक्रम जांच की अवधि से बाहर है।

366. कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादन और व्यापार में उद्यमों, आर्थिक संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना था जो निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक है। डब्ल्यूटीओ तक पहुंचने के लिए वियतनाम की प्रतिबद्धताओं के तहत, इस कार्यक्रम को 16 जनवरी 2007 को समाप्त कर दिया गया था, जैसा कि डिक्री 151/2006/एनडी-सीपी के तहत प्रावधान था।

367. इस कार्यक्रम के तहत निर्यात समर्थन क्रेडिट में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कम से कम 30% कुल वार्षिक राजस्व के लिए निर्यात राजस्व लेखांकन के साथ उत्पादन, विनिर्माण या प्रसंस्करण निर्यात माल की निवेश परियोजनाओं के लिए मध्यम और दीर्घकालिक निवेश ऋण और कुल राजस्व का कम से कम 80% यदि परियोजना निर्णय 133/2001/क्यूडी-टीटीजी के अनुच्छेद 6 के तहत प्रदान की गई संयुक्त उद्यम के रूप में है।
- निवेश पश्चात् ब्याज दर सहायता इन निवेश परियोजनाओं के लिए है (i) कम से कम 30% कुल वार्षिक राजस्व के निर्यात राजस्व के साथ निर्यात वस्तुओं का उत्पादन, विनिर्माण या प्रसंस्करण और (ii) मध्यम और दीर्घकालिक निवेश ऋण प्राप्त नहीं करने वाले उद्यम जैसा कि निर्णय 133/2001/ क्यूडी-टीटीजी के अनुच्छेद 3 के तहत प्रावधान है। ब्याज दर सहायता राशि क्रेडिट संस्थानों की ब्याज दर और राज्य निवेश क्रेडिट के बीच अंतर के बराबर है, जो क्रेडिट प्राप्त करने के समय है।
- निर्णय 133/2001/ क्यूडी-टीटीजी के अनुच्छेद 6 के तहत कम से कम 30% कुल वार्षिक राजस्व के लिए निर्यात राजस्व के साथ निर्यात वस्तुओं का उत्पादन, विनिर्माण या प्रसंस्करण के उद्यमों के लिए निवेश क्रेडिट गारंटी।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

368. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम 16 जनवरी 2007 को समाप्त कर दिया गया था और अब संचालन में नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि कम ब्याज दरों पर वीडिबी और अन्य राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा उद्यम के लिए ऋण प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के लिए प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाई

जानी चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी मानता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(viii) कार्यक्रम सं. 9 - निवेशकों के लिए अधिमन्य ऋण

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

369. कार्यक्रम के तहत, वित्त मंत्रालय ने विकास बैंक की भूमिकाओं और कार्यों को दोहराया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बैंक वियतनाम को निर्यात वस्तुओं को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। निर्यात क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उद्यम से बैंक के लिए ऋण अनिवार्य किया गया है। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित डिक्री या सूचनाएं प्रदान की हैं जो उनके लिए यथोचित उपलब्ध थीं।

➤ डिक्री सं. 108/2006 /क्यूडी-टीटीजी

➤ डिक्री सं. 75/2011 / एनडी-सीपी

370. कार्यक्रम के तहत, बैंक, निवेश ऋण नीति को क्रियान्वित करने के लिए निवेशकों से पूंजी प्राप्त करेगा। परियोजना के लिए उपलब्ध कराए गए क्रेडिट/ऋण की राशि का अधिकतम 70% है और निवेशक के लिए वियतनाम विकास बैंक की वास्तविक चार्टर पूंजी के 15% पर है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि डिक्री के क. 6 निवेशकों पर निर्यात ऋण प्राप्त करने के लिए उधार देने की शर्तों को लागू करता है।

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

371. कार्यक्रम 5 के उत्तर में ऋण कार्यक्रम के बारे में सूचना प्रदान की गई है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

372. प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि वीडिबी और राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकर शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(ix) कार्यक्रम संख्या 10 - निवेश ऋण की ब्याज दर

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

373. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वित्त मंत्रालय ने वियतनाम राज्य द्वारा दिए गए निवेश ऋण की ब्याज दर को विनिर्दिष्ट किया है। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचना प्रदान की है जो उन्हें यथोचित उपलब्ध थी

➤ परिपत्र संख्या 76/2015/टीटी-बीटीसी

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध

374. कार्यक्रम 5 के उत्तर में ऋण कार्यक्रम के बारे में सूचना प्रदान की गई है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

375. प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि वीडीडबी और राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(x) कार्यक्रम संख्या 11- छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों की स्थापना में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर निवेश सहायता

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

376. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के तहत, लघु और मध्यम उद्योगों को सभी चरणों में सहायता प्रदान की गई थी। उद्यम वित्तीय, उत्पादन, नवाचार और तकनीकी क्षेत्र में सहायता के पात्र हैं। सब्सिडी योजना वियतनाम में छोटे व्यवसाय में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को व्यापक सहायता की अनुमति देती है। यह सब्सिडी उद्योग को अनुचित लाभ प्रदान करती है। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने साक्ष्य के रूप में डिक्री नंबर 56/2009 / एनडी-सीपी प्रदान किया है।

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध

377. जांच के तहत कोई भी कंपनी कपड़ा और परिधान उद्योग में व्यवसाय नहीं कर रही है।
378. देश में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के विकास को सुकर बनाने के लिए, एसएमई की सहायता के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए डिक्री 56/2009 / एनडी-सीपी जारी किया गया था, जो किसी भी व्यापार के रूप और प्रकार पर ध्यान दिए बिना पूरे देश में एसएमई पर लागू होता है। वित्त मंत्रालय क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना और संचालन के लिए एक तंत्र तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिसे छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी के संचालन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अनुमोदित किया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंक प्रधानमंत्री को छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को क्रेडिट का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन तंत्र को बढ़ावा देने के प्रस्ताव के लिए उत्तरदायी है।
379. आवेदन प्रक्रिया, एसएमई सहायता कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए स्थानीय बजट की इनकी उपलब्धता के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सिद्धांतों और दिशानिर्देशों पर आधारित है, ।

क्षेत्र	छोटे आकार के उद्यम	
	कुल चार्टर पूंजी	श्रमिकों की संख्या
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	वीएनडी 20 बिलियन या उससे कम	10 से 200 कर्मचारियों के बीच
उद्योग और निर्माण	वीएनडी 20 बिलियन या उससे कम	10 से 200 कर्मचारियों के बीच
व्यापार और सेवा	वीएनडी 10 बिलियन या उससे कम	a. से 50 कर्मचारियों के बीच

380. परिभाषित सीमा के अंतर्गत आने वाली कंपनियां स्थानीय सरकार द्वारा उपलब्ध सहायता कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकती हैं।

381. बहुत सीमित राज्य बजट के कारण, अधिकांश प्रांतों ने अपने भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर एसएमई का समर्थन करने के लिए कोई कार्यक्रम विकसित नहीं किया है। यह कार्यक्रम निर्यात निष्पादन या आयातित वस्तुओं के घरेलू पर आकस्मिक नहीं है। जांच के तहत कोई भी कंपनी दिसंबर 56/2009/ एनडी-सीपी के मानदंडों के तहत एसएमई नहीं है। डिक्री 56/2009/एनडी-सीपी को डिक्री 39/2018/एनडी-सीपी दिनांक 11 मार्च 2018 से प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

382. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में एसएमई को सहायता प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में एसएमई को प्रदान की गई सहायता में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन शामिल हैं:
- प्रशिक्षण कार्यक्रम
 - एसएमई के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम करने की जागरूकता
 - क्रेडिट गारंटी फंड
 - निवेश प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भुगतान के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए सहायता
383. मौद्रिक शब्दों में कार्यक्रम के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन से निधियों और लाभ के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान होता है और इस तरह से पुष्टि होती है। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह एसएमई तक सीमित है। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(xi) कार्यक्रम सं. 13 - विएतिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

384. योजना के तहत, वित्त मंत्रालय में, एक अनुबंध में गारंटी पार्टी को विएतिन बैंक द्वारा प्रतिबद्धता का प्रावधान है, यदि वह भुगतान और दायित्वों के अपने हिस्से को उपकृत करने में विफल रहता है। कार्यक्रम के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने विएतिन बैंक की वेबसाइट का यूआरएल प्रस्तुत किया है जिसमें कार्यक्रम के सभी आवश्यक विवरण हैं।

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध

385. जांच के तहत किसी भी कंपनी को जांच के तहत उत्पाद के लिए विएतिन बैंक से कोई वित्तीय गारंटी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए, प्रश्न लागू नहीं होते हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क वी डी बी और राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा दिए गए क्रेडिट के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xii) कार्यक्रम सं. 14 - डिक्री 142 के तहत प्रोत्साहित उद्योगों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमों के लिए भूमि अधिमानताएं।

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

386. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि वियतनाम सरकार औद्योगिक जोन भूमि में स्थित उद्यमों को अधिमान्य भूमि दर और संबंधित सहायता उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय सरकार की स्थानीय कार्यकारी / प्रशासनिक शाखा, कैन थो पीपुल्स कमेटी द्वारा उद्यमों को उप-पट्टे पर भूमि दिया गया है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित डिक्री दस्तावेज़ प्रदान किया है जो उनके पास उचित रूप से उपलब्ध था-

➤ डिक्री संख्या 142/2005 / एनडी-सीपी दिनांक 14 नवंबर, 2005

387. डिक्री के अनुसार, साक्ष्य में प्रस्तुत, भूमि किराए और पानी की सतह के किराए का संग्रह बाजार मूल्य के लगभग बराबर करने के लिए फिर से समायोजित किया जाना चाहिए।

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध

388. उद्यमों को विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों वाले भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, वियतनाम सरकार ऐसे क्षेत्रों में निवेश परियोजनाओं वाली कंपनियों के लिए भूमि किराए में छूट और कटौती की नीति अपनाती है। विशेष मामलों जैसे गरीब श्रमिकों के लिए आवासों का निर्माण, विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए छात्रावास, पर्वतीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए कृषि भूमि, आदि के साथ-साथ प्रोत्साहित उद्योगों में निवेश परियोजनाओं में निवेश परियोजनाओं पर भूमि किराए में छूट भी लागू होती है।

389. यह नीति डिक्री 142/2005/एनडी-सीपी दिनांक 14 नवंबर 2005 द्वारा विनियमित किया गया है। डिक्री 142/2005/एनडी-सीपी को प्रतिस्थापित करने के लिए डिक्री 46/2014/एनडी-सीपी जारी किया गया था।

390. वे कंपनियां जो प्रोत्साहित उद्योगों में निवेश करती हैं या सूची में विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती हैं या डिक्री 142/2005 और इसके बाद की डिक्री 46/2014 के तहत विनिर्दिष्ट विशेष मामलों में निवेश करती हैं, वे भूमि किराए में छूट या कटौती के हकदार हैं। उनके निवेश प्रमाणपत्र या व्यवसाय पंजीकरण के आधार पर, संबंधित स्थानीय कर प्राधिकारी भूमि के किरायेदारों द्वारा देय राशियों का निर्धारण करेगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

391. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम डिक्री 142/2005/एनडी-सीपी दिनांक 14 नवंबर 2005 द्वारा शासित है। ऐसी कंपनियों को भूमि किराए पर छूट या कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है, जो प्रोत्साहित उद्योगों के लिए चिन्हित क्षेत्रों और निवेश परियोजनाओं में निवेश करते हैं, जैसा कि डिक्री 142/2005 और इसके बाद की डिक्री 46/2014 के तहत विनिर्दिष्ट है।

392. यह कार्यक्रम पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तु या सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह क्षेत्र विशिष्ट है और कुछ प्रोत्साहित क्षेत्रों तक ही सीमित है। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क(काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाया जाना चाहिए।

(xiii) कार्यक्रम संख्या 15- पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि का सरकारी प्रावधान और भूमि और पानी के किराए पर छूट या कटौती

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

393. याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान सब्सिडी स्कीम के तहत, डोंग नाई और सिविक अथॉरिटीज की राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए घर बनाने हेतु शुरू की गई परियोजना के लिए भूमि और पानी की सतह के किराए में छूट प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम सहकारी द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भूमि किराए में व्यापक कटौती का प्रावधान करता है। इस संबंध में उदाहरण निम्नलिखित हैं-

1. व्यवसाय और उत्पादन परिसरों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, भूमि पट्टे पर 50% की कटौती के पात्र हैं।
2. कृषि उत्पादन, वानिकी, मत्स्य पालन और नमक तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए भूमि और पानी की सतह का किराया कुछ शर्तों के अधीन कटौती के पात्र हैं।

394. कार्यक्रम की अर्हता प्राप्त करने के लिए उद्यम को डिक्री में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने अपने पास यथा उपलब्ध निम्नलिखित डिक्री दस्तावेज उपलब्ध कराया है -

➤ डिक्री संख्या 46/2014 / एनडी-सीपी दिनांक 15/5/2014

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध

395. कार्यक्रम 14 के उत्तर में कार्यक्रम के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

396. प्राधिकारी पहले ही यह निर्धारित कर चुके हैं कि पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि प्रावधान के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाई जानी चाहिए। प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।

वियतनाम के निर्यात / निर्यातक

397. वियतनाम से दो निर्यातकों नामतः डोंग वियत नॉन-फेरस मेटल और प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी और सीएफटी वीना कॉपर कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली उत्तर दायर की और जांच में भाग लिया था।

डोंग वियत नॉन-फेरस मेटल और प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी(डोविना)

398. डोविना वियतनाम में संबद्ध वस्तु का उत्पादक/निर्यातक है। डोविना ने प्रश्नावली उत्तर दायर की और उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।

399. प्राधिकारी ने डोविना द्वारा दायर किए गए उत्तर की जांच की और जाँच के आधार पर उनसे और अतिरिक्त सूचना देने तथा उत्तर में प्रदान की गई सूचना के सत्यापन के लिए भी अनुरोध किया। हालांकि, डोविना ने अधिक सूचना उपलब्ध कराने संबंधी प्राधिकारी के अनुरोध पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी। डोविना ने केवल साझा ड्राइव के माध्यम से दस्तावेज साझा किया और प्रश्नावली में पहले से ही उपलब्ध कराई गई जानकारी के ऑन-टेबल सत्यापन के दौरान या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मौजूद नहीं था। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि डोविना को सह-प्रचालन उत्पादक/निर्यातक के रूप में नहीं माना जा सकता है और डोविना के लिए कोई व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन दर निर्धारित नहीं की गई है। वियतनाम से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन डोविना पर लागू किया जा रहा है।

सीएफटी वीना कॉपर कंपनी लिमिटेड (सीएफटी)

400. सीएफटी वियतनाम में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। सीएफटी ने प्रश्नावली उत्तर दायर की और उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में सूचना प्रदान की।

401. सीएफटी ने सीधे भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। भारत को इसके निर्यात के संबंध में, सीएफटी ने संबद्ध वस्तुओं को सिंगापुर में अपनी संबंधित इकाई टोयोटा त्सुशो एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड को बेचा और टोयोटा त्सुशो एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। टोयोटा त्सुशो एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ने प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं की है और जांच प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। भारत में सभी निर्यातों की आपूर्ति/निर्यात श्रृंखला निर्यातक, टोयोटा त्सुशो एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड के उत्तर के बगैर अधूरी है, प्राधिकारी भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए सीएफटी के निर्यात मूल्य का निर्धारण करने में असमर्थ है।

402. इसके अतिरिक्त, पीटी. तेम्बागामुलियासेमनटीबीके, जो कि इंडोनेशिया से संबद्ध उत्पाद का उत्पादक/निर्यातक हैं, जिन्होंने जांच में भाग लिया है और प्रश्नावली उत्तर उपलब्ध कराया ने कहा कि सीएफटी इसके संबद्ध पक्षों में से एक है। हालांकि, सीएफटी ने अपने प्रश्नावली उत्तर के विशिष्ट प्रश्न के जवाब में संबंधित पक्षकार में से एक होने के संबंध में पीटी. तेम्बागामुलियासेमनटीबीके के नाम का खुलासा नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीएफटी ने प्राधिकारी से प्रासंगिक सूचना का खुलासा नहीं किया है।

403. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सीएफटी को उत्पादक/निर्यातक के रूप में नहीं माना जा सकता है और सीएफटी के लिए कोई व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन दर निर्धारित नहीं की जा सकती है। वियतनाम के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन सीएफटी पर भी लागू किया जा रहा है।

वियतनाम के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों का सार

404. वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिकारी शुल्क उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है

कार्यक्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
कार्यक्रम संख्या 1 और 3	आयकर प्राथमिकताएँ	***	0-1%
कार्यक्रम संख्या 2	कच्चे माल पर आयात शुल्क में छूट	***	0-5%
कार्यक्रम संख्या 5/7/8/9/10/13	अधिमान्य उधार	***	0-5%
कार्यक्रम संख्या 14 & 15	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि प्रावधान	***	0-1%
कार्यक्रम संख्या 6/11	अनुदान	***	0-5%
कुल		***	5-15%

इंडोनेशिया

(i) कार्यक्रम संख्या 2 – इंडोनेशिया एक्जिम से निर्यात निधियन

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

405. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडोनेशिया (इंडोनेशियाई निर्यात-आयात बैंक) निर्यात बढ़ाने के लिए अधिमान्य दरों पर निर्यात वित्तपोषण उपलब्ध कराता है। यह संस्थान ऐसे वित्तीय संस्थानों या बैंकों को निधि मुहैया कराता है जिसे ट्रेड बाजार में प्रवेश करने के लिए वित्तीय क्षमता की कमी होती है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज या सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं-

406. विश्व व्यापार संगठन दस्तावेज संख्या डब्ल्यूटी/ टीपीआर/एस278

- 2015 वार्षिक रिपोर्ट, इंडोनेशिया एक्जिम बैंक
- अमेरिका का अंतिम निष्कर्ष- इंडोनेशिया से कुछ अनकोटेड पेपर

ख. सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध :

407. सरकार ने कहा कि लेम्बागापेमवियानएकस्पोर इंडोनेशिया ("इंडोनेशिया एक्जिम बैंक") को रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के वित्त डिप्टी मंत्री, संख्या 366/केएमके 06/2009, दिनांक 24 अगस्त, 2009 के तहत 01/09/2009 को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। यह एक संविधि (एलपीईआई अधिनियम) के तहत स्वतंत्र रूप से प्रचालित होता है और सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है। विभिन्न अनुच्छेदों के तहत उल्लिखित संविधि कार्यों, निधि के स्रोतों, प्रदत्त-सेवा आदि नियंत्रित करती है।

408. स्थानीय और विदेशी उद्योगों को सहायता देने हेतु बैंक दो प्रकार का वित्तपोषण उपलब्ध करता है।

1. कार्यशील पूंजी (केमकेई) ;

2. और/या निवेश (केआईई)

409. एक्जिम बैंक द्वारा प्रक्रियाओं का पालन किया गया और अनुरक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यक्रम के तहत पात्रता मानदंड कुछ सेक्टर/क्षेत्र या उद्यम तक सीमित नहीं हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

410. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम को रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के वित्त मंत्री की डिक्री संख्या 366/केएमके 06/2009 के तहत संचालित किया जाता है।
411. इंडोनेशिया का एक्जिम बैंक इंडोनेशिया सरकार के स्वामित्व में है। यह इंडोनेशिया सरकार के सीधे नियंत्रण में है और सरकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना और निर्यातकों को उनकी व्यावसायिक क्षमता के विस्तार में सहायता करना है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्यातकों के लिए धन जुटाने में किसी भी तरह की कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करता है। एक्जिम बैंक की घरेलू वित्तपोषण सेवाओं में निर्यात कार्यशील पूंजी और निर्यात निवेश सुविधाएं शामिल हैं।
412. इंडोनेशिया एक्जिम बैंक को दिया गया एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा नियत विशेष असाइनमेंट प्रोग्राम है जिसे नेशनल इंटरस्ट अकाउंट (एनआईए) के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया एक्जिम बैंक के लिए विशेष असाइनमेंट से संबंधित इंडोनेशिया वित्त मंत्रालय विनियमन संख्या 134/पीएमके.08/2015 कार्यक्रम के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है, जिसका परिचालन 2015 में शुरू हुआ था। एनआईए ऐसे असाइनमेंट हैं जिन्हें इंडोनेशिया सरकार द्वारा इंडोनेशिया एक्जिम बैंक को सौंपे गए हैं जो ऐसे लेनदेन और/या परियोजनाओं के लिए निर्यात निधियन उपलब्ध कराता है, जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए व्यवहार्य नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार आशाजनक मानती है। एनआईए कार्यक्रम के माध्यम से वित्तपोषण अर्थव्यवस्था, पण्य, निर्यात गंतव्य देश, निर्यात एजेंट मानदंड और निर्यात वित्तपोषण के क्षेत्रों तक सीमित है। एनआईए वित्त पोषण के लिए योग्य माने जाने के लिए, सवाल के घेरे के लेनदेन और परियोजना को इंडोनेशियाई उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और मूल्य बढ़ाने, घरेलू उद्योग के विकास का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए और उसके पास सुधार तथा दीर्घकालिक निर्यात विकास की क्षमता होनी चाहिए।
413. एक्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है क्योंकि यह इंडोनेशिया सरकार द्वारा सृजित, स्वामित्व, नियंत्रित और वित्त पोषित है। एक्जिम बैंक निर्यात संवर्धन का सरकारी कार्य करता है और सरकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। वित्तीय योगदान के लिए मुहैया कराई गई ऋण राशि एक्जिम बैंक द्वारा प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में प्रदान की जाती है और इस प्रकार लाभ दिया जाता है। लाभ की राशि, इस सब्सिडी कार्यक्रम के अनुसार दिए गए ऋण पर किए जाने वाले भुगतान की राशि और किसी अन्य तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर किए जाने वाले भुगतान के बीच के अंतर के समान होती है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर है। प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(ii) कार्यक्रम संख्या 3- निर्यातकों को उनके नुकसान की प्रतिपूर्ति की जा रही है

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

414. वर्तमान कार्यक्रम के तहत, राज्य स्वामित्व वाला एक उद्यम, असुरानी एक्सपोर्ट इंडोनेशिया (पररसेरो) निर्यातकों को उनके नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करता है। उद्यम निर्यातकों द्वारा किए गए व्यय के 85% नुकसान की प्रतिपूर्ति उनकी बीमा पॉलिसी के माध्यम से करता है। राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम निर्यातकों और बैंकों को बाजार के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज या सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं:

- विश्व व्यापार संगठन दस्तावेज संख्या- डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस278

- वित्तीय और सेवा अवलोकन, इंडोनेशिया एक्जिम बैंक
- अंतिम निष्कर्ष- इंडोनेशिया से कुछ अनकवर्ड पेपर

ख. सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध :

415. इंडोनेशिया के निर्यातकों को गैर-भुगतान जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात ऋण बीमा और निर्यात ऋण गारंटी कार्यक्रमों के लिए सरकार ने विनियमन संख्या 1/1982 के तहत प्रावधान किया। विनियमन संख्या 20/1983 के तहत यह कार्य राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) द्वारा किया जाना था।
416. सरकार ने ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम का निष्पादन पीटी.एसुरांसीक्रेडिट इंडोनेशिया(परसेरो) से पीटी.एसुरांसीएक्सप्रो इंडोनेशिया (परसेरो), अतिरिक्त कार्यों सहित दोनों एसओई, को हस्तांतरित कर दिया था, जिसे बाद में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को एक बीमा प्रीमियम बहिर्वाह के कारण "नेशनल रीइन्श्योरंस कंपनी" के रूप में सौंपा गया था। एसुरांसीअसेई, जो कि पीटी.एसुरांसीएक्सप्रो इंडोनेशिया की सहायक कंपनी है, को दिसंबर 2014 में बीमा व्यवसाय सौंपा गया था। हालांकि यह उद्यम सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण(99.98%) में है, बोर्ड के सदस्यों को आंतरिक रूप से नियुक्त किया जाता है। सरकार ने कहा है कि एसईआई ने वर्ष 1995 से निर्यात गारंटी की पेशकश नहीं की है।
417. कार्यक्रम के तहत पात्रता मानदंड इंडोनेशिया में रहने वाले निर्यातकों, विदेशी निवेशकों और घरेलू निवेशकों तक सीमित है। प्रशासन प्राधिकारी यह तय करने में कुछ हद तक अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय कर सकता है कि किसी विशेष फर्म को कार्यक्रम के तहत लाभ मिल सकता है या नहीं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

418. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम विनियमन संख्या 1/1982 द्वारा प्रशासित है। राज्य-स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान निर्यात के लिए भुगतान न करने पर होने वाले नुकसान की गारंटी, ऋण बीमा और प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराता है।
419. राज्य-स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान सार्वजनिक निकाय हैं क्योंकि इसका सृजन, स्वामित्व, नियंत्रण और वित्तपोषण इंडोनेशिया सरकार द्वारा किया जाता है। वे निर्यात संवर्धन का सरकारी कार्य करते हैं और सरकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम निधि के संभावित प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान हेतु प्रावधान करता है और इस तरह लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर है। प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(iii) कार्यक्रम संख्या 5- मंदिरी बैंक द्वारा दिए गए विभिन्न ऋण

कार्यक्रम संख्या 5 (क)- निवेश ऋण

कार्यक्रम संख्या 5 (ख)- उद्यम के लिए ऋण

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

420. निवेश ऋण कार्यक्रम के तहत, मंदिरी बैंक पूंजीगत वस्तुओं के वित्तपोषण में सहायता के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है ताकि बाजार के विस्तार और नई परियोजनाओं के निर्माण में मदद मिल सके। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह कार्यक्रम 100 मिलियन रूपए से अधिक और 5 बिलियन रूपए तक की वित्तपोषण आवश्यकताओं के वाली व्यक्तिगत या कानूनी/गैर-कानूनी इकाई के लिए पात्र है। यह राशि विदेशी मुद्राओं में भी दी जा सकती है और ऋण निपटान के लिए अधिकतम अवधि 15 वर्ष है।
421. उद्यम कार्यक्रम के लिए ऋण के तहत, बैंक 100 मिलियन से 2 बिलियन तक की सीमा सहित उद्यमियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। यहाँ के मंदिरी बैंक द्वारा निर्धारित पूर्व-आवश्यकता केवल यह है कि उसे 2 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव होना चाहिए।

ख. सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध :

422. बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन संबंधी सरकार की योजना के तहत मंदिरी बैंक, एक एसओई, को वर्ष 1998 में स्थापित किया गया था। अधिकांश हिस्सेदारी जीओआई के पास है, लेकिन राष्ट्रीय और विदेशी निवेशक भी हिस्सेदार हैं। सरकार ने प्रस्तुत किया कि एक बैंक के रूप में, इसकी एक विशेषता, निवेश ऋण मध्यम और दीर्घकालीन ऋण सुविधा होते हैं जिसे पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए रूपया या विदेशी मुद्रा में प्रदान किया जाता है। उक्त ऋण का आधार दूसरों का वित्तीय विवरण, परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन, आवेदक की वैधता है और इसकी संपाश्विक राशि व्यावसायिक नकदी प्रवाह के आधार पर समायोजित की जाती है। इसे सीधे चालू खाते में जमा किया जाता है।
423. सरकार ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संस्थाओं के लिए पात्रता निर्धारित की है। आवेदक के प्रदर्शन और संभावनाओं के आधार पर मंदिरी बैंक ऋण प्रदान करने का अधिकार रखता है। सरकार ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उपर उल्लिखित कार्यक्रम और नियमित बैंक के रूप में कार्य के लिए कोई स्पष्ट कानून न तो पारित किया गया है या न ही उपलब्ध है।
424. इस योजना के तहत मंदिरी बैंक, जिसे मंदिरी यंग एंटरप्रेन्योर(डब्ल्यूएमएम) के नाम से जाना जाता है, में उद्यमी के लिए ऋण मंदिरी बैंक का मुख्य सीएसआर कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2007 से लागू किया गया है और इसका लक्ष्य इंडोनेशिया में उद्यमिता के विकास में, खासकर युवा पीढ़ी के बीच, सरकार की सहायता करना है।
425. सरकार द्वारा यथा प्रस्तुत पात्रता मानदंड, नए व्यक्तिगत उद्यमियों तक सीमित है। सरकार ने उक्त कार्यक्रम के तहत उद्देश्य, सुविधाएँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं, लेकिन इसके लिए कोई कानून पारित नहीं किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

426. प्राधिकारी ने पहले से ही निर्धारित किया है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा अधिमान्य उधार के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाई जानी चाहिए। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) कार्यक्रम संख्या 7- आयात शुल्क पर छूट**क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध**

427. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि कार्यक्रम की योजना के तहत, निर्यात उद्देश्यों के लिए विनिर्माता को कच्चे माल के आयात पर किसी भी प्रकार के आयात शुल्क (आमतौर पर 0-150% से) का भुगतान करने से छूट दी गई है।
428. कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज या सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं:
- ट्रेड पॉलिसी रिव्यू 2013: डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस278
 - वेब रिसर्च- पीडब्ल्यू(पीडीएफ) इंडोनेशियन कस्टम टैक्स टैक्स बुक 2017

ख. सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध:

429. वित्त मंत्री निर्णय संख्या 580/केएमके 04/2003 के अनुसरण में निर्यात उद्देश्यों के लिए आयात सुविधा (केआईटीई) योजना दिसंबर 2003 में स्थापित की गई थी। इस निर्णय में कई बार संशोधन किया गया था और अंतिम रूप से वित्त मंत्री विनियमन संख्या 254/पीएमके 04/2011 और वित्त मंत्री विनियमन संख्या 176 पीएमके 04/2013 के माध्यम से संशोधन किया गया था।
430. विनियमों, और आयात-शुल्क से छूट के अनुसार निर्यात उद्देश्यों के लिए संसाधित, असेंबल या विनिर्माण वस्तु में स्थापित होने पर वस्तु के आयात पर वैट और एलजीएसटी दिया गया था। एक वर्ष की अवधि में आयातित वस्तुओं का निर्यात

किया जाना आवश्यक है। सरकार ने इस तरह की छूट के लिए क्षेत्रीय सीमा-शुल्क अधिकारी की सख्त निगरानी की व्यवस्था की है। आयात की गई वस्तु की मात्रा और उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली मात्रा में किसी भी कमी के लिए दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने प्रस्तुत किया है कि क्षेत्रीय सीमा शुल्क अधिकारी का आचरण नियम सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क महानिदेशक की विनियम संख्या 16/बीसी/2012 के द्वारा निर्धारित किया गया, जिसे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क महानिदेशक की विनियमन संख्या 04/बीसी/2014 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया गया था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

431. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केआईटीई कार्यक्रम की प्रशासनिक देखरेख वित्त मंत्री विनियमन संख्या 254/पीएमके 04/2011 और वित्त मंत्री विनियमन संख्या 176/पीएमके 04/2013 द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत, निर्यातित वस्तु के विनिर्माण में नियोजित कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं को सभी आयात शुल्कों से छुट दिया गया है।
432. यह कार्यक्रम एससीएम समझौते के फुटनोट 1 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9बी(बी) के तहत एक अनुमत्य शुल्क छूट कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं दोनों को छूट प्रदान करता है। सत्यापन तंत्र का भी कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जो यह सुनिश्चित करता है कि उद्यम को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ऐसे उद्यम से वास्तव में जुर्माना या शुल्क की वसूली की गई थी जो निर्यातित वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल का उपयोग करने में असमर्थ थे।
433. यह कार्यक्रम व्यय हो चुके राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान के लिए प्रावधान करता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर है। प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रतिकारी शुल्क लगाई जानी चाहिए। पीटी तेम्बागामुलियासेमनन ने सब्सिडी कार्यक्रम का उपयोग किया है, लेकिन इस कार्यक्रम के तहत किए गए आयातों का पूरा विवरण नहीं दिया है। प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास किया है और पीटी कारया सुमिडेन इंडोनेशिया की सब्सिडी मार्जिन के आधार पर पीटी तेम्बागामुलियासेमनन के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है।

(v) कार्यक्रम संख्या 8- आयात शुल्क वापसी

क. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत-

434. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि इंडोनेशिया सरकार ऐसे कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क में छूट प्रदान करती है जिसे तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है और तत्पश्चात निर्यात किया जाता है। यह कार्यक्रम 2012 में प्राधिकारियों द्वारा जारी एक विनियमन पर आधारित है। यह छूट कच्चे माल पर लागू होती है, जो पहले आयात शुल्क में कटौती नहीं करने के अधीन थी। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज या सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं:
 - इंडोनेशिया गणराज्य के वित्त मंत्री की विनियम संख्या 254/पीएमएल.04/2011 जो अप्रैल 2012 से लागू हैं।
 - वेब रिसर्च- पीडब्ल्यूसी (पीडीएफ)/ कस्टम न्यूज फ्लैश 2012-01
 - ट्रेड पॉलिसी रिव्यू 2013-डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस278

ख. सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध:

435. इंडोनेशिया सरकार ने प्रस्तुत किया कि ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम को निर्यात उद्देश्यों के लिए आयात सुविधा (केआईटीई) स्कीम के तहत निर्धारित किया गया है, जिसे वित्त मंत्री निर्णय संख्या 580/केएमके 04/2003 और अंतिम रूप से वित्त मंत्री विनियमन संख्या 253/पीएमके 04/2011 और वित्त मंत्री विनियमन संख्या 177 पीएमके 04/2013 के माध्यम से संशोधन के अनुसरण में दिसंबर 2003 में स्थापित किया गया था।
436. वित्त मंत्रालय के विनियमन के अनुसार, ड्रॉबैक स्कीम वस्तुओं के आयात के लिए देय आयात शुल्क का प्रावधान करती है जिसे निर्यात उद्देश्यों के लिए संसाधित, इकट्ठा या विनिर्माण वस्तुओं में संस्थापित किया जाता है, को आंशिक या पूर्ण रूप से लौटाया जा सकता है, जो कि विनिर्मित वस्तु के निर्यात के समय प्राप्य है। वर्तमान स्कीम, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क महानिदेशालय- वित्त मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय सीमा शुल्क अधिकारी की देखरेख में भी है।
437. पात्रता मानदंड कंपनी की पहचान संख्या (एनआईपीआईआर) है जैसा कि वित्त मंत्री विनियमन संख्या 177/पीएमके.04/2013 में वर्णन किया गया है। जूटी ड्रॉबैक की राशि निर्यात के लिए तैयार वस्तु में शामिल वस्तुओं के लिए भुगतान की गई शुल्क की राशि पर निर्भर है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

438. प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट प्रदान करने वाले केआईटीई सब्सिडी कार्यक्रम पर प्रतिकार शुल्क लगाई जानी चाहिए। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत कोई अतिरिक्त प्रतिकार शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(vi) कार्यक्रम संख्या 9- लाभांश पर आयकर

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध

439. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून के अनुच्छेद 26 के तहत निर्धारित किया है कि लाभांश पर आयकर 10% है, जब तक कि संबंधित कर संधि इससे कम दर निर्धारित नहीं करती है। सरकार ने लाभांश पर अनुमत आयकर की उच्च श्रेणी का सीमांकन किया है। यह कार्यक्रम कंपनियों पर कुछ सेक्टरों और स्थानों के लिए लागू होता है और यह सरकार द्वारा वित्तीय योगदान होता है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज या सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं:
- डब्ल्यूटीओ दस्तावेज संख्या डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/278
 - इंडोनेशिया टैक्स गाइड 2016- डेलॉइट

ख. सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध:

440. कार्यक्रम के तहत सुविधा "कर भत्ता सुविधा" का हिस्सा है जैसा कि कुछ सेक्टरों और/या कुछ क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए आयकर सुविधा संबंधी सरकार की विनियमन संख्या 18/2015 में निर्धारित है, सरकार की विनियमन संख्या 9/2016 द्वारा यथा संशोधित। सरकार ने कुछ सेक्टरों और/या कुछ क्षेत्रों में नए पूंजी निवेश अथवा निवेश विस्तार में करदाता को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए आर्थिक प्रगति का लक्ष्य निर्धारित किया है।
441. सरकार ने कहा कि सिद्धांत रूप में, अधिनियम का अनुच्छेद 31ए लाभांश पर विदेशी करदाता के लिए भुगतान किए गए लाभांश पर लागू 20% की पूर्व दर के विपरीत आयकर में 10% की कटौती के रूप में लाभांश पर कर सुविधा की अनुमति देता है, जैसा कि अनुच्छेद 26 में संदर्भित है। यह कार्यक्रम इंडोनेशिया (बीकेपीएम) और वित्त मंत्रालय के निवेश समन्वय बोर्ड के प्रशासनिक देखरेख में है।

442. सरकार उद्योगों और क्षेत्र की एक सूची उपलब्ध कराती है, जिसमें कार्यक्रम के तहत विदेशी करदाता पात्र होंगे। इसके अलावा, कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। यदि पूरी की जाती है, तो विदेशी करदाता को लाभान्श या कम पर 10% आयकर मिलेगा। यदि निवेशक के मूल देश और इंडोनेशिया के बीच पी3बी (P3B) समझौता होता है। इसके अलावा, यह सुविधा उत्पाद आधारित है, लाभान्श की राशि संबद्ध उत्पादों की कुल आय से प्राप्त लाभान्श है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

443. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम इंडोनेशिया और अन्य देशों के बीच कर संधि के अनुसार विदेशी निवेशक के लिए अलग-अलग कर दरों के लिए प्रदान किया जाता है।
444. प्राधिकारी को संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा इस सब्सिडी का लाभ उठाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य/सामग्री नहीं मिल नहीं पाया है। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(vii) कार्यक्रम संख्या 10- निवल कर योग्य आय में कटौती

क. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत

445. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि इंडोनेशिया सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों में उद्योगों के लिए लागू कानून जारी किए हैं। उन्होंने छह साल के लिए 5% की दर से अचल संपत्तियों (भूमि सहित) में निवेश से निवल कर योग्य आय पर 30% की कटौती का लाभ जारी किया है। कार्यक्रम के तहत एकमात्र शर्त यह है कि उक्त अवधि में परिसंपत्तियों का दुरुपयोग या स्थानांतरण नहीं किया जाता है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज या सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं:
- कानून संबंधी एसईजेड 39/2009
 - वेब रिसर्च- पीडब्ल्यूसी (पीडीएफ) टैक्स फ्लैश फरवरी 2016

ख. सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध:

446. इंडोनेशिया सरकार ने विशेष आर्थिक जोन संबंधी अधिनियम संख्या 39-2009 के माध्यम से स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (केईके) के तहत सुविधा के लिए प्रावधान किया था। वर्तमान में पूरे इंडोनेशिया में केईके राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्थापित 12 नामित केईके हैं।
447. विनियमन के तहत, केईके में निवल कर योग्य आय, सरकारी विनियमन संख्या 96/2015 में यथा निर्धारित, को अचल संपत्तियों (भूमि सहित) के रूप में निवेश की गई राशि के 30% से घटाया गया है, जो कि वाणिज्यिक उत्पादन के छह वर्षों के लिए 5% पर पूर्व निर्धारित है। सरकारी विनियमन संख्या 18/2015 के तहत विनियमित आयकर भत्ता सुविधाओं के तहत इसी तरह की कटौती का प्रावधान किया गया है।
448. यद्यपि, जैसा कि सरकारी विनियमन संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 11 में निर्धारित है, केईके में करदाता केवल उक्त विनियमन में निवल कर योग्य आय में कटौती की सुविधा के लिए ही आवेदन कर सकता है, किसी अन्य में नहीं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जाँच

449. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम विशेष आर्थिक जोनों में स्थित उद्योगों के लिए उपलब्ध है और 30% तक कर योग्य आय में कटौती का प्रवधान करता है। इस कार्यक्रम की प्रशासनिक देखरेख सरकारी विनियमन संख्या 18/2015

द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक जोन में स्थित उद्योग द्वारा ही आयकर छूट का लाभ लिया जा सकता है, न कि किसी अन्य कार्यक्रम के तहत।

450. सब्सिडी कार्यक्रम व्यय किए गए राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान करता है, जो अन्यथा देय है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह क्षेत्र विशिष्ट है। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम पर प्रतिकारी शुल्क लगाई जानी चाहिए।

(viii) कार्यक्रम संख्या 11- घाटे को आगे ले जाना

क. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध:

- 451 कार्यक्रम के तहत, मंत्रालय ने निवेशकों को 5 वर्ष तक की अपनी क्षति को आगे ले जाने के एक विकल्प के प्रावधान की अनुमति दी है। इस अवधि को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल राष्ट्रीय निवेशकों पर लागू है, बल्कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के शर्ताधीन अंतरराष्ट्रीय निवेशकों पर भी लागू है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज या सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं जो उनके पास यथोचित उपलब्ध थीं।

- डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस278
- वेब रिसर्च- पीडब्ल्यूसी (पीडीएफ) टैक्स फ्लैश फरवरी 2016
- वेब रिसर्च- पीडब्ल्यूसी (पीडीएफ) टैक्स फ्लैश फरवरी 2015

ख. सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध:

- 452 इंडोनेशिया सरकार ने अधिनियम संख्या 39/2009 के तहत विशेष आर्थिक जोनों (केईके) की स्थापना की थी। इन जोनों को अपनाने के लिए व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन के रूप में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विनियमन संख्या 96/2015 ऐसा ही एक विनियमन है।
- 453 सरकारी विनियमन संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 10 में यथा निर्धारित केईके में आगे बढ़ाई गई क्षति के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के साथ 5 वर्ष से अधिक के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है लेकिन 10 वर्ष से अधिक के लिए क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है –
454. वित्त मंत्रालय के सीधे पर्यवेक्षण में छूट का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा दो विषयों व्यापारिक प्रतिष्ठानों और व्यापारिक भागीदारों तक ही उपलब्ध रहेगी।

- व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए – कंपनी को पदनामित किया जाना चाहिए क्योंकि उपक्रम के ई के का संचालन करता है, इसके पास के ई के विकास करार है और यह के ई के व्यापार क्रियाकलाप की सीमाओं के भीतर स्थापित करता है;
- व्यापारिक भागीदार के लिए – कंपनी अथवा अलग व्यक्ति को कोरपोरेट करदाता के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए और पूंजी निवेश के लिए प्रधान लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

455. इस कार्यक्रम व्यापार उपक्रम को हानि को अगले वर्ष ले जाने का प्रावधान है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आयकर से छूट देने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए किसी अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) कार्यक्रम सं. 12 – आयात शुल्क का स्थगन**क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध**

456. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि सरकार प्रसंस्करण के लिए पूंजीगत माल और उपकरण, सामान और सामग्री पर आयात शुल्क को स्थगित करने का प्रावधान करती है। इसके साथ ही, इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से पूंजीगत माल के आयात को किसी आयात शुल्क से छूट दी गई है। इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य इस प्रकार के क्षेत्रों के विकास और अनुरक्षण का प्रस्ताव करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर सरकार द्वारा विनियमित विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास और वृद्धि है। इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज अथवा अधिसूचनाएं उपलब्ध कराई हैं।

- कर फ्लेस सं. 4, फवरी, 2016 (पी डब्ल्यू सी रिपोर्ट)
- सरकारी विनियमन सं. 2016 का 96 (जी आर 96/2016) : विशेष आर्थिक क्षेत्र में सुविधाएं

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

457. विशेष आर्थिक क्षेत्र (के ई के) विनियमन सं. 39/2009 के अंतर्गत विभिन्न छूट और प्रोत्साहन के अध्यक्षीन हैं जिससे कि प्रचालन हेतु व्यापार और व्यापारिक भागीदारों को आकर्षित किया जा सके।
458. वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत, इण्डोनेशिया की सरकार ने के ई के में आयात शुल्क के भुगतान को स्थगित करने का अनुमोदन किया (विनियमन सं. 96/2015 में निर्धारित)। वही स्थगन 2 विषयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और व्यापारिक भागीदारों जो इस कार्यक्रम की सुविधा को प्राप्त करने के लिए सरकारी विनियमन सं. 96/2015 के अनुच्छेद 5 में दी गई आवश्यकताओं को पूरा करता है, द्वारा लागू किये जाने के लिए पात्र है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

459. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित उपक्रम के लिए आयात शुल्क को स्थगित करने हेतु प्रावधान करता है। इस प्रकार से इस कार्यक्रम में कुछ उपक्रमों के करों के आस्थगन का प्रावधान है। उपक्रम को दिया गया लाभ ब्याज रहित अल्पकालीन अथवा दीर्घकालिक ऋण के रूप में है। लाभ की राशि वाणिज्य ऋण पर बैंक द्वारा वसूले जा रहे ब्याज की राशि और इस अंतर के समतुल्य है।
460. इस कार्यक्रम छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित कुछ उपक्रमों को लाभ प्रदान करता है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारित किया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए जो आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का निर्धारण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(x) कार्यक्रम सं. 13 – उत्पादन के उद्देश्य से कच्चे माल और सहयोगी वस्तुओं पर शुल्क से छूट प्रदान करना**क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध**

461. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत नये निवेशक अथवा मौजूदा निवेशक जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर विस्तार कर रहे हैं और आयात किये गये कच्चे माल और सहयोगी वस्तु शुल्क से छूट दिये जाने के लिए पात्र है। यह कार्यक्रम दोनों करदाताओं अर्थात् जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में व्यापार आयोजित कर रहे हैं अथवा निष्पादित कर रहे हैं पर लागू है। इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज अथवा अधिसूचनाएं उपलब्ध कराई हैं।

- डब्ल्यू टी/ टी पी आर/ एस278
- सरकारी विनियमन सं. 2016 का 96 (जी आर 96/2016) : विशेष आर्थिक क्षेत्र में सुविधाएं

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

462. विशेष आर्थिक क्षेत्र (के ई के) जिसकी स्थापना अधिनियम सं. 39/2009 के माध्यम से की गई है के ई के में स्थित और मुख्य व्यापार चला रही कंपनी को कराधान से लेकर रोजगार तक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि अपने प्रचालन में, के ई के राष्ट्रीय परिषद प्रत्येक के ई के में संचालक को स्थापित करने सहित कार्यान्वयन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाता है।
463. वित्त मंत्रालय के विनियमन सं. 104/2016 के अंतर्गत, 3 वर्षों के लिए आयात शुल्क से व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजीगत माल के आयात को छूट दी गई है जबकि व्यापारिक भागीदार 2 वर्षों के लिए पूंजीगत माल/ अथवा सामग्री के लिए आयात शुल्क से छूट प्राप्त कर सकते हैं। उप छूट सरकार द्वारा अनुच्छेद 40 और 41 दी गई है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

464. यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित कुछ उपक्रमों को लाभ प्रदान करता है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारित किया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए जो आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का निर्धारण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(xi) कार्यक्रम सं. 14 – आयातों पर आयकर से छूट**क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध**

465. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि यदि कंपनी सरकार द्वारा पदनामित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित है तब इस कार्यक्रम के अंतर्गत करदाताओं को कुछ वस्तुओं के आयात पर सरकार द्वारा आयकर की छूट मंजूर की गई है। इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज अथवा अधिसूचनाएं उपलब्ध कराई हैं जो उन्हें तर्कसंगत रूप से उपलब्ध था।

- डब्ल्यू टी/ टी पी आर/ एस278
- सरकारी विनियमन सं. 2016 का 96 (जी आर 96/2016) : विशेष आर्थिक क्षेत्र में सुविधाएं

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

466. इण्डोनेशिया की सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (के ई के) के अंतर्गत सुविधा का प्रावधान किया। के ई के की स्थापना विशेष आर्थिक क्षेत्र पर अधिनियम सं. 39/2009 के माध्यम से स्थापित किया गया है। वर्तमान में के ई के राष्ट्रीय परिषद द्वारा पूरे इण्डोनेशिया क्षेत्र में स्थापित 12 पदनामित के ई के हैं। यह इस तर्क के बारे में निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेदार है कि कौन सा व्यापार उस विशेष के ई के में मुख्य व्यापार होगा। सरकार ने यह अनुरोध किया कि वर्तमान में विशेष आर्थिक क्षेत्र का अभी तक पूर्ण रूप से प्रचालन नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार, सरकार के विनियमन सं. 96/2015 में निर्धारित किये गये अनुसार के ई के में आयकर आयातों से छूट उन वस्तुओं पर लागू हैं जिन्हें के ई के में निम्नलिखित से व्यापार भागीदारों को पदनामित किया गया है :

1. सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर;
2. के ई के के भीतर अन्य व्यापारिक भागीदार;
3. अन्य के ई के में अन्य व्यापारिक भागीदार;
4. के ई के के बाहर बोन्डेड क्षेत्र

5. निःशुल्क व्यापार क्षेत्र और निःशुल्क पोर्ट; और/ अथवा

6. अन्य क्षेत्र टी एल डी पी पी

467. इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ अलग अलग के ई के संचालक के माध्यम से वित्त मंत्रालय को आवेदन देने के पश्चात प्राप्त किया जायेगा। यह सुविधा केवल दो विषयों, व्यापारिक प्रतिष्ठान और व्यापारिक भागीदारों को ही उपलब्ध होगी।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

468. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम छोड़े गये राजस्व की प्रकृति में विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित उपक्रम के लिए उपलब्ध है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारण किया है कि आयात पर शुल्कों के भुगतान से छूट पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xii) कार्यक्रम सं. 15 – विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए कटौती

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

469. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने कुछ शीर्षों का निर्धारण किया है जिसके अंतर्गत निवेशकों को आयकर में कटौती दी जाती है। वे शीर्ष निम्नलिखित हैं -

1. कम से कम 10 वर्षों से अधिकतम 25 वर्षों तक 20-100 प्रतिशत तक (1 ट्रिलियन रुपया से अधिक का अपेक्षित निवेश)
2. कम से कम 5 वर्षों से अधिकतम 15 वर्षों तक 20-100 प्रतिशत तक (500 बिलियन से 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक का अपेक्षित निवेश)
3. संबंधित मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित कुछ प्रतिशत तक (500 बिलियन रुपये से कम का अपेक्षित निवेश)

470. इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज अथवा अधिसूचनाएं उपलब्ध कराई हैं।

- कर फ्लेस सं. 4, फरवरी 2016 (पी डब्ल्यू सी की रिपोर्ट)

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध :

471. यह सुविधा विशेष आर्थिक क्षेत्र (के ई के) के अंतर्गत स्थापित की गई है। के ई के जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम सं. 39/2009 के माध्यम से स्थापित किया गया है। कंपनी को कराधान से लेकर रोजगार तक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। पूरे इण्डोनेशिया क्षेत्र में 12 पदनामित के ई के सी मांके, तनजुअंग अपिअपि, तनजुअंग केलयांग, तनजुअंग लेसुंग, मनडालिका, मल्यो बटूटा ट्रांस कलिमनथन, पालू, बिटंग, मोरोटई, सोरोंग, अरुण लहोसेमावे, गलंग बटांग हैं।

472. के ई के की स्थापना के ई के राष्ट्रीय परिषद द्वारा की गई है। के ई के राष्ट्रीय परिषद के मुख्य कर्तव्यों में एक कर्तव्य इस तथ्य का निर्धारण करना है कि कौन का व्यापारिक क्षेत्र के ई के में मुख्य व्यापार होगा। अपने प्रचालन ने, के ई के राष्ट्रीय परिषद प्रत्येक के ई के में संचालक को स्थापित करने सहित कार्यान्वयन संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाता है। क्षेत्रीय परिषद के ई के राष्ट्रीय परिषद को प्रत्येक के ई के में इसके प्रबंधन संबंधी कार्यनिष्पादन की सूचना भी देता है।

473. सरकारी विनियमन सं. 95/2015 में यथानिर्धारित के ई के में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आयकर में कटौती अथवा कर अवकाश है :

क) निवेश >आरपी. 1 ट्रिलियन, 10 से 25 वर्षों तक के लिए 20 से 100 प्रतिशत तक आयकर में कटौती;

ख) निवेश >आरपी. 500 बिलियन 1 ट्रिलियन, 5 से 15 वर्षों तक के लिए 20 से 100 प्रतिशत तक आयकर में कटौती;

ग) निवेश >आरपी. 500 बिलियन, 5 से 15 वर्षों तक के लिए 20 से 100 प्रतिशत तक आयकर में कटौती;

474. किसी भी उपक्रम को विशेष रूप से इस कार्यक्रम से बाहर नहीं रखा गया है। इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किये जाने का अनुमान नहीं है।

475. इस अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आयकर में कटौती की राशि वही रहती है। यह सुविधा अपने आप में विशेष रूप से के ई के में मुख्य व्यापार प्रचालन से प्राप्त आय पर दी जाती है, लेकिन इसके मुख्य प्रचालन को छोड़कर व्यापार क्रियाकलापों से प्राप्त आय अभी भी कराधान के अध्वधीन है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

476. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में आयकर से छूट का प्रावधान है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारण किया है कि आयकर से छूट देने वाले कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(xiii) कार्यक्रम सं. 17 – पायोनियर उद्योग दर्जा

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

477. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने औद्योगिक संपदाओं के लिए पर्यावरण के संबंध में सूचना देने संबंधी आवश्यकताओं और लाइसेंस देने संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाया है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे कर अवकाश और कर से छूट, क्षेत्रीय कर और शुल्कों से छूट अथवा कटौती इस कार्यक्रम में कुछ अतिरिक्त लाभ भी हैं।

478. सरकार ने चुने गये 14 औद्योगिक पार्कों में उद्योगों को ये प्रोत्साहन उपलब्ध कराये हैं। इस प्रकार के उद्योगों को औपचारिक परमिट प्राप्त करने से पहले निर्माण आरंभ करने की छूट भी मिलती है।

479. इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज अथवा अधिसूचनाएं उपलब्ध कराई हैं, जो उन्हें तर्कसंगत रूप से उपलब्ध था।

- बी के पी एम की रिपोर्ट
- अनुच्छेद : ग्लोब लीगल मॉनीटर – इण्डोनेशिया : विनियमन उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हैं
- द जर्काता पोस्ट : नये विनियमन का लक्ष्य उद्योग में निवेश को आकर्षित करना है
- द जर्काता पोस्ट : इस वर्ष प्रचालन आरंभ करने के लिए विलमर्श इंस्टीट्यूटल स्टेट

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

480. पायोनियर उद्योग कर लाभ कार्यक्रम की स्थापना 15 अगस्त, 2011 को की गई थी, उसका नवीकरण और उसमें संशोधन 14 अगस्त, 2015 को किया गया था और उसमें दूसरी बार संशोधन 27 जून, 2016 को किया गया था। इस कार्यक्रम में कुछ कोरपोरेट करदाताओं के लिए 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक पांच से पन्द्रह वर्षों के दौरान आयकर में कटौती का प्रावधान है। कर में कटौती निगम के वाणिज्य उत्पादन समय के प्रथम वर्ष से आरंभ होता है। कर में कटौती प्राप्त करने वाले निगम को 'व्यापार अंतर संबंध वाला जो बड़े हुए मूल्य और उच्च बाह्यता प्रदान करता है, नई प्रौद्योगिकी को आरंभ करता है और जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत मूल्य है' उद्योग के रूप में परिभाषित एक "पायोनियर उद्योग" में कार्य करना होता है।

481. कोरपोरेट आयकर कटौती सुविधा मुख्य व्यापार क्रियाकलाप जो वित्त मंत्रालय के विनियमन सं. 159/ पी एम के. 010/2015 में यथाउल्लिखित और वित्त मंत्रालय के विनियमन सं. 103/ पी एम के. 010/2016 द्वारा यथासंशोधित एक पायोनियर उद्योग होता है, से प्राप्त अथवा उर्पाजित आय पर दिया जायेगा।
482. वित्त मंत्रालय के विनियमन सं. 159/ पी एम के. 010/2015 जिसे वित्त मंत्रालय विनियमन सं. 103/ पी एम के. 010/2016 द्वारा संशोधित किया गया है, में आगे वित्त मंत्रालय के विनियमन सं. 35/2018 के अंतर्गत संशोधित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम में 100 प्रतिशत आयकर कटौती का प्रावधान है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

483. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में आयकर से छूट का प्रावधान है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारण किया है कि आयकर से छूट देने वाले कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(xiv) कार्यक्रम सं. 18 – सूचीबद्ध निवेशों के लिए आयकर लाभ

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

484. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि इण्डोनेशिया की सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू अथवा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर कर सब्सिडी के लिए पात्रता मानदंडों को स्थापित किया है -
1. 5 प्रतिशत की दर से 6 वर्षों के लिए वसूले गये कुल निवेश की 30 प्रतिशत निवल कटौती
 2. बड़े हुए ह्रास और ऋण परिशोधन जैसा की कानून द्वारा प्रावधान किया गया है
 3. विदेशी कर पर भुगतान किया गया लाभांश पर वसूला गया आयकर लागू डी टी ए ए के अनुसार अपेक्षाकृत 10 प्रतिशत कमतर प्रशुल्क होगा; और
 4. 5 वर्षों से अधिक और 10 वर्षों से कम के लिए हानि मुआवजा।
485. इस कार्यक्रम के लिए भौगोलिक सीमांकन सरकार द्वारा परिभाषित “विशिष्ट व्यापार क्षेत्र” तक सीमित है जिसकी सं. 77 है। इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज अथवा अधिसूचनाएं उपलब्ध कराई हैं।
- विनियमन सं. 1/2007
 - विनियमन सं. 18/2015

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

486. इस कार्यक्रम की स्थापना सरकारी विनियमन सं. 2/2007 के अनुसरण में 1 जनवरी, 2007 को किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ व्यापारिक क्षेत्रों और/ अथवा कुछ रिजन में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम का नवीकरण और उसे संशोधित 6 अप्रैल, 2015 को सरकारी विनियमन सं. 18/2015 को किया गया था, जिसे सरकारी विनियमन सं. 9/2016 द्वारा संशोधित किया गया था। यद्यपि सरकारी विनियमन सं. 18/2015 सरकारी विनियमन सं. 1/2007 को रद्द करता है फिर भी सरकारी विनियमन सं. 1/2017 के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही कंपनियां अपने मूल रूप से समाप्त होने की तिथि तक इस प्रकार के लाभों को प्राप्त करना जारी रख सकती हैं। सरकारी विनियमन सं. 1/2007 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए, करदाता को सरकारी विनियमन सं. 1/2007 के परिशिष्टों में सूचीबद्ध कुछ रिजनों में बड़ी संख्या में व्यापारिक क्षेत्रों और/ अथवा में से एक पर नई पूंजी विस्तार करना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर सुविधाओं को प्राप्त करने वाले को स सरकारी विनियमन सं. 94/2010 के अनुच्छेद 29 अंतर्गत (संस्थागत आयकर से छूट अथवा कटौती) लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

487. दोनों विनियमन चार प्रमुख साधनों : (1) मूर्त स्थायी परिसंपत्ति के रूप में निवेश के लिए कर में 30 प्रतिशत कटौती (व्यापार के प्रचालनों के पहले 6 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत); (2) बढ़ा हुआ ह्रास और ऋण परिशोधन; (3) गैर आवासीय करदाताओं को लाभांश वितरण पर कम किया गया कर दर; और (4) हानि का मुआवजा के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। ये कर लाभ 77 सूचीबद्ध उद्योगों में कंपनियों के लिए उपलब्ध है।
488. पात्रता उन उद्योगों तक सीमित है जो उन क्षेत्रों में कार्य करते हैं जो सरकारी विनियमन सं. 9/2016 द्वारा यथासंशोधित सरकारी विनियमन सं. 18/2015 के परिशिष्ट I और II में सूचीबद्ध है। किसी अन्य उपक्रम को विशेष रूप से इस कार्यक्रम से बाहर नहीं रखा गया है। इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किये जाने का अनुमान नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

489. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में आयकर से छूट का प्रावधान है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारण किया है कि आयकर से छूट देने वाले कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(xv) कार्यक्रम सं. 19 – कर अवकाश

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

490. इस कार्यक्रम के अंतर्गत इण्डोनेशिया की सरकार ने कोरपोरेट कर से छूट की घोषणा की है। इस प्रकार की राहत वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के कर वर्ष से 10 वर्षों और 5 कर वर्षों से कम नहीं हो, के लिए दी जायेगी।
491. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि सरकार ने इन उद्योगों को इस प्रकार की एक व्यापक राहत देने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत कठोर पात्रता मानदंड जारी किये हैं। इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज अथवा अधिसूचनाएं उपलब्ध कराई हैं, जो उन्हें तर्कसंगत रूप से उपलब्ध था।

- इण्डोनेशिया गणतांत्रिक के वित्त मंत्रालय के विनियमन सं. 159/ पी एम के.010/2015
- वित्त मंत्रालय के विनियमन सं. 130/ पी एम के 011/2011 – कोरपोरेट आयकर राहत अथवा कटौती सुविधा का प्रावधान

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

492. इस कार्यक्रम के लिए कोई पृथक स्पष्टीकरण अथवा सूचना नहीं दी गई है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

493. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में आयकर से छूट का प्रावधान है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारण किया है कि आयकर से छूट देने वाले कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(xvi) कार्यक्रम सं. 20 – भूमि कर की कटौती

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

494. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों को इण्डोनेशिया की सरकार से कटौती योग्य भूमि कर का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में भूमि कर विद्यमान कानूनों के अनुसार कटौती योग्य है। इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दस्तावेज अथवा अधिसूचनाएं उपलब्ध कराई हैं, जो उन्हें तर्कसंगत रूप से उपलब्ध था।

- डब्ल्यू टी/ टी पी आर/ एस278

- सरकारी विनियमन सं. 2016 का 96 (जी आर 96/2016) : विशेष आर्थिक क्षेत्र में सुविधाएं

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

495. यह सुविधा विशेष आर्थिक क्षेत्र (के ई के) अथवा कर छूट सुविधा के अंतर्गत स्थापित की गई है। के ई के जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम सं. 39/2009 के माध्यम से स्थापित किया गया है। कंपनी को कराधान से लेकर रोजगार तक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। पूरे इण्डोनेशिया क्षेत्र में 12 पदनामित के ई के सी मांके, तनजुअंग अपिअपि, तनजुअंग केलयांग, तनजुअंग लेसुंग, मनडालिका, मल्यो बटूटा ट्रांस कलिमनथन, पालू, बिटंग, मोरोटई, सोरोंग, अरुण लहोसेमावे, गलंग बटांग हैं।
496. के ई के की स्थापना के ई के राष्ट्रीय परिषद द्वारा की गई है। अपने प्रचालन ने, के ई के राष्ट्रीय परिषद प्रत्येक के ई के में संचालक को स्थापित करने सहित कार्यान्वयन संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाता है। क्षेत्रीय परिषद के ई के राष्ट्रीय परिषद को प्रत्येक के ई के में इसके प्रबंधन संबंधी कार्यनिष्पादन की सूचना भी देता है।
497. इण्डोनेशिया की कर प्रणाली में भूमि और भवन कर (पी बी बी) क्षेत्रीय/ शहरी कर अथवा सजा का हिस्सा है और इसका निर्धारण क्षेत्रीय प्रमुख/ मेयर विनियमन के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 31 में अधिनियम सं. 39/2009 में, पी बी बी की कटौती इस विनियमन के अनुरूप दिया गया है। हालांकि, सरकारी विनियमन सं. 96/2015 में, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत पी बी बी पर्यटन के लिए के ई के में सुविधाओं के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें यह प्रावधान है कि क्षेत्रीय सरकार 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक क्षेत्रीय कर में कटौती अथवा छूट अथवा दण्ड का निर्धारण कर सकती है।
498. एकमात्र के ई के जिसका मुख्य व्यापार पर्यटन में है जैसे के ई के तानजुंग केलयांग, के ई के मण्डालिका, के ई के तानजुंग लेसुंग, के ई के मोरोटाई, के ई के सोरोंग ने क्षेत्रीय/ शहरी कर अथवा सजा में कटौती के लिए आवेदन किया।
499. इस कार्यक्रम में किसी आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। पात्रता केवल उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों/ व्यापारिक भागीदारों तक सीमित है जो के ई के क्षेत्र के भीतर कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुमान नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

500. इस कार्यक्रम में विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित उपक्रम के लिए भूमि कर आवेदन में कटौती का प्रावधान है। हालांकि, कटौती का लाभ उस उपक्रम के लिए उपलब्ध है जो पर्यटन संबंधी व्यापारिक क्रियाकलाप करते हैं। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित नहीं है।

(xvii) जांच की प्रक्रिया के दौरान खोज किये गये नये कार्यक्रम : समुचित से कम पारिश्रमिक पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

501. घरेलू उद्योग ने जांच की प्रक्रिया के दौरान यह तर्क दिया है कि इण्डोनेशिया की सरकार ने लक्षित निर्यात नियंत्रणों और अन्य संबंधित उपाय कॉपर और पर लगाये हैं और यह उस पर संकेंद्रित है जिसके फलस्वरूप इण्डोनेशिया के घरेलू बाजार में इन उत्पादों के लिए अत्यधिक आपूर्ति और कम की गई कीमतों की स्थिति उत्पन्न होती हो। इसके परिणामस्वरूप कॉपर और संकेंद्रण का प्रावधान इण्डोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को उचित से कम पारिश्रमिक पर किया गया है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

502. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से कच्चे माल पर निर्यात नियंत्रण के संबंध में सूचना का अनुरोध किया है। हालांकि, कोई संतोषजनक सूचना/ उत्तर इण्डोनेशिया की सरकार अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इण्डोनेशिया की सरकार ने कॉपर संकेंद्रण पर निर्यात शुल्क लगाने और अन्य संबंधित

उपायों के रूप में लक्षित निर्यात नियंत्रण लागू किये हैं जिसके फलस्वरूप अत्यधिक आपूर्ति हुई है और उसके साथ ही इण्डोनेशिया के घरेलू बाजार में कॉपर और संकेंद्रण के लिए कृत्रिम रूप से कीमतें कम हुई हैं। इसके फलस्वरूप इण्डोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं को उत्पादकों को उचित से कम पारिश्रमिक पर कॉपर और एवं संकेंद्रण का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने उचित से कम पारिश्रमिक पर कच्ची सामग्री के प्रावधान के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण किया है।

इण्डोनेशिया के उत्पादक / निर्यातक

पीटी कारया सुमिदेन इण्डोनेशिया

503. पीटी कारया सुमिदेन इण्डोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/ निर्यातक है। पीटी कारया सुमिदेन इण्डोनेशिया ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और उनके द्वारा प्राप्त किये गये सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई।
504. प्राधिकारी ने पीटी कारया सुमिदेन द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की और जांच के उपरांत उनसे अतिरिक्त सूचना प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया और इसके साथ ही इस उत्तर में उपलब्ध कराई गई सूचना के सत्यापन का भी अनुरोध किया। प्राधिकारी ने पीटी कारया सुमिदेन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया और उन कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया जिसके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त हुआ था अथवा उपार्जित किया गया था। यह नोट किया जाता है कि पीटी कारया सुमिदेन ने कार्यक्रम सं. 7 और कार्यक्रम सं. 13 जिसका आरोप जांच शुरुआत संबंधी सूचना में लगाया गया है, के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया। इसके अलावा, उन्होंने अपने उत्तर में उनके द्वारा सूचित किये गये अनुसार बिजली पर मूल्यवर्धित कर से छूट भी प्राप्त की है। प्राधिकारी यह निर्धारण करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों के फलस्वरूप छोड़े गये राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान किया गया है जो अन्य प्रकार से उचित था। इसके फलस्वरूप, पीटी कारया सुमिदेन को इस अनुदान के प्राप्त करने वाले के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि वे पीटी कारया सुमिदेन सहित कुछ उपक्रम तक सीमित थी।
505. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान पता लगाये गये अन्य कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करने हेतु सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना पर विश्वास कर समुचित से कम पारिश्रमिक के लिए कच्ची सामग्री के प्रावधान हेतु सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भी विश्वास किया है।
506. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों का नाम और सदृश सब्सिडी मार्जिन दिया गया है।

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 7	आयात शुल्क से छूट	मशीनरी के आयात को सीमा शुल्क से छूट दी गई है	***	0-1%
कार्यक्रम सं. 13	उत्पादन के उद्देश्य से कच्चे माल पर शुल्क से छूट	कच्चे माल का आयात अधिमान्य सीमा शुल्क के अधीन है	***	0-5%
अन्य कार्यक्रम	बिजली पर मूल्यवर्धित कर से छूट	बिजली पर मूल्यवर्धित कर के भुगतान से छूट	***	0-1%
अन्य कार्यक्रम	उचित से कम पारिश्रमिक पर कॉपर संकेंद्रण का प्रावधान	इण्डोनेशिया में कॉपर संकेंद्रण पर 7.5% के निर्यात शुल्क के परिणामस्वरूप उचित से कम पारिश्रमिक पर कच्चे माल का प्रावधान किया गया है	***	0-5%
कुल			***	0-5%

पीटी टेम्बगा मुलिया सेमनन टीबीके

507. पीटी टेम्बगा मुलिया सेमनन टीबीके इण्डोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/ निर्यातक है। पीटी कारया सुमिडेन इण्डोनेशिया ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और उनके द्वारा लाभ उठाये गये सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई।
508. प्राधिकारी ने पीटी टेम्बगा मुलिया सेमनन टीबीके द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की और जांच के उपरांत उनसे अतिरिक्त सूचना प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया और इसके साथ ही इस उत्तर में उपलब्ध कराई गई सूचना के सत्यापन का भी अनुरोध किया। प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया कि छोड़े गये राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान जो अन्य प्रकार से देय थे, का प्रावधान सब्सिडी कार्यक्रम के फलस्वरूप किया गया। इसके फलस्वरूप, पीटी टेम्बगा मुलिया सेमनन टीबीके को इस अनुदान के प्राप्त करने वाले के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि वे पीटी टेम्बगा मुलिया सेमनन टीबीके सहित कुछ उपक्रम तक सीमित थी।
509. प्राधिकारी ने पीटी टेम्बगा मुलिया सेमनन टीबीके द्वारा उपलब्ध कराई सूचना का सत्यापन किया है और उन कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है जिसके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त हुआ था अथवा उपार्जित किया गया था। हालांकि, सब्सिडी कार्यक्रमों के अंतर्गत पीटी टेम्बगा मुलिया सेमनन टीबीके द्वारा प्राप्त किये गये लाभ की राशि जिसका लाभ उनके द्वारा उठाया गया था के संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तदनुसार, प्राधिकारी ने पीटी टेम्बगा मुलिया सेमनन टीबीके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विश्वास करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पीटी टेम्बगा मुलिया सेमनन टीबीके के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है।
510. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान पता लगाये गये अन्य कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करने हेतु सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना पर विश्वास कर समुचित से कम पारिश्रमिक के लिए कच्ची सामग्री के प्रावधान हेतु सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भी विश्वास किया है।
511. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों का नाम और सदृश सब्सिडी मार्जिन दिया गया है।

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 7	आयात शुल्क से छूट	मशीनरी के आयात को सीमा शुल्क से छूट दी गई है	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 13	उत्पादन के उद्देश्य से कच्चे माल पर शुल्क से छूट	कच्चे माल का आयात अधिमान्य सीमा शुल्क के अधीन है	***	0-5%
अन्य कार्यक्रम	उचित से कम पारिश्रमिक पर कॉपर संकेंद्रण का प्रावधान	इण्डोनेशिया में कॉपर संकेंद्रण पर 7.5% के निर्यात शुल्क के परिणामस्वरूप उचित से कम पारिश्रमिक पर कच्चे माल का प्रावधान किया गया है	***	0-5%
कुल			***	0-10

इण्डोनेशिया के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों का सारांश

512. इण्डोनेशिया से सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का निर्धारण सहयोगी पक्षकारों के लिए सब्सिडी मार्जिन की उच्चतम सीमा के आधार पर किया गया है। इसके अलावा, अन्य सभी दरों का निर्धारण करते समय कार्यक्रम सं. 2, 3 और 10 के लिए सब्सिडी मार्जिन भी जोड़ा गया है।

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
कार्यक्रम सं. 7	मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 7/8/12/13/14	उत्पादन के उद्देश्य से कच्चे माल पर शुल्क से छूट	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 2/3/5	अधिमान्य उधार	***	0-1%
कार्यक्रम सं. 10/11/15/17/18/19	आयकर लाभ	***	0-1%
अन्य कार्यक्रम	उचित से कम पारिश्रमिक पर कॉपर संकेंद्रण का प्रावधान	***	0-5%
अन्य कार्यक्रम	बिजली पर मूल्यवर्धित कर से छूट	***	0-1%
कुल		***	0-10%

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

ज. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

513. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :

- क) निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकार के आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करें क्योंकि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सब्सिडी दिये जाने की राशि एक प्रतिशत यथामूल्य से अधिक है; (ख) प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा नगण्य नहीं है; (ग) इन आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन आयात किये उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।
- ख) हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि मांग एवं आपूर्ति में अंतर के कारण आयात आवश्यक हो गया था, बहुत अधिक भ्रामक है। इस देश के पास केथोड के चरण में हमेशा अतिरिक्त क्षमताएं रही हैं और यह उद्योग केथोड का निर्यात करने के लिए बाध्य था।
- ग) संबद्ध देशों से पिछले दशक में उत्पाद के आयात बहुत कम हुए थे। यह दर्शाता है कि इस उत्पाद की मांग को घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया जा रहा था।
- घ) इस उद्योग ने 6एमएम से कम के तार के लिए क्षमताएं स्थापित नहीं की हैं क्योंकि उपभोक्ताओं ने अपनी आवश्यकताओं पर विचार करते हुए इच्छित इनहाउस आयाम का तार लेना पसंद किया है।
- ङ) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में आयातों में आधार वर्ष की तुलना में केवल 14 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि मांग में केवल 26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।
- च) प्रशुल्क सिर्फ 74081990 के लिए शुल्क की दर में आशियान मुक्त व्यापार करार (ए एफ टी ए) के अंतर्गत पिछली अवधियों में लगातार कटौती की गई है। संबद्ध देशों से शुल्क की दर में कमी के साथ, आयातों ने एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी है।

- छ) संबद्ध देशों से संबद्ध आयात भारत में घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत/ उचित कीमत से कम कीमतों पर हो रहे हैं और इसके फलस्वरूप सकारात्मक और अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन हुआ है।
- ज) घरेलू उद्योग के उत्पादन की मात्रा में बहुत मामूली सुधार देखा जाता है क्योंकि उत्पादन में केवल 6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जब मांग में 26 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान उत्पादन में सुधार घरेलू बिक्री की मात्रा में सुधार के अनुपात में नहीं हुआ है।
- झ) जबकि विचारधीन उत्पाद की मांग में 2015-16 और जांच की अवधि के बीच *** मी. ट. तक हुई, घरेलू उद्योग की बिक्री में *** मी. ट. तक गिरावट आई और घरेलू उद्योग को प्रतिकूल लाभप्रदता पर भी उत्पाद का अतिरिक्त निर्यात (*** मी. ट.) का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार के निर्यातों के बावजूद, घरेलू उद्योग के पास माल भंडार में हाल की अवधि में वृद्धि हुई।
- ञ) इस उत्पाद को 'अनंतिम कीमत निर्धारण' की अवधारणा पर बेचा जाता है जहां उपभोक्ता माल को लेने के लिए ऑर्डर बुक कर सकते हैं और उस कीमत पर सहमत हो सकते हैं जो भविष्य में हो सकती है। यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से विदेशी उत्पादकों ने अपने आंकड़े दिए हैं। घरेलू उद्योग ने वर्तमान अवधि के दौरान बीजक भेजे गए बिक्री के आधार पर अपने आंकड़े दिए हैं।
- ट) संबद्ध देशों से आयात किये गये माल का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है। भारतीय उत्पादकों की कीमत के लिए बेंचमार्क आयात कीमतें और एन एम ई कीमतें हैं। इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थानापन नहीं है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए जिम्मेदार एकमात्र कारक इस उत्पाद की आयात कीमतें और एन एम ई कीमतें हैं।
- ठ) उस दर पर जिस पर सस्ते और सब्सिडीयुक्त आयात बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं, भारतीय घरेलू बाजार में यह सामर्थ्य है कि वह भारतीय उद्योग को नष्ट कर सकता है।
- ड) इसके अलावा, सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा है। यदि यह स्थिति वैसी होती है तब आयात का समाधान नहीं किया जाता है और तब स्थिति निश्चित रूप से और खराब हो जायेगी।
- ढ) आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत अधिक कम है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आयातों के लिए मांग के घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की जा रही कीमत की तुलना में कम कीमत होने को देखते हुए आगे और बढ़ने की संभावना है और इससे यदि उसका समाधान नहीं किया जाता है तब घरेलू कीमत की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ता रहेगा।
- ण) कीमत में सकारात्मक कटौती का आशय यह है कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर इन आयातों के कारण और अधिक दबाव बनेगा। आवश्यक संरक्षण न दिये जाने पर घरेलू उद्योग जोखिम की स्थिति में रहेगा।
- त) संबद्ध विदेशी उत्पादकों के पास बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन क्षमताएं हैं। इन निर्यातकों के कारण उनके आयातों के बहुत अधिक बढ़ जाने की संभावना है जिसके कारण आगे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- थ) इन उत्पादकों के निर्यात उन्मुखीकरण के कारण, यदि वर्तमान स्थिति में कटौती नहीं की जाती है तब निर्यातक बढ़ती हुई मांग का लाभ उठायेंगे जिससे घरेलू उद्योग के लिए यह स्थिति और प्रतिकूल हो जायेगी।
- द) आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष के बाजार के जांच की अवधि में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निरंतर रूप से बढ़ी है।
- ध) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में क्षमता का विस्तार नहीं किया है। हालांकि, यदि घरेलू बाजार में सस्ती और सब्सिडीयुक्त सामानों की बाढ़ नहीं आई होती तब घरेलू उद्योग आसानी से अपेक्षाकृत अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त कर सकता था।

- न) घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान बाजार में अपने हिस्से का 8 प्रतिशत से अधिक खोना पड़ा।
- प) घरेलू उद्योग को संचित माल भंडार का सामना करना पड़ रहा है और उसमें जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। मात्रा के मामले में, मासिक माल भंडार *** मी. ट. तक पहुंच गया है।
- फ) घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है जबकि बिक्री कीमत उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है और आयात की कीमतों में गिरावट आई है।
- ब) संबद्ध आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना किये जाने से स्पष्ट है।
- भ) जबकि यह कटौती आरंभिक आधार वर्ष में नकारात्मक थी, यह सभी संबद्ध देशों के लिए क्षति की अवधि के दौरान सकारात्मक हो गई है। जांच की अवधि में विचारधीन उत्पाद की कुल खपत का लगभग 90 प्रतिशत 1.6 एमएम, 1.8 एमएम और 8 एमएम का हुआ है। इन तीन उत्पाद प्रकारों की कीमतों में एक दूसरे के अनुरूप वृद्धि हुई है।
- म) संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव है। संबद्ध वस्तुओं की कीमत का दैनिक उतार चढ़ाव 100 यू.एस. डॉलर प्रति मी. ट. तक हो सकता है। कीमत में अस्थिरता से यह आशय निकलता है कि ये कीमतें दैनिक आधार पर 6000-7000 रु. प्रति मी. ट. की सीमा तक परिवर्तित हो सकते हैं। कीमत में इतने अधिक परिवर्तन के साथ वास्तविक आधार पर कीमत में कटौती की गणना सही तस्वीर को नहीं दर्शायेगी। इस कारण से, माह दर माह आधार पर गणना की गई है। प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे कीमत में मासिक कटौती की गणना करें।
- य) घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि में बेची गई वस्तुओं के प्रति मी. ट. लाभ आधार वर्ष से 20 प्रतिशत से अधिक तक कम हो गया है। जबकि 2014-15 से वर्ष 2015-16 में लाभप्रदता में वृद्धि हुई, उस वर्ष के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई है। लाभप्रदता में वृद्धि के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा बेचे गये प्रति इकाई लाभ में जांच की अवधि में लगभग 43 प्रतिशत तक कमी आई है।
- र) प्रति मी. ट. आधार पर घरेलू उद्योग का नकद लाभ भी बदतर स्थिति को दर्शाता है। प्रति मी. ट. आधार पर घरेलू उद्योग का नकद लाभ आधार वर्ष से जांच की अवधि में स्वतंत्र आधार पर 31 प्रतिशत तक कम हुआ है।
- ल) मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। मजदूरी घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के आयात के प्रतिकूल प्रभावों को नहीं दर्शाता है क्योंकि इन कारकों को कंपनी अर्थव्यवस्था के समग्र प्रचालनों द्वारा शासित किया जाता है।
- व) अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है क्योंकि उनकी मात्रा या तो बहुत कम है अथवा उसकी कीमतें अपेक्षाकृत अधिक हैं।
- श) आयातों के विवरण से यह देखा जायेगा कि संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में सतत रूप से वृद्धि हुई है जबकि गैर संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन देशों में उत्पादकों को दी जा रही सब्सिडी प्राप्त करने वाले संबद्ध देशों से बड़े हुए आयातों के कारण न केवल घरेलू उद्योग को बहुत अधिक क्षति हुई है बल्कि अन्य देशों के अन्य उत्पादकों पर भी प्रभाव पड़ा है।
- ष) संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तदनुसार, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कारण नहीं हो सकता है।
- स) घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि बहुत अधिक मात्राओं में और कम कीमतों पर संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। व्यापार पर प्रतिबंधात्मक प्रथाओं, प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे, उत्पादकता से संबंधित मुद्दे या कोई अन्य कारक नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

- ह) प्राधिकारी को यह देखते हुए घरेलू और निर्यात प्रचालनों की संयुक्त सुविधा पर विचार करना चाहिए कि घरेलू उद्योग द्वारा किये गये निर्यात आयातों में वृद्धि का परिणाम है और न कि घरेलू उद्योग की व्यापारिक पसंद है। कोई उत्पादन सुविधा निर्यात के लिए स्थापित नहीं किया गया है।
- क्ष) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री में कुल लाभों और न की वर्तमान जांच के उद्देश्यों से घरेलू प्रचालन में ही अर्जित लाभों पर विचार करना उपयुक्त होगा।
- त्र) निर्यातों में अपेक्षाकृत कम लाभ पर विचार संबद्ध आयातों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले एक साक्ष्य के रूप में किया जाना चाहिए।
- ज्ञ) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- कक) ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यप्रणाली नहीं है जिसे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति का कारण माना जा सकता है।
- खख) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन की प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।
- गग) घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन और क्षति की जांच यथासंभव सीमा तक घरेलू बिक्री के प्रचालन के संबंध में की गई है। निर्यातों की मात्राओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इस कारण से घरेलू बिक्री में गिरावट आयातों के प्रतिकूल प्रभावों के परिणाम के रूप में दावा की जा रही है और यह निर्यातों में संभावित गिरावट के कारण नहीं है।
- घघ) संबद्ध आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है और परिणाम के तौर पर संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- ङङ) आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग कमतर मार्जिन पर अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए बाध्य है और इसके परिणाम के रूप में घरेलू उद्योग पर अलग अलग रूप में प्रभाव पड़ रहा है।

ज. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

514. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है :

- क) वैश्विक स्तर पर सभी कॉपर उत्पाद लंदन मेटल एक्सचेंज (एल एम ई) कॉपर केथोड कीमत अर्थात् एल एम ई कीमत + प्रीमियम से सूचीबद्ध है। इसके प्रीमियम पर क्रेता और विक्रेता के बीच समझौता किया जा सकता है जबकि एल एम ई कीमत आपूर्तिकर्ता के माध्यम एल एम ई पर निर्धारित है। सामान्य तौर पर, एक अज्ञात दिन अथवा कुछ दिनों के औसत को एल एम ई कीमत का निर्धारण करने के लिए चुना जाता है और तब अंतिम कीमत निकालने के लिए प्रीमियम जोड़ा जाता है।
- ख) एल एम ई कीमत जांच के अधीन अवधि के लिए बहुत गतिशील है और वह 4200 यू एस डॉलर से 7500 यू एस डॉलर तक की सीमा में रहता है। प्रीमियम कॉपर तार के लिए 100-400 यू एस डॉलर (कॉपर कीमत का 2-5 प्रतिशत) के बीच रहता है जो एल एम ई कीमत की तुलना में बहुत कम है।
- ग) कॉपर वायर रॉड संयंत्र कॉपर केथोड की खरीद एक निश्चित प्रीमियम पर करता है और उसे कॉपर रॉड में परिणत करता है और तब उसे विभिन्न आकारों के तार में परिणत करता है और फिर उसकी बिक्री निश्चित प्रीमियम पर ग्राहक को करता है। इस प्रीमियम में केथोड प्रीमियम, उत्पादन की लागत, वित्त लागत, संभार तंत्र और कॉपर वायर रॉड संयंत्रों के लिए असमान लाभ निर्धारित है।

- घ) आवेदकों के समान, तीसरा भारतीय उत्पादक नामतः हिंदुस्तान कॉपर क्रेता द्वारा मांग की गई संबद्ध वस्तुओं का विनिर्देशन और परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए एल एम ई कॉपर कीमत के आधार पर बिक्री कीमत का निर्धारण करता है।
- ङ) याचिकाकर्ता का यह आरोप की आयात कीमत लगभग 10 प्रतिशत सस्ती है, सही नहीं है।
- च) उत्पादक एक बहुगुणक कारक, उनकी कीमत निर्धारण नीति के हिस्से के रूप में ग्राहकों से कॉपर वायर रॉड पर आयात शुल्क के समतुल्य (5 प्रतिशत) लागत संगठक की वसूली करता है। जांच के अधीन अवधि के लिए, कॉपर रॉड उत्पादकों द्वारा वसूली जाने वाली औसत बहुगुणक कारक 1.04 है।
- छ) यह अंतर जैसा कि ऊपर लिया गया है किसी कंपनी के लिए अत्यधिक गतिशील कॉपर कीमतों का आयात करने और यू एस डॉलर/ रुपए में उतार चढ़ाव के भारी खतरे को उठाने के लिए बहुत अधिक कम प्रोत्साहन है।
- ज) यदि इस अंतर को दोनों उत्पादकों द्वारा 400,000 मी. ट. की कुल कॉपर रॉड की बिक्री पर वार्षिक आधार पर तय किया जाता है तब यह लगभग 82 करोड़ भारतीय रुपए होगा जो दोनों उत्पादकों की 3243 करोड़ रुपए की औसत वार्षिक संयुक्त ई बी आई टी डी ए से बहुत कम है।
- झ) भारत सरकार एक नीति के रूप में प्रशुल्क अवरोध लगाकर (इस मामले में 5.5 प्रतिशत) घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करता है, हालांकि घरेलू उत्पादकों ने इस संरक्षण को लाभ कमाने के लिए एक औजर के रूप में उपयोग किया है और इसे अपनी कीमत गणना में जोड़ दिया है।
- ञ) हमारा अनुमान है कि इस देश में "कॉपर वायर्स" का कुल उत्पादन 5-6 लाख मी. ट. है। आवेदक अधिकतम 12000 मी. ट. का प्रतिवर्ष अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं जो कुल घरेलू उत्पादन का 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है। हम यह समझते हैं कि केवल हिन्डालको के पास "कॉपर वायर्स" की उत्पादन करने की कुछ क्षमता है (अनुमानित तौर पर यह लगभग 12000 मी. ट. प्रतिवर्ष है) जबकि वेदांता के पास "कॉपर वायर्स" के उत्पादन करने की कोई सुविधा नहीं है।
- ट) कोई सार्थक क्षति विश्लेषण इस नियमावली के अनुबंध 1 के संबंध में नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदन में "कॉपर वायर" उत्पादकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इस कारण से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई क्षति विश्लेषण "कॉपर वायर्स" उद्योग के लिए किया जाना है।
- ठ) यह विशेष रूप से दर्शाना संगत है कि पाटनरोधी जांचों में प्रयोग किये गये कार्यपद्धति के अनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण इन आवेदकों को क्षतिरहित कीमत की सीमा तक अपनी कीमत को बढ़ाने में सक्षम बनायेगा क्योंकि गैर-संबद्ध देशों से आयात और आवेदक की घरेलू बिक्री कीमत एल एम ई कीमत से शासित होना जारी रहेगी। इस कारण से, संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की गणना लगाई गई पूंजी पर लाभ का 22 प्रतिशत की दर के आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह बढ़ा चढ़ाकर रखा गया है और वह संबद्ध वस्तुओं के लिए उपयुक्त नहीं है।
- ड) याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि उनका उत्पादन जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन के 90 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, सभी आर्थिक आंकड़े और सूचना जिसके बारे में याचिकाकर्ता द्वारा क्षति के साक्ष्य के रूप में दावा किया गया है केवल मैसर्स हिन्डालको इस्ट्रीज लिमि. से संबंधित है। मैसर्स वेदांता का कोई आर्थिक मानदंड उपलब्ध नहीं कराया गया है जो घरेलू उद्योग की उचित जांच को हानि पहुंचायेगा।
- ढ) क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में साक्ष्य जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है यह दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि चार संबद्ध देशों से आयात किये गये कॉपर वायर के कारण घरेलू भारतीय उद्योग को क्षति होती है।

- ण) हिन्डालकों और वेदांता दोनों निरंतर कास्ट कॉपर रॉड और कॉपर वायर का उत्पादन और बिक्री करता है जबकि निर्यातक भारत में कॉपर वायर केवल निर्यात करता है। कॉपर रॉड कॉपर वायर प्राप्त करने के लिए इनपुट के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार से आयात किया गया कॉपर वायर इन याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादन किये गये निरंतर कास्ट कॉपर रॉड के एक बड़े हिस्से से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करता है। इस प्रकार से संबंधित आयातों के द्वारा हुई कोई क्षति केवल कॉपर वायर के भारतीय घरेलू उद्योग के संबंध में होना चाहिए और याचिकाकर्ता का यह दायित्व है कि वह यह दर्शाये कि उनके कॉपर वायर उद्योग को आयात किये गये कॉपर वायर से क्षति उठानी पड़ती है।
- त) हालांकि, बाजार की मांग और उत्पादन की क्षमता के संबंध में इन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया क्षति संबंधी साक्ष्य कॉपर वायर के बजाय कॉपर रॉड के लिए विशिष्ट है और इस प्रकार से भारतीय उद्योग के उत्पादन पर इन आयातों के किसी प्रभाव को सिद्ध करने के लिए संगत नहीं है।
- थ) बाजार का हिस्सा, बिक्री की मात्रा, माल भंडार और लाभ के संबंध में सांख्यिकीय साक्ष्य कॉपर वायर और कॉपर रॉड को अलग अलग भी नहीं करता है जो इस मामले में क्षति की उचित जांच को सुरक्षित नहीं रख सकता है।
- द) वेदांता लिमि. का स्टर्लाइट कॉपर संयंत्र इस इकाई को स्थायी रूप से तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के अनुसार मई 2018 से बंद कर दिया गया है। इसका घरेलू कॉपर की खपत पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा जिसके बारे में यह अनुमान है कि यह पिछले 10 वर्षों में 5.9 प्रतिशत की एक चक्रवृद्धि वार्षिक औसत दर से बढ़ रहा है और यह भारत में संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति को भी प्रभावित नहीं करेगा।
- ध) इसके अलावा, वेदांता के कॉपर स्मेल्टर के बंद होने के समय से, दोनों आवेदकों ने अपनी कीमत निर्धारण नीति में ऊपर की ओर बहुगुणक कारक में 3.50 प्रतिशत से 5.00 प्रतिशत (43 प्रतिशत तक) संशोधन किया है। इस वृद्धि से प्रयोक्ता उद्योग पर अतिरिक्त कीमत दबाव पड़ा है।
- न) मौजूदा शुल्क संरचना और सरकार की नीतियां बड़े उत्पादकों के पक्ष में है जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र आयातों के कारण अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हुआ है। पिछले 4 वर्षों (पी यू आई) में ई ई और वायर एवं केबल के आयातों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आता है कि यह 32000 करोड़ भारतीय रुपए से अधिक हो जायेगा। कोई शुल्क लगाने के फलस्वरूप आगे इन उत्पादों के लिए कीमत हानि होगी। यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि संबद्ध वस्तुओं के अधिकांश प्रयोक्ता एम एस एम ई क्षेत्र हैं जो पहले से ही बहुत कम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहे हैं।
- प) भारत में उत्पादों की उपलब्धता के अभाव में, संबद्ध वस्तुओं का आयात भारत के बाहर से किया जायेगा और तदनुसार, आयातों में आगे वृद्धि होगी। सब्सिडीरोधी शुल्क लगाया जाने से उत्पादन प्रभावित होगा और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- फ) घरेलू उत्पादकों की अपनी कीमत में सीमा शुल्क वसूलने के लिए कीमत निर्धारण नीति एक बड़ा कारक भी है क्योंकि इन चार देशों से आयात ए आई एफ टी ए के अंतर्गत शुल्क मुक्त है और इस प्रकार से आयात किया गया वायर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है।
- ब) यह घरेलू उद्योग को उत्पादन प्रौद्योगिकी और कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए अनिच्छुक भी बना सकता है।
- भ) प्रमुख प्रवेशार्थी जैसे ट्राफिगुरा और अदानी द्वारा कॉपर वायर रॉड (कॉपर रॉड) खंड में नया निवेश आशावादी भावी परिदृश्य और आकर्षक पेयबैक का द्योतक है।
- म) याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किये गये प्रपत्र IV के अनुसार याचिकाकर्ता की क्षमता क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान अपरिवर्ती रहती है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष 2014-15 के दौरान 100 की तुलना में क्रमशः 106 और 103 हो गया है। इस प्रकार से, संबद्ध वस्तुओं से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को बिलकुल क्षति नहीं हो रही है।

- य) 2017-18 के दौरान, अनेक बड़े उत्पादकों ने स्थानीय उत्पादन के साथ आयात किये गये वायर रॉड को बदलने के उद्देश्य से नया उत्पादन लाइन संस्थापित करना शुरू कर दिया है। सर्वप्रथम हिन्डालकों की बिरला कॉपर यूनिट ने एक 240 केटीपीवाई वायर कोन्टीरॉड लाइन मार्च 2018 में आरंभ की गई थी और इसके फलस्वरूप 2017 की उसी अवधि में 79 केटी की तुलना में मार्च से सितंबर, 2018 की अवधि में हिन्डालकों के वायर रॉड उत्पादन में 110 केटी तक 39 प्रतिशत उछाल आया। दूसरा, हालोल, गुजरात राज्य में एक अन्य 240 केकेटीपीवाई वायर कोन्टीरॉड लाइन रायकर बेस प्राइवेट, स्थानीय भारतीय केबल निर्माता पोलीकेब वायर और ट्रेडिंग हाउस ट्राफिगुरा के बीच एक संयुक्त उद्यम में पिछले दिसंबर में आरंभ किया गया था। इस बीच ऐसा माना जाता है कि आगे 240 केटीपीवाई क्षमता कोन्टीरॉड लाइन 2018 के समाप्त होने के पूर्व वेदांता के सिलवासा संयंत्र में आरंभ किया जाना था, जो वर्ष के समाप्त होने के पूर्व आरंभ किया जायेगा।
- र) नई संस्थापित क्षमता के साथ, भारतीय वायर रॉड उद्योग समग्र भारतीय बाजार के मौजूदा आकार से बहुत अधिक नई वायर रॉड क्षमता का ऑन-स्ट्रीम 2018 में ला सकता है।
- ल) ये आवेदक पिछले तीन वर्षों से आदर्शतम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहे हैं। वास्तव में, हिन्डालको नियमित रूप से अपने रॉड उत्पादन के हिस्से को अन्य से आउटसोर्स करता रहा है क्योंकि उनके पास अपने केथोड्स को रॉड में प्रसारित करने की क्षमता नहीं है।
- व) कॉपर वायर रॉड (कॉपर रॉड) की संयुक्त संस्थापित क्षमता जांच की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 400,000 मी. ट. (हिन्डालको : 150,000 मी. ट. और वेदांता : 250,000 मी. ट.) है। हिन्डालको अपनी निजी क्षमता समाप्त होने के कारण "कॉपर वायर रॉड्स " उत्पादन की बहुत अधिक मात्रा की आउटसोर्सिंग नियमित रूप से करता रहा है।
- श) याचिकाकर्ताओं ने पहले ही 240,000 मी. ट. की परियोजनाओं की घोषणा की है जिसके फलस्वरूप उनकी मौजूदा क्षमताओं के दुगने से अधिक उत्पादन होगा। हिन्डालको ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2019 की पहली तिमाही में अपनी नई "कॉपर वायर रॉड्स " क्षमता आरंभ की है जबकि आशा है कि वेदांता की परियोजना शीघ्र ही आरंभ की जायेगी (यदि पहले आरंभ नहीं किया गया हो)।
- ष) आवेदक एकीकृत सीमा स्मेल्टर्स हैं और वे अपने कच्चे माल के रूप में कॉपर संकेंद्रण और अप्रसंस्कृत कॉपर (बिल्टर कॉपर, कॉपर एनोड और कॉपर स्क्रैप) का उपयोग करते हैं। उन पर उन्हें अपने कच्चे माल के आयातों पर सीमा शुल्क का लगभग शून्य प्रभावी दर मिलता है। दोनों आवेदक अपने मुख्य इनपुट्स प्रमुख रूप से (कॉपर संकेंद्रण और अपरिष्कृत कॉपर) एफ टी ए/ पी टी ए/ एल डी सी देशों से प्राप्त करते हैं।
- स) आवेदकों का मुख्य जोड़ कॉपर केथोड और कॉपर रॉड की बिक्री करने पर है। इसके फलस्वरूप आवेदकों के राजस्व का 95 प्रतिशत से अधिक केवल इन दो उत्पादों से है।
- ह) याचिकाकर्ता की बिक्री मात्रा आधार वर्ष 2014-15 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लगभग वही रहती है। जैसा कि ऊपर में दर्शाया गया है, याचिकाकर्ताओं की निर्यात बिक्री मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष 2014-15 के दौरान 100 से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 1138 हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता केवल निर्यात पर जोर दे रहा है और वह भी अपनी पसंद के अनुसार न कि संजोग से और यह भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर जोर नहीं दे रहा है।
- क्ष) मैसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमि. की बिक्री की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान 35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इसके अलावा, इन आवेदकों के दावे के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान इन आवेदकों की बिक्री की मात्रा स्थिर रही है। याचिकाकर्ताओं की बिक्री की मात्रा आधार वर्ष 2014-15 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लगभग

- वही रहती है। जैसा कि ऊपर में दर्शाया गया है, इन याचिकाकर्ताओं की निर्यात बिक्री मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष 2014-15 के दौरान 100 से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 1138 हो गयी है।
- त्र) औसत भंडार को अलग से नहीं देखा जायेगा। केवल औसत भंडार का कोई अर्थ नहीं है, इसे बिक्री अथवा उत्पादन के साथ संबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने वह उपलब्ध नहीं कराया है।
- ज) याचिकाकर्ता सतत रूप से प्रत्येक तिमाही के अंत में कॉपर वायर रॉड (कॉपर रॉड) के लिए “शून्य” माल भंडार बनाये रख रहे हैं। इस कारण से, माल भंडार वह कारक नहीं है जिसके कारण याचिकाकर्ता उद्योग को क्षति हो रही है।
- कक) विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की लागत में अचानक और पर्याप्त वृद्धि हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य कारक हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और जिसके फलस्वरूप बिक्री की लागत अधिक हो गई है।
- खख) कीमत में कटौती निर्धारण का आधार नहीं देता है और इसे अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। इसे घरेलू उद्योग के समग्र कार्यनिष्पादन के आलोक में देखा जाना है, चाहे इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही हो। वर्तमान मामले में, संबद्ध देशों से कीमत में कटौती 2014-15 और 2015-16 के दौरान नकारात्मक थी और 2016-17 एवं जांच की अवधि के दौरान मामूली रूप से सकारात्मक थी।
- गग) यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि आयात की कीमत (सी आई एफ मूल्य का उपयोग करते हुए) की गणना इसकी तुलना घरेलू कीमत से किये जाने से पहले उसी स्तर की स्थिति को प्राप्त करने के लिए रख-रखाव शुल्क और अन्य प्राथमिक सीमा शुल्कों को जोड़कर किया जाना है।
- घघ) इसके अलावा, भारत में इण्डोनेशिया का निर्यात केवल कॉपर वायर को शामिल करता है जिसका व्यास 2.6 एमएम से 1.6 एमएम है जो 8 एमएम से अधिक व्यास वाले कॉपर रॉड जिसका उत्पादन याचिकाकर्ताओं द्वारा किया जाता है, से अलग है। कॉपर वायर में आगे कॉपर रॉड से प्रक्रिया लेनी पड़ती है। अतः कॉपर वायर रॉड की घरेलू बिक्री कीमत की तुलना आयात किये गये कॉपर वायर की लागत से करने के लिए यह अनुचित है और आर्थिक रूप से न्यायोचित नहीं है।
- ङङ) कीमत में कटौती और पी वी आई टी के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। कीमत में कटौती क्षति की अवधि के दौरान प्रायः उसी सीमा में है, हालांकि, वर्ष 2016-17 और जांच की अवधि के दौरान पी वी आई टी में बहुत अधिक गिरावट आई है।
- चच) ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य कारक हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। पी वी आई टी में इस प्रकार की गिरावट अन्य उत्पादों में अंतरों का परिणाम हो सकता है और यह विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं हो सकता है।
- छछ) वेदांता और हिन्डालको के ई वी आई टी डी ए ने किसी कटौती को खानों से कटौती की गई टी सी आर सी (अपेक्षाकृत महंगा इनपुट्स) और उत्पादन की बड़ी हुई लागत को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका संबद्ध देशों की आयातों से कोई संबंध नहीं है। हिन्डालको की वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित विषय को नीचे फिर से प्रस्तुत किया जाता है : “प्रतिकूल संकेद्रण बाजार के फलस्वरूप लगातार दूसरे वर्ष के लिए निर्धारित टी सी आर सी मूल्य में गिरावट आई है . . .”
- जज) कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान 100 (2014-15) से जांच की अवधि के दौरान 89 हो गई है, हालांकि, वेतन और मजदूरी में आधार वर्ष 2014-15 के दौरान 100 से बहुत अधिक वृद्धि होकर जांच की अवधि के दौरान 130 तक पहुंच गयी है।

- झ) संबद्ध आयातों और याचिकाकर्ता के कार्यनिष्पादन के बीच कारणात्मक संबंध का उल्लंघन हुआ है। यह आवश्यक है कि अन्य संभावित कारकों जिसके कारण याचिकाकर्ता को क्षति हुई कि विस्तृत जांच की जाये।
- ञ) यह अनुरोध किया जाता है कि क्षति और कारणात्मक संबंध की गणना के लिए, संबद्ध आयातों के क्षतिकारक प्रभावों को अन्य कारकों जिसके कारण क्षति हुई है, से एस सी एम करार के अनुच्छेद 15.5 और सविसडीरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के अनुसरण में अलग किया ही जाना चाहिए।
- ट) याचिकाकर्ताओं ने यह उल्लेख नहीं किया है कि अन्य देशों से सतत् कास्ट कॉपर वायर रॉड के आयातों जो सीधे तौर पर उनके उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, के कारण भी उन्हें क्षति हो रही है।

क्र. सं.	देश	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
	संयुक्त अरब अमीरात	40,031	69,195	71,067	63,854
	रूस	29,286	50,999	12,400	133
	अन्य	10,945	13,979	25,587	16,829
	कुल आयात	80,262	134,173	109,054	80,817

- ठ) यू ए ई से आयात किसी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक है। आयातों में इस प्रकार की अत्यधिक वृद्धि का कारण यह है कि यू ए ई से प्रमुख निर्यात फूजेराह गोल्ड द्वारा किया जाता है, जो याचिकाकर्ताओं में से एक वेदांता ग्रुप की स्वामी वाली कंपनी है। फूजेराह गोल्ड की वेबसाइट में यह उल्लेख है कि :
- “फूजेराह गोल्ड एफ जेड सी फूजेराह फ्री जॉन II, फूजेराह, संयुक्त अरब अमीरात में रणनीतिक रूप से स्थित एक बहुमूल्य धातु रिफायनरी और एक सतत् कास्ट कॉपर रॉड संयंत्र चलाता है। फूजेराह गोल्ड एफ जेड सी जिंक, लेड, सिलवर, कॉपर, आयरन ऑर, एल्मुनियम, पावर और ऑयल एंड गैस में हितों के साथ वेदांता रिसोर्सेस टी एल सी का वैश्विक रूप से विधिकृत प्राकृतिक संसंधान कंपनी का एक हिस्सा है।*
- ड) यह स्पष्ट है कि फूजेराह गोल्ड संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में शामिल है।
- ढ) प्रमुख आयात वेदांता ग्रुप द्वारा किये जा रहे हैं और यही कारण है कि उसे आयातों में अधिक हिस्सा होने के बावजूद संबद्ध देशों में शामिल नहीं किया गया था।
- ण) याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर संबद्ध देशों की सूची से यू ए ई को हटा दिया है।
- त) यू ए ई से आयातों को शामिल करना क्षति के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, घरेलू उद्योग ने पूर्णरूप से उसकी उपेक्षा की है। यू ए ई को बाहर रखने का कारण इस याचिका में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
- थ) रूस से आयातों में उनके देश में नीतिगत परिवर्तन के कारण रुकावट आई है। 2018-19 में यू ए ई से आयात लगभग 75,000 मी. ट. होने की आशा है जो भारत में संबद्ध देशों से निर्यातों से अधिक है।
- द) यह स्मरण किया जाये कि घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के समक्ष अपनी प्रस्तुति में कार्यनिष्पादन में उनकी कथित गिरावट के लिए कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था।
- ध) यह तर्क दिया गया था कि घरेलू उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का मूल केंद्र भारत-आशियान एफ टी ए में पाया गया है। यह उल्लेख किया गया था कि एफ टी ए देशों से आयातों में वृद्धि हुई क्योंकि सीमा शुल्कों में कमी आई। यह सुझाव दिया गया था कि भारत सरकार को संभवतः इसे एक मामले के अध्ययन के रूप

- में लेना चाहिए ताकि भारत की सरकार द्वारा हस्ताक्षर किये गये एफ टी ए के गंभीर नकारात्मक प्रभावों की जांच की जा सके। उसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि कथित क्षति का प्रमुख और आवश्यक तत्व एफ टी ए है।
- नन) घरेलू उद्योग ने माननीय प्राधिकारी के समक्ष यह भी तर्क दिया कि निवेशों के स्तर उस पर निर्भर करते हुए जहां यह उत्पाद उस उत्पादन शृंखला में स्थित है, भयानक रूप से अलग अलग है। यह भी स्वीकार किया गया था कि “कॉपर वायर रॉड्स” का कीमत निर्धारण कॉपर की एल एम ई कीमतों पर निर्भर है और बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है जो दैनिक आधार पर अथवा दिन के दौरान अनेकों बार भी अलग अलग हो सकता है। इस कारण से यह संभव नहीं है कि घरेलू उद्योग के लिए सब्सिडीरोधी मामला विकसित किया जाये।
- पप) हमारे अनुरोध के संबंध में बिना की पूर्वाग्रह के कि क्षति के उनके दावे के समर्थन में समग्र सूचना/ आंकड़े भ्रामक और असंगत हैं, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि कथित क्षति अन्य कारकों के कारण हुई है जो संबद्ध वस्तुओं के कथित सब्सिडी दिये जाने से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति होने पर निवेदनपूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी केवल इसी आधार पर जांच को समाप्त कर सकते हैं।
- फफ) इसके अलावा, आवेदकों ने करार किया है जिसमें बिक्री कीमत का निर्धारण वर्तमान एल एम ई कॉपर कीमत के आधार पर किया गया था और इन वस्तुओं की आपूर्ति भविष्य में (“भावी संविदा”) की जानी थी।
- बब) संविदाओं का उपर्युक्त रूप अर्थात् फोरवर्ड संविदा और भावी संविदा इन पक्षकारों को जोखिम की हेजिंग करने की अनुमति देता है। इन संविदाओं के अंतर्गत क्रेता जो भावी कीमत में वृद्धि की आशा करता है संबद्ध वस्तुओं की खरीद वर्तमान कीमतों पर कर सकता है और भविष्य में वस्तुओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित कर सकता है। तदनुसार, ऐसा करार करके, क्रेता भावी कीमत में वृद्धि का जोखिम मामूली प्रीमियम की लागत पर विक्रेता (आवेदकों) को अंतरित करता है।
- भभ) चूंकि आवेदकों ने भावी संविदा की है अतः यह संभव है कि संबद्ध वस्तुओं की कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के पहले किया जाये और इन वस्तुओं की सुपुर्दगी जांच की अवधि के दौरान की जाये। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान इनपुट्स सामग्री की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है (2016-17 के दौरान 2.3/एलबी यू एस डॉलर से जांच की अवधि के दौरान 3.2/एलबी यू एस डॉलर) और इस कारण से यह संभव है कि आवेदकों को हानि हुई थी क्योंकि वे संबद्ध वस्तुओं की बिक्री घटा उठाकर अथवा उपयुक्त मार्जिन से कम पर जांच की अवधि से पूर्व की गई भावी संविदाओं का पालन करते हुए बिक्री करने के लिए बाध्य थे। उपर्युक्त वास्तविक परिस्थितियों के अंतर्गत और सी वी डी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 2 (1) के संबंध में प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे फोरवार्डिंग संविदाओं, भावी संविदाओं और अन्य कारकों जिसने उसी समय आवेदकों के आर्थिक मानदंडों को प्रभावित किया है, के प्रभाव का समायोजन करें।
- मम) संस्थापित क्षमता क्षति की समग्र अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है हालांकि नियोजित पूंजी में आधार वर्ष 2014-15 के दौरान 100 से बहुत अधिक बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 121 हो गई है।

ज. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

515. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किये गये विभिन्न निवेदनों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण वास्तव में याचिकाकर्ताओं और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये निवेदनों पर विचार करता है।
516. सब्सिडी नियमावली के नियम 13 में क्षति के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों की चर्चा की गई है जो नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान करता है :

13. क्षति का निर्धारण -

- (1) उल्लिखित देशों से आयातों के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष देंगे कि भारत में इस प्रकार की वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति होने का खतरा उत्पन्न होता है अथवा वास्तविक रूप से भारत में किसी उद्योग की स्थापना को बाधा पहुंच रही है।
- (2) केवल उस स्थिति को छोड़कर जब क्षति का जांच परिणाम उप-नियम (3) के अंतर्गत किया जाता हो, निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति, क्षति के खतरे, किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से बाधा और सब्सिडीयुक्त आयात तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण अन्य बातों के साथ साथ इस नियमावली के अनुबंधा निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखकर करेंगे।
- (3) आपवादिक मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह जांच परिणाम हो सकता है कि क्या क्षति की मौजूदगी वहां भी भी जहां घरेलू उद्योग को बहुत अधिक मात्रा में क्षति नहीं हुई है यदि -
 - (i) सब्सिडीयुक्त आयातों का अलग किये गये बाजार में संकेंद्रण है, और
 - (ii) सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण इस प्रकार के बाजार में प्रायः सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति हो रही है।

I. सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. मांग का आकलन

517. भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी अन्य देशों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
2	अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
3	संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	15,357	46,650	83,912	1,23,439
4	अन्य देशों से आयात	मी. ट.	79,957	89,827	76,358	63,647
5	कुल मांग	मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	120	122	125

ii. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और हिस्सा

518. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना सब्सिडीयुक्त आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	संबद्ध देश					
क	इण्डोनेशिया	मी. ट.	4,093	11,065	22,534	25,714
ख	मलेशिया	मी. ट.	10,841	27,473	32,137	46,328
ग	थाइलैंड से सब्सिडीकृत आयात	मी. ट.	***	***	***	***
ग.1	थाइलैंड से गैर सब्सिडीकृत आयात	मी. ट.	***	***	***	***
घ	वियतनाम	मी. ट.	20	4,015	16,096	32,035
2	संबद्ध देशों से कुल सब्सिडीकृत आयात	मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	301	493	712
2.1	संबद्ध देशों से कुल सब्सिडीकृत आयात	मी. ट.	-	434	8144	14,162
3	अन्य देश	मी. ट.	79,957	89,827	76,358	63,647
4	कुल	मी. ट.	95,314	1,36,477	1,60,270	1,87,086

519. यह देखा गया है कि :

- क. आधार वर्ष से जांच की अवधि में संबद्ध देशों से सब्सिडीकृत आयातों की संपूर्ण मात्रा में 612 प्रतिशत तक बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- ख. इन सब्सिडीकृत आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में *** प्रतिशत से *** प्रतिशत तक तेजी से वृद्धि हुई है।
- ग. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और आयातों का हिस्सा देश की मांग के *** प्रतिशत से बढ़कर *** प्रतिशत तक हो गया।

II. संबद्ध आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

520. कीमतों पर सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत से तुलना किये जाने पर सब्सिडीयुक्त आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक कीमतों में कमी होगी अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी, जो काफी हद तक अन्य प्रकार से हुआ होता।

iii. कीमत में कटौती

521. कीमत में कटौती जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करते हुए कीमत में कटौती का निर्धारण किया गया है। कीमत में कटौती का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक पी सी एन के लिए पृथक रूप से किया गया है और इसके पश्चात् विचाराधीन उत्पाद के लिए संपूर्ण रूप में किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	74081190	74081990	भारित औसत
1	इंडोनेशिया				
क	पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	-	4,38,937	4,38,937
ख	निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	-	***	***
ग	कीमत कटौती	रू./मी.ट.	-	***	***
घ	कीमत कटौती	%		***	***
	रेंज	%		0-5	0-5
2	मलेशिया				
क	पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	4,35,641	4,52,487	4,52,449
ख	निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***
ग	कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***
घ	कीमत कटौती	%	***	***	***
	रेंज	%	0-5	0-5	0-5
3	थाइलैंड				
क	पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	-	4,39,784	4,39,784
ख	निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	-	***	***
ग	कीमत कटौती	रू./मी.ट.	-	***	***
घ	कीमत कटौती	%		***	***
	रेंज	%		0-5	0-5
4	वियतनाम				
क	पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	-	4,28,243	4,28,243
ख	निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	-	***	***

क्र. सं.	विवरण	इकाई	74081190	74081990	भारित औसत
ग	कीमत कटौती	रू./मी.ट.	-	***	***
घ	कीमत कटौती	%		***	***
	प्रवृत्ति	%		5-10	5-10
5	संबद्ध देश समग्र रूप में				
क	पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	4,35,641	4,41,343	4,41,338
ख	कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***
	रेंज	%	0-5	0-5	0-5

522. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

iv. कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन

523. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमतों का निर्धारण किया है और उसकी तुलना आयात किये गये वस्तुओं के पहुंच मूल्य से की है ताकि कम कीमत पर बिक्री की सीमा तय की जा सके। कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण प्रत्येक पी सी एन के लिए पृथक् रूप से और उसके पश्चात् विचाराधीन उत्पाद के लिए संपूर्ण रूप में किया गया है।

524. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है और यह दर्शाती है कि बाजार में आयात क्षति कारक कीमतों पर हुई है।

525. सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का मूल्यांकन नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

देश	उत्पादक	पी सी एन	एन आई पी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
			अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	%	रेंज
इंडोनेशिया	पीटी. कारया सुमिदेन इण्डोनेशिया	पी5	***	***	***	***	5-10%
	पीटी. तेमबगा मुलिया सेमनन	पी5	***	***	***	***	0-5%
	अन्य	पी5	***	***	***	***	5-10%
वियतनाम	सभी उत्पादक	पी5	***	***	***	***	5-10%
थाइलैंड	एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर	पी5	***	***	***	***	0-5%

	कंपनी लिमिटेड						
	अन्य	पी5	***	***	***	***	5-10%
मलेशिया	मेट्रॉड मलेशिया एसबीएन बीएचडी			***	***	***	0-5%
	74081190	पी3	***	***	***	***	0-5%
	74081990	पी5	***	***	***	***	0-5%
	पेनासोनिक प्रोक्यूमेंट मलेशिया एसबीएन बीएचडी	पी5	***	***	***	***	0-5%
	मेट्रॉड + पेनासोनिक			***	***	***	0-5%
	अन्य	पी5	***	***	***	***	10-15%

526. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में सीएफटी विना कॉपर कंपनी लिमिटेड के लिए उन्हें असहयोगी पक्षकार माने जाने के बावजूद उपर्युक्त क्षति मार्जिन तालिका में अलग क्षति मार्जिन गलत दिया गया था। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में सुधारात्मक उपाय किया है। चूंकि वियतनाम में किसी भी पक्षकार को सहयोगी पक्षकार नहीं माना गया है, अतः प्राधिकारी ने अपनी सतत परिपाटी के अनुसार वियतनाम से कुल आयातों के आधार पर वियतनाम के सभी उत्पादकों/निर्यातकों का क्षति मार्जिन परिकलित किया है।

v. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

527. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की आयातों के प्रभाव से कीमतों ने बहुत अधिक हद तक कमी आयेगी और कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से हुई होती। प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयातों की पहुंच कीमत और लागत एवं कीमतों में परिवर्तन की जांच की है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
1	बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	86	104
3	बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	86	101
5	पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***

6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	83	99
---	-----------	----------	-----	----	----	----

528. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत दोनों में वृद्धि हुई है। हालांकि, बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री की लागत में वृद्धि से कम है। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योगों की बिक्री कीमत से कम है। यह दर्शाता है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं और कीमत में वृद्धि रुक रही है जो अन्य प्रकार से हुई होती।

III. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

529. इस नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर इन आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; वे कारक जो घरेलू कीमतें, नकदी के प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच क्षति के अवधि के दौरान की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग एवं बिक्री

530. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग एवं बिक्री के संबंध में क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
1	क्षमता	मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	100	118	118
2	उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	106	99	106
3	क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	104	80	87
4	घरेलू बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	105	99	99
5	निर्यात बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	87	169	1039

531. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि —

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है और 2016-17 से आगे काफी क्षमता अप्रयुक्त रही है।
ख. उद्योग के उत्पादन में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की घरेलू कीमतों में गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग के निर्यात में जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ii. बाजार का हिस्सा

532. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	बाजार शेयर	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
	रेंज		30-40	30-40	20-30	20-30
2	अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
	रेंज		40-50	40-50	40-50	30-40
3	संबद्ध देशों से सब्सिडीकृत आयात	%	***	***	***	***
	रेंज		0-10	0-10	10-20	15-25
3.1	अन्य देशों से गैर सब्सिडीकृत आयात		***	***	***	***
	रेंज		-	0-10	0-10	0-10
4	अन्य देश	%	***	***	***	***
	रेंज		10-20	10-20	10-20	10-20
5	कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

533. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई है जबकि संबद्ध देशों के आयात के हिस्से में वृद्धि हुई है। अन्य देशों से आयात के हिस्से में भी गिरावट आई है।

iii. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ

534. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभ की स्थिति नीचे दिये गये अनुसार थी :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***

2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	86	104
3	बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	86	101
5	लाभ/ (हानि)	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	96	64
7	लाभ/ (हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	95	63
9	पी बी आई टी	रु. लाख	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	99	68
11	नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	96	66
13	आर ओ सी ई	%	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	रेंज	25-35	30-40	25-35	15-25

535. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

क. घरेलू उद्योग के लाभ में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है।

ख. घरेलू उद्योग, नकद, पी बी आई टी और नियोजित पूंजी पर लाभ की वही प्रवृत्ति रही है।

iv. माल भंडार

536. संबद्ध वस्तुओं के माल भंडारों के संबंध में आंकड़े नीचे दिये गये अनुसार हैं :

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
1	औसत भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	443	325	461

537. यह नोट किया जाता है कि औसत भंडार ने 2016-17 में कुछ गिरावट को छोड़कर इस अवधि में वृद्धि हुई है।

v. रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

538. क्षति की अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
1	मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	111	119
3	रोजगार	सं.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	73	72
5	उत्पादकता प्रति दिन	मी. ट./ दिन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	100	106
7	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	प्रति सं.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	137	147

539. यह देखा गया है कि मजदूरी और प्रति कर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि के साथ क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

vi. वृद्धि

540. घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभ के मानदंडों की प्रवृत्ति ने नीचे दिये गये अनुसार दर्शाया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	उत्पादन	%	-	6%	-6%	6%
2	घरेलू बिक्री	%	-	5%	-6%	0%
3	लाभ प्रति इकाई	%	-	21%	-20%	-33%
4	प्रति इकाई नकद लाभ	%	-	21%	-19%	-31%
5	नियोजित पूंजी पर लाभ	%	-	19%	-23%	-36%

541. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हुई है, घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के

बाजार हिस्से में गिरावट आई है। लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ में भी क्षति के अवधि के दौरान गिरावट दर्शायी है।

vii. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक

542. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती रही है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति के अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में कमी आई है। यह दर्शाता है कि आयात कम कीमतों पर बाजार में पहुंच रहे हैं।

viii. पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

543. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने पूंजी निवेश करते हुए इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता में वृद्धि की है। हालांकि, मांग में वृद्धि के बावजूद, ये क्षमताएं पर्याप्त रूप से कम उपयोग किये हुए रही हैं।

544. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों ने वृद्धि को दर्शाया है। हालांकि, कीमत मानदंडों में गिरावट रही है। लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट दर्शायी है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

IV. क्षति संबंधी निष्कर्ष

545. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और इसका घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है। जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम है। यद्यपि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में केवल उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग के मामले में सुधार आया है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को कम उपयोग की गई क्षमताओं के कारण हानि हो रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है और इसका नकद लाभ, पी बी आई टी और निवेश पर लाभ की वही प्रवृत्ति रही है। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

V. कारणात्मक संबंध

546. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को नीचे दिये गये अनुसार क्षति हो सकती थी :

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

547. अन्य देशों से आयात संबद्ध देशों से सब्सिडीकृत आयात और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

ख. मांग का संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

548. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके विपरीत, संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग में क्षति की अवधि के दौरान सुधार देखा गया है। इसके अलावा, खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ग. विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यप्रणाली और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

549. कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

550. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी में किसी परिवर्तन को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ङ. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्यनिष्पादन

551. क्षति से संबंधित सूचना पर घरेलू और निर्यात के लिए उस सीमा तक पृथक् रूप से विचार किया गया है जिस सीमा तक उसे अलग किया जा सकता है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन

552. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में केवल आंकड़ों पर ही विचार किया है।

VI. कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

553. प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार नोट करते हैं :—

- क. संबद्ध देशों से सब्सिडीकृत आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।
- ख. संबद्ध देशों से सब्सिडीयुक्त आयात भारत में बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं।
- ग. इन आयातों के कारण घरेलू उद्योगों की कीमतों में कटौती हो रही है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है क्योंकि इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा है और इससे कीमतों में वृद्धि रुक गई जो अन्य प्रकार से हुई होती।
- घ. घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में कीमत में सकारात्मक कटौती के कारण गिरावट आई है।
- ङ. घरेलू उद्योग पर सब्सिडीयुक्त आयातों के परिणामी प्रभाव कम हुए क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, लाभप्रदता, आ ओ सी ई आदि के संदर्भ में काफी प्रतिकूल रहे हैं।

554. इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध वस्तुओं को सब्सिडी दिये जाने और घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

ट. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

555. प्राधिकारी ने अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणी आमंत्रित करते हुए 21 अक्टूबर, 2019 को एक प्रकटन विवरण जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात् अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उठाए गए अधिकतर मुद्दों को पहले ही पूर्व में उठा दिया गया है और उनका उपयुक्त रूप से समाधान भी कर दिया गया है। संगत मानी गई सीमा तक अतिरिक्त अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है :—

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध :

घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख करते हुए अपने अनुरोधों को दोहराया है कि :

- आयात आंकड़े और घरेलू उद्योग के आंकड़े पूर्णतः 7408 के तहत कॉपर वायर से संबंधित हैं। कॉपर वायर रॉड एक उद्योग शब्दावली है और वायर रॉड का प्रयोग 7407 के तहत आने वाले कॉयल रूप में रॉड के लिए शब्दावली के रूप में किया जाता है और वे स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका के क्षेत्र के अंतर्गत कॉयल रूप में रॉड को शामिल नहीं किया।
- सीमा प्रशुलक अधिनियम केवल वॉयर और रॉड को शब्दावली के रूप में प्रयुक्त करता है और वॉयर में उसमें डॉयमीटर का कोई प्रतिबंध नहीं है।
- 6 एमएम से अधिक अथवा कम की वायर, सभी अंतिम प्रयोग की आवश्यकताओं के लिए आगे ली जाती हैं। यह 0.19-0.20 एमएम तक की वॉयर है जो कि अंतिम उत्पाद है।

- वेदांता ने क्षति संबंधी सूचना नहीं दी है क्योंकि उसे आयातों के आधार पर अपात्र माना गया है परंतु यह वास्तविकता है कि वेदांता को भी क्षति हुई है।
- घरेलू उद्योग पूरी मांग को पूरा कर सकता है क्योंकि 6 एमएम. से कम की वायर के लिए संस्थापित क्षमताएं 6.6 लाख मी.टन की स्थापित मांग के रूप 11.33 लाख मी.टन के क्षेत्र में हैं।
- प्राधिकारी ने सही निर्धारित किया है अल्फा, डोविना, सीएफटी को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक नहीं माना जा सकता और इन पक्षकारों के लिए अलग से कोई सब्सिडी मार्जिन निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।
- संबद्ध देशों में उत्पादक इंडोनेशिया से खरीदे गए 8 एमएम से अधिक के सब्सिडीयुक्त कैथोड अथवा वायर से लाभान्वित हुए हैं और इंडोनेशिया से संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा खरीदे गए सभी इनपुटों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- चूंकि मूल देश के अधिमान्य नियम सी वी डी जांच पर लागू नहीं होते, अतः उत्पादकों ने दावा किया है कि सामान तब भी थाइलैंड, वियतनाम अथवा मलेशिया से खरीदे गए हैं जब इनपुट इंडोनेशिया से लिए जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इन उत्पादकों ने यह भी स्वीकार किया है कि आंशिक उत्पादन क्रियाकलाप इंडोनेशिया में हुए हैं। इंडोनेशिया में उत्पादक इन उत्पादकों द्वारा उपभोग किए गए इनपुट में प्राप्त खनन की सब्सिडियों से लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार, इंडोनेशिया से प्राप्त किए गए इनपुट में सब्सिडी लिए जाने की आवश्यकता है और थाइलैंड, वियतनाम और मलेशिया से निर्यातित उत्पाद में सब्सिडी में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।
- वियतनाम सरकार और वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर को इन तथ्यों को छिपाने के लिए रद्द किया जाना चाहिए कि उत्पादकों ने घरेलू खनन से खरीदे गए कैथोड आंशिक रूप से बाहर से लिए हैं।
- इंडोनेशियाई योजनाओं के संबंध में प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें कि कोयले की बिक्री कीमत की कैपिंग के कारण और इंडोनेशिया सरकार द्वारा लागू किए गए अन्य उपायों के कारण पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर इन उत्पादकों को बिजली दी जा रही है।
- प्राधिकारी ने कार्यक्रम सं. 2, 3 और 5 के तहत अन्य इंडोनेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों को इंडोनेशिया में अधिमान्य उधार के लिए अलग मार्जिन दिया है परंतु संबद्ध सामानों के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों दोनों के लिए वह लागू किया जाना चाहिए क्योंकि उधार की दरें प्राथमिक उधार दर से काफी कम हैं।
- इंडोनेशिया के कार्यक्रम सं. 10,11,15,17,18,19 के तहत आयकर लाभों के लिए अन्य इंडोनेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों पर अलग मार्जिन लगाए जाते हैं और वही दोनों उत्तरदाता कंपनियों पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं का विश्वास है कि दोनों उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक रियायती दरों पर आयकर दे रहे हैं।
- इंडोनेशिया का कार्यक्रम सं. 14 अर्थात् “आयात पर आयकर की छूट” अलग सब्सिडी योजना है जिसे आयात शुल्क छूट में नहीं मिलाया जाना चाहिए। यह योजना पी एम के 147/04.2011 के अनुच्छेद 14 के तहत 2.5 प्रतिशत के आयकर की छूट देती है। दोनों कंपनियों पर पृथक रूप से शुल्क लगाया जाना चाहिए।
- मलेशिया के कार्यक्रम सं. 33 भी प्रतिकारयोग्य सब्सिडी है।
- प्राधिकारी कृपया अन्य प्राधिकारी के जांच परिणामों पर विचार करें और कम से कम असहयोगी उत्पादकों के लिए मलेशिया में सीवीडी मार्जिन निर्धारित करने हेतु उनके मार्जिन पर विचार करें।
- मलेशियाई योजना/कार्यक्रम सं. 16 अर्थात् “संयंत्र एवं मशीनरी/ कैपिटल एलाउंस (सीए),” उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक, अल्फा इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी, मैट्रोड ओएफएचसी और मैट्रोड मलेशिया ने लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। आईटीए की अनुसूची-3 और पीयू (ए) 52/2000 में संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ते की प्रतिशतता 20 प्रतिशत आरंभिक भत्ता और 14 प्रतिशत वार्षिक भत्ता शामिल है और उस देश में प्रतिकार योग्य लाभ प्रदान करता है जिसमें प्राधिकारी ने माना है।

- मलेशियाई योजना और कार्यक्रम सं. 9 अर्थात् “पायनियर स्टेट्स” आयकर छूट प्रदान नहीं करता बल्कि अन्य प्रोत्साहन भी देता है। प्राधिकारी को अन्य प्राधिकारी के सीवीडी मार्जिन पर विश्वास करते हुए अवशिष्ट श्रेणी में पुनः मार्जिन निर्धारित करना चाहिए।
- थाइलैंड की योजनाओं/कार्यक्रम सं. 13 और 14 निवेश बोर्ड (बीओआई) द्वारा दिए गए गैर-कर प्रोत्साहन हैं और विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां पात्र हैं। चूंकि एस टीईसी एक विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी है और वे बीओआई के अनुसार, मानदंड पूरा करते हैं, अतः वे इन योजनाओं के तहत कर प्रोत्साहनों के अलावा लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस योजना के तहत सीवीडी मार्जिन निर्धारित करें।
- एसटीईसी ने स्वीकार किया है कि प्राधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि एसटीईसी को जांच अवधि के दौरान हानियां हुई हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कंपनी के पिछले रिकॉर्ड की जांच करें। निरंतर हानियों की स्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यातक की हानियों को किसी अन्य कंपनी द्वारा समाविष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार हानियों पर निर्यात और हानियों पर बिक्री का अभिप्राय पाटन की मौजूदगी है। प्राधिकारी कृपया थाइलैंड से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच स्व-विवेक से शुरू करें। यही दृष्टिकोण विगत में प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया था।
- एसटीईसी सुमितोमो इलैक्ट्रिक, जापान की एक सहायक कंपनी है और इसकी पूरी तरह से संभावना नहीं है कि उसे हानियां हो रही हैं जब तक कि वे कम प्रीमियम/कीमतों पर बिक्री अथवा सामान का अंतरण न कर रहे हों। सूचना यह दर्शाती है कि शुरुआत से ही निरंतर हानियों के उनके दावों के विपरीत कंपनी लाभ में रही है और वे लाभ बढ़ते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने आशियान से बाहर से भी कच्ची सामग्री ली है।
- वियतनाम में प्राधिकारी को दो कार्यक्रमों (i) “एसबीवी के तहत ब्याज दर सहायता कार्यक्रम” जिसके संबंध में प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर जांच शुरू की थी, और (ii) “नियत परिसंपत्ति सृजित करने के लिए उपस्करों और मशीनरी के लिए आयात कर छूट”, जैसा कि जीओवी द्वारा अपनी प्रश्नावली के उत्तर में प्रकट किया गया है, पर विचार करना चाहिए। इस याजना की जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा विगत में मानी गई है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विगत जांच परिणाम पर विश्वास करते हुए इस योजना की जांच करें और तदनुसार, सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करें।
- प्राधिकारी ने यह सही-सही निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग को सब्सिडीयुक्त आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है। पर्याप्त मांग के बावजूद 8 एमएम से कम के वायर के लिए पूरी तरह से कम उपयुक्त उत्पादन क्षमताएं, पर्याप्त कीमत कटौती और क्षति मार्जिन सामूहिक रूप से और संचयी रूप से यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- सब्सिडी शुल्क यथा मूल्य आधार पर निर्धारित किए जाने पर (क) निरंतर आधार पर एलएमई में परिवर्तन, (ख) दो पीसीएन की मौजूदगी, (ग) सी वी डी मार्जिन के कारण सीआईएफ कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त यथामूल्य आधार पर ही लगाया जाए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :

- प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में भिन्न विचाराधीन उत्पाद प्रस्तावित किया है अर्थात् “सीमा प्रशुल्क के प्रशुल्क शीर्ष 7408 के तहत आने वाला सतत कास्ट कॉपर वायर” जो जांच की शुरुआत की सूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद से भिन्न है। विचाराधीन उत्पाद के प्रस्तावित क्षेत्र से जांच का क्षेत्र बड़ा हो गया है। उत्पाद को कम मानने में प्रस्तावित परिवर्तनों से उसके क्षेत्र का बढ़ना कानून के प्राधिकार के बिना है।

- प्रकटन विवरण से उत्तरदाता उन पक्षकारों को सुनिश्चित करने में असमर्थ है जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है। संयोगवश सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण देर से 25.10.2019 को किया जाना ऐसी कोई सूचना नहीं दर्शाता।
- मैट्रोड ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी द्वारा पीसीएन शुरू करने के लिए 05 अप्रैल, 2019 के उनके पत्र में दिए गए स्पष्टीकरण पर उनकी टिप्पणियों और अन्य टिप्पणियों पर प्रकटन विवरण में बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।
- “कॉपर वायर रॉड” और “कॉपर वायर” पूर्णतः दो भिन्न उत्पाद हैं और यह सुझाव देने का कोई भी प्रयास कि दोनों शब्द परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किए जा सकते हैं, किसी भी औचित्य से परे है। यह भी नोट किया जाए कि “कॉपर वायर रॉड्स” और “कॉपर वायर्स” के लिए सीटीएच कोड 4 अंकीय स्तर पर भिन्न हैं। यद्यपि, “कॉपर वायर रॉड्स” सीटीएच कोड 7407 के तहत आता है, “कॉपर वायर्स” सीटीएच कोड 7408 के तहत आता है। “कॉपर वायर” एक पृथक उद्योग है, “कॉपर वायर” के किसी उत्पादक का उल्लेख आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पत्र में नहीं किया गया है। यह भी सिद्ध करता है और निसंस्देह स्थापित करता है कि “कॉपर वायर” जांच के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।
- 3 एमएम से कम की मोटाई के कॉपर वायर का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता उद्योग द्वारा नहीं किया गया था और इसीलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग के क्षेत्राधिकार से स्टर्लाइट को अलग करना कानून के विरुद्ध और प्राधिकारी की सुस्थापित परिपाटी के विरुद्ध है।
- याचिकाकर्ता उद्योग ने याचिका के अगोपनीय रूपांतर में यूआई के पक्षकार के साथ अपने संबंध के बारे में सूचना को रोका है।
- हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को इस तथ्य के बावजूद छोड़ा गया है कि उनकी कीमत सरकारी खरीद और अधिकतर उद्योग की खरीद के लिए निर्धारित दर है।
- प्राधिकारी ने भारत में कुल उत्पादन, उन घरेलू उत्पादकों के नाम भी प्रकट नहीं किए हैं जिनके उत्पादन पर कुल घरेलू उत्पादन में हिंडालको के प्रतिशत हिस्से और कुल उत्पादन को निर्धारित करने के लिए विचार किया गया है और इस प्रतिशत हिस्से पर कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात रखने के लिए पर्याप्त के रूप में क्यों माना गया है।
- संबद्ध सामानों के कई अन्य विनिर्माता हैं जिन्हें फिनोलैक्स केबल्स लिमिटेड, टीडीटी कॉपर लिमिटेड, जेएमडब्ल्यू, ओमेघा रोलिंग मिल्स, लीबो मेटल्स प्रा.लि., गुजरात कॉपर, रामय कॉपर, ताम्रधातु उद्योग, केसी मेटल्स, कॉपरोड, कॉसमॉस, भाग्यनगर मेटल्स, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और कई अन्य जैसे उत्पादकों के अलावा विचार नहीं किया गया है। इन कंपनियों का संयुक्त उत्पादन लगभग 300,000 मी.ट. प्रति वर्ष है जो जांच की अवधि में हिंडालको के उत्पादन से अधिक है।
- प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई दुगुनी गिनती की संकल्पना गलत है और उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। जब आवेदक एक ही समय पर दो भिन्न उत्पादों पर शुल्क लगाए जाने का तर्क देते हैं तो आधार तथा क्षति के प्रयोजन के लिए केवल निचले उत्पादों के लिए तर्कसंगत और कानूनी अर्थ बनता है।
- चूंकि प्राधिकारी का कॉपर वायर उत्पादकों की कीमतों पर सब्सिडी आयातों के प्रभाव पर विचार करने का दायित्व है, अतः वायर उत्पादकों के आंकड़ों/सूचना पर विचार किए बिना कोई भी विश्लेषण अतार्किक ही नहीं होगा बल्कि नियमों के विरुद्ध भी होगा।
- अकेले हिंडालको का उत्पादन घरेलू उद्योग का आधार सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
- विचाराधीन उत्पाद/घरेलू उद्योग तथा अलग किए गए आयात आंकड़ों की स्पष्टता के अभाव में क्षति संबंधी मानदंडों पर कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।

- घरेलू उद्योग को लाभ में हुई कमी भारतीय ग्राहकों को कॉपर वायर उपलब्ध कराने में याचिकाकर्ता उद्योग की अक्षमता के कारण है।
- संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं द्वारा कॉपर रॉड से कॉपर वायर में माल पैटर्न में परिवर्तन से नियत लागत और कम लाभ मार्जिन बढ़ा है।
- एफटीए के तहत आशियान देशों से आयात शुल्कों में कमी लाभप्रदता में गिरावट के लिए दूसरा कारण है।
- वेदांता ने कठोर प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के कारण अपना उत्पादन रोका है न कि आयातों के कारण।
- चूंकि कॉपर वायर और कॉपर रॉड आंतरिक रूप से तुलनीय नहीं हैं, अतः क्षति के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उन्हें एक साथ रखना वाणिज्यिक रूप से तर्कसंगत नहीं होगा।
- प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से आयातों की निर्धारित मात्रा वही है जोकि याचिका में दी गई संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा है। यह संभव नहीं है कि प्रशुल्क शीर्ष 7408 के तहत कॉपर वायर का कुल आयात प्रशुल्क शीर्ष 7407, 7408 और 7409 के तहत क्रमशः कॉपर रॉड, कॉपर वायर और कॉपर स्ट्रिप के कुल आयात के समान हो। यदि संबद्ध देशों से कॉपर बार एवं रॉड अथवा कॉपर स्ट्रिप्स के आयात नहीं थे तो घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत कॉपर रॉड और कॉपर स्ट्रिप्स को शामिल करने के लिए अनुरोध न किया होता।
- यदि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की सही मात्रा प्रशुल्क शीर्ष 7407 के तहत कॉपर रॉड के आयातों और प्रशुल्क शीर्ष 7408 के तहत कॉपर स्ट्रिप्स के आयातों को अलग करने के बाद हिसाब में ली जाती है तो वह आयातों की कम मात्रा दर्शाएगी।
- प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि एस टी ई सी का सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम है। इसका अर्थ है कि एस टी ईसी द्वारा विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सब्सिडीयुक्त नहीं है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों में वृद्धि पर विचार करते हुए और वास्तविक क्षति का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी को निर्यातों की कुल मात्रा से एसटीईसी के निर्यातों को अलग करने की आवश्यकता है।
- विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए घरेलू मांग और याचिकाकर्ताओं की क्षमता के बीच एक अंतराल है। वस्तुतः यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की क्षमताओं में वृद्धि मांग में वृद्धि के बनाए रखने में सक्षम नहीं रही है।
- याचिकाकर्ताओं की कीमत और लागत एक-दूसरे के अनुरूप व्यापक रूप से गई है।
- पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होने के बावजूद जांच की अवधि से तीन वर्ष पूर्व में कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं था, वस्तुतः केवल उस वर्ष जिसमें याचिकाकर्ताओं की लागत और कीमत के बीच बहुत कम अंतराल है, वह जांच की अवधि में है जिसमें कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से तीन सूचकांक कमतर थी।
- घरेलू उद्योग क्षति की अवधि में उत्पादन बढ़ाने में सफलतापूर्वक सक्षम रहा है।
- यद्यपि, घरेलू बिक्री क्षति की अवधि में समान स्तर पर रही है, तथापि, निर्यात बिक्री में पर्याप्त वृद्धि है।
- घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर आय पहले से ही अर्थात् 15-25 प्रतिशत की निर्धारित दर पर रही प्रतीत होती है।
- मलेशिया से आयातों के लिए कीमत कटौती मार्जिन 0.5 प्रतिशत है और मलेशियाई सहयोगी निर्यातकों से आयातों के लिए क्षति मार्जिन भी 0.5 प्रतिशत है।
- विश्वव्यापी प्रवृत्ति पर कॉपर उत्पादों, की कीमतें अतिरिक्त प्रीमियम के साथ लंदन मैटल एक्सचेंज (एल एम ई) से जुड़ी हैं जिस पर सामान्यतः वार्ता की जाती है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान एल एम ई कीमत बहुत ही अस्थिर रेंज में थी जोकि घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए की है।

- घरेलू उद्योग पर गैर संबद्ध आयातों के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए और उसका पृथक् रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- यू ए ई से आयात भारत में कुल आयातों के लगभग 30 प्रतिशत थे। ये आयात संबद्ध देशों से आयात कीमतों की तुलना में तुलनीय अथवा कम कीमतों पर आ रहे थे। यू ए ई से आयातों की मात्रा किसी भी संबद्ध देश को अलग-अलग लेने पर वहां से आयात से अधिक हैं।
- संचित मालसूची के संबंध में घरेलू उद्योग का विवरण वास्तविक रूप से गलत है क्योंकि प्रत्येक तिमाही में वे मालसूची को शून्य तक कम करते हैं।
- कॉपर उत्पादकों का उत्कृष्ट क्षमता उपयोग और बहुत ही अच्छा ईबीआईटीडीए है। संयुक्त औसत ईबीआईटीडीए जांच की अवधि में 3242 करोड़ भारतीय रूपए प्रति वर्ष है।
- वेदांता के ईबीआईआईटीडीए में कमी मुख्य रूप से खानों से कम टीसीआरसी तथा बढ़ी हुई उत्पादन लागत के कारण है।

मलेशिया सब्सिडी कार्यक्रम

- यह अनुरोध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अल्फा क लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण यह दर्शाता है कि उसने कार्यक्रम 1,3,4,7,8,14,24,30,34 और 35 के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- अल्फा की एग्जिम बैंक के साथ कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है।
- कार्यक्रम सं. 12 के संबंध में प्राधिकारी की टिप्पणी के संबंध में यह अनुरोध है कि मेट्रोड इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बड़ा हुआ पूंजी भत्ता, जो मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी ने प्राप्त किया है, संयंत्र और मशीनरी के लिए कार्यक्रम सं. 16- भत्ते का भाग है।
- मशीनरी और उपस्करों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट मेट्रोड द्वारा पूंजीगत सामानों के रूप में नई भट्टी में प्रयुक्त की जाने वाली रिफैक्ट्री के लिए प्राप्त की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि कंपनी ने इस आधार पर एमआईटीए से छूट के लिए अनुरोध किया था कि पूंजीगत सामानों के आयात पर शून्य प्रतिशत आयात शुल्क लगता है और इसीलिए रिफैक्टरीज पर भी आयात शुल्क की छूट होनी चाहिए। कंपनी ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया कि चूंकि छूट पूंजीगत सामानों पर शून्य प्रतिशत आयात शुल्क के अनुरूप प्रदान की गई थी, अतः इस योजना पर कंपनी को किसी लाभ के रूप में अथवा प्रतिकार योग्य सब्सिडी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- कार्यक्रम-12 सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है तथा अंतरदेशीय राजस्व बोर्ड ए सी ए प्रदान करने में उद्देश्यपरक मानदंड लागू करता है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में प्रतिकार योग्य सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह निर्यात शर्तों से संबद्ध नहीं है, सब्सिडी पर डब्ल्यू टी ओ करार के तहत अपेक्षित तरीके में तथा प्रतिकारी उपायों (एससीएम करार) में विशिष्ट नहीं है।
- कार्यक्रम 23 के तहत अल्फा ने केवल मशीनरी और उपस्करों पर आयात शुल्क की छूट प्राप्त की जहां वे मशीनरी और उपस्कर स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे।
- यह अनुरोध है कि कार्यक्रम 24 प्रतिकार योग्य नहीं हो सकता क्योंकि इस कार्यक्रम में आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्कों की छूट शामिल है, जिनका प्रयोग निर्यात सामानों के उत्पादन में किया जाता है। निर्यात सामानों के उत्पादन में निहित आयात शुल्कों की छूट को प्रतिकार योग्य सब्सिडी मानना एएससीएम के अनुबंध-1 के पैरा (एच) और सीवीडी नियमावली के अनुबंध-2 भाग-1 (एच) के तहत दायित्वों के पूरे उल्लंघन में होगा।
- कार्यक्रम 35 के तहत तथाकथित लाभ वास्तविक लाभ निकालने के लिए निर्यातक द्वारा अर्जित कुल लाभ पर बचाए गए शुल्क (24 प्रतिशत) तक ही समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसी प्रतीत होता है कि यह परिकलन अर्जित लाभ की कुल राशि के आधार पर है न कि बचाए गए कर पर।

- अल्फा को 1 अक्टूबर, 1987 से 30 सितंबर, 1992 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए पायनियर स्तर प्रदान किया गया था। तथापि, पायनियर स्तर 1992 में समाप्त हो गया और अल्फा ने जांच की अवधि शामिल करते हुए पूर्व प्रोत्साहन की समाप्ति के बाद आगे पायनियर स्तर प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया है।
- प्राधिकारी ने मलेशिया से किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा सब्सिडी कार्यक्रम प्राप्त करने का कोई साक्ष्य नोट नहीं किया है।
- जांच के तहत किसी भी कंपनी ने कार्यक्रम 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,18,21,25,27,28,30,31,32,34 से किसी लाभ के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- कार्यक्रम 1 और 34 केवल लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए हैं और जांच किए गए उत्पादक इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं।
- कार्यक्रम 11 निर्यात शर्तों से संबद्ध नहीं है, विशिष्ट नहीं है और सामान्यतः उपलब्ध है। अन्य सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जांचों में भी यह निर्धारित किया गया है कि कार्यक्रम 11 प्रकृति में विशिष्ट नहीं है।
- प्राधिकारी ने कार्यक्रम 16- संयंत्र एवं मशीनरी पर भत्ते (पूँजीगत भत्ते) पर एक गैर प्रतिकार योग्य कार्यक्रम के रूप में विचार किया है। मूल्यह्रास से संबंधित प्रावधानों को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था और यह स्पष्ट किया गया था कि मूल्यह्रास की योजना विश्व में अन्यत्र अन्य मूल्य ह्रास की तरह काम करती है। दोनों मूल्य ह्रास से संबंधित योजनाएं हैं जिसे समान व्यवहार दिया जाना चाहिए और उसे प्रतिकार योग्य नहीं माना जाएगा।
- कार्यक्रम 15 प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। यह आवासीय और गैर आवासीय कंपनियों जैसी सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है तथा पूर्ण स्वामित्व तथा भागीदारी वाले जैसे गैर-निगमित व्यापारों के लिए उपलब्ध है। आईबीए प्रदान करने के लिए निर्यत मानदंड नहीं हैं।
- कार्यक्रम 19 प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एस सी एम करार के अनुच्छेद I, II और III के अनुरूप है।
- डी जी टी आर ने ए एस सी एम करार के अनुच्छेद-2 क अपने निर्वचन में गलती की है जिससे विशेष रूप से कार्यक्रम 14, 23 और 24 के संबंध में इस कार्यक्रम का कम विचार हुआ है।
- सभी कार्यक्रम जिनके लिए डी जी टी आर ने प्रतिकूल मध्यस्थाओं पर विश्वास किया है, का 30 सितंबर, 2019 को आयोजित स्थल पर सत्यापन के दौरान डी जी टी आर द्वारा सत्यापन किया गया था।
- जी ओ एम ने अपने 2 नवंबर, 2018 के प्रश्नावली उत्तर में और अपरे पूरक उत्तर में जी ओ एम द्वारा किए गए कार्यक्रमों और नीतियों के संबंध में डी जी टी आर को पहली सूचना दी है। यह प्रथम सूचना प्रयुक्त की जानी चाहिए और उस सहायक सूचना पर विश्वास किए बिना इस पर विश्वास किया जाना चाहिए जोकि आगे लागू नहीं हो सकती।

थाइलैंड सब्सिडी कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 2 कतिपय उद्यम, उद्योग अथवा भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ऐसा कोई उद्योग अथवा बाजार क्षेत्र नहीं है जो कार्यक्रम के क्षेत्र से अलग हो अथवा निवेश बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पात्र न हो।

- कार्यक्रम सं. 3 के संबंध में निवेश संवर्धन अधिनियम के तहत आयकर की छूट गैर-प्रतिकार योग्य है क्योंकि वह कतिपय उद्योग क्षेत्र अथवा भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं है। सभी उद्यम, कंपनियां, अथवा क्षेत्र इस कार्यक्रम के तहत लाभ लेने के लिए पात्र हैं। प्राधिकारी ने इस अवधारणा पर इस कार्यक्रम का प्रतिकार किया है कि लाभ उन उत्पादकों के लिए उपलब्ध था जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान निवल लाभ अर्जित किया। तथापि, यह अनुरोध है कि निवेश बोर्ड द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमत कंपनी इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त न करने का विकल्प चुन सकते हैं और वे कंपनियां लाभ का दावा करने के अपने अधिकार को छोड़ सकते हैं।

- जांचकर्ताओं ने अतिरिक्त दस्तावेजों का अनुरोध किए बिना अथवा आगे कोई प्रश्न किए बिना सत्यापन के दौरान दी गई कार्यक्रम 5 से संबंधित प्रस्तुत सूचना को स्वीकार किया।
- निवेश बोर्ड ने सत्यापन बैठक में पहले ही स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम सं. 13 और 14 कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है बल्कि इसके बजाए नई निवेश संवर्धन योजना के तहत लाभों की श्रेणी है जो 1 जनवरी, 2015 से प्रभावित हुई, अतः यह सब्सिडी नहीं है।
- कार्यक्रम सं. 6,7,8,9,और 10 के संबंध में निवेश बोर्ड का निवेश संवर्धन प्रदान करने के लिए मानदंड एस सी एम करार के अनुच्छेद 2 विशिष्टता की परिभाषा के तहत विशिष्ट नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि निवेश संवर्धन कंपनी, उद्योग अथवा क्षेत्र तक सीमित प्रदान नहीं किया जाता है। निवेश बोर्ड उस मानदंड को भी नहीं लगाता जो एस सी एम करार के अनुच्छेद 3 निषेध के तहत आता है।

इंडोनेशिया सब्सिडी कार्यक्रम :

- बी जैड कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह बिना किसी सीमा के उद्योग और क्षेत्र के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। बी जैड सामानों के भंडारण का क्षेत्र भी हो सकता है और यह कार्यक्रम सामान जमा करने तथा निर्यात के लिए बांडेड जोन से मुक्त व्यापार जोन तक बांडेड जोन के अंतर्गत सामानों का संचलन करने के लिए लागू होता है।
- कठोर मॉनीटरिंग, सत्यापन और नियमित लेखा परीक्षा के तहत के एस आई सहित बी जैड के अंतर्गत किसी भी कंपनी द्वारा इस कार्यक्रम का प्रयोग करने में कोई अधिकता नहीं होगी।
- यहां तक कि यदि डी जी टी आर इस कार्यक्रम के तहत के एस आई के लिए सब्सिडी मार्जिन परिकलित करना चाहता है तो वह प्रकटन पर अपनी टिप्पणियों में प्रस्तुत हित के कारक का उल्लेख करते हुए ही ऐसा कर सकता है।
- डी जी टी आर के लिए निर्यात शुल्क को शामिल करना कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे इस जांच के भाग के रूप में कॉपर संग्रहण पर पर्याप्त पारिश्रमिक से कम (एलटीएआर) पर कच्ची सामग्री का प्रावधान हो। डी जी टी आर ने इस कार्यक्रम के संबंध में के एस आई को कभी भी सूचित नहीं किया है और ई एफ प्रकटन में किया गया परिकलन अस्पष्ट रहता है क्योंकि केएसआई नहीं जानता कि आंकड़े कहां से लिए गए हैं। डी जी टी आर यह दर्शाने के भार को पूरा करने में विफल रहा है कि इस कार्यक्रम से वित्तीय अंशदान जो लाभ प्रदान करता है, से संबंधित उत्पाद के इंडोनेशियाई उत्पादकों को आपूर्ति करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को कैसे सौंपता है अथवा निर्देश देता है।
- टी एम एस केआईटीई के तहत है, और किसी भी तरह एस ई जैड में स्थित नहीं है। ई एफ प्रकटन गलती से उपर्युक्त रिसाइल 430 में यह उल्लेख करता है कि के आई टी ई भी मशीनरी के लिए आयात शुल्क की छूट संबंधी कार्यक्रम में शामिल है। मिनिस्टर फाइनेंस रेगुलेशन नं. 254/पीएमके.04/2011 के अनुच्छेद 2 में यह उल्लेख है कि:
- "छूट, सामानों और/अथवा प्रसंस्कृत की जाने वाली सामग्री, एसेंबल की जाने वाली अथवा निर्यात प्रयोजन के लिए अन्य सामानों पर संस्थापित की जाने वाली सामग्री पर दी जाएगी।
- कार्यक्रम जो कच्ची सामग्री के आयात पर अधिमान्य सीमाशुल्क के अध्यधीन है, प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि (i) इसमें सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से कठोर सत्यापन प्रक्रिया है; (ii) कार्यक्रम का प्रयोग करने में कोई अधिकता नहीं है; (iii) सभी आयातित सामग्री पुनः निर्यात की जाती है; और (iv) टीएमएस द्वारा कॉपर कैथोड के सभी आयात शून्य प्रतिशत आयात शुल्क के साथ एफटीए देशों से थे।
- कच्ची सामग्री कॉपर अयस्क तथा सघन संबंधी निर्यात प्रतिरोध पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्ची सामग्री के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान में नहीं होते। यू.एस. निर्यात प्रतिरोध में डब्ल्यू टी ओ पैनल ने पाया कि निर्यात प्रतिरोधक सामानों के सरकार द्वारा सौंपे गए अथवा सरकार द्वारा निर्देशित प्रावधान नहीं हैं और इसीलिए वित्तीय अंशदान नहीं होते।

- एग्जिम बैंक तथा बैंक मंडीरी द्वारा अधिमान्य दर जांच में भाग लेने वाले इंडोनेशियाई उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त नहीं किए गए हैं। एग्जिम बैंक और बैंक मंडीरी लाभ सापेक्ष वित्तीय संस्थाएं हैं और वे विशिष्ट नहीं हैं क्योंकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
- एस ई जैड प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि एस ई जैड में होने का अर्थ यह नहीं है कि कार्यक्रम स्वतः लागू होगा। कंपनियों को कार्यक्रम के लिए अलग से आवेदन करना होता है।
- वैट छूट का कार्यक्रम वापस लिया गया था और सरकार के 2015 के विनियम संख्या 81 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके तहत नीतिगत उद्योगों की विभिन्न रेंज में आते हैं और किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है।

वियतनाम सब्सिडी कार्यक्रम

- कार्यक्रम सं. 1 और कार्यक्रम सं. 3 के तहत निगम आय कर की कमी “प्रोत्साहित उद्योग” और “प्रोत्साहित भौगोलिक क्षेत्र” के सिद्धांतों पर आधारित है।
- कार्यक्रम सं. 2 के संबंध में परिपत्र सं. 38/2015/टीटी-बीटीसी के अनुच्छेद 59 के अनुसार निर्यात सामानों के उत्पादन में आयात शुल्क छूट वाली कच्ची सामग्री के उपयोग की मॉनीटरिंग के लिए वियतनाम के सीमाशुल्क सामान्य विभाग के लिए एक प्रणाली है। यह एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रयुक्त नीति है जिससे अन्य देशों की सरकारें भी निर्यात उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की छूट देती हैं/आयात शुल्क की प्रतिपूर्ति करती हैं। भारतीय उत्पादक/निर्यातक भी भारत में इस नीति का लाभ लेते हैं जिसे अग्रिम लाइसेंसिंग के रूप में जाना जाता है।
- वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी निकाय के रूप में नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी ने कोई साक्ष्य दिए बिना आंशिक अथवा समग्र राज्य स्वामित्व वाले वियतनामी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों तथा प्रचालन की प्रकृति के झूठे आरोप लगाए हैं।
- वेटिन बैंक द्वारा दी गई वित्तीय गारंटी पूरे विश्व में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लाभ सेवा के लिए नियमित है।
- जी ओ वी द्वारा व्यापार संवर्धन कार्यक्रम के लिए पात्र क्षेत्रों की कोई पूर्व परिभाषित सूचियां नहीं हैं। प्रति वर्ष कार्यक्रम का सरकारी निकाय स्थानीय प्राधिकारियों और एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर वर्ष के लिए कार्यक्रम अनुमोदित करता है। अतः संवर्धन क्रियाकलापों के लिए पात्र क्षेत्र वर्ष वार भिन्न होते हैं और किसी तरह से “विशिष्ट” नहीं हैं।
- कार्यक्रम 14 एवं 15 के तहत जांच के अधीन किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

सब्सिडी कार्यक्रम संबंधी विविध अनुरोध

- कतिपय गतिविधियों के कारण स्तर पर सत्यापन के लिए अनुरोध हेतु उत्तर देना नहीं दिया जा सका। अल्फा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करना चाहेगा कि वे उसे एक सहयोगी उत्पादक के रूप में जांच में भाग लेने की अनुमति दें और सिद्ध करें कि उसने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की गई किसी भी सब्सिडी/कार्यक्रम से या तो (क) कोई लाभ नहीं लिया अथवा (ख) लाभान्वित नहीं हुआ।
- टीएमएस ने स्थल पर सत्यापन दौरे के बाद डी जी टी आर को अपना पूरा उत्तर संतोषजनक रूप से प्रस्तुत कर डीजीटीआर के साथ पूरा सहयोग किया है। टीएमएस ने वास्तव में अपने पूरे सत्यापन प्रदर्श प्रस्तुत किए हैं जिसे डी जी टी आर यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग कर सकता है कि किस तथाकथित कार्यक्रम का उपयोग किया गया, भले ही कोई भी प्रयुक्त कार्यक्रम प्रतिकार्य योग्य हो तथा क्या सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर है।
- प्राधिकारी ने वियतनाम से निर्यातों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने हेतु वास्तविक आधार प्रस्तुत नहीं किया है और केवल यह नोट किया है कि सब्सिडी मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

- प्राधिकारी ने अन्य सभी निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करते समय सीएफटी वीना कॉपर और डोमिना द्वारा दिए गए सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में सूचना को ध्यान में नहीं रखा है।
- पूरी प्रश्नावली के उत्तर, विशेष रूप से विशिष्ट सब्सिडी कार्यक्रमों के प्रयोग के संबंध में सूचना और वियतनाम से निर्यातकों द्वारा प्राप्त लाभ की राशि रद्द नहीं की जानी चाहिए, यदि निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना पूर्ण नहीं थी अथवा पूरी तरह से सत्यापित नहीं थी।
- नियम 7(8) के तहत प्राधिकारी द्वारा “उपलब्ध तथ्यों” का प्रयोग गायब सूचना के अंतराल को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यह भी निर्धारित है कि इन तथ्यों में हितबद्ध पक्षकार द्वारा दिए गए तथ्य शामिल हो सकते हैं, यहां तक कि यदि इन तथ्यों में पूरी सूचना न हो।
- यदि संबद्ध देशों से भारत को अधिकतर निर्यात सहायगी निर्यातकों द्वारा किए जाते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रम संबद्ध देशों के अन्य सभी निर्यातकों द्वारा प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रमों के प्रतिनिधिकारक हैं और उस सूचना को उपलब्ध तथ्यों के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक फाइल में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाए कि थाई उत्पादकों न कच्ची सामग्री पर कोई आयकर छूट अथवा आयात शुल्क की छूट प्राप्त की है। संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त इनपुट कच्ची सामग्री शुल्क की शून्य दर के अध्यधीन है जिसका स्थल पर सत्यापन के दौरान प्राधिकारी द्वारा सत्यापन कर दिया गया है।
- असहयोगी निर्यातों के लिए अन्य सभी दर के सब्सिडी निर्धारण के संबंध में यह अनुरोध है कि सब्सिडी मार्जिन के परिकलन के लिए सिद्धांत तथा थाइलैंड से “अन्य सभी निर्यातकों” के लिए वास्तविक दर गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता।

प्राधिकारी द्वारा जांच

556. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध प्रकृति में दोहराए गए हैं और प्रकटन विवरण में पूर्व में उनका पहले ही समाधान किया गया था। उपर्युक्त जांच परिणाम यथातथ्यतः पक्षकारों के इन तर्कों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की यहां संगत सीमा तक और अन्यत्र हल न किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की है।

- जहां तक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को व्यापक करने से संबंधित अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि (i) “कॉपर बार, रॉड्स और प्रोफाइल्स” प्रशुल्क शीर्ष 7407 के तहत आयात किए जाते हैं (ii) “कॉपर वायर” प्रशुल्क शीर्ष 7408 के तहत आयात किया जाता है, और (iii) “0.15 एम एम से अधिक मोटाई की कॉपर प्लेट, शीट्स और स्ट्रिप्स” प्रशुल्क शीर्ष 7409 के तहत आयात की जाती हैं। प्रतिकारी शुल्क जांच में विचाराधीन उत्पाद भारत में आयातित उत्पाद हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों की जांच पर और डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क के प्रशुल्क शीर्ष 7408 के तहत आने वाला “सतत कॉस्ट कॉपर वायर” है। विचाराधीन उत्पाद में कॉपर वायर शामिल है जिसका अधिकतम क्रॉस सेक्सनल आयाम 6 एमएम से अधिक तथा 6 एमएम तथा उससे कम है।
- जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद “सतत कॉस्ट कॉपर वायर रॉड” के रूप में परिभाषित किया गया था जो सीमाशुल्क उपशीर्ष 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11, 7409.19 के तहत वर्गीकरणीय हैं। प्राधिकारी ने वस्तुतः प्रशुल्क शीर्ष 7408 के तहत आने वाले “सतत कॉस्ट कॉपर वायर” को ही शामिल करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को संकीर्ण किया है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र व्यापक नहीं बनाया है।

- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि विचाराधीन उत्पाद में दो भिन्न उत्पाद हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद केवल एक उत्पाद अर्थात् “सतत कॉस्ट कॉपर वायर” है। सतत कॉस्ट कॉपर वायर के भिन्न क्रास सेक्सन आयातों के परिणामस्वरूप भिन्न आयात नहीं होते।
- प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में प्रशुल्क कोड के आधार पर पीसीएन सिद्धांत से संबंधित दावे का पहले ही उत्तर दिया है। जहां तक इस अनुरोध का संबंध है, कि पी सी एन ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बाहर के उत्पाद शामिल थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रशुल्क कोड पर आधारित पीसीएन जांच की शुरुआत के चरण में घरेलू उद्योग द्वारा सुझाए गए विचाराधीन उत्पाद के पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और उत्पाद के विभिन्न किस्मों/रूपों के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पीसीएन प्रशुल्क कोडों पर आधारित नहीं हो सकता। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा नहीं किया है कि प्रशुल्क कोड के आधार पर पी सी एन से उनके हित का पूर्वाग्रह हुआ है अथवा विचाराधीन उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच अनुचित तुलना हुई है।
- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है, कि तीन एमएम से नीचे के कॉपर वायर को अलग किया जाना चाहिए क्योंकि उसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि घरेलू उद्योग 3 एमएम से कम के कॉपर वायर का उत्पादन करता है और इसीलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता।
- यूआई में मै. वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाइट कॉपर) द्वारा यू ए ई में उसकी संबद्ध कंपनी के संबंध में दी गई सूचना का प्रकटन न होने से घरेलू उद्योग का आधार प्रभावित नहीं होता क्योंकि वेदांता उद्योग घरेलू उद्योग का भाग नहीं है।
- हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित “सतत कॉस्ट कॉपर वायर” के अन्य उत्पादक या तो “सतत कॉस्ट कॉपर वायर” के आयातक हैं अथवा कम क्रॉस-सेक्सनल डायामीटर में “सतत कॉस्ट कॉपर वायर” लेने के लिए घरेलू उद्योग से उच्चतर क्रॉस सेक्सन डायामीटर के “सतत कॉस्ट कॉपर वायर” की खरीद कर रहे हैं। ऐसे घरेलू उत्पादकों के उत्पादन को शामिल करने से भारत में कुल उत्पादन की दोहरी गिनती होगी।
- गैर-सब्सिडी युक्त आयात मात्रा को संबद्ध आयातों की कुल मात्रा निर्धारित करने के लिए तथा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अलग रखा गया है।
- प्राधिकारी ने प्रशुल्क शीर्ष 7408 के तहत आने वाले “सतत कॉस्ट कॉपर वायर” के आयातों की मात्रा पर ही विचार किया है और क्षति विश्लेषण में प्रशुल्क शीर्ष 7407 और प्रशुल्क शीर्ष 7409 के तहत आयातित क्रमशः “कॉपर रॉड” और “कॉपर स्ट्रिप्स” के आयातों को शामिल नहीं किया है।
- मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश न करने का कारण नहीं हो सकता, यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात सब्सिडीयुक्त थे और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे थे।
- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि गैर संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां तक कि यद्यपि गैर संबद्ध देशों से आयात मात्रा काफी है परंतु यह संबद्ध देशों से सब्सिडीयुक्त आयातों और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है।

घरेलू उद्योग द्वारा सब्सिडीकरण से संबंधित दावे

- घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम में उत्पादक इंडोनेशिया से इनपुट (कॉपर केथोड) की खरीद कर रहे हैं और इसीलिए इंडोनेशियाई सब्सिडियां मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम में संबद्ध सामानों के उत्पादकों को दी जा रही हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करते समय इन तीन देशों में उत्पादकों को दी गई इंडोनेशियाई सब्सिडियां भी

शामिल की जानी चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना यह दर्शाती है कि उनके अधिकतर इनपुट लेने का कार्य इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य देशों से है।

- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है, सब्सिडी मार्जिन इंडोनेशिया में उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अधिमान्य उधार हेतु निर्धारित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने इंडोनेशिया से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन किया है और सहयोगी पक्षकारों के लिए अधिमान्य उधार कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिकार याग्य सब्सिडी मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता।
- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि मलेशिया सरकार द्वारा संयंत्र और मशीनरी पर भत्ते के लिए और थाइलैंड सरकार द्वारा दिए गए गैर कर लाभों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयंत्र और मशीनरी कार्यक्रमों पर सामान्य भत्ते प्रतिकारी शुल्क नियमावली और एस सी एम करार के अनुसार, प्रतिकार योग्य सब्सिडी के लिए प्रावधान नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पहले ही मलेशिया से सभी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए बड़े हुए पूंजीगत भत्ता कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने थाइलैंड में उत्पादकों/निर्यातकों को गैर कर प्रोत्साहन प्रदान करते हुए सब्सिडी कार्यक्रम के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर थाइलैंड से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भी सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है।
- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि एस टी ई सी लाभ अर्जित कर रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे पक्षकार की वेबसाइट के स्क्रीन शॉट के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की बारीकी से जांच यह दर्शाती है कि एस टी ई सी ने कलेंडर वर्ष 2017 और 2018 के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया।
- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि यदि उत्पादक/निर्यातक असहयोगी हैं, तो प्राधिकारी को उपलब्ध प्रतिकूल तथ्य लागू करने चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वस्तुतः संबद्ध देशों से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों को लागू किया है।

मलेशियाई सब्सिडी कार्यक्रमों से संबंधित दावे

- प्राधिकारी ने अल्फा इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडी मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया है न कि उनके प्रश्नावली के उत्तर में किए गए दावों के आधार पर क्योंकि अल्फा इंडस्ट्रीज को संबद्ध जांच में सहयोगी उत्पादक/निर्यातक नहीं माना गया है।
- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि मलेशिया सरकार द्वारा मशीनरी पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट को प्रतिकार योग्य नहीं माना जा सकता क्योंकि दी गई छूट पूंजीगत सामान के आयात पर शून्य प्रतिशत की नीति के अनुरूप थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिकारी शुल्क नियमावली अथवा नियमावली के तहत अथवा एस सी एम करार के तहत इस तर्क के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
- जहां तक बड़े हुए पूंजीगत भत्ते से संबंधित कार्यक्रम सं. 12 की प्रतिकारिता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बढ़ा हुआ पूंजीगत भत्ता संवर्धित क्रियाकलाप करने के लिए कुछ उद्यमों को मलेशिया सरकार द्वारा दिया जाता है और इसीलिए इसे सभी उद्यमों को उपलब्ध संयंत्र और मशीनरी के सामान्य भत्ते/मूल्य ह्रास से नहीं मिलाया जा सकता तथा विशिष्टता के मानदंड को विधिवत पूरा करता है।
- मेट्रोड मलेशिया ने बड़े हुए पूंजीगत भत्ता कार्यक्रम के प्रयोग के संबंध में पूरे तथ्य प्रकट नहीं किए, यहां तक कि यदि यह घरेलू उद्योग द्वारा विशेष रूप से आरोप लगाया गया था और उससे संबंधित सूचना के लिए प्रश्नावली के उत्तर में विशेष रूप से अनुरोध किया गया था। प्रकटन संबंधी टिप्पणियों के भाग के रूप में मेट्रोड मलेशिया ने पहली बार यह प्रकट किया है कि बढ़ा हुआ पूंजीगत भत्ते का उनके द्वारा प्रयोग किया गया था और तदनुसारी लाभ की राशि कार्यक्रम सं. 16 के तहत संयंत्र एवं मशीनरी पर भत्ते के लिए प्रकट की गई कुल राशि में शामिल की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया सरकार द्वारा दायर उत्तर में कार्यक्रम सं. 16 के तहत मेट्रोड मलेशिया द्वारा लिए गए संयंत्र एवं

मशीनरी एवं भत्ते के लिए लाभ की राशि कार्यक्रम सं. 12 के तहत बड़े हुए पूंजीगत भत्ते के लिए मेट्रोड मलेशिया द्वारा लिए गए राशि से अतिरिक्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को उस प्रत्येक सब्सिडी कार्यक्रम के प्रयोग के संबंध में पूरी सूचना देनी होती है, जिसके लिए प्रश्नावली के उत्तर में विशेष सूचना के लिए अनुरोध किया गया हो। प्राधिकारी को विशेष रूप से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रतिकार योग्यता निर्धारित करनी होती है। हितबद्ध पक्षकार सूचना देने के लिए एक सामान्य श्रेणी के तहत विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों को संचित नहीं कर सकते।

- प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मेट्रोड मलेशिया ने यह गलत दावा किया है कि बड़ा हुआ पूंजीगत भत्ता संगत नियमों के तहत सभी उद्यमों को उपलब्ध है और इसीलिए विशिष्ट नहीं है। आयकर नियमावली, के नियम 8.2.1 (बड़ा हुआ पूंजीगत भत्ता) (पात्र परियोजनाओं का पुनर्निवेश) 2000 [पी.यू. (क) 506/2000] में यह प्रावधान है कि संवर्धित क्रियाकलाप अथवा संवर्धित उत्पाद के संबंध में योग्य परियोजना के प्रयोजन के लिए संयंत्र अथवा मशीनरी के के प्रावधान पर किया गया पात्र संयंत्र व्यय पर ये नियम लागू होते हैं। नियम 8.2.4 यह भी कहता है कि ये नियम उस कंपनी पर लागू नहीं होते जिसे पुनर्निवेश भत्ता दिया गया हो। इस प्रकार, प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि कार्यक्रम विशिष्ट है और इसमें संयंत्र तथा मशीनरी के सामान्य भत्ते/मूल्यहास के लिए प्रावधान नहीं है तथा सभी उद्यमों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, मेट्रोड मलेशिया द्वारा दायर उत्तर में पूर्ण प्रकटन के अभाव और इस संबंध में मेट्रोड मलेशिया तथा मलेशिया सरकार द्वारा दायर उत्तर में विसंगति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने बड़े हुए पूंजीगत भत्ते के तहत लाभ निर्धारित करने के लिए मेट्रोड मलेशिया द्वारा दी गई सूचना पर विचार नहीं किया है।
- मेट्रोड ग्रुप ने गलत बताया है कि कार्यक्रम सं. 24 का प्राधिकारी द्वारा यह बताते हुए प्रतिकार किया गया था कि इसमें निर्यात सामानों के उत्पादन में प्रयुक्त आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की छूट शामिल है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा-253 में स्पष्ट रूप से नोट किया है कि कार्यक्रम सं. 24 में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और साथ ही विशिष्ट भी है क्योंकि यह उस उद्यम तक सीमित है जो उस कच्ची सामग्री का प्रयोग करता है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है।
- प्राधिकारी ने नोट किया है कि मेट्रोड मलेशिया ने निर्यात सामानों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के आयातों पर छूट के रूप में लाभ प्राप्त किया है क्योंकि मेट्रोड मलेशिया ने विशेष रूप से प्रदर्श 14 में अपनी प्रश्नावली के उत्तर में स्वीकार किया है कि *“निर्यात सामानों के लिए बनी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की छूट प्रदान करना (कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की) छूट के तहत शामिल है। इस योजना के तहत शुल्क की कोई छूट उन सामानों के लिए उपलब्ध नहीं है जो घरेलू बाजार के लिए लक्षित परिसंस्कृत उत्पादों के उत्पादन के लिए आयात किए जाते हैं।”* प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में गलती से नोट किया था कि मेट्रोड द्वारा लिया गया यह लाभ कार्यक्रम सं. 24 के तहत लाभ है।
- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि मलेशिया सरकार द्वारा कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की निर्यात मात्रा छूट को प्रतिकार योग्य सब्सिडी के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि यह एससीएम करार के अनुबंध-1 के विशिष्ट प्रावधान के अनुपालन में है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात सामानों के उत्पादन में प्रयोग के लिए कच्ची सामग्री का आयात केवल तब प्रतिकार योग्य सब्सिडी के रूप में नहीं माना जा सकता यदि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हो कि यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन तंत्र है कि कोई अधिक प्रेषण नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने केवल तंत्र की मौजूदगी और पर्याप्त साक्ष्य दिए बिना अधिक प्रेषण का अभाव अथवा इस सत्यापन तंत्र की एक-एक कर व्याख्या के अभाव का दावा किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने उस कंपनी पर सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क का कोई उदाहरण नहीं दिया है, जहां वह निर्यात दायित्व को पूरा करने में असमर्थ थी। निर्यातक द्वारा और विशेष रूप से मलेशिया सरकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आयात शुल्क छूट के लिए पात्र आयात मात्रा की राशि सरकार द्वारा सामान्य रूप से और विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री के मामले में कैसे निर्धारित की गई थी।

- प्राधिकारी ने उपलब्ध लाभ की वास्तविक राशि के आधार पर मेट्रोड ग्रुप के लिए आयकर से छूट प्रदान करने वाले कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन परिकलित किया है। सब्सिडी मार्जिन वास्तविक लाभ निकालने के लिए निर्यातक द्वारा अर्जित कुल लाभ पर बचाए गए कर की राशि पर आधारित है। मलेशिया के निर्यातकों ने इसकी सत्यता अथवा उन्हें सूचित सिद्धांत की वैधता तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए सिद्धांत का विरोध नहीं किया है।

थाइलैंड सब्सिडी कार्यक्रम से संबंधित दावे

- इस दावे के संबंध में कि थाइलैंड सरकार द्वारा दिए गए सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पहले ही प्रत्येक सब्सिडी कार्यक्रम के लिए विशिष्टता के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया है।
- जहां तक इस दावे का संबंध है कि कार्यक्रम सं. 13 और 14 प्रतिकार योग्य सब्सिडी नहीं बनाते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाइलैंड सरकार ने कार्यक्रम सं. 13 के तहत गैर-कर प्रोत्साहनों के संबंध में पूर्ण सूचना तथा यह कि वे गैर कर प्रोत्साहन प्रतिकार योग्य लाभ क्यों नहीं माने जा सकते, से संबंधित सूचना नहीं दी है।
- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि थाइलैंड सरकार द्वारा कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की निर्यात मात्रा की छूट को प्रतिकार योग्य सब्सिडी नहीं माना जा सकता क्योंकि यह एस सी एम करार के अनुबंध-1 के विशिष्ट प्रावधान के अनुपालन में है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातित सामानों के उत्पादन में प्रयोग के लिए कच्ची सामग्री का आयात तब प्रतिकार योग्य सब्सिडी के रूप में नहीं माना जा सकता यदि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हो कि यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन तंत्र है कि कोई अधिक प्रेषण नहीं है। थाइलैंड सरकार ने केवल तंत्र की मौजूदगी और पर्याप्त साक्ष्य दिए बिना अधिक प्रेषण का अभाव अथवा इस सत्यापन तंत्र की एक-एक कर व्याख्या के अभाव का दावा किया है। थाइलैंड सरकार द्वारा यह दर्शाने के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आयात शुल्क छूट के लिए पात्र आयात मात्रा की राशि सरकार द्वारा सामान्य रूप से और विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री के मामले में कैसे निर्धारित की गई थी।
- प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यात उत्पादन में प्रयोग के लिए आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की छूट के तहत थाइलैंड से सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए कोई प्रतिकारी शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि उनके द्वारा आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क जांच की अवधि के दौरान शून्य था।

इंडोनेशिया सब्सिडी कार्यक्रम से संबंधित दावे

- कच्ची सामग्री के आयात पर आयात शुल्क छूट से संबंधित कार्यक्रम के संबंध में इंडोनेशिया पीटी तेमबागा मूलिया सेमानन (टीएमएस) के उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने दो मुद्दे उठाए हैं (i) कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क का कोई अधिक प्रेषण नहीं था क्योंकि कठोर मॉनीटरिंग तंत्र है और कमी के संबंध में पीटी तेमबागा मूलिया सेमानन द्वारा सीमाशुल्क का भुगतान किया गया था और (ii) यदि इस कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया जाता है तो कुल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी मार्जिन नगण्य है।
- इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी तेमबागा मूलिया सेमानन ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का, विशेष रूप से कच्ची सामग्री के आयात पर आयात शुल्क छूट से संबंधित सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया। पीटी तेमबागा मूलिया सेमानन ने केवल यह उल्लेख किया है कि "यह कार्यक्रम टी एम एस को वास्तविक लाभ प्रदान नहीं करता क्योंकि सामग्री के भारी मात्रा में आयात शून्य आयात शुल्क के साथ इंडोनेशिया अथवा आसियान में एफटीए वाले मूल देशों से थे"। सत्यापन के दौरान पीटी तेमबागा मूलिया सेमानन ने माना कि वस्तुतः गैर आशियान देशों से आयात थे और शुल्क छूट के रूप में इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया गया था। यहां तक कि सत्यापन दौरे के दौरान गैर-आशियान देशों से आयातों के पूर्ण ब्यौरे तथा उन पर बचाया गया शुल्क उपलब्ध नहीं कराया गया था। बाद में केवल यह था कि ये ब्यौरे दे दिए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी तेमबागा मूलिया सेमानन ने उपयुक्त समय पर पूर्ण सूचना नहीं दी और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सहयोग नहीं किया।
- पीटी तेमबागा मूलिया सेमानन ने प्रकटन विवरण की टिप्पणियों के भाग के रूप में कुल निर्यात कारोबार के बजाए कुल काराबार की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी मार्जिन का परिकलन कर सब्सिडी मार्जिन का परिकलन दिया है। प्राधिकारी

नोट करते हैं कि पीटी तेमबागा मूलिया सेमानन द्वारा परिकलित सब्सिडी मार्जिन प्रतिकारी शुल्क नियमावली के अनुसार नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने पी टी कारयासुमिडेन द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास कर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पी टी तेमबागा के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है।

- जहां तक पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कॉपर कंसट्रेट के प्रावधानों से संबंधित सब्सिडी कार्यक्रम संबंधी अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह एस सी एम करार और प्रतिकारी शुल्क नियमावली के अनुसार प्रतिकार योग्य कार्यक्रम है। वस्तुतः कई देशों ने उनके द्वारा की गई प्रतिकारी शुल्क जांचों में समान कार्यक्रमों का प्रतिकार किया है।

वियतनाम सब्सिडी कार्यक्रम संबंधी दावे

- जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों ने उन सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए लाभ प्राप्त नहीं किया जिनके लिए प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारी शुल्क निर्धारित किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक नहीं माना गया है और इसीलिए वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ठ. निष्कर्ष

557. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के संबंध में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि

- i. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत में संबद्ध देशों से मै. एस ई आई थाई इलैक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड से निर्यातों को छोड़कर सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर की गई है।
- ii. घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद को सब्सिडी दिए जाने के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।
- iii. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण हुई है।

ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

558. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर सब्सिडी दिए जाने की अनुचित व्यापार प्रथाओं के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने से किसी भी रूप में संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

559. यह मान लिया गया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं की लागत पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को लगाए जाने से विशेषकर यदि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से सब्सिडी प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित होता है, तब उस सीमा तक कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लगाने से सब्सिडी दिए जाने के कारण प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएंगे और समान अवसर दिया जाएगा।

ढ. सिफारिशें

560. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच को शुरू किया गया था और इसे मलेशिया की सरकार, थाइलैंड की सरकार, इंडोनेशिया की सरकार और वियतनाम की सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा सब्सिडी दिए जाने, क्षति और कारणात्मक संबंधों के पहलुओं पर उसके पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध सूचना/साक्ष्य उपलब्ध

कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था। सब्सिडी दिए जाने, क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच निर्धारित नियमावली के संबंध में शुरू किए जाने और उसे पूरा किए जाने के बाद तथा सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन तथा घरेलू उद्योग को इस प्रकार के सब्सिडी प्राप्त आयातों के द्वारा हुई वास्तविक क्षति को स्थापित करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है ताकि सब्सिडी दिए जाने और क्षति के प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सके। इस कारण से, प्राधिकारी यहां नीचे दिए गए निर्धारित रूप में और तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक मानते हैं।

- 561 प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कमतर शुल्क नियमावली के संबंध में, प्राधिकारी इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए सब्सिडी के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के समतुल्य निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम सं. 7 में किए गए उल्लेख के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

शुल्क तालिका	शीर्षक / उपशीर्षक	वस्तुओं का विवरण	उत्पत्ति का देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	पहुंच मूल्य के % के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7408	कॉन्टीन्यूअस कॉस्ट कॉपर वायर	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लि.	NIL
2.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	क्र. सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर कोई उत्पादक	3.46%
3.	-वही-	-वही-	थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम को छोड़कर कोई देश	थाइलैंड	कोई भी	3.46%
4.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी. टेम्बागा मुलिया सेमनन, टीबीके	3.75%
5.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी. कारिया सुमिडेन इंडोनेशिया	4.98%
6.			इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 4 और 5 में उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर कोई उत्पादक	7.94%
7.			थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम को छोड़कर कोई देश	इंडोनेशिया	कोई भी	7.94%

8.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी	2.47%
9.			मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	कं.सं. 8 में उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर कोई उत्पादक	10.27%
10.			थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम को छोड़कर कोई देश	मलेशिया	कोई भी	10.27%
11.			वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	कोई भी	7.13%
12.			थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम को छोड़कर कोई देश	वियतनाम	कोई भी	7.13%

562. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल हैं।

563. इस अंतिम जांच परिणाम के फलस्वरूप निकलने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2019

FINAL FINDINGS

Sub: Final Findings in Anti-subsidy investigation concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam.

No. 6/17/2018 -DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time thereof:

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, M/s. Hindalco Industries Limited and M/s. Vedanta Industries (Sterlite Copper) (collectively referred as “Petitioners” or “Applicants”), have filed an application on behalf of Domestic Industry before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for imposition of Countervailing Duty on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or “PUC”) from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Petitioners, issued a public notice vide Notification No. 6/17/2018 - DGAD dated 10th September, 2018, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a) The Authority notified the Embassies of subject countries in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 6 supra.
 - b) The Authority invited the Government of Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on subsidies and countervailing measures. The consultation was held on 12th July, 2018 and 13th July, 2018 in New Delhi, which was attended by the representatives of the Government of Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam.
 - c) The Authority issued a public notice dated 10th September, 2018 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating countervailing duty/anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods.
 - d) The Authority sent a copy of the initiation notification dated 10th September, 2018 to the Embassies of subject countries, known producers/exporters from subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Petitioners and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - e) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of subject countries in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.
 - f) The Embassies of subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - g) The Authority sent questionnaires to the Governments of subject countries in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred by the Governments. Governments of Thailand, Malaysia, Vietnam and Indonesia filed a questionnaire response, which has also been taken into account.

- h) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in subject countries, in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
- i. M/s. Krontong Scraps Company Ltd., Thailand
 - ii. M/s. Cosco Yu Metal Ltd., Thailand
 - iii. M/s. Siam Pacific Electric Wire & Cableco, Thailand
 - iv. M/s. Sei Thai Electric Conductor Co. Ltd., Thailand
 - v. M/s. Alpha Industries, Malaysia
 - vi. M/s. Metrod, Malaysia
 - vii. M/s. MettubeSdn. Bhd., Malaysia
 - viii. M/s. PM Copper Wire & Cables Sdn. Bhd., Malaysia
 - ix. M/s. LuvataMalasiaSdn. Bhd., Malaysia
 - x. M/s. PT. SnolictianTechnolica, Indonesia
 - xi. M/s. PT Karya Sumiden, Indonesia
 - xii. M/s. Nam Trieu Welding Material Industry Joint Stock Company, Vietnam
 - xiii. M/s. Muon Anh Trading Company Limited, Vietnam
 - xiv. M/s. SNC Vietnam JSC, Vietnam
 - xv. M/s. SNC Joint Stock Co., Vietnam
 - xvi. M/s. Dong Viet Non Ferrous Metal Joint Stock Company, Vietnam
 - xvii. M/s. Ngohan Joint Stock Company, Vietnam
- i) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:
- i. M/s. CFT Vina Copper Co. Ltd., Vietnam
 - ii. M/s. Dong Viet Non-ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company, Vietnam
 - iii. M/s. Alpha Industries Sdn. Bhd., Malaysia
 - iv. M/s. SEI Thai Electric Conductor Co. Ltd., Thailand
 - v. M/s. PT TembagaMuliaSemananTbk, Indonesia
 - vi. M/s. PT Karya Sumiden, Indonesia
 - vii. Metrod Malaysia SdnBhd
 - viii. Metrod (OFHC) Sdn Bhd.
 - ix. Metrod Copper Products SdnBhd
 - x. Panasonic Procurement Malaysia SdnBhd
- j) Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject countries, Government of Malaysia, Thailand, Vietnam and Indonesia have also filed the questionnaire response.
- k) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
- i. M/s. Polycab Wires
 - ii. M/s. Trafigura India Pvt. Ltd.
 - iii. M/s. Havells
 - iv. M/s. Precision
 - v. M/s. ASTA India Private Limited
 - vi. M/s. Crompton Greaves
 - vii. M/s. KEC International Limited
 - viii. M/s. Mothersons
 - ix. M/s. Duplex Wires
- l) In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response.
- i. M/s. Apar Industries Ltd.
 - ii. M/s. GK Winding Wires Ltd.

- iii. M/s. Great White Global Pvt. Ltd.
- iv. M/s Savli Copper products Pvt. Ltd.
- v. M/s Anchor Electricals Pvt. Ltd.
- m) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation.
 - (i) Government of Thailand
 - (ii) Winding Wires Manufacturers' Association of India
- n) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented/ submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- o) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCIS data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- p) The Non-Injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- q) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present Final Findings.
- r) Verification of the information provided by the producers/exporters and Government of Vietnam, Thailand, Indonesia and Malaysia to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and such verified information has been relied upon for the purpose of present Final Findings .
- s) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from April, 2017 to March, 2018 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.
- t) In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 29th March, 2019. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were advised to offer their rebuttals.
- u) The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present Final Findings.
- v) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this Final Findings.
- w) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- x) The Authority also called for comments on the proposed PCN methodology from the interested parties including domestic industry in order to have fair comparison vide Notification dated 5 April, 2019. Thereafter, PCN wise information was called for vide Notification dated 13 May, 2019.
- y) Further information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary.
- z) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the Final Findings on the basis of the facts available.
- aa) A Disclosure Statement was issued to interested parties on 21st October, 2019 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 29th October, 2019 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately in the present final findings.
- bb) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹ 65.33.

- cc) In this final findings, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

The product under consideration in the present investigation is “Continuous Cast Copper Wire Rods”, classifiable under Customs Subheading 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11, 7409.19.

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

- a) The product under consideration in the present petition is “Continuous cast copper wire rod”. The product scope specifically includes the following:
- Continuous cast copper wire rod
 - Copper wire
 - Copper rod
 - Copper wire rod
 - Continuous cast copper rod
 - Copper strip
 - Welding wires
- b) The scope of the PUC excludes the following:
- Rods made of copper-zinc base alloys (brass) or bronze (and similar alloys);
 - Copper weld wires
 - Wires made of copper- zinc based alloys (brass) or copper- nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) or bronze (and similar alloys);
 - Silver plated copper wires;
 - Tinsel wires;
 - Enameled copper wires;
 - Metal coated copper wires;
 - Insulated copper wires cables.
- c) The PUC is a solid uniform cross section along its whole length. The cross section can be round, oval, square, hexagonal, rectangular and other shapes. The PUC is generally in coil form. Copper wire & rod is reddish-orange in color and are made from one of the basic chemical elements- copper, a metal.
- d) The PUC is entering the Indian domestic market with various dimensions including 1.6mm, 1.8mm, 2mm, 2.6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm and 20mm.
- e) The Continuous cast copper wire rods of different diameters constitute one article for the purpose of present investigation, as these bear the same technical and physical characteristics.
- f) The investment required for drawing rod for making wires is negligible and cannot be treated as a different article.
- g) Copper wire rod and copper wire contain the same physical and technical characteristics.
- h) Both products are the outputs of continuous casting process. Copper wire imported also remains an intermediate product and is eventually drawn into desired sizes. The basic process up to the stage of rod or rod wire is the same for producing both rod or wire.
- i) The pricing of copper wire rods and wires also have a similar movement across the year.
- j) The primary raw material involved in making the PUC is copper cathode. Copper ore (containing less than 2% copper) is beneficiated into concentrates (containing 25%-30% copper).
- k) As seen in investigations pertaining to Glass Fibre and Articles thereof from China PR, Peroxosulphates also known as Persulphates from China PR and Japan, and Caustic Soda, a mere change in form does not necessarily mean a different article.

- l) All wire rods and wires perform the function of transmission of power and eventually find application in the cable, housing wire, winding wire, strips & transformers and auto industries.
- m) Copper wire rods of 8mm and above or copper wire of 1.6-5.7 mm cannot be directly used. They have to be drawn into wires up to 0.04 mm.
- n) The goods produced by the domestic industry are similar to the product under consideration in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers use the two interchangeably.
- o) Further, Chapter 74 of the Customs Tariff Act recognizes only (a) bars, (b) rods, (c) profiles, (d) wires. It does not recognize 'wire rods'. Petitioners are selling the product by clearing their production under '7408'.
- p) There is a significant difference between "wire/rod-in-coil" form which is 7408 products and "rod not in coil" form which is 7407. Petitioners have not sought CVD on the latter.
- q) Alpha Industries has provided a Product Catalogue, wherein they have identified themselves as "rods/wires" manufacturers. It has made no distinction between rods and wires. It is also evident that it uses 2/3rd of its rod production capacity for the purposes of drawing wires. This is indicative of copper wire below and above 6mm being one article with the only difference that rods are further drawn into thinner dia and are commercially described as wire.

C.2. Submissions made by the other interested parties

6. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:

- a) The present petition has been filed for the product "continuous cast copper wire rods" as per initiation notification. The initiation notification does not specify other forms of the products.
- b) "Continuous cast copper wire rod", "continuous cast copper rod" and "copper rod" are same product and can be used interchangeably but copper wire is a different product and is different from rods.
- c) As per para 6.5 of Chapter VI of Report No. 1 of 2017 Union Government (Indirect Taxes-Customs), copper wire and copper rods may be defined as under:

"6.5 Copper wire misclassified as copper bar/rods

As per note 1 (d) & (f) of Chapter 74, Bars and rods are defined as Rolled extruded, drawn or forged products not in coils. While wire is defined as Rolled extruded, drawn products in coils. Further, as per Bureau of Indian Standard (BIS) wire rod means rod products of uniform cross section dimension exceeding 6 mm used as intermediate product for further working supplied in cold form. Copper wire having cross sectional dimension exceeding 6 mm is classifiable under Customs tariff heading (CTH) 74081190 and attract Basic customs duty (BCD) at the rate of 5 per cent."

- d) Copper wire and copper rods are two distinct products and cannot be used interchangeably. The manufacturing process of the two are also different. Copper rod is produced by casting whereas copper wires are drawn from Copper Rods. Copper Wires are downstream products of Copper Rods.
- e) End use of the products are also different, rods are converted into wires and then used primarily for power and communication cables, transformers and magnet wires. Copper wires are made from Copper Rods. Copper Rods cannot be made from wires. Different machines are used for making copper wires from copper rods. The thickness of Rods is above 6 mm and of wires are below 6 mm.
- f) After the initiation of the present investigation, the Authority issued a notice to all the interested parties and requested to file data as per the PUC defined in the Initiation Notification, pursuant to which the petitioner deceived the Authority by furnishing data inclusive for PUC as well as non-PUC.
- g) Further, subsequent to the oral hearing, the Authority has issued a letter dated 5th April 2019 for adopting PCN methodology by adopting following PCNs for having a fair comparison between PUC and like article: (a) Continuous cast copper wire rods and (b) Copper wire. As established above, these are two different products.
- h) Authority has placed confidence in the claims of the petitioners without analyzing the PUC and like article on their own and at this stage proposed PCN methodology by adopting PCN for widening the scope of PUC. It is submitted that the Authority has not done due diligence before defining the scope of PUC.
- i) By adopting the PCN Method, the Authority is enlarging/widening the scope of PUC which is not permissible at this stage as per para 3.4 and 3.5 of Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations issued by DGTR.
- j) The PCN letter issued by the Authority is in contravention of the operating practices of the Authority.
- k) As per para 3.23 of Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations issued by DGTR, a letter for PCN shall be issued within 60 days of initiation of the investigation.
- l) The present PCN letter is issued after more than 200 days which is not in conformity with the operating practices followed by Directorate General of Trade Remedies. Thus, the scope of PUC cannot be enhanced at this stage.

- m) The objective of anti-subsidy investigation is to prove the existence of the benefit conferred by the government's financial contribution having specificity and then calculate the amount of such benefit to reach at subsidy rate level. As such, for the calculation of subsidy rate it is not required to compare the domestic price (normal value) with export price. In this situation, PCN may not be required.
- n) The customs headings are indicative only and not sacrosanct. The product may be classifiable under various customs headings, all those cannot be considered unless clearly specified by the Authority.
- o) It has been indicated by the Authority that the product is classifiable under various HS codes. The said HS codes include different products such as copper rods, copper wires, copper plates, sheets, strips and others. The Authority must clearly specify which is more relevant the description mentioned in PUC or the HSN codes.
- p) Reference to Chapter Headings is only for the purpose of indicating that the PUC (as defined by them) is also being imported under various headings. The PUC would be restricted to what is unambiguously mentioned within quotes i.e., "Continuous Cast Copper Wire Rods" both in the application as well as in the initiation notification.
- q) The product being imported from subject countries is only copper wire, not copper rods or other forms.
- r) Copper wires are used in critical sectors of the economy including Power Generation, Power Transmission & Distribution, Railways & Defence, Industrial Equipment, Automobiles, Refrigeration & Air Conditioner, Fans, Washing Machines, Appliances, Lighting, Electronics etc.
- s) Indonesia's export to India only covers copper wire with a diameter from 2.6mm to 1.6mm (the majority is 1.6mm) which is far below the Petitioners' copper rod production with a diameter of 8 mm and above.

C.3. Examination by the Authority

7. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes as follows:
 - a) The very first step in an investigation is to identify the product under consideration. The product under consideration is the imported product which is allegedly causing injury to the domestic industry. On the basis of submissions made by various interested parties and the examination of import statistics, the Authority holds that the product under consideration in the present investigation is "Continuous Cast Copper Wire falling under tariff heading 7408 of the Customs Tariff". The product under consideration includes Copper Wire of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm as well 6 mm and below. As per Chapter note (f) to Chapter 74, Wire means "Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section exceeds one-tenth of the width". The following are excluded from the scope of the PUC:
 - i. Rods made of copper-zinc base alloys (brass) or bronze (and similar alloys);
 - ii. Copper weld wires;
 - iii. Wires made of copper- zinc based alloys (brass) or copper- nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) or bronze (and similar alloys);
 - iv. Silver plated copper wires;
 - v. Tinsel wires;
 - vi. Enameled copper wires;
 - vii. Metal coated copper wires;
 - viii. Insulated copper wires cables.
 - b) The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.
 - c) Continuous Cast Copper Wire produced by the domestic industry is a like article to the Continuous Cast Copper Wire imported from the subject countries. The Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic Industry and that exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable, collectively and cumulatively, in terms of product characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority holds that product under consideration produced by the applicant domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from subject countries in accordance with the Anti-Subsidy Rules.

- d) As regards to submissions that by adopting the PCN Methodology at a belated stage, the Authority is enlarging/widening the scope of PUC, the Authority notes that in order to have a fair comparison between different types/forms of the product, the Authority has proposed the PCN methodology in the present investigation.
- e) As regards the contention made by some interested parties that for the first time PCN methodology was developed on the basis of tariff code, the Authority notes that it was done to address the concerns raised by some of the stakeholders that the imported product are different from the one produced by the domestic industry. It was therefore considered appropriate to develop a PCN methodology based on tariff code.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

8. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:
 - a) Production of Hindalco constitutes a major proportion of Indian production of the like article. Hindalco has been considered as the domestic industry and all the injury parameters have been analysed considering Hindalco data.
 - b) Vedanta could not provide its injury information in the form and manner prescribed in view of difficulties in compiling relevant information due to difficulties being faced by the Company due to Government orders. Vedanta is willing to provide relevant information but was unable to.
 - c) Hindalco has neither imported the subject goods nor is related to any of the importer or exporter.

D.2. Submission of other interested parties

9. The submissions made by interested parties with regard to the scope and standing of the domestic industry are as follows:
 - a) As per the Application, there are three major producers of subject goods namely (a) M/s Hindalco Industries; (b) M/s Vedanta Industries (Sterlite Copper); and (c) Hindustan Copper Ltd. Amongst three producers, leading producers namely M/s Hindalco Industries and M/s Vedanta Industries (Sterlite Copper) have filed the application and supported the application. The third Indian producer namely Hindustan Copper Ltd. has neither claimed subsidy/injury nor supported the Application.
 - b) Vedanta could not provide injury information due to difficulties faced by them due to Government orders, therefore, Hindalco has been considered as domestic industry since its production of like article constitutes a major proportion of the total domestic production. There must be some other factors causing injury to the petitioners because of which they are not even able to provide the injury information to the Authority.
 - c) Further, the petitioners considered Hindalco as the domestic industry themselves and stated in written submissions that Hindalco constitutes “domestic industry” as its production of the like article constitutes a major proportion of the total domestic production of like article.
 - d) The composition of domestic industry must be defined before the initiation and that the petitioners cannot redefine the standing of domestic industry themselves. It is the discretion of Hon’ble Director General to consider the request or not.
 - e) In terms of Rule 6 of the Anti-subsidy Rules, the applicants should account for at least 25% of the total domestic production. In the absence of the necessary and mandatory condition being fulfilled, there is no question of this investigation to continue as regards the “Copper Wires”. Applicants clearly would fail the test of standing in terms of Rule 6 for “Copper Wires”.
 - f) The applicants also do not constitute the “Domestic Industry” as they do not account for “a major proportion” of the total domestic production once the production of the “Copper Wires” is also included in the total domestic production in the country. As submitted above, the applicants constitute a meagre less than 2% of the total domestic production. It is apparent that the Domestic Industry has attempted to surreptitiously rope in the “Copper Wires” by obfuscating the two altogether different products namely, “Copper Wire Rods” and “Copper Wires”.
 - g) Further, as per para 4.9.16 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations issued by DGTR, if the companies do not provide the relevant information, disciplinary actions shall be taken. In the present investigation, since Vedanta has not provided the relevant and mandatory injury information, disciplinary actions should be taken and the present investigation must be terminated.

D.3. Examination by the Authority

10. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

“domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”.

11. The petition was filed by M/s. Hindalco Industries and M/s. Vedanta Industries (Sterlite Copper).
12. There are three producers of the subject goods in India, namely, M/s. Hindalco Industries Limited, M/s. Vedanta Industries (Sterlite Copper) and M/s. Hindustan Copper Limited. The Authority notes that one of the petitioner company M/s. Vedanta Industries (Sterlite Copper) has imported the subject goods during the period of investigation and thus becomes ineligible to be a part of the domestic industry. M/s. Vedanta Industries (Sterlite Copper) has also not submitted the requisite information to the Authority to consider it as a part of the domestic industry.
13. There are certain producers of copper wire in India who import copper wire of higher dia and draw it into copper wire of lower required dia. The Authority has not considered the production of such producers of copper wire in India because they are importing one form of the PUC and converting it into other form of PUC. With respect to those producers who do not import but procure copper wire of higher dia from domestic producers, taking their production into account would lead to a situation of double counting.
14. The Authority further notes that M/s. Hindalco Industries Limited has neither imported the subject goods nor is related to any importer or exporter of the subject goods. The Authority holds that M/s. Hindalco Industries Limited commands a major proportion of the production of the subject goods in India. Accordingly, for the purpose of this investigation, M/s. Hindalco Industries Limited satisfies the standing requirement and constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 6(3) of the Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by domestic industry

15. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
 - a) Excessive confidentiality has been claimed by exporters and governments of the subject countries.
 - b) The Parent Company of M/s SEI Thai Electric Conductor Co. Ltd. (STEC) Thailand has abstained from responding to the Exporter Questionnaire.
 - c) STEC has failed to prove why exports on 'VAT Exemption on Exports Scheme' is not a subsidy and has further claimed excessive confidentiality with regard to information pertaining to the scheme.
 - d) Alpha Industries has not stated whether they are related to any company engaged in the production or sales of the PUC. However, one of the responding companies from Indonesia, namely, PT. Tembaga Mulia SemananTbk, in the current investigation itself has provided in their questionnaire response that Alpha Industries is one of their affiliated companies.
 - e) The questionnaire response made by the exporters is deficient and suppresses the information, or the information is otherwise incomplete as the responses are not provided as per the format specified in the exporter questionnaire response.
 - f) Panasonic Procurement Malaysia has stated that Metrod Malaysia Copper Products Sdn. Bhd. is one of the factories involved in the production of the product. However, Metrod Malaysia Copper Products Sdn. Bhd in its questionnaire response has stated that they are solely a trader. Hence, there is a clear contradiction, making the two responses unreliable.
 - g) Indonesia has resorted to excessive confidentiality by not providing the Annual report of "Bank Mandiri" to the extent of abuse of confidentiality law.
 - h) Merely because the domestic industry may not be precisely aware of the way schemes operate, eligibility criteria, application process, etc. does not imply that the same can be claimed confidential.

E.2. Submissions by other interested parties

16. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
 - a) The non-confidential version of the petition violates the requirements and standards laid down in in Rule 7 and 8 of the CVD Rules and Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the DGTR.
 - b) The Petition does not comply with Trade Notice no. 10/2018 dated 7th September 2018, which sets standards for disclosure of information in confidential version/non-confidential version of responses filed by the domestic industry and other interested parties with a view to streamline the investigation process.
 - c) The petitioners have claimed excessive confidentiality and filed an incomplete petition.
 - d) The Petitioners have failed to provide sufficient evidence to substantiate the claims of injuries suffered in terms of production, capacity utilisation, sales volume and value, profitability, employment and wages and return on investment.
 - e) The Petitioners have not provided the minimum information in a non-confidential summary or in indices form for price undercutting and stocks to allow affected parties a meaningful understanding to raise appropriate defence.
 - f) The petitioners have provided the numbers of existing and potential capacities of other producers in India. However, the same was not provided for themselves.

- i) The information supplied by the Petitioner in its application does not allow reasonable understanding of the magnitude of subsidy margin and injury suffered by the local industry.
- j) The Petition does not contain the injury information of both the applicants. Therefore, initiation of the present investigation is not valid.

E.3. Examination by the Authority

17. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

“Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

18. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.
19. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

20. The petition filed by Domestic Industry provided prima facie evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country to initiate the instant investigation prior to initiation of investigation. Government of Indonesia, Malaysia, Vietnam and Thailand were invited for consultation, which was held on 12th and 13th July, 2018 in New Delhi. The producers and exporters from Indonesia, Malaysia, Vietnam and Thailand were advised to file response to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.
21. The following producers/exporters from Indonesia, Malaysia, Vietnam and Thailand including the Governments of Indonesia, Malaysia, Vietnam and Thailand have filed questionnaire responses.
- i. M/s. CFT Vina Copper Co. Ltd., Vietnam
 - ii. M/s. Dong Viet Non-ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company, Vietnam
 - iii. M/s. Alpha Industries Sdn. Bhd., Malaysia
 - iv. M/s. SEI Thai Electric Conductor Co. Ltd, Thailand
 - v. M/s. PT Tembaga Mulia SemananTbk, Indonesia
 - vi. M/s. PT Karya Sumiden, Indonesia
 - vii. Metrod Malaysia Sdn Bhd
 - viii. Metrod (OFHC) Sdn Bhd.

- ix. Metrod Copper Products SdnBhd
- x. Panasonic Procurement Malaysia SdnBhd

General overview of the alleged Subsidy Programs

F.1. Submissions made by domestic industry

22. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. Exporters have stated "not applicable" on all the schemes on the grounds that the company did not avail the specified programs. However, when a company is eligible for a program, there is no reason to believe it would not have benefited under program. Thus, either the company should show absence of eligibility or must demonstrate why it has not availed benefit that is available under the program.
- ii. Alpha Industries has only responded with respect to four programs, and haven't provided even a single submission for the rest of the 30+ programs alleged by the petitioners.
- iii. The response filed by the Government of Malaysia is contradictory to the response filed by Alpha. The Government of Malaysia has stated that Alpha meets the eligibility criteria for Program 23: Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment. However, Alpha Industries hasn't responded for this program.
- iv. Moreover, for Program No. 19- Draw back on Import duty, Sales tax and Excise duty the Government of Malaysia stated that it is not applicable to any of the companies under investigation; however, Alpha Industries has accepted to receive benefits in their specific response.
- v. Government of Vietnam has provided information with regard to other subsidies information apart from initiated schemes.
- vi. Program no. 5 and 9 are not preferential and at concessional rates but Government of Vietnam has not provided the details with regard to interest rate and concessional rate.
- vii. With regard to termination of P-8 Export Support Credit, information has been suppressed. Regarding Decree 151/2006/ND-CP -2006, none of the responding exporters stated that the said scheme is terminated. They simply stated that they have not availed the said benefit.
- viii. Petitioners submit that the Government of Vietnam has not filed a complete questionnaire response.
- ix. Government of Vietnam (GOV) stated in their questionnaire response that there are other "import duty exemption for equipment for equipment and machinery to create fixed asset". The said program is administered by Ministry of Finance department of Vietnam Customs (GDVC). GOV stated that CFT Vina Copper was entitled to exemption from import duty for imported equipment and machinery to certain fixed assets in 1996, which was prior to POI. However, the exporter has suppressed the said fact.
- x. With regard to exemption on corporate income tax for enterprises Government of Vietnam stated that Copper is entitled for the exemption. However, the responding exporters CFT Vina Copper & Dong Viet Nonferrous and Plastic JSC have suppressed the information with regard to availment of any such benefit.
- xi. Government of Vietnam stated that Program 1 is terminated. In contradiction to Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint stock Company stated that they have availed the said benefit during POI.
- xii. Information on the companies under investigation as to which companies have applied for, claimed, received or used assistance under Program No. 3 and have met the eligibility criteria has not been provided for. No information is provided whether the companies have taken any benefit under the scheme or not.
- xiii. The company which is eligible for benefit and has applied for benefit under Programme no. 6, 7, 17 has allegedly not received/utilized any benefit. It remains beyond reasonable comprehension that a company applied for benefit but has not received the benefit.
- xiv. The company received a 50% deduction of normal tax rate corporate income tax exemption period granted under Section 31 of Programme No. 8. The mere fact that the company is eligible should be disclosed by the Government of Thailand and further information with regard to the scheme and quantum on the basis of entitlement should be provided.
- xv. The company received double deduction of transportation, electricity and water supply costs from assessable income for a period of 10 years under Programme 9. The Government of Thailand evaded the question related to this posed in the questionnaire.
- xvi. The company received permission to deduct from the net profit an amount not exceeding 25% of the cost of installation and facilities used in the promoted activity under Section 35(3) of Programme 10. The Government of Thailand evaded the question related to this posed in the questionnaire.

- xvii. Programme 18 and 19 are mentioned but no further information has been provided.
- xviii. For loan benchmark schemes, it has been stated that the company has not used program listed in the investigation nor taken loan from any state-owned bank. It cannot be assumed that a loan from a private bank amounts to no subsidy.
- xix. For tax program, the company has stated that it has not availed any benefit under any scheme but has made disclosures under Program No. 7. There is a clear contradiction and suppression of facts.
- xx. For LTAR, the company has stated that there is no provision of goods or services applied in the company. The exporter is completely silent about mining subsidies.
- xxi. No response is provided in the EQR in relation to 'other subsidies'. The exporter should either report 'other subsidies' or state that there are no other subsidies.
- xxii. Program No. 11- Reinvestment Allowance: Benefit under this programme is given to existing companies engaged in manufacturing activities that reinvest for the purposes of expansion, automation, modernization or diversification of its existing businesses into any related products with the same industry on condition that such companies have been in operation for at least 36 months effective from the Year of Assessment 2009. Eligibility is key to consideration of de jure specificity.
- xxiii. Program No. 12: Accelerated Capital Allowance (ACA): The petitioners have submitted that the Accelerated Capital Allowance (ACA) is available to enterprises reinvesting in manufacturing of promoted products. The eligibility criterion thereby becomes specific as only the enterprises that promoted products and thereby reinvest are the only ones who can benefit from manufacture from the special allowance provided under this program.
- xxiv. Program No. 13: Group Relief: The petitioners submit that in order to avail the benefit under the Group Relief program, one of the eligibility criterion requires the enterprise to be using an automation equipment that is used directly in manufacturing activities, and the enterprise should have a paid-up capital in respect of ordinary shares of more than RM 2.5 million at the beginning of the basis period for that year of assessment. Such a criterion which is favourable to existing enterprises engaged in manufacturing activities can't be argued to be neutral, and this program prima facie favours certain enterprises over others. Hence, the concerned program is to be considered countervailable as per ASCM and Indian rules.
- xxv. Program No. 15: Allowance industry Building/ Industrial Building Allowance: In order to avail the benefit under the Industrial Building Allowance program, the enterprise should have incurred capital expenditure on the construction or purchase of a building that is used for specific purposes, which includes manufacturing, agriculture, mining, infrastructure facilities, research, Approved Service Projects and hotels that are registered with the Ministry of Tourism. Since the purposes behind the usage of building has been narrowed down to a list, it is clear that this scheme is only limited to certain kind of enterprises who are engaging in such activities; hence, this program is enterprise specific. Therefore, the concerned program is countervailable as per SCM Agreement and Indian rules.
- xxvi. Program No. 16: Allowance for plants and machinery/Capital Allowance (CA): An objective criteria which is favourable to enterprises carrying out a commercial activity with a certain amount of qualifying expenditure which is then being used in plants and machinery can't be argued to be neutral, and this program prima facie favours certain enterprises over others. Hence, the concerned program is to be considered countervailable as per SCM Agreement and Indian rules.
- xxvii. Program No. 19: Draw back on import duty, sales tax and excise duty, Program No. 21: Exemption from Import duty and sales tax for outsourcing manufacturing activities, Program No. 23: Exemption from Import duty and sales tax on machinery and equipment, Program No. 14: Tariff Related Incentives/ Exemption on import duty from raw materials & Program No. 24: Exemption from import duty on raw materials/equipment:: It is important to check whether the amount of credit is calculated in relation to actual inputs used. Moreover, there should be a system or procedure in place to confirm which inputs (including their amounts and origin) are consumed in the production process of the exported product or whether an excess payment of import duties occurred within the meaning of item (l) of Annex I, and Annexes and III of the basic Regulation.
- xxviii. Program No. 5 (a): Investment Loan & Program 5(b): Loan for entrepreneur: Mandiri Bank is a State-Owned Bank established in 1998 as part of Governments program to restructure banking sector. While majority of the bank's share is owned by Government of Indonesia, 7.01% of share is owned by national investors and the balance 32.99% is owned by foreign investors. This SOE Bank is the administrative authority acting in the form of public body and providing medium and long term credit facility at concessional rate of interest. Program 5(a) Investment Loan is specific because it is available only to limited number of business enterprises and individuals, program 5(b) Loan for entrepreneur because it is available only to limited number of enterprises which are new individual entrepreneurs and SME businesses with financing needs above 100 million Rupiah and up to 5 billion Rupiah. The program provides a benefit to the extent that the amount of interest the firm paid on the guaranteed loan is less than the amount of interest the firm would pay for a comparable loan.

- xxix. Program No. 2: Exporter (STEC) has claimed that they have received benefit under Investment Promotion Act 2002, but they have suppressed the fact that the said act has been updated in 2017. Received exemption from Import Duty on capital goods but suppressed the information with regard to AUL period with regard to exemption. Accounting treatment given to the benefits received under this program does not capture the benefit under this program. Exporter has completely suppressed the fact that under which system benefit is reflected.
- xxx. Program no. 5: Exporters stated that it is not applicable because import duty on primary raw material i.e. copper cathode is NIL from 1st Jan 2017.
- xxxi. Program No. 9: Exporters claimed excessive confidentiality with regard to nature of scheme and description.
- xxxii. The Government of Thailand in their response have stated that STEC has taken the benefit under three programs, namely program no. 13, 14, 15. STEC has not agreed having taken the benefit under any of the above mentioned programs.

F.2. Submissions made by other interested parties

23. The following submissions have been made by the other interested parties:

- i. Article 11.3 of the SCM Agreement requires an investigating authority to review the accuracy and adequacy of the evidence provided in a petition in order to determine whether it is "sufficient" to justify the initiation of an investigation.
- ii. Para 8 of the initiation notification read as follows:
*"8. The Authority finds that there is **prima facie evidence** of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject countries and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their volume and price effects. Further the threat of material injury to the domestic industry on account of subsidized imports has also been alleged by the domestic industry."*
- iii. It must be noted that "prima facie" and "sufficient" are two completely distinct terms, imply different standards and are not interchangeable.
- iv. The petitioner could not establish the existence of the three elements comprising a countervailable subsidy, i.e. financial contribution by a government or public body; benefit; and specificity.
- v. The GOI's consistent use of a lower standard of assessment and its failure to first determine that the petition provides "sufficient evidence" of subsidization of the continuous cast copper wire rods exporting producers and resulting injury to the Indian industry is a fatal error.
- vi. The GOI should justify:
 - i. whether it has assessed the adequacy and accuracy of evidence concerning subsidization provided by the petitioner; and
 - ii. the basis on which it considers that the petition contains adequate and accurate information with respect to each subsidy scheme as regards to the exporting producers of the product.
- vii. The failure to provide "sufficient evidence" cannot be shielded by the claim that a petition contains such information as is "reasonably available" to the petitioner.
- viii. No details of calculations have been provided. The petitioners cannot keep assessment of subsidy as confidential from the exporting members.
- ix. None of the programs that is claiming to be benefitting the producers/exporters listed in the petition is substantiated with sufficient evidence
- x. In its submission, the petitioners stated that "The Government of Vietnam has specified that the responding producer/exporter CFT Vina Copper Co. Ltd. has taken a benefit under Program No.2: Import duty exemption or reimbursement for raw material" without providing any supporting citation.
- xi. The Government of Vietnam responded to the Authority's questions on Program No.2 on pages 25-32 of the non-confidential response and nowhere in such discussion indicates that CFT took a benefit under this Program.
- xii. CFT also notes that in its response, it clearly stated that it did not receive any benefit under Program 2 and provided supporting data to show no benefit because the standard import duty rate for the raw materials imported by CFT is 0%.
- xiii. No subsidy allegation is supported by any citation evidence, which demonstrates their superficial understanding of the Vietnam's law and practice applicable to copper wire rod producers or their intention of misleading the authority by using unfounded allegation.

- xiv. In Program 11, Investment support on foreign investors who invested in establishing small and medium scale enterprises, it has been claimed that it is a "Foreign investors specific subsidy".
- xv. CFT discussed the program of "Interest Rate Support by SBV" at pages 34-35 of its initial response. Accordingly, the 4% support on interest payments for short-term loans of up to an 8-month term disbursed by credit institutions between February 1 and December 31, 2009 while 4% support on interest payments for medium- to long-term loans of up to a 24-month-term disbursed by credit institutions between April 1, 2009 and December 31, 2011.¹⁰ Thus, the support under this program ceased long before the POI. The discussion repeatedly demonstrates that the interest rate support by the SBV was not available during the POI and CFT did not receive any benefit from this program. Exhibit 32 to CFT's initial response providing the legal regulations governing this program is the public and obvious evidence to prove that no interest rate support was provided during the POI.
- xvi. Although the Applicants have alleged that the Government of Thailand is providing subsidies under the alleged 20 programs, it is submitted that most of the programs are repetitive and no countervailable duty is leviable on subject goods exported from Thailand.
- xvii. As per the questionnaire response filed by the Government of Thailand, alleged programs can be categorized under three broad categories: (i) First Programs which are terminated; (ii) Second Programs which are consistent with WTO-ASCM; (iii) Third Programs which do not confer a benefit.
- xviii. Program alleged by the Applicants are already terminated by the Applicants: In terms of Rule 5 (3) (b) of the CVD Rules, no investigation should be initiated unless there is evidence of (a) subsidy, (b) injury and (c) causal link. However, the present application is filed based on obsolete data and contrary to the data/notifications filed by the Government of Thailand before the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
- xix. Unless the Applicants substantiate the existence of subsidy, the investigation cannot be initiated against such alleged program.
- xx. It is submitted that programs alleged by the Applicants are either non-countervailable or discontinued or does not exist at all. As an illustration, the Authority may note that program titled 'Gold Card Scheme' has been discontinued by the Government of Thailand
- xxi. Duty exemption and remission programs are not prima-facie countervailable, unless the Applicants place documents on record to reflect that "the remission of such duties or taxes is in excess of those which have accrued". The duty remission or exemption program in Thailand are WTO compliant.
- xxii. The United States Department of Commerce examined Program No. 5 of the present investigation i.e. Exemption of Import duty on Raw Material Imported for use in Production for Export and determined this alleged program as non-countervailable.
- xxiii. Alleged programs do not confer benefit to the recipients.
- xxiv. The RTG highlights that the USDOC has recently examined Program No. 2 of the present investigation i.e. Exemption/Reduction of Import Duties on Machinery –Section 28 of the Investment Promotion Act ('IPA'). While examining the program, USDOC noted that VAT exemption on import of capital goods from China in terms of Section 28 is not countervailable since the import of capital goods from China is subject NIL VAT rate under ASEAN China Free Trade Area. Accordingly, USDOC held that the importer of capital goods from China has not received a benefit in the form of VAT exemption. Further, in absence of benefit, USDOC held that tax exemption under Section 28 of IPA is not countervailable
- xxv. The Kingdom of Thailand and Republic of India entered into an FTA for enhanced cooperation and progressive reduction of trade barriers. Applicants should not be allowed to offset the benefit under the FTA by seeking a levy of duty.
- xxvi. In terms of Article 15 of the FTA, if the alleged injury is on account of concession under the FTA, the applicant can seek appropriate relief under the FTA framework.
- xxvii. The listing of 34 alleged Malaysian programmes were merely downloaded and without justification the listed programmes were tied to the Product under Consideration (PUC).
- xxviii. The Petition fails to provide on how the Malaysian producers could have availed to the listed programmes. The GOM concerns were substantiated through our submission of questionnaire responses dated 2 November 2018 where it is clearly proven none of the companies under investigation applies for, accrued, or received benefit from all alleged programmes except for six programmes. In fact the six programmes do not constitute countervailable subsidies as it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available to all companies in Malaysia.
- xxix. Based on these arguments, it is clearly established that the Petition lacks accuracy and adequacy to establish sufficient evidence to justify even the initiation of anti-subsidy action.

- xxx. The Government of Malaysia (GOM) requests the observations raised be given serious consideration in making the decision on the anti-subsidy investigation. The GOM reserves the right to raise these and any other issues concerning this investigation at a later date.
- xxxi. It is important to emphasize that subsidy allegation concerning export tax regime is no longer the subject of the current investigation.
- xxxii. The essence of our argument on the export tax regime is that it does not constitute subsidy as there is no financial contribution which can confer benefit.
- xxxiii. Moreover, in no way, such restriction can distort the price of copper ore or concentrates in Indonesia due to the fact that the products that contain copper are determined by the spot price set by the London Metal Exchange (LME). For domestic sales, Indonesian smelter companies purchase materials (Concentrate) using LME's price. Furthermore, the Indonesian Copper Wire Rods producers purchase Cathodes using the same standard. For export sales, Indonesian smelter companies sell their products using LME's price plus premium. Nonetheless, due to the price in the domestic market use LME's price, the export tax regime does not have any impact on the domestic price.
- xxxiv. The Petitioners also refer in their submission on the export restriction for coal. This is again irrelevant, and coal is used for energy and as such this restriction is for all sectors of industry. Thus, the export restriction for coal does not even have specificity.
- xxxv. It is completely unacceptable that the Petitioners' alleged FTA within ASEAN Countries is subsidy which "pass-through" benefit for the countries. This is entirely irrelevant as FTA is justified under the WTO Agreement and numerous FTA are existing nowadays in which India is also taking an active part.
- xxxvi. In petitioners' submission, they claimed that a contradictory response between the Indonesian government and Indonesian producers occurred when answering subsidy program No. 12. Program No. 12 refers to the facility under the Special Economic Zone (SEZ). Since the two producers are not conducting operation within any SEZ in Indonesia, they are not entitled to avail the facilities. However, neither Indonesian government nor Indonesian producer erred in this respect.

F.3. Calculation Methodology

24. Article 14 of ASCM, provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lays down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.

F.4. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners

Thailand

F.5. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners

(i) Program No. 1: Gold Card Scheme

a. Submission by the Petitioners

25. The Petitioners submitted that under this subsidy program, imports and exports are processed via "green line". These imports and exports are exempted from examination. Tax claims as well as drawback claims are approved at the time of filing. The Gold Card Scheme is administered and provided by Government of Thailand and Ministry of Finance which provides a measure to enable to assist Importer and Exporter for Customs Clearance under Electronic Data Interchange (EDI) as per Custom notification dated 25th January, B.E. 2542 (2000)

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

26. Importer and Exporter with Gold Card Status expired on 1st October 2013. Importer and Exporter with Authorised Economic Operator (AEO) Status has been in force from February 5th, 2013 vide B.E. 2556 (2013). Privileges are granted in the form of speedy tax refund and compensation, customs procedure for import and export, legal case under specified conditions etc.

c. Examination by the Authority

27. The Authority notes that Gold Card Scheme expired on 1st October 2013 and was not in force during the period of investigation. Gold card scheme was replaced by Authorised Economic Operator (AEO) status vide Customs Notification no. 12/2556.
28. Authority notes that certain privileges are granted under the AEO status. Privileges granted under the AEO status to the beneficiary are in the form of trade facilitation measures, which are administrative in nature and are not in the nature of financial contribution. Therefore, the benefit received by AEO status holder is not a subsidy. Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(ii) Program No. 2: Exemption/reduction of import duty on machinery**a. Submission by the Petitioners**

29. The petitioners submitted that the said program is administered by the Office of the Board of Investment ("BOI") and Investment Promotions act (IPA). Section 28 of Investment Promotion Act, 2002 (IPA) provides exemption/reduction on import duty for any imports of machinery/equipment for approved investment projects. The program provides repayment of import duties which is specific because it is available only to limited number of enterprises under this subsidy program, import duty is reduced up to 90% on the import of machineries.

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

30. The purpose of this program is to facilitate companies that are entitled to receive benefits under Section 28 of the Investment Promotion Act (IPA) by exempting import duties of certain imported machinery that is needed for the Board of Investment (BOI)-promoted projects.
31. Companies that wish to apply for BOI investment promotion must submit one application form for each project. If the project meets the approval criteria, the BOI will grant rights and benefits as a package. BOI investment promotion will not be granted on the incentive program basis. In other words, the BOI does not grant incentives program-by-program, but rather as a package of IPA benefits the companies are entitled to receive. However, when (or if) a BOI-promoted company actually decides to utilize particular benefits granted under the IPA package, the company must submit a request separately for utilizing each benefit. GOT stated that SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd applied for BOI investment promotion for production of copper wire rod which is eligible to receive investment promotion under BOI Announcement No. 10/2552 (2009). SEI Thai Electric Conductor Ltd submitted that they have availed the said benefit under Section 28 of the Investment Promotion Act, 2002.

c. Examination by the Authority

32. Authority notes that Investment Promotion Act, 2002 (the Act) provides for certain rights and benefits to promoted entities/projects/activities (Investment Promotion Package Scheme). Section 16 of the Act prescribes that the Board of Investment (BOI) will make an announcement designating the types and sizes of investment activity eligible for benefit specified under the Act.
33. Section 28 of the Act provides exemption from payment of import duties on machinery under approved investment projects and not for reduction of import duties on machinery. Section 30 of the Act provides for reduction (not exceeding ninety percent) of import duty on raw materials and not for exemption/ reduction of import duty on machinery.
34. STEC, the sole responding exporter from Thailand has submitted in its questionnaire response that it availed exemption from import duty on the import of machinery under the Investment Promotion Package Scheme and has provided information with regard to the amount of subsidy received by them during the POI.
35. Program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. The fact that STEC benefitted from the program shows that program was in fact used by the producer/exporter in Thailand that exported the subject product to India during the POI. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(iii) Program No. 3: Income Tax Exemption**a. Submission by the Petitioners:**

36. The petitioner submitted that under this subsidy program, exemption is provided from income tax to eligible entities.

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

37. This exemption is provided under the BOI scheme. BOI grants benefit on corporate income tax exemption for the BOI-promoted projects only. The benefit will be provided under Section 31 of the Investment Promotion Act.

c. Examination by the Authority

38. The Authority notes that the subsidy program is one of the benefit provided under the investment promotion package scheme. Section 31 of the Act provides exemption from corporate income tax to eligible entities.
39. Program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. STEC, the sole responding producer/exporter from Thailand has submitted in its questionnaire response that it did not avail this subsidy because it did not earn any profit since the commencement of its business including the POI. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for STEC.
40. However, Authority notes that the benefit under this subsidy program was available to producer/exporter of subject product in Thailand who earned net profit during the POI. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program for all other producer/exporters of this product from Thailand.

(iv) Program No. 4: Exemptions with regard to investment promotion zone**a. Submission by the Petitioner**

41. Petitioner submits that entities are granted 50 percent reduction in the normal rate of corporate income tax on the net profit derived from the promoted activity for a period of not more than five years.

b. Submission by the Government of Thailand/Other interested parties

42. Under the Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977), the exemptions that the BOI grants to the promoted companies include:

- (1) Section 28: Exemption of Import Duties on Machinery
- (2) Section 31: Exemption of Corporate Income Tax
- (3) Section 36: Exemption of Import Duties on Raw and Essential Materials

c. Examination by the Authority

43. Authority notes that exemption of import duties on machinery and raw materials and exemption of corporate income tax have already been countervailed by the Authority in other programs. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this subsidy program.

(v) Program No. 5: Exemption of Import duty on Raw Material Imported for use in Production for Export**a. Submission by the Petitioner**

44. Petitioner submitted that under this program, exemption is granted from import duties on raw materials, which are used for producing commodities for export. Exemption is granted from import duties and export duties for promoted persons products and assembly operations.

b. Submission by the Government of Thailand/Other interested parties

45. Investment Promotion Act created the investment promotion program and authorized the BOI to grant investment promotion incentives, including import duty exemption on raw materials or essential materials used in the BOI-promoted projects under Section 36.
46. The investment projects that are entitled to receive benefits under Section 36 are granted one or more of the following special benefits:

- (1) Exemption of import duties on the raw and essential materials imported for use specifically in producing, mixing, or assembling products or commodities for export; and
- (2) Exemption of import duties on items which the promoted person imports for re-export. The foregoing shall be in accordance with the conditions, procedures, and certain period of time as prescribed by the BOI. Also, the raw materials and essential materials must be used for the promoted projects only.

47. The purpose of this program is to facilitate companies that are entitled to receive benefits under Section 36 by exempting import duty on raw or essential materials used in BOI-promoted projects. BOI has an effective system in place in order to ensure that the import quantity of the raw or essential materials are not exceeding the revolving maximum stock and to ensure that the companies do export those imported raw or essential materials as finished goods.

c. Examination by Authority

48. Authority notes that Section 36 of the Act provides for exemption from import duty on raw or essential materials used in BOI-promoted projects. Under this subsidy program, the products produced using duty free inputs are

required to be re-exported or exported after undergoing mixing, assembling and production activity. This subsidy program is a part of investment promotion package scheme.

49. Government of Thailand has submitted that BOI has an effective system to ensure that companies export the imported raw material as finished goods and there is no excess benefit to the producer/exporters carrying out the promoted activity. Government of Thailand has not provided any explanation and has not provided any evidence to show how the mechanism operates under the BOI scheme to ensure that there is no excess benefit and that raw material that is imported duty free is used in the exported product. In absence of any evidence to show that the program provides for permissible tax remission program, it is determined that the subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is contingent on export and is also limited to promoted enterprise carrying out promoted activity.
50. STEC, the sole responding producer/exporter from Thailand has submitted in its questionnaire response that it did not avail this subsidy because the import duty on the raw material copper cathode imported by STEC was already zero. Authority has verified the claim of STEC. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for STEC.
51. However, Authority notes that in absence of complete details with regard to raw material used by other producers/exporters in Thailand, source of procurement and the applicable import duty details, the Authority notes that the benefit under this subsidy program can be availed by other producers/exporters of subject product in Thailand. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program for all other producer/exporters from Thailand.

(vi) Program No. 6: Reduction of import duties for raw or essential materials

a. Submission by the Petitioner

52. Petitioner submitted that exemption is granted from import duties on raw or essential materials for the purpose of carrying out promoted producing, assembling or mixing operations.

b. Submissions by the Government of Thailand/other interested parties

53. Investment Promotion Act created the investment promotion program and authorized the BOI to grant investment promotion incentives, including reduction of import duties not exceeding ninety percent of the normal rate on raw materials or essential materials which are imported into the Kingdom for the purpose of producing, mixing, or assembling in the promoted projects.
54. Companies that wish to apply for BOI promotion program, must submit one application form for each project. If the project meets the approval criteria, the board of investment will grant rights and benefits as a package. BOI does not grant incentives program-by-program, but rather as a package of benefits that the companies are entitled to receive. However, if and when a promoted company actually decides to utilize particular benefits granted under the investment promotion package, the company must submit a request separately for each benefit

c. Examination by the Authority

55. Authority notes that Section 30 of the Investment Promotion Act provides for reduction of import duties not exceeding ninety percent of the normal rate on raw materials or essential materials which are imported into the Kingdom for the purpose of producing, mixing, or assembling in the promoted projects, each time for a period not more than one year from the date prescribed by the BOI provided that such raw materials or essential materials comparable in quality are not being produced or originated within the Kingdom in sufficient quantity to be acquired for used in such project. The subsidy program is part of the investment promotion incentive package.
56. The subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity.
57. However, Authority notes that the benefit under the subsidy program providing exemption from import duty on raw material is already countervailed. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this program for all other producer/exporters from Thailand.

(vii) Program No. 7: Exemption of Corporate Income Tax for BOI promoted activities

a. Submission by the Petitioner

58. Petitioner submitted that net profit derived out of the Promoted activity is granted exemption from income tax for the period as may be specified by the BOI but not more than 8 years from the date of income. In the case where a loss has been incurred during the eligible exemption, the BOI may grant permission to deduct such annual loss from the

net profits accrued after the expiration of the eligible exemption period for a period of not more than five years from the expiry date of such period. The promoted person may choose to deduct such loss from the net profit of any one year or several years

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

59. Investment Promotion Act created the investment promotion program and set forth the authority for the board of investment to grant investment promotion incentives, including exemption of corporate income tax on the net profit derived from the promoted projects under Section 31.
60. In the case where activities are of special importance and benefit to the country as prescribed by an announcement of the BOI, a promoted person in such activities shall be granted exemption of corporate income tax on the net profit derived from the promoted activity for a period as prescribed by the BOI but not more than eight years from the date income is first derived from such activity.
61. The income on which the computation of net profit is derived from the activity shall include income from the sale of such by-products and semi-manufactured products as the BOI may deem appropriate.
62. Where a loss has been incurred during the period of receiving exemption of corporate income tax referred to under either paragraph one or paragraph two, the BOI may grant permission to the promoted person to deduct such annual loss from the net profits accrued after the expiration of the period of exemption of corporate income tax for a period of not more than five years from the expiry date of such period. The promoted person may choose to deduct such loss from the net profit of any one year or several years.

c. Examination by Authority

63. Authority notes that Section 31 of the Investment Promotion Act provides for exemption of corporate income tax on the net profit derived from the promoted activity as prescribed by an announcement of BOI. Exemption from income tax is not available for more than eight years from the date income is first derived from such activity.
64. In the case where a loss has been incurred during the eligible period in which exemption of corporate income tax was available, the BOI is empowered grant permission to the promoted person to deduct such annual loss from the net profits accrued after the expiration of the eligible period of exemption of corporate income tax for a period of not more than five years from the expiry date of such period. The promoted person may choose to deduct such loss from the net profit of any one year or several years. This subsidy program is part of the investment promotion package scheme.
65. The Authority notes that the subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity.
66. STEC, the sole responding exporter from Thailand did not benefit from this program because it did not earn any profit since its establishment including the POI. However, Authority notes that the benefit under the subsidy program providing exemption from income tax is already countervailed. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this program for all other producer/exporters from Thailand.

(viii) Program No. 8: 50% reduction of corporate income tax in investment promotion zones

a. Submission by the Petitioner

67. Petitioner submits that the subsidy program provides for 50% reduction from normal rate of income tax rate for net profit derived from promoted activity for a period of not more than five years from the date income is first derived from the promoted activity.

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

68. Investment Promotion Act created the investment promotion program and set forth the authority for the BOI to grant investment promotion incentives, including a 50 percent reduction of the corporate income tax on the net profit derived from the promoted activity under Section 35(1).
69. The investment projects that are entitled to receive benefit under this program are granted 50 percent reduction of the normal rate of corporate income tax on the net profit derived from the promoted activity for a period of not more than five years commencing from the date income is first derived from the promoted activity.
70. Companies that wish to apply for BOI promotion program, must submit one application form for each project. If the project meets the approval criteria, the board of investment will grant rights and benefits as a package. It will not be granted on the incentive program basis. In other words, board of investment does not grant incentives program-by-program, but rather as a package of benefits that the companies are entitled to receive. However, if and when a

promoted company actually decides to utilize particular benefits granted under the investment promotion package, the company must submit a request separately for each benefit.

c. Examination by the Authority

71. Authority notes that under this program, 50% reduction is available from normal rate of corporate income tax on the net profit derived from promoted activity. This subsidy program is part of investment promotion package scheme.
72. The Authority notes that the subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. However, Authority notes that the benefit under this subsidy program in the form of exemption from income tax is not in addition to the subsidy program granting full exemption from corporate income tax.
73. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. The Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program.

(ix) Program No. 9: Income tax double deduction form the costs of double the cost of transportation, electricity and water

a. Submission by the Petitioners

74. The petitioner submits that under this subsidy program, income derived from promoted activity will be allowed to deduct double the cost of transportation, water and electricity for ten years.

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

75. Investment Promotion Act created the investment promotion program and set forth the authority for the board of investment to grant investment promotion incentives, including permission to deduct double the costs of transportation, electricity, and water supply for the purpose of assessing corporate income tax.
76. The investment projects that are entitled to receive this benefit under Section 35(2) of the Investment Promotion Act are granted permission to deduct for the purpose of assessing corporate income tax an amount double the costs of transportation, electricity, and water supply incurred by the promoted person in the operation of the promoted activity. Conditions, procedures, and periods of time for availing this benefit are prescribed by the board of investment.

c. Examination by the Authority

77. The Authority notes that under this subsidy program, benefit is provided in the form of double deduction of transport, electricity and water expenses for computing total income for the purpose of income tax. This subsidy program is part of the investment promotion incentive package. The benefit under this subsidy program is equal to the difference between the amount of tax that would have been payable in absence of double deduction and the amount of income tax actually paid.
78. STEC, the sole responding producer/exporter from Thailand claimed double deduction of expenses under this program. However, STEC did not incur net profit and would not have incurred net profit even in absence of double deduction. Thus, no benefit is received by STEC during the POI.
79. The Authority notes that the subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and the benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(x) Program No. 10: Additional 25 percent deduction of the cost of installation or construction of facilities

a. Submission by the Petitioners

80. Petitioner submitted that under this subsidy program, the promoted firms are allowed to deduct on their tax returns 25% of the cost of installation or construction of facilities used in promoted activities.

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

81. The investment projects that are entitled to receive benefit under Section 35(3) of the Investment Promotion Act are granted permission to deduct from the net profit an amount not exceeding 25 percent of the cost of installation or construction of facilities used in the promoted activity, according to the rules prescribed by the board of investment, under which the promoted person may, in addition to normal depreciation, choose to make such deductions from the

net profit of any one year or several years within 10 years from the date income is first derived from the promoted activity.

c. Examination by the Authority

82. Section 35(3) of the Act provides for the reduced income tax through deduction from net profit of amount not exceeding 25% of cost of installation or construction of facilities used in the promoted activity. The benefit under this subsidy program is equal to the difference between the amount of tax that would have been payable in absence of such deduction and the amount of income tax actually paid. The subsidy program is part of the investment promotion incentive package.
83. The subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xi) Program No. 11: Tax and duty compensation/Tax Coupons

a. Submission by the Petitioners

84. Petitioner submitted that this subsidy program provides for duty drawback on imported inputs that are consumed in the production of exported product. Benefit exist under this duty drawback program to the extent that the amount of drawback exceeds the amount of import charges on imported inputs that are consumed in the production of the exported product, making normal allowances for waste.

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

85. The Ministry of Finance ("MOF") and the Thai Customs Department administer a tax coupon system for exporters. The tax coupon system is authorized under the 1981 Tax and Duty Compensation of Exported Goods Produced in the Kingdom Act. The value of a tax coupon is calculated by multiplying a product-specific coupon rate by the FOB value of a company's exported goods. To derive the coupon rate for a particular exported good, the MOF examines the import duties and indirect taxes paid for the raw materials and other inputs used to produce the exported good. The tax coupon system refunds the import duties and indirect taxes paid for the raw materials and other inputs used in the production of exported goods.

c. Examination by the Authority

86. This program is established pursuant to the Tax and Duty Compensation of Exported Goods produced in the Kingdom Act B.E. 2524 (1981) and became effective on August 15, 1981. Under this subsidy program, import duties and indirect taxes paid for the raw material and other inputs used in the production of exported goods are refunded.
87. To administer this program, the Ministry of Finance and the Thai Customs Department administer a tax coupon system for exporters. The value of a tax coupon is calculated by multiplying a product-specific coupon rate by the FOB value of a company's exported goods. Coupon rate for a particular exported good is determined by the import duties and indirect taxes paid for the raw materials and other inputs used to produce the exported goods. Exporting companies may also use tax coupons as credits against corporate income taxes.
88. The Authority notes that Government of Thailand has not provided any evidence or established the existence of a mechanism to ensure that value of tax coupon does not exceed the amount of import duties and other taxes paid on the raw material used in the production of exported goods. Therefore, the program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to certain enterprise holding tax coupons.
89. However, the Authority notes that the benefit in the form of exemption of import duty on raw material has already been proposed to be countervailed through other subsidy program(s). The Authority therefore holds that no additional benefit is conferred through refund of import duty suffered on raw materials/inputs provided the benefit of duty exemption on the inputs has been availed.

(xii) Program No. 12: Exemption of import/export duty for bonded warehouses

a. Submission by the Petitioners

90. Petitioner submits that under this bonded warehouse scheme, the imported goods stored in a bonded warehouse for the purpose of re-exportation shall be exempted from payment of import/export taxes and duties, regardless of being exported in the same nature as imported or in the nature of having been produced, mixed or assembled as other goods.

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

91. Business operators granted to operate bonded warehouse of manufacturing type shall be exempted from the payment of import taxes and duties provided the goods imported and stored in such bonded warehouse are used in the process of producing, mixing or assembling and then exported, regardless of being exported in the same nature as imported or in the nature of having been produced, mixed, assembled as other goods or transferred to other bonded warehouses or sold to importers under a drawback scheme under Section 29 of the Customs Act.

c. Examination by the Authority

92. Authority notes that countervailing duty is already determined against the subsidy program providing exemption from import duty on raw materials. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this program for all other producer/exporters from Thailand.

(xiii) Program No. 13: Incentives for activities in infrastructure for the country's development, activities using advanced technology to create value added with no or very few existing investments in Thailand

a. Submission by the Petitioners

93. Petitioner submits that under this program incentives are granted in the form of exemption from import duties on machinery and raw materials used in production of exports for specified investment activities.

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

94. The BOI introduced new investment promotion scheme since January 2015. Under the new scheme, the board grants incentive package according to investment activity instead of investment zone. The aim is to focus on value creation and high technology in line with a new economic model of the country.
95. Board of investment Announcement No.2/2557 (2014) stipulates 2 types of incentives: Activities-based Incentives and Merit-based Incentives. For activities-based incentives, the board of investments classifies this incentive into 2 groups which are Group A (A1 – A4) and Group B (B1 – B2). For each group, the BOI sets clear and objective criteria for granting incentives.
96. Activities in infrastructure for the country's development, activities using advanced technology to create value added with no or very few existing investments in Thailand is the criteria set out for describing activities under group A2. Investment projects that are categorized as group A2 will be entitled to receive benefits as follows: (1) 8-year corporate income tax exemption, accounting for 100% of investment (excluding cost of land and 22 working capital) (2) exemption of import duty on machinery (3) exemption of import duty on raw or essential materials used in manufacturing export products for 1 year, which can be extended as deemed appropriate by the Board and (4) other non-tax incentives aiming at facilitating investors.

c. Examination by the Authority

97. This subsidy program is announced by the BOI as authorised under the Investment Promotion Act. Under this subsidy program, specified investment projects are entitled to receive exemption from income tax, exemption from import duty on machinery, exemption on import duty of raw materials used in the manufacturing of exported product and other non-tax incentives aiming at facilitating investors. The subsidy program is part of the investment promotion incentive package.
98. The Authority notes that each of the incentive provided under this subsidy program except non-tax incentives has already been examined and countervailed by the Authority. Therefore, Authority holds that additional countervailing duty to the extent of non-tax incentives should be imposed against this subsidy program.

(xiv) Program No. 14: Incentives for High Technology activities which are important to the country's development, with a few investments already existing in Thailand

a. Submission by the Petitioners.

99. Petitioner submits that under this program high technology activities are granted exemption from corporate income tax and from import duties on machinery and raw materials.

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

100. The BOI introduced new investment promotion scheme since January 2015. Under the new scheme, the board grants incentive package according to investment activity instead of investment zone. The aim is to focus on value creation and high technology in line with a new economic model of the country.
101. Board of investment Announcement No.2/2557 (2014) stipulates 2 types of incentives: Activities-based Incentives and Merit-based Incentives. For activities-based incentives, the board of investments classifies this incentive into 2

groups which are Group A (A1 – A4) and Group B (B1 – B2). For each group, the BOI sets clear and objective criteria for granting incentives.

102. “High technology activities which are important to the country's development, with a few investments already existing in Thailand” is the criteria set out for describing activities under group A3. Investment projects that are categorized as group A3 will be entitled to receive benefits as follows: (1) 5-year corporate income tax exemption, accounting for 100% of investment (excluding cost of land and working capital) (2) exemption of import duty on machinery (3) exemption of import duty on raw or essential materials used in manufacturing export products for 1 year, which can be extended as deemed appropriate by the Board and (4) other non-tax incentives aiming at facilitating investors.

c. Examination by the Authority

103. This subsidy program is announced by the BOI as authorised under the Investment Promotion Act. Specified investment projects are entitled to receive exemption from income tax, exemption from import duty on machinery, exemption on import duty of raw materials used in the manufacturing of exported product and other non-tax incentives aiming at facilitating investors. This subsidy program is part of the investment incentive promotion package.
104. The Authority notes that each of the incentive provided under this subsidy program has already been examined and countervailed by the Authority. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xv) Program No. 15: Merit based incentive for increase in competitive enhancement

a. Submission by the Petitioners

105. Petitioner submits that under this program projects that invest or have prescribed expenditure on the activities get additional exemption from Corporate Income Tax for one, two or three years.

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

106. The board of investment introduced new investment promotion scheme since January 2015. Under the new scheme, the board grants incentive package according to investment activity instead of investment zone. The aim is to focus on value creation and high technology in line with a new economic model of the country.
107. Board of investment Announcement No.2/2557 (2014) stipulates 2 types of incentives: Activities-based Incentives and Merit-based Incentives. The aim of merit-based incentives is to attract and stimulate more investment or spending on merit-activities that benefit the country or industry at large. Therefore, the projects that are invest or have expenditure on the prescribed merit-activities are eligible for merit-based incentives as an additional incentive granted on top of what the projects are entitled to receive under the activities-based incentives.
108. Merit-based incentives can be categorized into 3 main groups which are (1) Merit on competitiveness enhancement (2) Merit on decentralization and (3) Merit on industrial area development. Therefore, merit-based incentive on competitiveness enhancement is one of the three types of merit-based incentives the BOI grants to the projects that invest or have expenditure on the activities as prescribed in the BOI Announcement No. 2/2557 (2014). The BOI sets clear and objective criteria for granting merit-based incentive on competitiveness enhancement. These criteria are also made known to public.

c. Examination by the Authority

109. This subsidy program is announced by the BOI as authorised under the Investment Promotion Act. The subsidy program is part of the investment promotion incentive package.
110. Financial contribution is provided in the form of exemption from income tax and benefit is thereby conferred. The Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against exemption from income tax. Therefore, no additional countervailing duty is required to be imposed against this subsidy program.

(xvi) Program No. 16: VAT exemption on exports

a. Submission by the Petitioners

111. Petitioner submits that under this program, exemption is provided from VAT on export of goods.

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

112. A business person who carries on his business in sale of goods or provision of services in Thailand and such business has the prescribed value of tax base, such business person shall be liable to value added tax as prescribed in Section 80/2 of the Revenue code.

113. According to the Section 80/1 of the Revenue code, export of goods which is not exempt from value added tax under Section 81(3) shall use zero rate value added tax calculation.

c. Examination by the Authority

114. Section 82/16 of the Revenue Code of Thailand provides for payment of value added tax by business person engaged in sales of goods or services. However, this value added tax rate is zero for certain specified enterprises.
115. Authority notes that this subsidy program provides for exemption from value added tax on export of goods, which is applicable to other business. The Authority notes that the subsidy program provides for remission of tax on exported goods which is otherwise borne by the like product when destined for domestic consumption in accordance with footnote 1 of the SCM Agreement and Section 9B(b)(i) of the Customs Tariff Act. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xvii) Program No. 17: Promotional Privileges

a. Submission by the Petitioners

116. Petitioner submits that under this subsidy program, exemption is granted from the payment of import duty on machinery and from income tax.

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

117. Under the Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977), the incentives that the BOI provides include:

Tax Incentives:

1. Section 28: Exemption of import duties on machinery
 2. Section 30: Reduction of Import duties for raw materials or essential materials
 3. Section 31: Exemption of corporate income tax
 4. Section 35(1): A 50 percent reduction of the corporate income tax
 5. Section 35(2): Double deduction from the costs of transportation, electricity and water supply
 6. Section 35(3): Additional 25 percent deduction of the cost of installation or construction of facilities
 7. Section 36: Exemption of import duties on raw and essential materials
118. The BOI also provides non-tax incentives for facilitating foreign investors such as permission for foreign nationals to enter the Kingdom for the purpose of studying investment opportunities, permission to own land, and permission to take out or remit money abroad in foreign currency etc.

c. Examination by Authority

119. The authority notes that under the Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977), the incentives that the BOI provides Tax Incentives such as (1) Section 28: Exemption of import duties on machinery (2) Section 30: Reduction of Import duties for raw materials or essential Materials (3) Section 31: Exemption of corporate income tax (4) Section 35(1): A 50 percent reduction of the corporate income tax (5) Section 35(2): Double deduction from the costs of transportation, electricity and water supply (6) Section 35(3): Additional 25 percent deduction of the cost of installation or construction of facilities (7) Section 36: Exemption of import duties on raw and essential materials have already been covered under other schemes. Therefore, the Authority does not find it appropriate to quantify this scheme separately as it will amount to double counting of the benefit.
120. Therefore, no additional countervailing duty is required to be imposed against this subsidy program.

(xviii) Program No. 18: Duty Drawback under Section 19 of the Customs Laws

a. Submission by the Petitioners

121. Petitioner submits that under this program exporting companies obtain a refund of Customs duty paid on imported goods where those goods will have undergone production, mixing, assembling, or packing and then exported

b. Submission by Government of Thailand/Other interested parties

122. Duty drawback under Section 29 of the Customs Act means the refund of import duty already paid or the return of guarantee placed on imports which have undergone production, mixing, assembling, or packing and then exported.
123. Eligible goods for duty drawback are:
1. Raw materials which are obviously seen in the exports e.g. fabrics, buttons, zippers and thread in garments, plastic sheeting in plastic products, etc.
 2. Raw materials used directly in the manufacturing process and contained in the exports but not obviously seen e.g. preservatives in canned food, stiffening agents in garments, solvents for glue in cellophane and anti-rust agents in electronic circuits, etc.

3. Raw materials required in the manufacturing process e.g. sizing materials and bleaching agents used in textile products, sand paper, scouring powder, varnish, velvet, scouring agents, chalk, carbon paper and pattern.

c. Examination by Authority

124. Section 29 of the Customs Act provides for duty drawback. The subsidy program provides for refund of import duty paid on raw materials which have undergone production, mixing, assembling, or packing and then exported. There is no evidence before the Authority about the mechanism, which ensures that there is no excess remission of import duty and that amount of duty drawback will not exceed the amount of duty paid on raw material used in production of exported goods.
125. Thus, Authority notes that the subsidy program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and the benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is contingent on export. Therefore, the Authority determines that the subsidy program is countervailable. However, the Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against exemption of import duty on raw materials and therefore no additional countervailing duty is required to be imposed against this subsidy program.

(xix) Program No. 19: Free Trade Zone under Chapter X of the Customs Act

a. Submission by the Petitioners

126. Petitioner has not provided any explanation or evidence regarding the existence of this subsidy program.

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

127. The Free Zone Scheme encourages Thailand-based operations by removing certain disincentives associated with manufacturing in Thailand. Products made in the Zone are treated for the purpose of tariff assessment as if it were manufactured abroad. Free trade zone provides number of incentives such as relief from import duty on goods imported into free trade zone, relief from quality control requirements for merchandise imported into free trade zone for producing exported product etc.

c. Examination by Authority

128. Authority notes that free trade zone is an area designated by the Director-General of Customs under Section 136 of the Customs Act for industrial or commercial operation or any other activities beneficial to economy of the country.
129. Free trade zone is treated as foreign territory for the purpose of tariff assessment of goods manufactured in such free trade zone. Free trade zone provides for many incentives to entities located in such zone. For financial incentives in the form of exemption from import duty on raw materials and exemption on import duty on machinery, the Authority has already determined that countervailing duty is required to be imposed. Therefore, no additional countervailing duty is required to be imposed for this subsidy program.

(xx) Program No. 20: Export processing zone (EPZ) under the industrial estate Authority law

a. Submission by the Petitioners

130. Petitioner has not provided any explanation or evidence regarding the existence of this subsidy program.

b. Submission by Government of Thailand/other interested parties

131. Business operator in export processing Zone can submit application for construction/certification of building, additional/change of type of business operation, Tax-Privileges (established in I-EA-T Free Zone only), or Non- Tax Privileges (established in General Industrial Zone, and I-EA-T Free Zone).
132. The privileges are based on Location/Zone of the established operations. Incentives are widely provided to all the industrial operators who are permitted to engage in industrial operations in privilege areas in industrial estates. During the POI, there were fifty-seven general industry zones and thirteen IEA-T free (export processing) zones located in Thailand.

c. Examination by Authority

133. Export processing zones provide for tax incentives to entities located in such zone. For financial incentives in the form of exemption from import duty on raw materials and exemption on import duty on machinery, the Authority has already examined and countervailed the benefit. Therefore, no additional countervailing duty is required to be imposed for this subsidy program.

Producers/Exporters from Thailand**SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (Producer/Exporter)**

134. SEI Thai Electric Conductor Co. Ltd (“STEC”) is a producer and exporter of subject goods from Thailand. Subject Goods produced by STEC are exported to India directly by STEC. STEC filed questionnaire response and provided information regarding the benefits availed by them.
135. Authority has verified the information provided by STEC and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to STEC as a recipient of this grant. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including STEC.
136. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

Program No.	Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 2	Exemption from import duty on machinery approved by the Board of Investment.	Exemption from import duty on certain machinery has been received by STEC and the details of the same have been provided under Section II of this EQR. Please see Exhibit 13 attached herewith for details of exemption from imported duty upon import of machinery.	***	0-1%

137. The Authority notes that subsidy margin for SEI Thai Electric Conductor Co. Ltd is *de-minimis*.

Summary of Subsidy Programs for Thailand

138. No other producer/exporter from Thailand has filed questionnaire response. Countervailing duty for all other producers/exporters from Thailand has been determined based facts available and countervailability of the respective programs.

Program Nos.	Name of the Program	Subsidy Margin %	Range%
Program No. 2	Exemption of import duty on machinery under Investment Promotion Act	***	0-1
Program No. 3/4/7/8/9/10/15	Exemption from Income Tax under Investment Promotion Act	***	0-5
Program No. 4/5/6/11/12/18/19/20	Exemption of import duty on raw material imported for use in production for export	***	0-1
Program No. 13/14	Incentives for activities in infrastructure for the countries development, activities using advanced technology to create value added with no or very few existing investment in Thailand	***	0-1
Total		***	0-5%

Malaysia**F.6. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners****(i) Program No. 1: Market Development Grant (MDG)****a. Submission by the Petitioners**

139. The Petitioner submitted that the scheme is introduced by Malaysian Investment Development Authority (MIDA) for SMEs to promote export promotional activities. The maximum grant for an SME under the MDG program is RM 200,000. The SME should have been incorporated under the Companies Act, 1965 with at least 60% Malaysian equity ownership. The evidence and the legal basis are General Policies, Facilities, and Guidelines for Market Development Grants (MDG)-2016.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

140. It is a continuous program structured under the 11th Malaysia Plan (2016 - 2020) for increasing the SME's participation in export promotional activities.
141. The MDG provides an opportunity for Malaysian SMEs to apply for a reimbursable grant up to RM 200,000 for participation in export promotional activities namely International Trade Fairs, Trade & Investment Missions/ Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-in-Malaysia Products in supermarkets, hypermarkets or retails centres overseas.

c. Examination by the Authority

142. The Authority notes that Market Development Plan (MDP) was introduced in 2002. It is part of the 11th Malaysian Plan (2016-20). It is intended to increase participation of SMEs in export promotional activities. The MDP provides SMEs a reimbursable grant up to RM 2,00,000 for their participation in export promotional activities such as International Trade Fairs, Trade & Investment Missions /Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-in-Malaysia Products in supermarkets, hypermarkets or retails centres overseas.
143. The subsidy program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred to the recipient. The subsidy program is also specific because is contingent on export. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(ii) Program No. 2: Science Fund

a. Submission by the Petitioners

144. The Petitioner submitted that this is a grant provided by Government to carry out R&D projects that can contribute to the discovery of new ideas and the advancement of knowledge in applied sciences. The fund is open to all research scientists and engineers who are employed on contractual/permanent basis from Government Research Institutions (GRIs), Government Science, Technology and Innovation (STI) Agencies and Public and Private Institutions of Higher Learning (IHL).

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

145. The Science Fund is no longer offered beginning 1 January 2017. For this, reference has been made to official announcement by the Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI). Based on the records, none of the companies under investigation is Science Fund recipient.

c. Examination by the Authority

146. The Authority notes that the program is administered by Ministry of Energy, Science, Technology, Environment and Climate Change (MESTECC).
147. Science Fund is a grant provided by Government to carry out R&D projects in applied sciences, focusing on high impact and innovative research. The subsidy program is terminated from 1 January 2017. Subsidy program was operational till 31 December 2016 and during the period of its operation, the subsidy program provided financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit was thereby conferred. The subsidy program was also specific because it was provided to enterprise engaged in R&D projects. However, the subsidy program was only available to research and educational institutes and therefore was not available to producers of the product under consideration in Malaysia. Thus, Authority holds that no countervailing duty can be imposed for this subsidy program.

(iii) Program No. 3: Techno Fund

a. Submission by the Petitioners

148. The Petitioner submitted that this is a grant scheme which aims to stimulate the growth and successful innovation by Malaysian enterprises, Institutions of Higher Learning (IHL), and Research Institutes. It provides funding for technology development, up to the pre-commercialization stage, with commercial potential to create new businesses and generate economic wealth. Project must contain elements of technological innovation leading to commercialization of innovative products, processes and services. The applicants can be researchers and other individuals from SMEs, IHL, Research Institutes and STI Agencies. All categories of companies must have minimum 51% equity held by Malaysians. Applicant under SME must have minimum paid up capital in cash of RM

10,000, however start-ups are exempted from the same with just explanation. Projects under scope/portfolio of a certain Ministry/ Department/Agency and applications from Research Institutions with internal research funding like CESS Fund are not eligible under Techno Fund.

b. Submission by the Government of Malaysia/other interested parties

149. MESTECC believes that it can work together with researchers in Research Institutes, Universities and Industry to overcome some of these constraints, thus ensuring that more R&D products are brought to the market, thus spurring economic returns for the country. Hence this category of funds, called Pre-Commercialisation Funds i.e. Techno Fund was introduced.

c. Examination by the Authority

150. The Authority notes that the program is administered by MESTECC. There is no law, regulation or decree governing the administration of this program in Malaysia. MESTECC has created Pre-Commercialisation fund or Techno fund for supporting Research Institutes, Universities and Industry in research and development initiatives.
151. The subsidy program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is available to SMEs apart from institutions of higher learning and other research institutes. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(iv) Program No. 4: Inno Fund

a.Submission by the Petitioners

152. The Petitioner submitted that under this grant scheme, development/improvement of new or existing products, processes or services with elements of innovation is funded. The project should have economic value leading to development of products, processes and services that improve society well-being. The funds are categorised as Enterprise Innovation Fund and Community Innovation Fund. The former applies to Individual, Sole Proprietor, Micro Companies, and Small Companies, whereas the latter applies to Registered Associations/NGOs, Registered Companies and Community Groups. Applicant under SME must have minimum paid up capital in cash of RM 10,000, however start-ups are exempted from the same. The Quantum varies according to the Project but it can't exceed RM 500,000.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

153. The program intends to support innovation of new products, processes or systems by which value can be created for customers, businesses and society. Realising the importance of innovation for wealth creation and social well-being, Inno Fund was initiated.

c. Examination by the Authority

154. The Authority notes that the program is administered by MESTECC. The program was started in the year 2015. There is no law or legal regulation governing the program. MESTECC created innovation fund for promoting innovation by enterprises.
155. The program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is specific to enterprise carrying out innovation activity. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(v) Program No. 5: Cradle Investment Program

a. Submission by Petitioners

156. The Petitioner submitted that this grant scheme is Malaysia's first development and technology commercialization funding program wherein Malaysia's innovators and aspiring entrepreneurs transform their raw technology-based ideas to commercially viable ventures or local start ups to attain commercialization. The 2 types of conditional grants are- pre-seed development (CIP Catalyst, U-CIP Catalyst) and seed commercialization (CIP 500). The applicant under CIP Catalyst and U-CIP Catalyst should be Malaysian aged 18 years and above, permanent resident of Malaysia, with a team of minimum 2 and maximum 5 applicants. The maximum funding under CIP Catalyst and U-CIP Catalyst is RM 150,000 and under CIP 500 is RM 500,000.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

157. Cradle Investment Program ensures that aspiring entrepreneurs become the leading start-up with the necessary assistance provided by Cradle. Cradle has two (2) types of products which are grant funding & equity investment. The grant product, CIP 300 is a pre-seed program which provides grant and value-added assistance up to RM 300,000. The other product is DEQ 800 which provides direct equity investment between RM 300,000 and

RM 800,000 to areas that have good growth potential. Not all individuals/firms who applied and met all the eligibility criteria will benefit on getting the funding.

158. The shortlisted applicants also need to go through the Approval Committees (Grant) or Investment Committees (Equity) before benefiting from this scheme. Traditional businesses are specifically excluded from having access to the program.

c. Examination by the Authority

159. The Authority notes that Cradle was established as an agency under the Ministry of Finance in 2003. Cradle provides effective grant, equity, commercialisation support, coaching etc. to accelerate the growth of start-up companies. There is no law or legal regulation governing this program. The program was used by companies engaged in digital and renewable energy sector.
160. The program provides financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to start-up (less than 3 years) enterprise with minimum 51% Malaysian equity. Accordingly, the subsidy program is countervailable. However, the program was not used by any producer of the product under consideration in Malaysia because there has not been any start up enterprise for the product under investigation for last 10 years. Thus, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(vi) Program No. 6: Export excellence award

a. Submission by petitioners

161. The Petitioner submitted that this is an allowance given to increase exports of the prescribed product. Allowance given is equal to 100% of the value of the increased exports which is deductible from 70% of the Statutory Income. The eligibility for the same is that the company must be exporting the prescribed product.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

162. Award is to recognize and acknowledge outstanding companies in export performance, market penetration and market operation. Program has been discontinued since 2012.

c. Examination by Authority

163. The Authority notes that the program is administered by Ministry of International Trade and Industry (MITI). The award is provided to companies for export performance, market penetration, market operation and contribution to community and industry. Since 2012, MITI has discontinued this award and Business excellence award has replaced Export excellence award.
164. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is contingent on export and it is limited to enterprise that satisfy other criteria relating to market penetration, contribution to community etc. The Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. The Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program.

(vii) Program No. 7: Export credit and Export Financing

a. Submission by petitioners

165. The Petitioner contended that this scheme is in the form of export credit. It is a short term and post shipment financing to direct and indirect exporters. Exporters can obtain financing up to 95% of the value of their export order.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

166. Export Credit Refinancing (ECR) scheme is used to promote Malaysia's exports and international trade in the form of Pre-shipment and Post-shipment financing. ECR is available to all companies incorporated in Malaysia and involved in export activity.
167. The operational procedure of the ECR Scheme is governed by the ECR Guideline which is issued by EXIM Bank.

c. Examination by the Authority

168. The Authority notes that the program is administered by Export-Import Bank of Malaysia (EXIM Bank). Export credit refinancing program provides loan to enterprise to finance export of products. The program is governed by Export Credit Refinancing guideline issued by the Bank, which provides for eligibility criteria including eligibility of product (negative list of products which is maintained by bank) for the purpose of the program. The subsidy program is not restricted to any particular sector and is available to all companies incorporated in Malaysia.

169. EXIM Bank is a government-owned Development Financial Institution. It is a wholly-owned subsidiary of the Minister of Finance Incorporated (Inc.). As an agency under the purview of the Ministry of Finance, EXIM Bank's mandated role is specified by the Government. It is to provide credit facilities to finance and support exports and imports of goods, services and overseas projects with emphasis on non-traditional markets, providing export credit insurance services, export financing insurance, overseas investments insurance and guarantee facilities.
170. The Authority determines that EXIM Bank is a public body because it is owned by Government and is vested with the Government Authority to carry out governmental functions. Accordingly, the loan provided by EXIM Banks are financial contribution in the form of direct transfer of funds by a public body. The benefit conferred on the recipient is in the form of difference between the amount of interest charged by the EXIM bank and the amount of interest charged by the comparable commercial loan. The program is also specific because it is contingent on export. Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(viii) Program No. 8: Buyer Credit Guarantee

a. Submission by the Petitioner

171. The Petitioner submitted that under this program the overseas buyers are backed by EXIM Bank's unconditional and irrevocable guarantee in which lending bank is guaranteed repayment of due and interest amount. Malaysian exporter can help the overseas buyer to secure a long-term financing with a lender using the BCG. Malaysian exporter is paid as if he has a cash contract, whilst the overseas buyer has time to pay the contract through financing secured from the lender which is backed by EXIM Bank's guarantee. The evidence given is Buyer Credit Insurance by EXIM Bank. The loan amount under this program must be minimum value of RM 2mn in support of a cash contract and the repayment period should be at last 2 years and maximum 15 years.

b. Submission by Government/other interested parties

172. Bankers Trade Credit Takaful (BTCT) is a Credit Takaful designed to protect the Islamic Financial Institutions (IFIs) against risk of non-payment by their exporters arising from default by the overseas buyers. It's available against a trade finance facility on trade terms such as Open Account, Documentary Collection and/or Letter of Credit.

c. Examination by Authority

173. The Authority notes that the program is administered by EXIM Bank. There is no law or legal regulation governing the program.
174. The Authority has already determined that EXIM Bank is a public body. Under this program, EXIM Bank provides guarantee to financial institutions against risk of non-payment by their exporters (customers) because of default arising from overseas buyers. The program provides for financial contribution in the form of potential direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The benefit conferred on the recipient is equivalent to (i) the difference between the fee paid by the recipient for availing guarantee from EXIM Bank and the fee that would have been paid to any other commercial bank for such guarantee and (ii) the difference between the loan repayment to the lending bank in question (owing to less than normal commercial interest rate because of EXIM Bank guarantee) and the amount that would have been payable in absence of such guarantee (based on normal commercial interest rate). The subsidy program is also specific because it is contingent on export.
175. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(ix) Program No. 9: Pioneer Status

a. Submission by Petitioner

176. The Petitioner submitted that under this program a company granted Pioneer Status will enjoy tax exemption from corporate income tax. The program encourages investments in promoted activities/products in the manufacturing sector that can contribute to development and growth of economy. It applies to both local and foreign investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. Five-year partial exemption is provided from payment of income tax. A company pays tax on 30% of its statutory income, with exemption period commencing from its Production Day. Unabsorbed capital allowances and accumulated losses incurred during the pioneer period can be carried forward and deducted from post pioneer income of company. As evidence of existence of the program, petitioners have relied on:

- Promotion of Investment Act, 1986
- New and full notification pursuant to article xvi:1 of the Gatt 1994 and article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing measures-Malaysia dt. 5 October, 2017
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

- Laws of Malaysia Act 327 of Promotion of Investment act, 1986 Part-II Sec 5,6,7, deals with pioneer status
- Web Report: EXIM Bank's Export Credit Refinancing
- US Extruded through Malaysia

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

177. Pioneer Status may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product. Promoted activities and promoted products are determined by Minister of Finance and Minister of International Trade and Industry. The promoted products and activities cover all sectors. Pioneer status is limited to companies involved in specific industries. The applicants will need to go through the Approval Committee also. Since Malaysia is committed to adopt the Forum on Harmful Tax Practices program under the OECD, changes will be made to the program.
178. The major tax incentives for companies investing in the agricultural and manufacturing sectors are the Pioneer Status and Investment Tax Allowance. These incentives are mutually exclusive. Sections 5-25 Promotion of Investments Act 1986 are evidence of the same. The benefit is an exemption from taxes owed. Also, losses can be carried forward.
179. The eligibility criteria for the Pioneer Status are Level of value-added (VA) percentage and Level of technology as measured by the Managerial, Technical and Supervisory (MTS) Index.

c. Examination by Authority

180. The Authority notes that Sections 5 to 25 of the Promotion of Investment Act 1986 provides for pioneer status program. The program provides for tax incentives in the form of exemption from income tax. Losses incurred during the exemption period can be carried forward for subsequent years to offset taxable income/net profit. The program is available for pre-specified list of promoted products/activities.
181. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to promoted activity/product mentioned in the list. Examination of the list shows that the product list includes the product under investigation. Questionnaire response filed by Alpha Industries Sdn. Bhd shows that benefit is received by producers of the product under investigation for subsidy programs based on the promoted product list. Therefore, The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(x) Program No. 10: Investment Tax Policies/Allowance

a. Submission by Petitioners

182. The Petitioner submitted that under this program, a company granted Investment Tax Allowance (ITA) is entitled to offset this allowance against the statutory income for each year of assessment. The program encourages investments in promoted activities/products in the manufacturing sector, that can contribute to development and growth of economy. It applies to both local and foreign investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. An allowance of 60% on its qualifying capital expenditure incurred within 5 years from the date the first qualifying capital expenditure is incurred is given. Company can offset this allowance against 70% of its statutory income for each year of assessment. Remaining 30% of its statutory income will be taxed at the prevailing company tax rate. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:
- Promotion of Investment Act, 1986
 - New and full notification pursuant to article xvi:1 of the Gatt 1994 and article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing measures-Malaysia dt. 5 October, 2017
 - <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
 - List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

183. Investment Tax Allowance (ITA) may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia. Promoted activities and promoted products are determined and gazetted by the Minister of International Trade and Industry. Sections 26 – 29 of the Promotion of Investments Act 1986 (Act 327) are evidence of the same.
184. The allowance is only given on capital expenditure incurred on industrial buildings, plant and machinery directly used for promoted activities or the production of the promoted products. Companies are required to submit the applications for ITA program to MIDA, an agency under MITI. The company will then be required to establish the commencement of ITA period which is on the incurrence of the first capital expenditure duly certified by MIDA.

Later, companies approved with the program submit their claims to the Inland Revenue Board (IRB) together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax deductions.

185. The eligibility criteria for the ITA are value added (VA) percentage and level of technology as measured by the MTS Index.
186. Not all individuals/firms who applied and met all the eligibility criteria are approved. The applicants will need to go through the Approval Committee. The assistance is a deduction from taxable income. The allowance can be carried forward until fully utilized.
187. A company can elect to receive Pioneer Status but not receive the Investment Tax Allowance, or can elect to receive the Investment Tax Allowance, but not Pioneer Status.

c. Examination by Authority

188. Authority notes that Sections 26 to 29 of the Promotion of Investments Act 1986 provides for Investment Tax Allowance program. Promoted activities and promoted products are granted capital allowance. Value addition and technological requirements are also to be fulfilled. Out of the total capital expenditure, 60% of the capital expenditure is granted as allowance and can be deducted against 70% of statutory income for 5 years. Remaining income can be taxed at normal income tax rate. Even for companies that meet the listed criteria of promoted activity, value addition and level of technology, Authority retains the discretion to reject the applicant seeking benefit under this program.
189. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific since it is limited to certain enterprises, which meets the promoted product and are approved by the Authority. A company that has received income tax exemption from Pioneer Status cannot avail benefit under this program. The Authority has already determined that countervailing duty should be imposed for exemption from income tax under Pioneer Status. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xi) Program No. 11: Re-investment Allowance

a. Submission by Petitioners

190. Deduction is granted for capital expenditure incurred by the company for determining statutory income for purpose of determining income tax.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

191. In *Certain Textile Mill Products and Apparel from Malaysia (1985)* & *Certain Steel Wire Nails from Malaysia (1989)* (US CVD determinations), the USDOC determined that re-investment allowance is not countervailable. In *Stainless Steel Fasteners from Malaysia* (EU CVD determination) (2000), the EU determined that the re-investment allowance is not countervailable.

c. Examination by Authority

192. Authority notes that a company or a person resident in Malaysia is granted Reinvestment Allowance if the company is in operation for 3 years and has incurred capital expenditure on factory, plant and machinery for qualifying project. Deduction is granted from 70% of statutory income for 60% of such capital expenditure. Re-investment allowance can be claimed for 15 years beginning from the year of assessment in which a claim is made. Inland Revenue Board is responsible for administration of this program.
193. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. Even though the subsidy program is not limited to promoted activity, the subsidy program is also specific because it is available to enterprise that in operation for at-least 3 years and are undertaking qualifying project (expanding, modernizing or automating its existing business in respect of manufacturing). The Authority has determined subsequently in program no. 12 that deduction from statutory income by way of capital investment and allowance is countervailable. Therefore, the Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this subsidy program.

(xii) Program No. 12: Accelerated Capital Allowance

a. Submission by Petitioners

194. The Petitioner submitted that under this program a special allowance, where the capital expenditure is written off within 3 years, i.e. an initial allowance of 40% and an annual allowance of 20%, is given. After the 15-year period of eligibility for Reinvestment Allowance, companies that reinvest in the manufacture of promoted products are eligible to apply for Accelerated Capital Allowance. Applications have to be submitted to the IRB accompanied by a letter from MIDA certifying that the companies are manufacturing promoted activities/products. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

- Promotion of Investment Act, 1986
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

195. Accelerated Capital Allowance (ACA) provides allowances to write off the capital expenditure within three years, i.e., an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 40 percent. This program is available to all companies and the IRB applies objective criteria in granting ACA. Program does not constitute a countervailable subsidy because it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available. The assistance is an accelerated capital allowance to be deducted from taxable income. The allowance can be carried forward. Generally, to be eligible for accelerated capital allowance (ACA), a person must meet the following conditions:
- He was carrying on a business during the basis period
 - He has incurred qualifying expenditure in the basis period
 - The asset was used for purposes of a business, and
 - At the end of the basis period, he was the owner of the asset and the asset was in use
196. The companies under investigation will be eligible to claim ACA if they fulfill the criteria and government doesn't exercise discretion as to which firm is eligible to benefit.
197. For 2017, Alpha Industries Sdn. Bhd. and Metrod (Malaysia) Sdn. Bhd. used this program.

c. Examination by Authority

198. Authority notes that the program provides for capital allowance i.e. deduction of capital expenditure from statutory income to promoted activity after the expiry of 15 years of re-investment allowance period. The program allows to write off the total capital expenditure within three years, i.e., an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 40 percent in the next two years.
199. Authority notes that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to certain enterprise carrying out promoted activity that qualify for using this allowance and does not qualify for re-investment allowance on account of expiry of 15 years period of eligibility. Government of Malaysia has informed that responding exporters Alpha Industries and Metrod Malaysia availed benefit under this program. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(xiii) Program No. 13: Group Relief

a. Submission by Petitioners

200. The Petitioner submitted that under this program, group relief is increased from 50% to 70% of the current year's unabsorbed losses to be offset against the income of another company within the same group. It is provided under the Income Tax Act, 1967 to all locally incorporated resident companies. The Claimant and the surrendering company should have a paid-up capital of ordinary shares exceeding RM2.5mn. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:
- Income Tax Act 1967
 - <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
 - List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

201. Group relief is available to all locally incorporated resident companies subject to the terms and conditions as provided under section 44A of the Income Tax Act 1967. It allows a company in a group to surrender (referred to as surrendering company) not more than 70% of its loss in the basis period for a year of assessment to offset the income of one or more related companies (referred to as claimant company) within the same group. The assistance is a deduction from defined aggregate income. No deduction can be carried forward.
202. This program is available to all companies and the IRB applies objective criteria in granting Group Relief. Program does not constitute a countervailable subsidy because it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available. There are no anticipated changes to the program.

c. Examination by Authority

203. Authority notes that the program is governed by Section 44A of the Income Tax Act. The subsidy program allows to set off not more than 70% of its loss incurred by a company in a group against profit of one or more related companies within the same group. All companies that meet the eligibility criteria can claim the Group Relief. This program is available to all companies.
204. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to enterprise having related companies. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. The Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program.

(xiv) Program No. 14: Tariff Related Incentive**a. Submission by Petitioners**

205. The Petitioner submitted that under this program, full exemption from import duty on raw materials/components is normally granted, provided raw materials/components are not produced locally or if produced locally, they aren't of acceptable quality and price. This is regardless of whether the finished products are meant for export or domestic market. The eligibility is that the companies should be involved in manufacturing activities.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

206. The subsidy program is same as program No. 24.

c. Examination by Authority

207. The Authority notes that the program is administered by Director General of Customs. The program provides import duty exemption on raw material / component to qualified manufacturer. Exemption is granted when the raw materials / components are not locally available and used directly in the production of the finished product at the approved manufacturer's premise(s).
208. The Authority notes that the program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program does not qualify to be permissible duty remission program because it provides exemption from import duty for raw material used in all kinds of manufacturing activities and not only for raw materials used in exported products, as provided in footnote 1 of the SCN Agreement and Section 9B(b) of the Customs Tariff Act. The program is specific because it is limited to enterprise that use raw materials that are not available locally. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xv) Program No. 15: Industrial Building Allowance**a. Submission by Petitioners**

209. The Petitioner submitted that under this program, Initial allowance of 10% and an annual allowance of 3% is given to companies incurring capital expenditure on the construction or purchase of a building that is used for specific purposes, including manufacturing, agriculture, mining, infrastructure facilities, research, Approved Service Projects and hotels that are registered with the Ministry of Tourism. The evidence given is Income Tax Act 1967.

b. Submission by Government/Other interested parties

210. An industrial building allowance (IBA) is available to a person who has incurred capital expenditure on the construction or purchase of an industrial building which is used for the business of that person. IBA is deducted against adjusted income to arrive at statutory income. The assistance is an allowance to be deducted from taxable income. The allowance can be carried forward. Schedule 3 of the Income Tax Act 1967 is evidence of the same. No changes are anticipated to the program.
211. IBA is generally available to all companies such as resident and non-resident companies and unincorporated businesses such as sole proprietorships and partnerships. Export is not a criterion for granting IBA. IBA is granted to all buildings notwithstanding the use of the building. IBA is also applicable to buildings which are used as warehouses for storage of goods for export or for storage of imported goods which are to be processed and distributed or re-exported.
212. All companies that meet the eligibility criteria can claim the deductions. Program does not constitute a countervailable subsidy because it is not specific. Qualifying person:
- incurs capital expenditure on a building.
 - the building must be an industrial building
 - the building must be used for the purpose of a business carried on by the person

c. Examination by Authority

213. Authority notes that industrial building allowance (IBA) is available to a person who has incurred capital expenditure on the construction or purchase of an industrial building which is used for the purpose of the business of that person. Industrial Building Allowance is deducted against adjusted income to arrive at statutory income.
214. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against accelerated capital allowance. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xvi) Program No. 16: Allowance for Plant & Machinery**a. Submission by Petitioners**

215. The Petitioner submitted that under this program, capital allowance is given to give relief for wear and tear of fixed assets for business. The expenditure must be capital in nature and used for business purposes. Initial allowance is fixed at 20% based on the cost of asset at the time when capital expenditure is incurred. Annual allowance is flat rate given every year based on original cost of asset and varies accordingly. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on
- Schedule 3 of Income Tax Act 1967
 - Web Research- Inland Revenue Board of Malaysia Qualifying Expenditure and Computation of Capital Allowances Public Ruling No. 6/2015

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

216. Capital allowance (CA) provides deductions for qualifying expenditure on machinery or plant. CA is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. It is calculated on a straight-line method based on a prescribed rate of allowance. The companies under investigation will be eligible to claim CA if they fulfil the criteria. The allowance can be carried forward. No changes are anticipated to the program.
217. All companies that meet the eligibility criteria can claim the CA. This program is available to all companies and the IRB applies objective criteria in granting CA. Qualifying person:
- carry on a business
 - incurs capital expenditure on plant and machinery
 - the plant and machinery must be used in that business
 - owner of the plant and machinery at the end of basis period

c. Examination by Authority

218. Authority notes that capital allowance provides deductions for qualifying expenditure on machinery or plant. It is given to enterprise that incurs the qualifying expenditure. It is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. It is calculated on a straight-line method on the basis of a prescribed rate of allowance.
219. Responding producers/exporters Metrod Malaysia, Metro OFHC and Alpha Industries have claimed allowance on plant and machinery.
220. Authority notes that the program does not provide any countervailable benefit because it provides for normal deduction of depreciation on plant and machinery as per straight-line method to all enterprises. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(xvii) Program No 17: Double deduction for promotion of Malaysian Brand**a. Submission by Petitioners**

221. The Petitioner submitted that under this program, expenditure incurred on advertising local brand products domestically is allowed double deduction i.e. expenses incurred on certain activities can be set off twice as against taxable profits. The local brand must be owned more than 50% by the registered proprietor of the Malaysian brand name which should be owned by a company that's locally incorporated with at least 70% Malaysian owned and registered in Malaysia or overseas. The deduction can only be claimed by one company in a year of assessment. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on
- Promotion of Investment Act, 1986
 - Income tax promotion of export rules 1986
 - Inland Revenue Board of Malaysia Public Ruling No.1/2013
 - Malaysian External Trade Development Corporation

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

222. Expenditure for qualifying advertisements in advertising Malaysian brand name goods is eligible for a double deduction in arriving at adjusted income from a business. Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) Rules 2002 are given in evidence. Applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred within Malaysia for advertising Malaysian brand goods. The original supporting documents must be retained by the company for audit purposes by the IRB. The claim can be made in the annual tax returns for the fiscal year (basis period) in which the expenditure is incurred. The companies under investigation will be eligible to claim the deductions if they fulfill the criteria. The assistance is a deduction from taxable income. The deduction can be carried forward.
223. No changes are anticipated to the program.

c. Examination by Authority

224. The Authority notes that this program is governed by Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) Rules 2002. Under this program, expenditure incurred in advertising Malaysian brand is eligible for double deduction from business income. To qualify for this double deduction, the company must have 70% Malaysian equity and the brand name should be of goods of export quality.
225. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to enterprise that incur expenses on advertising Malaysian brand. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. The Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program.

(xviii) Program No. 18: Incentives for Manufacturing and manufacturing related services in East coast Economic Corridor**a. Submission by Petitioner**

226. The Petitioner submitted that under this program, various tax exemptions-revenue forgone are given to a company, situated in East Coast Economic Corridor, involved in manufacturing of selected and agro-based products and manufacturing related services. Customised incentives based on merit of each case, or, Income Tax exemption of 100% for 10 years starting from year company derives statutory income or Income Tax exemption of 100% on the qualifying capital expenditure for 5 years is given. Stamp duty exemption on land or building acquired for development and Import duty and sales tax exemption on machinery and consumables that are produced locally and used directly in the activity are also available.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

227. Tax Exemption may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia.
228. Companies are required to submit the applications for the tax exemption program to the East Coast Economic Region Development Council (ECERDC), an agency under MOF. The company will then be required to get the verification of compliance letter from ECERDC upon the company receiving the first statutory income for tax exemption will be issued upon the company meet all the conditions. After ECERDC is satisfied that the company has complied with the conditions, it will issue the said letter of which the company then can enjoy the incentive for the period of 10 years. Later, companies approved with the program will submit their claims to the IRB together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax exemption. Changes will be made to the program as Malaysia is committed to adopt the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) program under the OECD. The assistance is an exemption from taxes owed. There is a provision of losses and carry forward is allowed. Not all individuals/firms who applied and met eligibility criteria will be approved of the program. The applicants will need to go through Approval Committee.
229. The eligibility criteria for the program are:
- project is located in East Coast of Malaysia;
 - value added; and
 - level of technology as measured by the Managerial, Technical and Supervisory (MTS) Index.
230. The company under investigation met the eligibility criteria on location, MTS and value added.

c. Examination by Authority

231. The Authority notes that full income tax exemption is granted under this program to the company whose project is located in the east coast economic corridor and is intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia.
232. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to promoted products and also specific to region i.e. enterprise whose project is located in east coast economic corridor. The Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against income tax exemption. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xix) Program No. 19: Drawback on Import duty, Sales tax and Excise duty**a. Submission by the Petitioner**

233. The Petitioner submitted that under this program, drawback on import duty, sales tax and excise duty that have been paid may be claimed by a manufacturer if the parts, raw materials or packaging materials are used in the manufacture of goods for export within a year based on conditions stipulated in the acts. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on
- Section 99 of the Customs Act 1967
 - Section 29 of the Sales tax Act 1972
 - Section 19 of the Excise Act 1976

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

234. Program provides for Duty Import Refund on imported goods that are subsequently re-exported. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). No changes are anticipated to the program. Companies are required to submit the applications for Drawback under sections 93, 95, 99 of Customs Act 1967 to Royal Malaysian Customs Department (RMCD). Then the companies are required to provide proof of import/export declaration and relevant import/export documents. RMCD will verify the documents before refund is made or disapprove.

c. Examination by Authority

235. Authority notes that the program is administered by the Royal Malaysian Customs Department. The program provides import duty refund on goods that are subsequently re-exported. Responding exporter Alpha Industries has availed benefit under this program.
236. Authority has already determined that exemption from import duty on raw material is countervailable. Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program while working out subsidy margin for residual category.

(xx) Program No. 21: Exemption from Import duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activity**a. Submission by Petitioners**

237. The Petitioner submitted that under this program, to reduce cost of doing business and enhance competitiveness, import duty and sales tax exemption are given to Malaysian brands with at least 60% Malaysian equity who outsource manufacturing activities. Import duty and sales tax exemption on raw materials and components used in manufacturing of finished products by their contractual manufacturers locally/abroad and import duty and sales tax exemption on semi-finished goods from their contract manufacturers abroad to be used by their local contract manufacturers to manufacture finished products are available. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

238. The program provides import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD, MIDA and IPC. Section 14(2) Customs Act 1967 is given as evidence. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from scheme and the authorities do not exercise discretion. No changes are anticipated to the program.
239. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annex I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition).

240. To qualify for the exemption,

- Imported raw materials and components which are used to manufacture finished products with nil import duty.
- Semi-finished products which are imported from contract manufacturers abroad and are used in the manufacture of finished products by local contract manufacturers.

c.Examination by Authority

241. Authority notes that Section 14(2) Customs Act 1967 governs the administration of the program. The program is administered by Malaysian Investment Development Authority. The program provides import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. Raw materials which are used in the production of exported product and semi-finished goods which are imported from contract manufacturers for use by local manufacturers qualify for this exemption.
242. The Authority has already determined countervailing duty should be imposed on program providing exemption from import duty/taxes on raw material. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xxi) Program No. 23: Exemption from import duty and sales tax on machinery and equipment

a.Submission by Petitioners

243. The Petitioner submitted that since it is the policy of the government not to impose taxes on machinery and equipments used directly in manufacturing process and not produced locally, tax exemption-Revenue forgone is given where imported machinery and equipment are taxable but not available locally. Full exemption is given on import duty and sales tax. For locally purchased machinery and equipment full exemption is given on sales tax. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

244. The program provides import duty exemption on machinery and equipment to qualified manufacturer. MIDA issues a letter to confirm the status of the manufacturer. The manufacturer then claims for exemption. To qualify for the exemption, the machinery and equipment must be new, unused and directly used in the manufacturing process of the finished product at the approved manufacturer's premise(s). All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. No changes are anticipated to the program. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The laws and regulations governing this program are contained in Customs Duties (Exemption) Order 2017.
245. The company under investigation conformed with the eligibility criteria which are under MIDA's purview. MIDA has issued one confirmation letter to Alpha Industries Sdn. Bhd. dated 2 January 2018 with which the company can apply for import duty exemption starting 1 January 2018 until 31 December 2020.
246. The license which exempts manufacturers from paying sales tax under the Sales Tax Act 1972 is no longer applicable since The Sales Tax Act 1972 [Act 64] was repealed with the enactment of the Goods and Services Tax Act 2014 [Act 762] from 1 July 2014.

c.Examination by Authority

247. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on new and unused machinery and equipment to qualified manufacturer. There is no exemption from sales tax during the POI because Sales Tax Act 1972 [Act 64] was repealed with the enactment of the Goods and Services Tax Act 2014 [Act 762] entered into force 1 July 2014. The program is administered by Malaysian Investment Development Authority.
248. Responding producer/exporter Alpha industries has obtained license for the exemption and is eligible to use this exemption from 1st January 2018. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to certain enterprises that import new machinery and equipment for manufacturing activity. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xxii) Program No. 24: Exemption from import duty on raw materials/components

a.Submission by Petitioners

249. The Petitioner submitted that under this program, full exemption from import duty can be given for raw materials/components, regardless of whether finished goods are meant for export or domestic market, provided raw materials/components are not produced locally or if produced locally, they aren't of acceptable quality and price. Where finished products are for export market, full exemption from import duty is normally granted. Where finished

products are for domestic market, full exemption from import duty on raw materials/components not produced locally can be considered. Full exemption can also be considered if finished products made from raw materials/components aren't subject to import duty. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

250. The program involved evaluating import duty exemption on raw material / component to qualified manufacturer. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD and MIDA. To qualify for the exemption, the raw materials / components are not locally available and used directly in the production of the finished product at the approved manufacturer's premise(s). The laws and regulations governing this program are contained in section 14(2) of Customs Act 1967. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. No changes are anticipated to the program. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition).
251. The company under investigation conformed with the eligibility criteria. Copper Cathode (raw material) for product under consideration carries no import duty.

c. Examination by Authority

252. Authority notes that the program is governed by Section 14(2) of Customs Act 1967. The program provides for import duty exemption to qualified manufacturer on raw material / component that are not locally available.
253. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to enterprise that use raw material that are not locally available. The Authority has already determined that countervailing duty should be imposed on program providing exemption from import duty/taxes on raw material. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xxiii) Program No. 25: Double deduction for promotion of exports

a. Submission by Petitioner

254. The Petitioner submitted that under this program tax deduction is given to exporters for expenses which are aimed at promoting exports and supply of goods overseas, cost of maintaining office overseas for purpose of promotion of services, publicity and advertisements in any media outside Malaysia for promotion of export of services and export market research. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on

- Section 41 of Promotion of Investment Act, 1986
- Income tax promotion of export rules 1986
- WT/TPR/S/292
- WTO-Notification-G/SCM/N/3/MYS-1995
- US carbon steel wire rod from Malaysia

b. Submission by Government of Malaysia

255. The program which is provided under section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) read together with rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986 is applicable to all resident trading, manufacturing or agricultural companies in respect of expenses incurred in the basis period primarily and principally for the purpose of seeking opportunities, or in creating or increasing a demand for the export of Malaysian manufactured goods or agricultural products. This program's focus is on supporting Malaysian companies' participation in eligible export promotional activities, not on their goods' export performance or on the use of domestic good. All firms which can meet the eligibility criteria can benefit from this program. The companies under investigation will be eligible to claim the deductions if they fulfil the criteria. There are no anticipated changes to the program. The deduction can be carried forward.
256. Applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred overseas for advertising, travelling and related export promotional expenditure. The original supporting documents must be retained by the company for audit purposes by the IRB.
257. In the case of participation in an international trade fair, companies are required to get a letter of approval from MATRADE.

c. Examination by Authority

258. Authority notes that the program is governed by Section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) & Rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986. Under this program double deduction from income to enterprise involved in manufacturing, trading and agricultural activities is available for expenses incurred

for promotion of export. Expenses incurred by a company for increasing demand for exports are allowed for double deduction.

259. The Authority notes that the program provides for financial contribution the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The benefit is the difference between the amount of income tax paid after double deduction and the amount of income tax that would have been payable in absence of such double deduction. The program is also specific because it is contingent on export performance and is limited to enterprise engaged in export promotion activity. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program

(xxiv) Program No. 26: Double deduction for promotion of export cargo

a.Submission by the Petitioners

260. The Petitioner submitted that under this program an exporter may make a deduction from taxable income for premium insurance on export cargo and regional tax deduction for tax insurance. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on
- Promotion of Investment Act, 1986
 - Income tax promotion of export rules 1986
 - Tax incentives for Companies
 - Other Authority findings

b. Submission by Government of Malaysia/Other Countries

261. A double deduction is allowed to a person who incurs premium on the insurance of cargo exported from Malaysia provided that the risks are insured with an insurance company incorporated in Malaysia. The premium paid must be in accordance to section 33 of Income Tax Act 1967. The assistance is a deduction from taxable income. The deduction can be carried forward.
262. This program has been revoked since 2016. Income Tax (Deductions of Insurance Premiums for Exporters) (Revocation) Rules 2012 is given as evidence.

c.Examination by Authority

263. The Authority notes that the program was governed by Income Tax (Deductions Of Insurance Premiums For Exporters) Rules 1995 and is revoked by Income Tax (Deductions Of Insurance Premiums For Exporters)(Revocation) Rules 2012. The program was recurring in nature and is terminated from 1st January 2017. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xxv) Program No. 27: Incentives for small and medium enterprise

a.Submission by the Petitioners

264. The Petitioner submitted that under this program, reduced corporate tax from 25% to 20% on chargeable incomes up to RM 500,000 is given to SMEs. This is available only to SME resident in Malaysia with paid up capital of RM 2.5mn or company which is not controlled by other company with a paid-up capital exceeding RM 2.5mn.

b. Submission by the Government of Malaysia/other interested parties

265. Special tax rate of 18% is applicable for a resident company with paid up capital of RM2.5 million and below, on first RM 500,000 chargeable income and 24% on subsequent chargeable income as per Schedule 1 of the Income Tax Act 1967. There are no anticipated changes to the program. If a company is in a tax loss situation, preferential rate is not applicable.
266. A company is eligible to claim the preferential tax rate upon fulfilling the following conditions:
- resident and incorporated in Malaysia
 - has a paid-up capital in respect of ordinary shares of RM2.5 million and less
 - the companies must not be part of a group of companies where any of their related companies have a paid-up capital of more than RM2.5 million

267. The companies under investigation will be eligible to claim preferential tax rate if they fulfil the criteria.

c.Examination by Authority

268. The Authority notes that under this program, preferential income tax rate is provided for SMEs i.e. enterprise with paid up capital of RM 2.5 million and below. On the income upto RM 500,000, chargeable income tax rate is 18%. Chargeable income tax for income above RM 500,000 is 24%.

269. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to small and medium scale enterprise. The Authority has already determined that countervailing duty should be imposed for subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xxvi) Program No. 28: Allowance for increased export

a.Submission by the petitioners

270. The Petitioner submitted that this program is a form of tax incentive granted to companies under section 154(1) of Income Tax Act 1967 and Rule 3 of Income Tax (Allowance for increased exports) Rules 1999 and Income Tax (Allowance for increased exports) amendment Rules 2003. An exporter can avail 70% tax deduction from taxable income for increased exports. Also, if the said allowance is not used during the earned year that can be forwarded to the following assessment year. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

- Promotion of Investment Act, 1986
- Income tax act 1967
- Customs Act 1967
- Sales tax Act 1972
- Excise Act 1976
- Free zones act 1990

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

271. A resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The assistance is an exemption from taxable income. The allowance can be carried forward. There are no anticipated changes to the program. Income Tax (Allowance for Increased Exports) Rules 1999 is given in evidence. The Rules contain the following definitions:

- a) agricultural produce means fresh and dried fruits, fresh and dried flowers, ornamental plants and ornamental fish, frozen raw prawn or shrimp, frozen cooked and peeled prawn and frozen raw cattle fish and squid;
- b) export means direct exports not including sales to Free Industrial Zones and Licensed Manufacturing Warehouses;
- c) value added means the sale price of goods at ex-factory price less the total cost of raw materials; and
- d) value of increased export means the difference of the Free-On-Board (FOB) value of products exported in the basis period and that of the immediately preceding period. FOB value will exclude the freight charges and insurance cost.

272. The allowance is determined as follows:

a. Manufactured products

- 10% of the value of increased exports of the manufactured products by the company where the products exported attained at least 30% of value added;
- 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company where the products exported attained at least 50% of value added.

b. Agricultural products

- 10% of the value of increased exports of agricultural produce by the company.

273. The allowance will be given against seventy per cent of statutory business income of the company. Any export allowance not set off would be carried forward to be set-off against seventy per cent of the statutory income in future years.

c.Examination by Authority

274. Authority notes that a resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The allowance is equivalent to 10% or 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company. Allowance will be given against 70% of the statutory business income.
275. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific because it is contingent on export performance. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program

(xxvii) Program no. 29: Tax exemption for exporters in Free Trade Zone**a.Submission by Petitioners**

276. The Petitioner submitted that under this program, as per section 4 of the Free trade zones act 1990, exporters are exempted from custom duty, sales or service tax and excise duty. Free zones such as Port Klang Free Zone, is one of a free commercial zone which is permitted to import raw materials, components, equipment, and machinery free of taxes.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

277. Free Zones in Malaysia are established for manufacturing and commercial activities to be carried out on with minimum Customs intervention. A free zone is an area declared by the Minister of Finance under Section 3(1) of the Free Zone Act 1990. There are two types of free zones, a Free Industrial Zone meant primarily for manufacturing activities and a Free Commercial Zone meant for commercial activities. Free zones are places outside the Principal Customs Area (any part of Malaysia excluding a free zone, Labuan, Langkawi and Tioman) except in respect of prohibition of exports and imports under Section 31 of the Customs Act 1967. As such, goods and services of any description except those specifically and absolutely prohibited by law, may be brought into, produced, manufactured or provided in a free zone without payment of any duty/tax. There is no application form. Application can be submitted to Ministry of Finance for policy approval and will be declared by the Minister of Finance under Section 3(1) of the Free Zone Act 1990. There are no anticipated changes to the program.
278. None of companies are located in any of the gazette free zone areas under the Free Zones Act 1990.

c.Examination by Authority

279. Authority notes that the program is administered by Free Zone Act 1990 and Free Zone Regulations 1991.
280. Free zones are managed by Free Zone Authorities appointed by the Minister of Finance to administer, maintain and operate a free zone. Free Zones in Malaysia are established for the purpose of manufacturing and commercial activities to be carried out on with minimum Customs intervention. Goods and services of any description except those specifically and absolutely prohibited by law, may be brought into, produced, manufactured or provided in a free zone without payment of any duty/tax.
281. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific since it is available to enterprise located in free zone. The Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this subsidy program because no producer/exporter of subject product are located in free trade zone. In any case, Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from import duties. The Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program

(xxviii) Program No. 30: Research and Development Fund**Program No. 30(a): Commercialization of Research and Development Fund (CRDF-1)****Program No. 30(b): Commercialization of Research and Development Fund (CRDF-2)****Program No. 30(c): Commercialization of Research and Development Fund (CRDF-3)****a.Submission by Petitioners**

282. The Petitioner submitted that CRDF-1 is a grant for commercialization of R&D output from public and private University (PPU)/Government Research Institute (GRI) by a spin off company Syarikat Terbitan Universiti (STU). Funding in form of partial grants with a max of 500000 RM or 90% of eligible expenses (whichever is lower) is provided. The STU is required to operate their business from any recognised Technology Centres locally. The company is also required to focus their commercialization activities on business development while producing their product via out-sourcing mode. The proposed technology to be commercialized must be from one of the Priority Technology Clusters identified by MOSTI excluding ICT and project should be tangible in nature. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on Research and Development Booklet prepared by MIDA.
283. The Petitioner submitted that CRDF-2 is funding in form of partial grants with a max of 500000 RM or 70% of eligible expenses (whichever is lower) is provided for commercialization of R&D output from public and private University (PPU)/Government Research Institute (GRI) by a start-up company. The start-up is required to operate their business from any recognised Technology Centres. The company is required to focus their commercialization activities on business development while producing their product via out-sourcing mode. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on Research and Development Booklet prepared by MIDA.

284. The Petitioner submitted that CRDF 3(a) is a grant for commercialization of any local R&D by SME and CRDF 3(b) is a grant for commercialization of public sector R&D by a non-SME. In CRDF-3(a) funding in form of partial grants with a max of 400,000 RM or 70% of eligible expenses (whichever is lower) is provided and in CRDF-3(b) funding in form of partial grants with a max of 400,000 RM or 50% of eligible expenses (whichever is lower) is given. The company should've been incorporated under the Companies Act, 1965, with at least 51% owned by Malaysians and less than RM 25mn annual turnover or less than 150 employees. Also, the proposed technology to be commercialized must be from one of the Priority Technology Clusters identified by MOSTI excluding ICT, and the R&D must be completed successfully, and commercial ready prototype should be available. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on Research and Development Booklet prepared by MIDA.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

285. Commercialisation of Research and Development Fund (CRDF) is a program which provides funding assistance to aid commercialization activities of locally developed technologies undertaken by Malaysian-owned companies. The technologies can be those developed by the public sector or an output of in-house research and development (R&D) activities by the companies. The program was established in 1997. Program was not provided pursuant to a statute, regulation, decree, or other legal measure. Any company that intends to apply for CRDF must first participate in a pitching session which is organised by MTDC on a weekly basis. From the pitching session, the potential applicant will be informed if the company is eligible to apply for CRDF. If the company is deemed eligible, they will be invited to submit an application to be processed and evaluated. Eligibility is limited to technology-based companies. There are no anticipated changes to the program.
286. The duration for CRDF 1 is one year and the maximum amount of funding is RM500,000 in the form of a partial grant. The duration of CRDF 2 and 3 is 6 years and the maximum amount of funding is RM 4,000,000 in the form of partial grant and partial soft loan based on Convertible Promissory Notes.
287. For CRDF2 and 3, disbursement of funds takes place in the first 2 years of the project and repayment of the soft loan portion will take place from the third to sixth year. Throughout the project duration, companies will be monitored on its progress, achievements, funding utilisation and business activities.

c. Examination by Authority

288. The Authority notes that Commercialisation of Research and Development Fund (CRDF) is a program under the Ministry of Science, Technology, Climate Change and Environment (MESTECC). It provides funding assistance to aid commercialization activities of locally developed technologies undertaken by Malaysian-owned companies (51% share).
- CRDF 1 provides funds for market validation and technology validation for new technologies;
 - CRDF 2 provides funds commercialisation activities for start-ups and small and medium enterprises;
 - CRDF 3 provides fund for commercialisation activities for large companies.
289. Maximum amount of funding for CRDF-1 is RM 500,000 and maximum amount of funding for CRDF 2 & 3 is RM 4,000,000.
290. The program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to enterprise with Malaysian ownership. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xxix) Program No. 31: Tax incentives for in-house R&D

a. Submission by Petitioners

291. The Petitioner submitted that under this program any company which undertakes in-house R&D to further its business can apply for tax allowances. Application for an ITA of 50% of the qualifying capital expenditure incurred within 10 years and Offset of the allowance against 70% (100% for promoted areas) of its statutory income for each year of assessment is available. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on Research and Development Booklet prepared by MIDA.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

292. The incentive for In-house R&D activity is an Investment Tax Allowance (ITA) of 50% on the qualifying capital expenditure incurred within 10 years. The ITA can be offset against 70% of statutory income of each year of assessment. In-house R&D is one of the promoted activities which is determined by Ministry of Finance and Ministry of International Trade and Industry. The purpose of this incentive is for its own business. Not all companies who applied and met all the eligibility criteria will be approved of the program. The applicants will still need to go through the Approval Committee. Sections 26E, 27E and 29F of the Promotion of Investment Act 1986 are given in evidence. There are no anticipated changes to the program. Qualifying capital expenditure incurred in the basis period for a year of assessment is deducted from the statutory income. Losses can be carried forward

293. The eligibility criteria for in-house R&D Incentive:

- The company must be incorporated under the Companies Act 1965 / Companies Act 2016 and resident in Malaysia
- The R&D activities undertaken must comply with the definition of R&D under Section 2 of the Promotion of Investment Act (PIA), 1986
- The R&D activities undertaken must be in accordance with the needs of the country and bring benefit to the Malaysia Economy

c.Examination by Authority

294. Authority notes that the program is governed by Sections 26E, 27E and 29F of the Promotion of Investment Act 1986. Under this program, incentive is provided for in-house R&D activity as an Investment Tax Allowance of 50% of capital expenditure. Allowance can be offset against 70% of statutory income of each year of assessment. The allowance may be granted to any company participating or intending to participate in-house research activity in Malaysia.
295. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to enterprise engaged in research and development. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program.

(xxx) Program No. 32: Double deduction for Research & Development

a.Submission by Petitioners

296. The Petitioner submitted that under this program, any company that undertakes in-house R&D to further its business can apply by application for an ITA of 50% of the qualifying capital expenditure incurred within 10 years and Offset of the allowance against 70% (100% for promoted areas) of its statutory income for each year of assessment is available. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on Research and Development Booklet prepared by MIDA.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

297. Revenue expenditure on research directly incurred by a person resident in Malaysia would be eligible for a claim for double deduction. These expenses must be incurred specifically in undertaking in-house research by that person in relation to his business. The said research must be approved by the Minister of Finance. The Minister has, however, delegated such powers to the Director General of Inland Revenue (DGIR). Section 34A Income Tax Act 1967 given in evidence. Government does exercise discretion as to which firm is eligible to benefit. There are no anticipated changes to the program. The deduction can be carried forward.
298. Companies are required to submit the applications for the Research and Development program to the IRB, an agency under MOF. The company will then be required to get the approval letter from IRB. After IRB is satisfied that the company has complied with the conditions, IRB will issue the approval letter. Later, companies approved with the program submit their claims to the IRB together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax deductions.

c.Examination by Authority

299. Authority notes that program is administered by Section 34A Income Tax Act 1967 (Annex D-32.1) & Public Ruling No. 5/2004. Revenue expenditure on research directly incurred by a person resident in Malaysia would be eligible for a claim for double deduction from net profit. The research activity in question must meet the prescribed criteria and definition and should be approved by the Minister of Finance.
300. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is other wise due and benefit is thereby foregone. The subsidy program is also specific because it is limited to enterprise engaged in research and development activity. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program.

(xxxi) Program No. 34: Soft loans to Small and Medium Enterprise

a.Submission by Petitioners

301. The Petitioner submitted that under this program, loans to SME's and new start up companies in project, fixed assets and working capital financing is given, to relocate their operations to legal industrial sites and improve their productivity through adoption of ICT in business management and operations. Min RM 50000 and Max 3 Million loan is granted. SME incorporated under Companies Act, 1965 should have at least 60% equity by Malaysians, and

with shareholding not exceeding 20% held by public listed companies. They should possess a valid premise license. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on SME Corporation of Malaysia.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

302. The SLSME was launched in December 2001 to promote the development of small and medium enterprises (SMEs) in Malaysia. The fund for SLSME is channelled by the Government of Malaysia via SME Corporation Malaysia to MIDF for the implementation of the Scheme. There are no anticipated changes to the program. Program was not provided pursuant to a statute, regulation, decree, or other legal measure.
303. SMEs incorporated under the Malaysian Companies Act 2016 or Registration of Business Ordinance 1956 with at least 60% equity held by Malaysians or with shareholdings not exceeding 20% held by public-listed companies (only if applicable) as well as with business operations in manufacturing sector, manufacturing related sector and services sectors (excluding insurance and financial services) are eligible to apply for financing under SLSME.
304. Applicants/SMEs are required to complete the Financing Application Form and submit to MIDF. Application Forms are to be submitted via online through MIDF's official website or to MIDF officers at the Head Office/ regional offices. Thereafter, MIDF's officers will contact the Applicant/SME for further discussion on the financing needs of the SME. MIDF will proceed to process the application once the Applicant/SME submits complete documents to MIDF's officers.

c. Examination by Authority

305. Authority notes that the program was launched in December 2001 and provides for loan to SMEs. This program provides financing for existing as well as newly start-up enterprises for project, fixed assets and working capital requirement.
306. The program provides financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The amount of benefit is equal the difference between the amount of payment to be made on loans granted pursuant to this subsidy program and the amount payment to be made on any other comparable commercial loan. The program is also specific because it is limited to SMEs which meet the specified criteria. The Authority holds that the countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xxxii) Program No. 35: International Procurement Centre

a. Submission by Petitioners

307. The program provides for exemption of income tax to Malaysian companies.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

308. The program was governed by Income Tax Exemptions No. 42 Order 2005. Program has expired on 30th April, 2015. Therefore, no new IPC status and fiscal incentives will be granted to fresh applicants beginning 1st May, 2015. Existing IPC Companies may however complete 10 years of their IPC fiscal incentive and may retain their IPC status thereafter subject to meeting the conditions of IPC Status approval. Not all companies who applied and met all the eligibility criteria were approved for the program.

c. Examination by the Authority

309. Authority notes that program was administered by Income Tax Exemptions No. 42 Order 2005. Program provides full exemption from income tax. Program has terminated on 30 April 2015 but existing status holder will continue to get the benefit of full tax exemption under the program for 10 years and thereafter if they continue to meet the criteria.
310. Program continues to remain in operation for entities who were already granted IPC status before 30th April 2015. The program was in operation during the POI for such enterprises. The program provides full exemption from income tax. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to enterprise with IPC status. Metrod OFHC has received benefit from the program and the Authority has determined countervailing duty against such benefit.

(xxxiii) Other Program used by Metrod Group: Exemption on import duties on raw material which are used in production of exported goods.

Authority notes that Metrod Malaysia has received benefit in the form of exemption on import of raw material for export production because Metrod Malaysia specifically admitted in its questionnaire response in Exhibit 14 that *"Grant of exemption of import duty on the raw material meant for export goods is covered under the exemption [of import duty on raw material]. No duty exemption under the scheme is available for goods which are imported for production of finished products destined for the domestic market."* Authority had inadvertently noted in the disclosure statement that this benefit availed by Metrod is a benefit under Program no. 24.

311. The Authority notes that program provides for financial contribution in the form of revenue forgone which is otherwise due through exemption from import duty on raw materials and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is contingent on export performance. The Authority notes that import of raw material for use in the production of exported goods cannot be considered as countervailable subsidy only if there is sufficient evidence to demonstrate that there is a verification mechanism to ensure that there is no excess remission. Metrod group has merely claimed existence of a mechanism and absence of excess remission without providing sufficient evidence or step by step explanation of such verification mechanism. Metrod group has not provided any instance of duty imposition by the Government on the company where it was unable to meet the export obligation.

Producers/Exporters from Malaysia

Alpha Industries Sdn. Bhd.

312. Alpha Industries Sdn. Bhd. is a producer/exporter of subject goods in Malaysia. Alpha Industries filed questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.
313. Authority examined the response filed by Alpha Industries Sdn. Bhd. and upon examination requested further information from them and also requested for verification of information provided in the response. However, Alpha Industries did not respond to the request of the Authority for further information and verification of information already provided in the questionnaire. Authority determines that Alpha Industries has not co-operated fully in the investigation and accordingly no individual subsidy margin rate can be determined for Alpha Industries. Subsidy margin determined for all other producers/exporters from Malaysia is being made applicable for Alpha Industries.

Metrod Malaysia SdnBhd (Producer), Metrod (OFHC) SdnBhd (Trader), Metrod Copper Products SdnBhd ("MCP") (Trader), Panasonic Procurement Malaysia SdnBhd, (Trader), Savli Copper Products Pvt Ltd, India (Importer)

314. Metrod Malaysia SdnBhd ("**Metrod Malaysia**") is a producer of subject goods in Malaysia. Metrod OFHC SdnBhd ("**Metrod OFHC**") and Metrod Copper Products SdnBhd ("**MCP**") are wholly owned subsidiaries of Metrod Malaysia. Metrod OFHC and MCP are engaged in marketing activities for Metrod Malaysia. Metrod OFHC and MCP also supply raw materials to Metrod Malaysia for manufacturing subject goods. Metrod Malaysia does not export goods directly to India. Goods produced by Metrod Malaysia were sold to Metrod OFHC and MCP. Metrod OFHC exported the goods to India directly to related end user Savli Copper Products Pvt Ltd, India ("**Savli**") and to other unrelated end users. MCP exported goods to India through unrelated trader Panasonic Procurement Malaysia SdnBhd, ("**Panasonic**"). All exports of subject goods to India by Panasonic were made to Anchor Electricals Pvt. Ltd., which is subsidiary of Panasonic.
315. Metrod Malaysia, Metrod OFHC, Metro Copper and Panasonic filed questionnaire response. Metrod Malaysia and Metrod OFHC benefitted from the subsidy programs of Government of Malaysia.
316. Authority has verified the information provided by Metrod Malaysia, Metrod OFHC, Metrod Copper and Panasonic and determined subsidy margin for program no. 23, 24 and 35 for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. The Authority further notes that with respect to Program no. 12, it has been claimed by Metrod Malaysia that no benefit has been availed whereas Government of Malaysia has submitted that Metrod Malaysia has received benefit under Program No. 12. Accordingly, the Authority holds to determine benefit under Program No. 12 for Metrod Malaysia based on facts available. As a result, benefit was conferred to Metrod group as a recipient of this program. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including Metrod group.
317. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

Program No.	Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 12	Accelerated Capital Allowance	Accelerated deduction of capital expenditure from taxable income	***	0-1%
Program No. 23	Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment	The program involves import duty exemption on machinery and equipment to qualified manufacturer.	***	0-1%
Program No. 35	International Procurement Centre (IPC status)	Full Income Tax exemption on statutory income	***	0-1%
Other	Exemption from Import	The program involves exemption of	***	0-5%

program	Duty on Raw Materials/ Components	import duties on the imported raw materials which are used in the production of export goods.		
Total			***	0-5%

Summary of subsidy programs for Malaysia

318. Countervailing duty for all other producers/exporters from Malaysia has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating party, Metrod Group for the subsidies availed by them and based on facts available for other subsidy programs.

Program Nos.	Name of the Program	Subsidy Margin %	Range%
Program No. 12	Accelerated Capital Allowance	***	0-1%
Program No. 23	Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment	***	0-1%
Program No. 14/19/21/24	Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components	***	0-5%
Program No. 9/10/11/12/13/15/17/18/25/27/28/31/32/35	International Procurement Centre (IPC status) / Income Tax benefit.	***	0-1%
Program Nos. 1, 3, 4, 6 & 30	Grant Programs	***	0-5
Program No. 34	Loan Programs	***	0-5
Program No. 7&8	Loan Guarantee	***	0-5
Total		***	5-15

Vietnam

F.1. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners

(i) Program No. 1: Income Tax Preferences under Chapter V of Decree 24 (Implementation of the Law on Enterprise Income Tax)

a. Submission by the Petitioner

319. Petitioner submitted that under Article 9, the Ministry of finance has specified income tax rate applicable to-

1. Business establishments is 28%.
2. Business establishment is involved in activities of exploration and exploitation of Oil and Gas and/or any other rare natural resources, the tax applicable to such enterprise shall range from 28%- 50%.

320. Under the Program, Specific Income tax rates for such establishments (Type 2) shall be decided by the Prime Minister at the proposal of Minister of Finance. The limitation of the program is restricted to certain specified enterprises. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following decrees or notifications as was reasonably available to them.

- Decree No 48/2009/ND-CP, May 19, 2009
- Decree No 164/2003/Nd-cp of Dec 22, 2003 detailing the Implementation of the Law on Enterprise Income Tax to the Government
- Pursuant to the Dec 25, 2001 Law on Organization of the Government
- Pursuant to the June 17, 2003, Law No. 09/2003/Qh11 on Enterprise Income Tax

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

321. Decree 24/2007/ND-CP implementing the Law on Enterprise Income Tax 2003 ceased with effect from January 1, 2009 because it was replaced by the Law on Enterprise Income Tax 2008. Thus, Decree 24 was not applicable during the POI of this investigation.

322. Corporate income tax benefits including preferential income tax rate, tax exemption and tax reduction are governed by Article 1.7 of the Amending Law 2013 and Article 1.7 of the Amending Law 2014.
323. Law of Foreign Investment in Vietnam in 1996 was amended in 2000. Corporate income tax benefits including preferential income tax rate, tax exemption and tax reduction are governed by Article 46 to 49 of Decree 24/2000/ND-CP.
324. There is no application and approval process. Enterprises rely on the applicable tax law and regulations to identify the benefits they are entitled to, declare the benefits in the tax returns, and pay the income tax in accordance with the declaration. Eligibility is not contingent upon export performance or on the use of domestic goods.
325. There is no criterion governing the size of the benefit. The amount of income tax benefits is the amount of difference between standard tax rate and preferential tax rate and/or the amount of tax payment in the absence of exemption or reduction.
326. Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (DOVINA) received corporate income tax benefits under this program. During the period of investigation, DOVINA received a 50% reduction on the tax payable to the Government on income from new investment projects for the 2017 tax period. This preference is based on the fact that DOVINA invested on new projects in Long An Economic Zone, which falls into the list of encouraged geographical areas under Decree No. 218/2013/ND-CP. There is no deferral of taxes owed involved in the program.
327. No anticipated changes in the program have been made.
328. CFT COPPER VINA Ltd., Co received corporate income tax benefits as foreign invested enterprise in Bien Hoa Industrial Park, pursuant to Article 46 of Decree 24/2000/ND-CP. It is subject to a preferential income tax rate of 15% on the tax payable to the Government for the duration of its investment project, which is 30 years from the date of establishment. This preference is based on the fact that CFT COPPER VINA was established as a foreign-invested company.

c. Examination by Authority

329. Authority notes that the program providing exemption from income tax is governed by Corporate Income Tax 2008 as amended in 2013 and Law of Foreign Investment as amended in 2000. Standard rate of corporate income tax in Vietnam is 20%. Decree 218/2013/ND-CP provides cases where tax payers are entitled to tax reduction of 50%. Reduction is available to investment projects falling in the specified sectors or in encouraged geographical region.
330. For foreign invested enterprise, preferential rate of 15% and 10% are specified as per Article 46 of Decree 24/2000/ND-CP.
331. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also sector specific and region specific because it is limited to encouraged sectors or encouraged geographical regions. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(ii) Program No. 2: Import duty exemption or reimbursement for raw material

a. Submission by the Petitioner

332. Petitioner submitted that import duty exemption for “raw material and supplies used for manufacture of equipment and machinery” is provided under Law no.45, Chapter IV. Ministry of Finance under Article 16.6(d) & 16.9 has specified raw material, supplies and accessories imported for production activities of investment projects on the list of domains where investments is particularly encouraged or the list of geographical areas meeting with exceptional socio-economic difficulties.
333. Under the Program, raw material or supplies imported for the production of export goods, for which tax has been paid, is subject to duty-free imports (u/A. 16.4) or reimbursement (u/A.19). As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following decrees or notifications as was reasonably available to them.
 - Law No 45/2005/QH-11 (Law No 45)
 - Decree No 87/2010/ND-CP (Decree 87) Law No. 45 Chapter IV

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

334. This policy is regulated by the Law on Export and Import Duty and applied to every form and type of business throughout the country.
335. The amount of the exemption is equal to the amount of the duty corresponding to the value of imported materials actually used in the production of the finished goods that are exported. This amount is determined or declared at the time of reporting to Customs on the use of imported raw materials for production of exported goods in accordance

with customs regulations. The applicable Customs regulations are Decree 08/2015/ND-CP, dated January 21, 2015 ("Decree 08") and Circular 38/2015/TT-BTC, dated March 25, 2015. General Department of Vitenam Customs (GDVC) under the Ministry of Finance is in charge of development of track system.

336. There is no application and approval process. As long as the imported materials are used in the production of exported goods, such materials are exempted from import duties regardless of the sector, location, or size of the importing producers. No changes are anticipated for this program. There is no deferral of taxes owed.

c. Examination by Authority

337. Authority notes that the program is administered by Law on Import and Export Duty 2016 and Customs Regulations 08/2015/ND-CP dated 21, 2015 and Circular 38/2015/TT-BTC. The program provides for exemption on import duty on raw materials used in the manufacture of exported product. There is no evidence and details regarding the track system maintained by GDVC to ensure that entire raw material imported duty free is consumed in the production of exported product.
338. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is contingent on export. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(iii) Program No. 3: Exemption on Corporate income tax for enterprises

a. Submission by the Petitioner

339. The petitioner submitted that the above-mentioned program is applicable to enterprises of textile & garments; leather & footwear; electronics & IT products; manufacturing of cars and fabricating mechanics. As per the scheme of the Government of Vietnam enterprises shall be benefited if, -
1. the enterprises opting to 50% tax reduction in the tax period of year 2014, this reduction shall be enjoyed for the tax period of following 3 fiscal years
 2. the maximum duration for exemption is 1 year, commencing from the date of performance of contracts or commencing trail production or production with technologies applied for the first time in Vietnam.
 3. The income of the enterprises is eligible for a preferential tax rate of 20% for 10 years, tax exemption for 02 years and 50% reduction for next 04 years

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

340. Information regarding income tax program and benefit is provided in response to Program No. 1.

c. Examination by Authority

341. Authority notes that it has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program providing exemption from Income Tax. The Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this subsidy program.

(iv) Program No. 5: Preferential lending to exporters

a. Submission by the Petitioner

342. The petitioner stated that the Ministry of finance along with banks regulate the loans under the program. Banks provided loans to enterprises for the post-investment interest rate to implement state policies on development investment credits and export credits. It is also submitted that the State is a major regulator in the banking industry and therefore 50% of the loans by the major banks in Vietnam are low- interest loans. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following decrees or notifications as was reasonably available to them.

- Decree No 75/2011/ND-CP, Aug 30, 2011
- Decree No 106/2008/Nd-cp
- Decree No 106/2004/Nd-cp
- Resolution No 02/NQ-CP (Government 7 Jan 2013)
- Official Letter no 2667/NHNN-Vp (State Bank of Vietnam 17 April 2014)

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

343. The GOV does not maintain records of the loans provided by the banks. All financial institutions, regardless of the shareholding structure, carry out their lending operations independently according to commercial considerations.
344. These programs are managed by Vietnam Development Bank ("VDB"), which is a state policy bank established by Decision 108/2006/QD-TTg, May 19, 2006 on the Establishment of Vietnam Development Bank. The VDB has

three basic state credit tools: (i) investment credit loans; (ii) export credit loans; (iii) post-investment credit assistance.

345. During the POI, the provision of investment credit loans, export credits, and post-investment credit assistance complied with Decree 75/2011/ND-CP and Decree 32/2017/ND-CP.
346. Ministry of Finance issues circulars to provide guidelines for the implementation of the program. The Vietnam Development Bank provides investment credits to eligible entities in accordance with the above regulations and its own regulations on credit provision.

c. Examination by Authority

347. Authority notes that the program is administered by Decree 75/2011/ND-CP. Article 5 of Decree 75 authorises the Vietnamese Development Bank to provide investment credit to investors having investment projects on the list of eligible projects. Investment credit is in the form of credit loans, export credit loan, post-investment credit assistance etc. Guidelines for administering the program are issued by Ministry of Finance.
348. The Vietnam Development Bank (VDB) is established under the Decision No. 108/2006/QĐ-TTg dated May 19th 2006 to execute the state development investment and export credit policies as regulated by the Government. The organizational and operational regulations of VDB are in accordance with the Decision No. 1515/QĐ-TTg dated September 3rd 2015 by the Prime Minister.
349. Financial mechanism of VDB is executed in accordance with the Decision No.44/2007/QĐ-TTg dated March 30th. The Vietnam Development Bank is recognized as legal entity. The operation of VDB is for not profit oriented purposes.
350. Main duties of the Vietnam Development Bank with regard to credit are:
- Mobilize and receive capital from domestic and foreign organizations to implement investment and development credit and export credit of the State.
 - Execute the policy of investment and development credit, policy of export credit of the State.
 - Provide credit guarantee for SMEs' loans from commercial banks.
351. Authority notes that VDB and other state owned banks in Vietnam are a public body because it is owned and controlled by the Government of Vietnam and exercises Governmental authority. Loans granted by VDB or any other state owned bank are in the nature of financial contribution in the form of direct transfer of funds. Benefit is conferred on the recipient in the form of difference between the interest charged by VDB and the interest rate charged on comparable commercial loan. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(v) Program No. 6- Export Promotion Program

a. Submission by the Petitioner

352. The petitioner submitted that under the regulations of Ministry of Trade, Ministry of Finance and other relevant ministries and agencies, the provision and allocation of funds for trade promotion is overseen by the evaluation council. The governing Article is 9 of Decision 279, which specify the types of trade promotion schemes that are eligible for support and the following Article (10) specifies the level of support that is available to each scheme. It is further submitted that the government will cover 50% of the expenses associated with hiring domestic and foreign experts under this program. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following decrees or notifications:
- National Trade Promotion program was established by decision 279 and governed by Decision 90

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

353. The GOV has an annual trade promotion program which aims to support relevant companies to expand trade to foreign markets, mountainous and bordering (poor) areas.
354. The national trade promotion program aims to support trade activities, notably for export and trade in mountainous and poor areas, activities connecting trade with investment and tourism. Annually, the MOIT, based on prescribed criteria and based on proposals submitted by the local authorities and associations, approves trade promotion programs for the year. Associations or local authorities, based on approved programs, conduct promotion activities for its relevant companies. The presiding bodies prepare the proposals and send the proposal to the Trade Promotion Department (the National Trade Promotion Program Management Board) within the prescribed time limit (usually 15 May of the year preceding the project implementation year).
355. Eligibility criteria is that Program owners have a trade promotion plan that meets the objectives, requirements and criteria as provided in Decision No. 72/2010/QĐ-TTg.

356. The program is still being implemented. Currently this program has not been replaced by any new program.

c. Examination by Authority

357. Authority notes that the program is administered by Decree No. 72/2010/QD-TTg. It provides support to trading activities of enterprises for specified sectors or geographical locations.

358. The program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to enterprise performing support activities or enterprise located in the certain geographical region. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(vi) Program No. 7- Export credits from the Vietnam Development Bank

a. Submission by the Petitioner

359. The petitioner submitted that the Ministry of finance had specified certain enterprises eligible for credit loans. Vietnam Development Bank provides loans for investment projects and contracts on export/import of Vietnamese goods which have an impact on the capital. A pre-requirement set-up by the bank is that the financial plans and repayment plans shall be appraised by them beforehand. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following decrees or notifications as was reasonably available to them.

- Decree No 75/2011/ND-CP, Aug 30, 2011
- Decree No 108/2006/QD-TTg
- US Final finding on Certain Steel Nails from Socialist Republic of Vietnam

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

360. Information regarding loan program is provided in response to Program 5.

c. Examination by Authority

361. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against credit provided by VDB and state owned banks. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

(vii) Program No. 8- Export Support Credit

a. Submission by the Petitioner

362. Under the program Ministry of Finance has provision for loan for enterprises that qualify the criteria established by the decision. It also provides guidelines for the purpose of the loan. Article 7 & 8 lays down the condition and the loan amount that has been prescribed by the Government of Vietnam. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following decrees or notifications as was reasonably available to them.

- Decision No. 133/2001-QD-TTg

363. In this decision, the government states that the export credit shall be applicable to the-

1. Investors that have the financial capability to repay the debt;
2. The project must have completed the investment and construction stage;
3. The investor has been evaluated by the Development Assistance Fund for financial plans and loan repayment plans.

364. Under A. 8- the level of loan capital has been divided into three groups by the Ministry. Group A shall follow the Prime Minister's decision and the rest are applicable for not more than 90% of the investment capital.

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

365. Export support credit program was triggered in 2001 and terminated on 16 January 2007. Therefore, this program is outside the period of investigation.

366. The program was aimed at encouraging enterprises, economic entities and individuals in the production and trading which produce export goods and is contingent upon export performance. As part of Vietnam's commitments to access the WTO, this program was terminated on 16 January 2007 as provided under Decree 151/2006/ND-CP.

367. Export support credits under this program include the following:

- Medium and long-term investment loans for investment projects of producing, manufacturing or processing export goods with export revenue accounting for at least 30% total annual revenue and at least 80% of total revenue if the project is a joint-venture as provided under Article 6 of Decision 133/2001/QD-TTg.

- Post investment interest rate support for investment projects (i) of producing, manufacturing or processing export goods with export revenue accounting for at least 30% total annual revenue and (ii) not receiving medium and long-term investment loans, as provided under Article 3 of Decision 133/2001/QD-TTg. The interest rate support amount is equal to the difference between the interest rate of credit institutions and that of the state investment credit at the time of receiving the credit.
- Investment credit guarantee for enterprises of producing, manufacturing or processing export goods with export revenue accounting for at least 30% total annual revenue as provided under Article 6 of Decision 133/2001/QD-TTg.

c. Examination by the Authority

368. The Authority notes that the subsidy program was terminated on 16 January 2007 and is no longer in operation. Moreover, the Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program providing loans to enterprise by VDB and other state owned banks at lower interest rates. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty is required to imposed against this subsidy program.

(viii) Program No. 9- Preferential lending for investors

a. Submission By the Petitioners

369. Under the program, the Ministry of Finance has reiterated the roles & tasks of the Development bank. The petitioner submitted that the bank was formulated to regulate exporting goods to Vietnam. A loan from the bank has been made a mandatory requirement for an enterprise to avail export credits. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following decrees or notifications as was reasonably available to them.
- Decree No 108/2006/QD-TTg
 - Decree No 75/2011/ND-CP
370. Under the program, the bank shall establish & receive capital from investors to execute the Investment credit policy. The amount of credit/loan provided towards the project is 70% at most and for the investor at 15% of the actual charter capital of Vietnam Development bank. Further, it is submitted that the A. 6 of the decree imposes lending conditions in order to attain export credit on investors.

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

371. Information regarding loan program is provided in response to Program 5.

c. Examination by Authority

372. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against credit provided by VDB and state owned banks. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

(ix) Program No. 10- Interest rate of the investment credit loans

a. Submission by the Petitioner

373. The petitioner submitted that the Ministry of Finance has specified the interest rate of the investment credit loans granted by the State of Vietnam. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following notification as was reasonably available to them
- Circular No. 76/2015/TT-BTC

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

374. Information regarding loan program is provided in response to Program 5.

c. Examination by Authority

375. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against credit provided by VDB and state owned banks. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

(x) Program No. 11- Investment support on foreign investors who invested in establishing small and medium scale enterprises

a. Submission by the Petitioner

376. The petitioner submitted that under this program, assistance at all stages was provided to Small-&Medium Scale Enterprises. The Enterprises are entitled to assistance in the financial, production, innovation & technological field. The subsidy scheme allows for extensive support to foreign investors investing in small business in Vietnam. This subsidy provides an undue advantage to the industry. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the Decree No 56/2009/ND-CP as evidence.

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

377. None of companies under investigation is operating business in textile and garment industry.
378. To facilitate development of small and medium sized enterprises (SMEs) in the country, Decree 56/2009/ND-CP was issued to provide guidelines for support of SMEs, which applies to SMEs throughout the country regardless of any form and type of business. The Ministry of Finance is responsible for formulating a mechanism for establishment and operation of credit guarantee funds, which should be submitted to and approved by the Prime Minister, and for guiding operations of credit guarantee for small- and medium-sized enterprises. The central bank is responsible for proposing the Prime Minister to promulgate incentive mechanisms to expand credits to small- and medium-sized enterprises.
379. Application process is based on principles and guidelines issued by central agencies, local authorities as per their own availability of local budget, develop SMEs support programs.

Sector	Small-sized enterprises	
	Total charter capital	Number of laborers
Agriculture, forestry and fishery	VND 20 billion or less	Between over 10 - 200 employees
Industry and construction	VND 20 billion or less	Between over 10 - 200 employees
Trade and service	VND 10 billion or less	Between over 10 - 50 employees

380. Companies falling under the defined range could apply for available support programs by the local government.
381. Due to very limited state budget, most of provinces have not developed any programs to support SMEs within their geographical regions. This program is not contingent upon export performance or domestic over imported goods. None of the companies under investigation is SME under the criteria of Decree 56/2009/ND-CP. Decree 56/2009/ND-CP was replaced by the Decree 39/2018/ND-CP dated 11 March 2018.

c. Examination by Authority

382. Authority notes that the program provides support to SMEs in the form of financial and non-financial incentives. Support provided to SMEs under the guidance of Ministry of Finance comprises of various types of incentives:
- Training programs
 - Awareness of doing business programs for SMEs
 - Credit guarantee funds
 - Support for payment full or partial payment of fee for obtaining investment certification
383. The incentives provided under the program in monetary terms results in financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby confirmed. The subsidy program is also specific because it is limited to SMEs. Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xi) Program No. 13- Financial Guarantees by Vietin Bank**a. Submission by the Petitioner**

384. Under the scheme, the Ministry of finance, provides for commitment by Vietin Bank to the guaranteeing party in a contract, in case he fails to oblige his part of the payments and obligations. As an evidence of the existence of the program, the petitioners have submitted the URL of the website of Vietin Bank which has all the required details of the program.

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

385. None of companies under investigation received any financial guarantees from Vietinbank for the product under investigation. The questions, therefore, are not applicable.

c. Examination by Authority

Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against credit provided by VDB and state owned banks. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

(xii) Program No. 14- Land Preferences for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones under Decree 142.**a. Submission by the Petitioner**

386. The petitioner has submitted that the Government of Vietnam provide preferential land rates and related assistance to enterprises located in the industrial zone land. The land is subleased to the enterprises by People's Committee of Can

Tho, a local executive/ administrative branch of the national government. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following decree document as was reasonably available to them-

➤ Decree No 142/2005/ND-CP dt. Nov 14, 2005

387. As per the decree, provided in evidence, collection of land rents & water surface rents have to be re-adjusted to be close to the market price.

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

388. In order to encourage enterprises to invest into geographical regions or areas with specially difficult socio-economic conditions, the Government of Vietnam pursues a policy of exemption and reduction of land rent for companies who have investment projects in such regions. Exemption of land rent also applies to investment projects in special cases such as construction of lodging houses for poor workers, dormitory for students in universities, agricultural land for minority citizens in mountainous areas, etc, as well as investment projects in encouraged industries.
389. This policy is regulated by Decree 142/2005/ND-CP dated 14 November 2005. Decree 46/2014/ND-CP was issued to replace decree 142/2005/ND-CP.
390. Companies who invest in encouraged industries or encouraged geographical regions specified in the list or invest special cases specified under the Decree 142/2005 and succeeding Decree 46/2014, are entitled to land rent exemption or reduction. Based on their investment certificate or business registration, the relevant local tax authority shall determine the amounts payable by the land tenants.

c. Examination by Authority

391. Authority notes that the program is governed by Decree 142/2005/ND-CP dated 14th November 2005. Exemption or reduction is provided on land rent to companies who have investment in identified regions and investment projects for encouraged industries as specified under the Decree 142/2005 and succeeding Decree 46/2014.
392. The program provides financial contribution in the form of provision of goods or services at less than adequate remuneration. The program is also specific because it is region specific and is limited to certain encouraged sectors. Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xiii) Program No. 15- Government Provisions of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents

a. Submission by the Petitioner

393. The petitioner submitted that under the present subsidy scheme, the State Government of Dong nai & Civic Authorities provide exemption of land and water surface rent for a project undertaken to build houses for the workers of the industrial zone. The program further provides for extensive reduction in the land rent for the land leased by a cooperative. Following are examples-
1. Land used for business and productions premises are eligible for 50% reduction on land lease.
 2. Land & water surface rent for a land used for agricultural production, forestry, aquaculture and salt making are eligible for reduction subject to certain conditions.
394. The enterprise, in order to qualify under the program, shall have to meet the criteria set in the decree. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following decree document as was reasonably available to them-

➤ Decree No 46/2014/ND-CP dt. 15/5/2014

b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties

395. Information regarding program is provided in response to Program 14.

c. Examination by Authority

396. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against provision of land at less than adequate remuneration. Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

Producers/Exporters from Vietnam

397. Two exporters from Vietnam namely, Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company & CFT Vina Copper Co., Ltd filed questionnaire response and participated in the investigation.

Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (DOVINA)

398. DOVINA is a producer/exporter of subject goods in Vietnam. DOVINA filed questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.
399. Authority examined the response filed by DOVINA and upon examination requested further information from them and also requested for verification of information provided in the response. However, DOVINA did not respond fully to the request of the Authority for further information. DOVINA merely shared documents via common drive and was not present during the on-table verification of information already provided in the questionnaire either in person or through their representative to respond to the queries. In view of the above, the Authority determines that DOVINA cannot be treated as co-operating producer/exporter and no individual subsidy margin rate is determined for DOVINA. Subsidy margin determined for all other producers/exporters from Vietnam is being made applicable for DOVINA.

CFT Vina Copper Co.,Ltd (CFT)

400. CFT is a producer/exporter of the subject goods in Vietnam. CFT filed questionnaire response and provided information regarding the subsidy program availed by them.
401. CFT has not exported the subject goods to India directly. With respect to its exports to India, CFT has sold the subject goods to its related entity Toyota Tsusho Asia Pacific Pte. Ltd. in Singapore and Toyota Tsusho Asia Pacific Pte. Ltd has exported the subject product to India. Toyota Tsusho Asia Pacific Pte. Ltd has not filed questionnaire response and has not participated in the investigation process. Supply/export chain of all the exports to India is incomplete in absence of response by the exporter, Toyota Tsusho Asia Pacific Pte. Ltd, Authority is unable to determine the export price of CFT for subject goods to India.
402. Also, PT. TembagaMuliaSemananTbk, producer/exporter of subject product from Indonesia who has participated in the investigation and provided questionnaire response has mentioned that CFT is one of its affiliated party. However, CFT has not disclosed name of PT. TembagaMuliaSemananTbk as one of its related party in response to the specific question in its questionnaire response. Authority notes that CFT has not revealed relevant information from the Authority.
403. In view of the above, the Authority determines that CFT cannot be treated as cooperating producer/exporter and no individual subsidy margin rate can be determined for CFT. Subsidy margin determined for all other producers/exporters from Vietnam is being made applicable for CFT.

Summary of Subsidy Programs for Vietnam

404. Countervailing duty for producers/exporters from Vietnam has been determined based on facts available.

Program Nos.	Name of the Program	Subsidy Margin %	Range%
Program Nos. 1 & 3	Income Tax Preferences	***	0-1%
Program No. 2	Exemption from import duty on raw material	***	0-5%
Program Nos. 5/7/8/9/10/13	Preferential lending	***	0-5%
Program Nos. 14 & 15	Provision of land at less than adequate remuneration	***	0-1%
Program No. 6/11	Grants	***	0-5%
Total		***	5-15%

Indonesia**(i) Program No. 2 – Export Financing from Indonesia EXIM****a. Submission by the Petitioner**

405. The petitioner has submitted that the Export-Import Bank of Indonesia provides export financing at preferential rates for advancement of Indonesian exports. The institution provides funding to financial institutions or banks that lack the financial capability to enter the trade market. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:
406. WTO Document No. WT/TPR/s278
- 2015 annual report, Indonesia Exim bank

- US final finding- certain uncoated paper from Indonesia

b. Submission by the Government/ other interested parties:

407. The Government stated that the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Exim bank”) officially commenced on 01/09/2009, under Minister of Finance Decree of the Republic of Indonesia no. 366/KMK.06/2009, dated August 24, 2009. It operates independently under a statute (Act of LPEI) and is a Government-owned institution. The said statute regulates the functions, sources of funds, services-provided etc. under various articles.
408. The bank provides two types of financing to support local and overseas industries
1. Working Capital (KMKE);
 2. And/or Investment (KIE)
409. Processes followed and documents maintained by the EXIM bank are available. The eligibility criteria are not limited to certain sector/ region or enterprise under the program.

c. Examination by Authority

410. Authority notes that the program is administered under Minister of Finance Decree of the Republic of Indonesia no. 366/KMK.06/2009.
411. EXIM Bank of Indonesia is owned by Government of Indonesia. It is under direct control of the Government of Indonesia and exercises Government Authority. Its main objective is to boost national export growth and to assist exporters in expanding their business capacity. It also assists banks and financial institutions in overcoming any difficulties in extending funding for exporters. EXIM Bank’s domestic financing services comprise of export working capital and export investment facilities.
412. One important task mandated to Indonesia Exim bank is the government-assigned special assignments program known as the National Interest Account (NIA). The Regulation of the Indonesian Finance Ministry No. 134/PMK.08/2015 concerning the Special Assignment for Indonesia Exim bank acts as a legal basis for the program, which began operating in 2015. NIAs are assignments assigned by the Indonesian government to Indonesia Exim bank to provide export financing for transactions and/or projects that are not viable for commercial banks, but are considered promising by the government to boost national export. Financing through the NIA program is limited to sectors of economy, commodities, export destination country, export agent criteria, and export financing. To be considered eligible for NIA financing, the transaction and project in question must be able to increase the competitiveness and value of Indonesian products, support domestic industry growth, and to have the potential for improvement and long-term export development.
413. EXIM bank is a public body because it is created, owned, controlled, and funded by the Government of Indonesia. EXIM bank performs government function of export promotion and exercises governmental authority. The loans provided by EXIM bank amount to financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The amount of benefit is equal to the difference between the amount of payment to be made on loans granted pursuant to this subsidy program and the amount payment to be made on any other comparable commercial loan. The program is also specific because it is contingent on export performance. Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(ii) Program No. 3- Exporters being reimbursed for their losses

a. Submission by the Petitioner

414. Under the present program, a State-owned Enterprise, Asuransi Export Indonesia (persero) provides reimbursement to exporters for their losses. The Enterprise reimburses as much as 85% of the losses incurred by the exporters, through their insurance policy. The State-owned enterprise provides protection against the risks of the market to the exporters and banks. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:
- WTO Document no- WT/TPR/S278
 - Financial and Service overview, Indonesia Exim Bank
 - Final Finding- Certain Uncoated Paper from Indonesia

b. Submission by the Government/ other interested parties:

415. The government under Regulation No. 1/1982 provided for export credit insurance and export credit guarantee programs with an objective to provide protection to Indonesian exporters against the risk of non-payment. This function was to be carried out by State-owned Enterprises (SOE), under regulation no. 20/1983.

416. The government had transferred the performance of aforesaid program from PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to Pt. AsuransiEkspro Indonesia (persero), both SOEs with added functions, which was later assigned to be “National Reinsurance Company” due to an insurance premium outflow to foreign reinsurers. AsuransiAsei, a subsidiary of Pt. AsuransiEkspro Indonesia was assigned the insurance business in December 2014. Although the enterprise is under direct control of the government (99.98%), members of the board are appointed internally. The government submitted that ASEI has not offered export guarantees since 1995.
417. The eligibility criteria under the program is limited to exporters residing in Indonesia, foreign investors and domestic investors. Administering authority can exercise certain amount of discretion in deciding whether a particular firm can benefit under the program or not.

c. Examination by Authority

418. Authority notes that the program is administered by Regulation No. 1/1982. State owned financial institution provides guarantee, credit insurance and re-imbursements of losses arising out of non-payment for exports.
419. State owned financial institutions are a public body because it is created, owned, controlled, and funded by the Government of Indonesia. They perform governmental function of export promotion and exercises governmental authority. The program provides for financial contribution in the form of potential direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is contingent on export. Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(iii) Program No. 5- Various Loans Provided by Mandiri Bank

Program no. 5 (a)- Investment Loan

Program No. 5 (b)- Loan for Entrepreneur

a. Submission by the Petitioner

420. Under the investment loan program, the Mandiri Bank provide middle and long-term loan to aid financing capital goods in order to help the market flourish for expansion and building new projects. The petitioner has submitted that the program is eligible to individual or legal/non-legal entity with financing needs above 100 million Rupiah and up to 5 billion Rupiah. The amount can be given out in foreign currencies too and the maximum period for debt settlement is 15 years.
421. Under loan for entrepreneur program, bank provides working capital loan for entrepreneurs with a limit of 100 million up to 2 billion. The only pre-requisite set by the Mandiri bank herein is that it shall have a business experience of 2 years.

b. Submission by the Government/ other interested parties:

422. Bank Mandiri, an SOE, was established in the year 1998 as part of Government’s plan to restructure the banking sector. The majority share is held by the GOI, but the national & foreign investors also are part owners. The government submitted that as a bank, one of its features, Investment Loan are medium and long-term credit facility provided in Rupiah or foreign currency to finance procurement of capital goods. The said loan is based on among others financial statement, feasibility study of the project, legality of the applicant and its collateral amount is adjusted based on business cash flow. It is directly credited to the current account.
423. Government has set the eligibility for both individual and business entities. Bank Mandiri holds the discretion to provide loan based on the applicant performance and prospects. The government has also submitted that no explicit law has been passed or is available for the above-mentioned program and functions as a regular bank.
424. Under the scheme, Loan for Entrepreneur in Bank Mandiri known as Mandiri Young Entrepreneur (WMM) is the main CSR program of Bank Mandiri which has been implemented since 2007 and aims to assist the government in developing entrepreneurship in Indonesia, especially among the younger generation.
425. The eligibility criteria, as submitted by the Government, is limited to new individual entrepreneurs. The government has laid down the aims, features and processes under the said program but has not passed a law for the same.

c. Examination by Authority

426. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against preferential lending by state owned banks. Authority holds that no additional countervailing duty is required be imposed against this subsidy program.

(iv) Program No. 7- Exemption on Import Duty**a. Submission by the Petitioner**

427. The petitioner has submitted that under the scheme of the program, manufacturer for export purposes are exempted to pay any kind of import duty (generally ranging from 0-150%) on the import of raw materials.
428. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:
- Trade Policy Reviews 2013: WT/TPR/S278
 - Web Research- PW(PDF) Indonesian Customs Tax Book 2017

b. Submission by the Government/ other interested parties:

429. Pursuant to Minister of Finance Decision No. 580/KMK. 04/2003 import facility for export purposes (KITE) scheme was established on December 2003. The Decision was amended several times and lastly by Minister Finance Regulation No. 254/PMK.04/2011 and Minister Finance Regulation No. 176/PMK.04/2013.
430. As per the regulations, and exemption from import-duty, VAT and LGST was granted on import of goods when processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes. In one year period the imported goods are required to be exported. The government has set up a system of strict surveillance of the Regional Custom Officer for such an exemption. Any deficiency between the quantities imported and that used for production shall be penalized. The government has further submitted that the rule of conduct of the Regional Customs officer were laid by Director General of Customs and Excise Regulation No. 16/BC/2012 as partly amended by Director General of Customs and Excise Regulation No. 04/BC/2014.

c. Examination by Authority

431. Authority notes that the KITE program is administered by Minister Finance Regulation No. 254/PMK.04/2011 and Minister Finance Regulation No. 176/PMK.04/2013. Under this program, raw material and capital goods employed in manufacturing of exported goods are exempted from all import duties.
432. The program is not a permissible duty remission program under footnote 1 of SCM Agreement and Section 9B(b) of the Customs Tariff Act. The program provides exemption to both raw material and capital goods used in the production of exported product. There is also no sufficient evidence of verification mechanism which ensures that there is no excess benefit to enterprise. There is no evidence to show that penalty or recovery of duty was actually made from enterprise who were unable to utilize the raw material in the production of exported goods.
433. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is contingent on export. Authority holds that countervailing duty should be imposed under this program. PT Tembaga Mulia Semanan has used the subsidy program but has not provided complete details of the imports made under this program. Authority has relied on facts available and determined subsidy margin for PT Tembaga Mulia Semanan based on the subsidy margin of PT Karya Sumiden Indonesia.

(v) Program No. 8- Import Duty Drawback**a. Submission by the Petitioner-**

434. The petitioner has submitted that the Government of Indonesia provides exemption of import duty on imports of raw material which are converted into finished goods subsequently exported. The program is based on a regulation issued by the authorities in 2012. The exemption is applied on raw material which earlier was subject to no reduction of import duty. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:
- Regulations of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 254/Pml.04/2011 which has been affected from April 2012
 - Web Research- PWC (PDF) Customs News Flash 2012-01
 - Trade Policy Review 2013- WT/TPR/s278

b. Submission by the Government/ other interested parties:

435. The government of Indonesia submitted that the above-mentioned program is set under import facility for export purposes (KITE) scheme which established on December 2003, pursuant to Minister Finance Decision No. 580/KMK.04/2003, and lastly amended by Minister Finance Regulation No. 253/PMK.04/2011 and Minister Finance Regulation No. 177/PMK.04/2013.
436. As per the Ministry of Finance regulation, the drawback scheme provides import duties payable for imports of goods when processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes, may be partially or wholly

returned, receivable at the time of export of end-goods. The present scheme is also under the supervision of the Regional Customs Officer operated under Directorate General of Customs and Excise – Ministry of Finance.

437. The eligibility criterion is Company Identification Number (NIPER) as explained in the Minister Finance Regulation No. 177/PMK.04/2013. The amount of the duty drawback is contingent to the amount of the duty paid of goods contained in the end-goods for exports.

c. Examination by Authority

438. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against KITE subsidy program providing exemption on the import of raw material and capital goods. Authority holds that no additional countervailing duty is required be imposed under this subsidy program.

(vi) Program No. 9- Income Tax on Dividend

a. Submission by the Petitioner

439. The petitioner submitted that the Ministry of Finance has stipulated under Article 26 of the Income Tax Law that income tax on dividend is 10%, unless the relevant tax treaty stipulates a lower rate. The government has demarked the higher range of income tax allowed on dividends. The program is applicable to companies for certain sectors and locations and is a financial contribution by the government. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:

- WTO Document No. WT/TPR/S/278
- Indonesia Tax Guide 2016- Deloitte

b. Submission by the Government/ other interested parties:

440. The facility under the program is part of the “Tax Allowance Facility” as stipulated in Government Regulation No. 18/2015 on Income Tax Facility for Capital Investment in Certain Sectors and/or Certain Regions as amended by the Government Regulation No. 9/2016. The government aimed at economic progress by providing fiscal incentive to taxpayer in new capital investment or expansion of investment on certain sectors and/or regions.
441. The government submitted that in principle, the *article 31A* of the Act, allows tax facilities in the form of reduction of 10% on income tax on dividend as referred to *article 26*, contrary to the prior rate of 20% applicable on dividend paid to foreign taxpayer. The program is administered by the Investment Coordinating Board of Indonesia (BKPM) and Ministry of Finance.
442. The government provided for a list of industries and region, in which foreign taxpayers shall be eligible under the program. In addition, certain conditions are also laid. If met, the foreign taxpayer would get the 10% income tax on dividend or lower if there is P3B agreement between origin country of the investor and Indonesia. Moreover, the facility is product bound, the amount of dividend is the dividend derived from the total incomes of subject products.

c. Examination by the Authority

443. Authority notes that the program provides for different tax rates for foreign investor according to tax treaty between Indonesia and other countries.
444. The authority could not find sufficient evidence/material in regard to availment of this subsidy by producers/exporters of subject goods. Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(vii) Program No. 10- Reduction of Net Taxable Income

a. Submission by the Petitioner

445. The petitioner has submitted that the Government of Indonesia issued laws applicable to industries in the Special Economic Zones. They have issued benefit of 30% reduction on net taxable income from the investment in fixed assets (incl. land) prorated at 5% for six years. The only condition under the program is that the assets is not misused or transferred in the said period. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:

- Law Concerning SEZs 39/2009
- Web Research- PWC (PDF) Tax Flash February 2016

b. Submission by the Government/ other interested parties:

446. The government of Indonesia provided for a facility under Special Economic Zones (KEK) established through Act No. 39/2009 on Special Economic Zone. Currently there are 12 designated KEK across Indonesia region established by KEK National Council.

447. Under the regulation, the net taxable income in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 is reduced by 30% of the amount invested in the form of fixed assets (including land), prorated at 5% for six years of commercial production. Similar reduction is provided under Income Tax Allowance facilities, regulated under Government Regulation No. 18/2015.
448. However, as stipulated in the article 11 of Government Regulation No. 96/2015, the taxpayer in KEK may only apply the reduction of net taxable income facility in the said regulation and none other.

c. Examination by Authority

449. Authority notes that the program is available to industries located in Special Economic Zones and provides for reduction of taxable income by 30%. The program is governed by Government Regulation No. 18/2015. The income tax exemption can be availed by the industry located in Special Economic Zone under this program only and not under any other program.
450. The subsidy program provides for financial contribution the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific because it is region specific. Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(viii) Program No. 11- Carry Forward of losses

a. Submission by the Petitioner

451. Under the program, the Ministry has allowed provision to the investors with an option to carry forward their losses up to a span of 5 years. This period is further extendable to another 5 years. The petitioner submitted that the program is applicable to not only the national investors but includes international investors also subject to investment in Special Economic Zones. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications as was reasonably available to them.
- WT/TPR/S278
 - Web Research- PWC (PDF) Tax Flash February 2016
 - Web Research- PWC (PDF) Tax Flash February 2015

b. Submission by the Government/ other interested parties:

452. The Government of Indonesia, under Act No. 39/2009 established Special Economic Zones (KEK). Various programs have been launched as an incentive to the businesses to adopt these zones. One such regulation is No. 96/2015.
453. Carry forward losses in KEK as stipulated in article 10 of Government Regulation No. 96/2015 compensate losses for more than 5 years but no more than 10 years with provision as follows:
454. Allowances have been provided for under the direct supervision of the Ministry of Finance. The facility shall only be available to two subjects, business entities and business players.
- For business entity- the company should be designated as enterprise administer the KEK, possess KEK development agreement, and establish within boundary of KEK business activity;
 - For Business Player- the company or individuals should be designated as corporate taxpayer and obtain principal license for capital investment.

c. Examination by Authority

455. Program provides for carry forward of losses to business enterprise. Authority has determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program providing exemption from income tax. Authority holds that no additional countervailing duty should be determined for this subsidy program.

(ix) Program No. 12- Postpone on Import Duty

a. Submission by the Petitioner

456. The petitioner submitted that the Government provides for postponement of import duty on capital goods and equipment, goods & material for processing. Also, under the program, import of capital goods for the purpose of development of a Special Economic Zone is exempted from any import-duty. The aim behind the program is the development and flourishing of the government regulated Special Economic zones by encouraging private sector to propose development and maintenance of such zones. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:
- Tax Flash No.4, February 2016 (PWC Report)
 - Government Regulation no.96 of 2016 (GR 96/2016): Facilities in SEZ

b. Submission by the Government/ other interested parties:

457. The Special Economic Zones (KEK), under Regulation no. 39/2009, are subject to various allowances and incentives, in order to, attract business and business players to operate.
458. Under the current program, The Government of Indonesia approved for postponement of payment of import duty in KEK (Stipulated in Regulation No. 96/2015). The same postponement is eligible to be applied for by 2 subjects, business entities and business players which fulfill the requirements provided in Article 5 of the Government Regulation No. 96/2015 to receive the facility of the program.

c. Examination by Authority

459. Authority notes that the program provides for postpone of import duty for enterprise located in the Special Economic Zone. Thus, the program provides for deferral of taxes owed to certain enterprise. Benefit conferred on the enterprise is in the form of interest free short term or long term loan. Amount of benefit is equivalent to the difference between amount of interest charged by bank on commercial loan.
460. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone. Program is also specific because it provides benefit to certain enterprise located in Special Economic Zone. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against program granting exemption from import duty. Authority holds that no additional countervailing duty is required to be determined against this subsidy program.

(x) Program No. 13- Exemption of Duty on Raw Material and Supporting Goods for Production Purpose**a. Submission by the Petitioner**

461. The petitioner submitted that under the program new investors or existing investors who are expanding within the SEZ and import raw materials and supporting goods are eligible for an exemption from duty. The program is applicable on both taxpayers, organizing and carrying out business the Special Economic zone. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:

- WT/TPR/S278
- Government Regulation no.96 of 2016 (GR 96/2016): Facilities in SEZ

b. Submission by the Government/ other interested parties:

462. Special Economic Zones (KEK) established through Act No. 39/2009 allows company located and operating main business in KEK to obtain wide range of facilities and incentives from taxation to employment. The government has also provided for that in its operative, KEK National Council forms Region Council to perform implementation duties including establish administrator in each KEK.
463. Under the Ministry of Finance Regulation No. 104/2016, import of capital goods by Business Entities is exempted from import duty for 3 years, while Business Players may get import duty exemption for capital goods and/or materials for 2 years. The said exemption are laid in Article 40 & 41 by the Government.

c. Examination by Authority

464. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against program granting exemption from import duty. Authority holds that no additional countervailing duty is required to be determined against this subsidy program.

(xi) Program No. 14- Exemption from Income Tax on Imports**a. Submission by the Petitioner**

465. The petitioner has submitted that taxpayers, under the program, have been granted exemption of income tax by the Government on importation of certain goods if the company is located in the government designated Special Economic Zones. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications as was reasonably available to them.

- WT/TPR/S278
- Government Regulation no.96 of 2016 (GR 96/2016): Facilities in SEZ

b. Submission by the Government/ other interested parties:

466. The government of Indonesia provided for a facility under Special Economic Zones (KEK). KEK as it is established through Act No. 39/2009 on Special Economic Zone. Currently there are 12 designated KEK across Indonesia region established by KEK National Council. The council is also responsible to decide which business shall be the

main business in that particular KEK. The government submitted that currently the SEZ is not fully operated yet. As per the program, exemption of income tax imports in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 is applied for goods designated to business players in the KEK from:

1. Outside of Customs Area;
2. Other Business Players within the KEK;
3. Other Business Players in other KEK;
4. Bonded Zones outside of the KEK;
5. Free Trade Zone and Free Port; and/or
6. Other Region TLDPP

467. The benefit under the present program shall be obtained after an application to the Ministry of Finance via the Administrator of the respective KEK. The facility shall only be available to two subjects, business entities and business players.

c. Examination by the Authority

468. Authority notes that the program is available to enterprise located in Special Economic Zone in the nature of revenue foregone. The authority has already determined that exemption from payment of duties on import should be countervailed. Therefore, authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this program.

(xii) Program No. 15- Reduction for Investors investing in SEZ

a. Submission by the Petitioner-

469. The Petitioner has submitted that the Government under the program has stipulated certain heads under which investors are provided reduction in income tax. Following are the heads-

1. Up-to 20-100% for at least 10 years to a maximum of 25 years (required investment of more than 1 trillion Rupiah)
2. Up to 20-100% for at least 5 years to a maximum of 15 years (required investment of more than 500 billion up to 1 trillion Rupiah)
3. Up to certain percentage as determined by the relevant ministry. (required investment of less than 500 billion Rupiah)

470. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:

- Tax Flash No. 4, February 2016 (PWC Report)

b. Submission by the Government/ other interested parties:

471. This facility is set under Special Economic Zones (KEK). KEK, as it is established through Act No. 39/2009 on Special Economic Zone, allows company located and operating main business in KEK to obtain wide range of facilities and incentives from taxation to employment. The 12 designated KEK across Indonesia region are SeiMangke, TanjungApiApi, TanjungKelayang, TanjungLesung, Mandalika, MaloyBatuta Trans Kalimantan, Palu, Bitung, Morotai, Sorong, ArunLhokseumawe, GalangBatang.

472. KEK is established by KEK National Council. One of main duties of KEK National Council is to determine which business sector to be main business in KEK. In its operative, KEK National Council forms Region Council to perform implementation duties including establish administrator in each KEK. Region Council also reports to the KEK National Council of its management performance in each KEK.

473. Reduction in Income Tax for Investors investing or Tax Holiday in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 is:

- a) Investment >Rp. 1 trillion, reduction in income tax ranging from 20 – 100% for 10 – 25 years;
- b) Investment Rp. 500 billion - Rp.1 trillion, reduction in income tax ranging from 20 – 100% for 5 – 15 years;
- c) Investment <Rp. 500 billion, reduction in income tax ranging from 20 – 100% for 5 – 15 years;

474. No enterprise is specifically excluded to the program. No changes are anticipated in the program.

475. The amount of Income Tax reduction for each year of the period remains the same. The facility itself is given upon income specifically received from main business operation in KEK. But, income received from business activities other than its main operation is still subject for taxation.

c. Examination by Authority

476. Authority notes that the program provides exemption from income tax. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against program granting exemption from income tax. Authority holds that no additional countervailing duty is required to be determined against this subsidy program.

(xiii) Program No. 17- Pioneer Industry Status**a. Submission by the Petitioner-**

477. The petitioner has submitted that under the program the Government has simplified the environmental reporting requirements and licensing requirements for the industrial estates. The fiscal incentives such as tax holidays and tax allowances at national and regional levels, reduction or exemption from regional tax & levies are also certain added benefits in the program.
478. The government has made available these incentives to industries in selected 14 industrial parks. Such industries also have allowance to start construction before obtaining a formal permit.
479. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications as was reasonably available to them.
- BKPM Report
 - Article: Global Legal Monitor- Indonesia: Regulations to encourage investment in Industry
 - The Jakarta Post: New regulations aims to attract investment in industry
 - The Jakarta Post: Wilmar's Industrial estate to kick off operations this year

b. Submission by the Government/ other interested parties:

480. The Pioneer Industry Tax Benefits program was established on August 15, 2011, renewed and modified on August 14, 2015, and modified for the second time on June 27, 2016. The program provides an income tax reduction in the range of 10 percent to 100 percent over five to fifteen years for certain corporate taxpayers. The tax reduction starts from the first year of the corporation's commercial production time. The corporation receiving the tax reduction has to be working in a "pioneer industry" defined as an industry "with extensive interconnection that provides added value and high externality, introduces new technology, and has strategic value for the national economy."
481. Corporate Income Tax Reduction Facility shall be granted to income received or accrued from main business activity which constitutes a Pioneer Industry as mentioned in the Ministry of Finance Regulation No. 159/PMK.010/2015 and amended by Ministry of Finance Regulation No.103/PMK.010/2016.
482. Ministry of Finance Regulation No. 159/PMK.010/2015 as amended by Minister of Finance Regulation No.103/PMK.010/2016 has been further amended under the Ministry of Finance Regulation No. 35/2018. The amended program provides 100% income tax reductions.

c. Examination by Authority

483. Authority notes that the program provides exemption from income tax. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against program granting exemption from income tax. Authority holds that no additional countervailing duty is required to be determined against this subsidy program.

(xiv) Program No. 18- Income Tax benefits for listed Investments**a. Submission by the Petitioner**

484. The petitioner has submitted that the government of Indonesia, under the program, has established eligibility criteria for tax subsidies on domestic or foreign direct investment-
1. 30% net deduction of the total investment charged for 6 year @ 5%
 2. Accelerated depreciation and amortization as provided by the law.
 3. Income tax charged on dividend paid to Foreign Tax subject shall be 10% lower tariff according to effective DTAA; &
 4. Loss compensation for more than 5 years but not more than 10 years.
485. The geographical demarcation for this program is restricted to government defines "Specific Business Area" which are 77 in number. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications:
- Regulation No. 1/2007
 - Regulation No. 18/2015
 -

b. Submission by the Government/ other interested parties:

486. This program was established on January 1, 2007, pursuant to Government Regulation No. 1/2007. The purpose of the program is to stimulate investment in certain business fields and/or certain regions. The program was renewed and modified on April 6, 2015 by Government Regulation No. 18/2015, which was amended by Government Regulation No. 9/2016. Although Government Regulation No. 18/2015 repeals Government Regulation No.1/2007, companies receiving benefits under Government Regulation No. 1/2017 can continue receiving such benefits until their original expiration date. To receive benefits under Government Regulation No. 1/2007, taxpayers must carry out new capital expansion on one of a large number of business fields and/or business fields in certain regions listed in the appendices to Government Regulations No. 1/2007. Recipients of tax facilities under this program may not also receive benefits under Article 29 of Government Regulation No. 94/2010 (institutional income tax exemptions or reductions).
487. Both regulations accomplish their purposes through four principal means: (1) 30 percent (five percent per year for the first six years of the business's operations) tax deduction for investments in the form of tangible fixed assets; (2) accelerated depreciation and amortization; (3) lowered tax rate on dividend distributions to non-resident taxpayers; and (4) loss compensation. These tax benefits are available to companies in 77 listed industries.
488. The eligibility is limited to industries that operate in sectors that listed in the appendix I and II of the Government Regulation No. 18/2015 as amended by the Government Regulation No. 9/2016. No certain enterprise is specifically excluded from to the program. No change is anticipated in the program.

c. Examination by Authority

489. Authority notes that the program provides for exemption from income tax. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against program granting exemption from income tax. Authority holds that no additional countervailing duty is required to be determined against this subsidy program.

(xv) Program No. 19- Tax Holiday**a. Submission by the Petitioner**

490. Under the program, the government of Indonesia has declared exemption from Corporate Tax. Such a relief shall be granted for 10 years and not less than 5 tax years, from the tax year the commercial production commences. And after such period tax reduction of 50% shall be granted for 2 years.
491. The petitioner has submitted that the government has issued strict eligibility criteria under the program to grant such an extensive relief to the industries. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications as was reasonably available to them.
- Regulation of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number 159/PMK.010/2015
 - Regulation of the Ministry of Finance Number 130/ PMK 011/2011- Provision of Corporate Income Tax Relief or Reduction Facility.

b. Submission by the Government/ other interested parties

492. No separate explanation or information is provided for this program.

c. Examination by Authority

493. Authority notes that the program provides for exemption from income tax. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against program granting exemption from income tax. Authority holds that no additional countervailing duty is required to be determined against this subsidy program.

(xvi) Program No. 20- Deduction of Land Tax**a. Submission by the Petitioner**

494. The petitioner submitted that under the program, enterprises located in the Special Economic Zones are allowed to get a benefit of land tax deductible from the government of Indonesia. The land tax, presently, is deductible in accordance with the prevailing laws. As evidence of the existence of the program, the petitioners have provided the following documents or notifications as was reasonably available to them.

- WT/TPR/S278
- Government Regulation no.96 of 2016 (GR 96/2016): Facilities in SEZ

b. Submission by the Government/ and other interested parties:

495. This facility is set under Special Economic Zones (KEK) or Tax Allowance facility. KEK as it is established through Act No. 39/2009 on Special Economic Zone, allows company located and operated in KEK to obtain wide range of

facilities and incentives from taxation to employment. The 12 designated KEK across Indonesia region are SeiMangke, TanjungApiApi, TanjungKelayang, TanjungLesung, Mandalika, MaloyBatuta Trans Kalimantan, Palu, Bitung, Morotai, Sorong, ArunLhokseumawe, GalangBatang.

496. KEK is established by KEK National Council. In its operative, KEK National Council forms Region Council to perform implementation duties including establish administrator in each KEK. Region Council also reports to the KEK National Council of its management performance in each KEK.
497. Land and Building Tax (PBB) in Indonesia tax system is part of the regional/city tax or retribution, and it is determined by the regional government through head of regional/mayor regulation. In article 31 Act No. 39/2009, reduction of PBB is provided in line with regulation. However, in Government Regulation No. 96/2015, under article 22, PBB is provided under facilities in KEK for Tourism which provides that regional government may determine reduction or exemption of regional tax or retribution ranging from 50% and 100%.
498. Only KEK with main business in Tourism such as KEK TanjungKelayang, KEK Mandalika, KEK TanjungLesung, KEK Morotai, KEKSorong applied reduction in regional/city tax or retribution.
499. No application process is needed in this program. The eligibility is limited to business entities/business players operate within KEK region. No change is anticipated in the program.

c. Examination by Authority

500. The program provides reduction in land tax application to enterprise if the enterprise is located in Special Economic Zone. However, the benefit of reduction is available to enterprise carrying out tourism related business activity. Therefore, Authority holds that no countervailing duty is required to be imposed under this program.

(xvii) New program discovered during the course of investigation: Provision of Goods and Services at Less than adequate Remuneration

a) Submission made by Domestic Industry

501. The domestic industry has contended during the course of investigation that Government of Indonesia has placed targeted export restraints and other related measures on copper ore and concentrate leading to a situation of excess supply and reduced prices for these products in the domestic market of Indonesia. This results in provision of copper ore and concentrate at less than adequate remuneration to the producers of subject goods in Indonesia.

b) Examination by the Authority

502. The Authority requested information regarding export restraint on raw material from the interested parties. However, no satisfactory information/reply was provided by Government of Indonesia or any of the other interested party. The Authority notes that Government of Indonesia has placed targeted export restraints in the form of levy of export duty on copper concentrate and other related measures which has led to an excess supply and artificially lower prices for copper ore and concentrate in Indonesian domestic market. This has resulted in provision of copper ore and concentrate at less than adequate remuneration to the producers of subject goods in Indonesia. Accordingly, Authority has determined subsidy margin based on facts available for provision of raw material at less than adequate remuneration.

Producers/Exporters from Indonesia

PT Karya Sumiden Indonesia

503. PT Karya Sumiden is a producer/exporter of subject goods in Indonesia. PT Karya Sumiden Indonesia filed questionnaire response and provided information regarding the subsidy program availed by them.
504. Authority examined the response filed by PT Karya Sumiden and upon examination requested further information from them and also requested for verification of information provided in the response. Authority has verified the information provided by PT Karya Sumiden and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. It is noted that PT Karya Sumiden availed benefit under Program No. 7 and Program No. 13 alleged in the initiation notice. In addition, they have also availed exemption from VAT on electricity as reported by them in their response. Authority determines that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to PT Karya Sumiden as a recipient of this grant. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including PT Karya Sumiden.
505. Authority has also relied on facts available to determine the subsidy margin for provision of raw materials for less than adequate remuneration by relying on information available publicly, to determine subsidy margin for other program discovered during the investigation process.

506. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

Program No.	Name of the program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 7	Exemption from import duty	Import of machinery is exempted from customs duty	***	0-1%
Program No. 13	Exemption of duty on raw material for production purpose	Import of raw material is subject to preferential customs duty	***	0-5%
Other program	Exemption from VAT on Electricity	Exemption from payment of VAT on electricity	***	0-1%
Other program	Provision of Copper concentrate at less than adequate remuneration	Export duty of 7.5% on copper concentrate in Indonesia results in provision of raw material at less than adequate remuneration	***	0-5%
Total			***	0-5%

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk

507. PT TembagaMuliaSemananTbk is the producer/exporter of subject goods in Indonesia. PT Karya Sumiden Indonesia filed questionnaire response and provided information regarding the subsidy program availed by them.

508. Authority examined the response filed by PT TembagaMuliaSemananTbk and upon examination requested further information from them and also requested for verification of information provided in the response. Authority determined that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to PT TembagaMuliaSemananTbk as a recipient of this grant. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including PT TembagaMuliaSemananTbk.

509. Authority has verified the information provided by PT Tembaga Mulia SemananTbk and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. However, complete information was not provided regarding the amount of benefit received by PT TembagaMuliaSemananTbk under the subsidy programs availed by them. Accordingly, Authority has determined subsidy margin for PT TembagaMuliaSemananTbk based on facts available by relying on information provided by PT Karya Sumiden.

510. Authority has also relied on facts available to determine the subsidy margin for provision of raw materials for less than adequate remuneration by relying on information available publicly, to determine subsidy margin for other program discovered during the investigation process.

511. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

Program No.	Name of the program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 7	Exemption from import duty	Import of machinery is exempted from customs duty	***	0-5%
Program No. 13	Exemption of duty on raw material for production purpose	Import of raw material is subject to preferential customs duty	***	0-5%
Other program	Provision of Copper concentrate at less than adequate remuneration	Export duty of 7.5% on copper concentrate in Indonesia results in provision of raw material at less than adequate remuneration	***	0-5%
Total			***	0-10

Summary of Subsidy Programs for Indonesia.

512. Countervailing duty for all other producers/exporters from Indonesia has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties. In addition, subsidy margin for program nos. 2, 3, & 10 have also been added while determining the all others rate.

Program Nos.	Name of the Program	Subsidy Margin %	Range%
Program No. 7	Exemption from import duty on Machinery	***	0-5%
Program No. 7/8/12/13/14	Exemption of duty on raw material for production purpose	***	0-5%
Program No. 2/3/5	Preferential lending	***	0-1%
Program No. 10/11/15/17/18/19	Income Tax benefit	***	0-1%
Other program	Provision of Copper concentrate at less than adequate remuneration	***	0-5%
Other program	Exemption from VAT on Electricity	***	0-1%
Total		***	0-10%

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK**H.1. Submission made by the Domestic Industry**

513. The submissions made by domestic industry are as follows:

- a) The designated authority is requested to cumulatively assess the effect of such imports as (a) the amount of subsidization in relation to the imports from each country is more than one per cent ad valorem; (b) the volume of imports from each country is not negligible and (c) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.
- b) Interested parties' contention that the imports were necessitated due to demand-supply gap is highly misleading. The country has always had excessive capacities at the stage of cathode and the industry was forced to export cathodes.
- c) The imports of the product from the subject countries in the last decade were quite low. This shows that the demand of the product was being catered by the domestic industry.
- d) The industry has not set up capacities for wire below 6mm since consumers have preferred to draw wire to the desire dimension in-house considering their requirements.
- e) The volume of imports from the subject countries has increased significantly over the injury period. The imports in the period of investigation have increased by 714% as compared to the base year, while the demand merely increased by 26%.
- f) The rate of duty for the Tariff heading 74081990 has been continuously reduced in the past periods under the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). With the decrease in the rate of duty from the subject countries, the imports have shown an increasing trend.
- g) The subject imports from subject countries are coming to India at prices below the non-injurious price/fair price of the domestic industry, thus resulting in positive and significant price underselling/injury margin.
- h) The domestic industry's production volume shows a very marginal improvement as the production increased only by 6% when the demand grew by more than 26%. The improvement in the production over the period has not resulted in proportionate improvement in the domestic sales volume.
- i) Whereas the demand for the product under consideration increased by *** MT between 2015-16 and POI, the sales of the domestic industry declined by *** MT and the domestic industry had to resort to additional export of the product (*** MT) even at adverse profitability. Despite such exports, the inventories with the domestic industry increased in the recent period.
- j) The product is sold on the on the concept of 'provisional pricing' where a consumer may book an order to take material and agree to a price which may prevail in the future. It is unclear how the foreign producers have given

their data. The domestic industry has given its data on the basis of the sales invoiced during the present period.

- k) Landed value of imported material from subject countries is significantly below the selling price of the domestic industry. The benchmark for the Indian producers' price is the import prices and LME prices. There is no viable substitute to the product. Thus, the only factor responsible for the domestic industry's prices is the import prices and LME prices of the product.
- l) The rate at which the cheap and subsidized imports are flooding the Indian domestic market holds potential to destroy the Indian industry.
- m) Further, the subsidized imports are suppressing the prices of the domestic industry. If the situation remains the same and the imports remain unaddressed, then the situation would surely deteriorate.
- n) The landed price of imports is significantly below the selling price of the domestic industry. This situation clearly indicates that the demand for imports is likely to further increase in view of their being low priced as compared to the price offered by the domestic industry and would keep suppressing the prices of the domestic industry if the same is not addressed.
- o) The positive price undercutting implies that the imports would create a further pressure on the prices of the domestic industry. In the absence of necessary protection, the domestic industry would be left vulnerable.
- p) The subject foreign producers are holding huge surplus production capacities. The exporters are likely to intensify their exports causing further injury to the domestic industry.
- q) Due to the export orientation of the producers, if the current situation is not curtailed the exporters would take advantage of the growing demand making situation further adverse for the domestic industry.
- r) The market share of the imports has increased constantly with an increase of 25% in the POI from that of the base year.
- s) The domestic industry has not expanded the capacity in the investigation period. However, had the cheap and subsidized goods not flooded the domestic market, the domestic industry could have easily achieved higher capacity utilization.
- t) The domestic industry lost more than 8% of its share in the market across the injury period.
- u) The domestic industry is facing accumulated inventories and same has increased during POI. In terms of volume, the monthly inventory has reached to *** MT.
- v) The cost of sales of the domestic industry have increased whereas the selling price has not increased in the same proportion and import prices have declined.
- w) The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market which is clear by a comparison of landed price of imports from the subject countries with the selling price of the domestic industry.
- x) While the undercutting was negative in the initial base year, it has become positive over the injury period for all the subject countries. 1.6 mm, 1.8mm and 8mm constitute approx. 90% of total consumption of the PUC in the POI. The prices of the three product types have moved in tandem.
- y) The prices of the subject goods are very volatile. Daily price movement of the subject goods can be as much as 100 US\$/MT. The price fluctuation implies that prices may change to an extent of Rs. 6000-7000 per MT on a daily basis. With so much variation in the pricing, calculation of the price undercutting on a yearly basis would not reflect the true picture. Therefore, calculations have been made on a month to month basis. The Authority is requested to calculate monthly price undercutting.
- z) The profit per MT of goods sold by the domestic industry in the period of investigation has reduced by more than 30% from the base year. While the profitability did increase in the year 2015-16 from the year 2014-15, it has fallen sharply post that year. Post the increase in profitability the profit per unit sold by the petitioners has reduced by around 43% in the period of investigation.
- aa) The cash profits of the domestic industry on per MT basis also show a deterioration. The cash profits of the domestic industry on per MT basis have reduced by 31% on absolute basis in the period of investigation from base year.
- bb) The wages have increased over the injury period. Wages are not reflective of the adverse effects of the import of subject goods on the domestic industry, as these factors are governed by overall operations of the company and the economy.
- cc) The imports from other countries are not causing injury to the domestic industry as the same are either insignificant in volume or higher in prices.

- dd) It would be seen from the statement of imports that the share of imports from subject countries has constantly increased, while imports from non-subject countries have declined. This clearly shows that the increased imports from the subject countries receiving subsidies being granted to the producers in these countries have caused significant injury not only to the domestic industry, but also has impacted other producers from other countries as well.
- ee) Overall demand for the subject goods has increased over the injury period. Accordingly, fall in demand cannot be a reason for injury to the domestic industry.
- ff) The domestic industry submits that the subject imports in significant volumes and at low prices is causing injury to the domestic industry. There are no trade restrictive practices, technology issues, productivity issues or any other factor which can be attributed to the injury being suffered by the domestic industry.
- gg) The Authority should consider the combined facility of domestic and export operations, given that the exports made by the domestic industry are a result of increase in imports and not the business choice of the domestic industry. No production facility has been set up for exports.
- hh) It would be appropriate to consider total profits in the production and sale of PUC and not the profits earned solely in domestic operation for the purposes of current investigation.
- ii) Lower profits in exports should be considered as an evidence showing injury caused by the subject imports.
- jj) The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any material change. Possible decline in consumption could not have contributed to the claimed injury to the domestic industry.
- kk) There is no trade restrictive practice which could have contributed to the claimed injury to the domestic industry.
- ll) The technology as also the production process for producing product under consideration has not undergone any significant development.
- mm) The performance of the domestic industry and injury has been examined with respect to the domestic sales operation to the extent possible. The volumes of exports have significantly increased and therefore the decline in domestic sales is being claimed as a result of adverse effect of imports and is not because of the possible deterioration in exports.
- nn) The volume of subject imports has significantly increased over the injury period and resultantly the market shares of the subject countries have increased significantly.
- oo) In order to compete with imports, the domestic industry is forced to sell its products at lower margins, and as a result of this the domestic industry is severely getting impacted.

H.2. Submission by other interested parties

514. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link, are as follows:

- a) Globally, all copper products are indexed to London Metal Exchange (LME) Copper Cathode Price i.e. LME Price + Premium. Its premium is negotiable between buyer and seller while LME Price is fixed on LME through supplier. Generally, an unknown day or average of few days is chosen to fix the LME Price and then premium is added to arrive at final price.
- b) The LME price is very volatile ranged from USD 4200 to 7500 for the period under investigation. The premium ranges from USD 100-400 (2-5% of Copper Price) for Copper wire which is miniscule compared to LME Price.
- c) The Copper wire Rod plants purchase Copper Cathode at a certain Premium and convert them to Copper Rod and then draw down to wire of different sizes and then sell to Customer at certain premium. The premium covers Cathode Premium, cost of production, finance cost, logistics and off-course profit for Copper Wire Rod Plants.
- d) Similar to the applicants, the third Indian producer namely Hindustan Copper determines the selling price on the basis of LME copper price, taking into account the conversion cost and specification of subject goods demanded by the buyer.
- e) The petitioners' allegation that the import price is around 10% cheaper is incorrect.
- f) The producers charge cost component equivalent of import duty on copper wire rod (5%) from customers as a multiplying factor, part of their pricing policy. For the period under investigation, the average multiplying factor charged by both copper rod producers is 1.04.
- g) The difference is, as derived above, abysmal low incentive for any company to Import and take huge risk of highly volatile Copper Prices and USD / Rupee fluctuation.
- h) If the difference is annualised on total Copper Rod sale of 400,000 MT by both Producers, it will be around INR 82

Cr which is far below the avg. yearly combined EBITDA of Rs 3243 Cr of both Producers.

- i) The Govt. of India as a policy protects the domestic Industry by way of imposing Tariff Barrier (5.5% in the case). However, the domestic Producers have made this Protection as a tool to make Profit and added it into their Price Calculation.
- j) We estimate that the total production of “Copper Wires” in the country is in the region of 5-6 lakh MT. The applicants, at best, account for a maximum of 12000 MT per annum which is not more than 2% of the total domestic production. We understand that only Hindalco has some capacity to produce “Copper Wires” (estimated to be about 12000 MT/annum) while Vedanta does not have any facility to produce “Copper Wires”.
- k) No meaningful injury analysis can be done in terms of Annexure I of the Rules, as there will be no representation of “Copper Wire” producers in the application. Therefore, no injury analysis can be said to be made for the “Copper Wires” industry.
- l) It is relevant to highlight that the determination of NIP as per the methodology applied in anti-dumping investigations will not enable the applicants to raise their price to the extent of NIP since the imports from non-subject countries and the domestic selling price of the applicant will continue to be governed by the LME price. Therefore, the NIP of subject goods cannot be computed on the basis of 22 percent rate of return on capital employed, as the same is inflated and not appropriate for the subject goods.
- m) Petitioners claim that their output constitutes more than 90% of the Indian production in the POI. However, all the economic data and information as claimed by petitioners to be evidence of injury are pertaining to M/s Hindalco Industries Limited only. No economic parameter of M/s Vedanta is provided, which would undermine a proper examination of the domestic industry.
- n) Injury and causal link evidence presented by the petitioners is insufficient to demonstrate that the imported copper wire from the four subject countries cause injury to the domestic Indian industry.
- o) Both Hindalco and Vedanta produce and sell continuous cast copper rod and copper wire while the exporters only export the copper wire to India. Copper rod serves as the input to draw the copper wire and thus, the imported copper wire does not even directly compete with a large segment of continuous cast copper rod produced by the petitioners. Thus, any injury caused by the concerned imports must be pertaining to the India domestic industry of copper wire only and the petitioners are under obligation to demonstrate that their copper wire industry suffers injury by the imported copper wire.
- p) However, injury evidence presented by the petitioners regarding the market demand and production capacity is specific to copper rod instead of copper wire and thus irrelevant to establish any impact of the imports on the Indian industry's production.
- q) Statistical evidence on the market share, sale volume, inventories and profit does not also separate copper wire and copper rod, which cannot secure a proper examination of injury in this case.
- r) The Sterlite copper plant of Vedanta Limited has been shut since May 2018 as per Tamil Nadu Pollution Control Board's directive to permanently close the unit. This will have wide ranging repercussions on domestic copper consumption, which is estimated to be growing at a compounded annual average rate of 5.9% in the last 10 years and will also affect the supply of the subject goods in India.
- s) Further, since the closure of Vedanta's Copper Smelter, both applicants have revised upwards the multiplying factor from 3.50 % to 5.00 % (by 43%) in their pricing policy. This increase has put additional price pressure on the user industry.
- t) The existing duty structure and government policies are in favour of big producers which has resulted in the electronics sector becoming more vulnerable to imports. The imports of EE and wire & cables in last four years (PUI) have increased by almost 50%. In FY 2018-19 it is expected to cross INR 32000 Cr. Any imposition of duty will further lead to price disadvantage to products. It is also important to note that most of the users of the subject goods are in the MSME sector already operating at a very low capacity utilization.
- u) In the absence of availability of products in India, subject goods shall have to be imported from outside India and accordingly imports will further increase. Imposition of anti-subsidy duty will be counterproductive and will have no impact.
- v) Pricing Policy of Domestic Producers to charge the Customs Duty in their price is also a big factor as imports from these four countries are duty free under AIFTA thus making the imported wire more competitive.
- w) It may also make domestic industry reluctant to improve the production technology and efficiency.
- x) New investment in the Copper Wire Rod (Copper Rod) segment by major entrants like Trafigura and Adani is indicative of optimistic future scenario and attractive payback.
- y) As per Proforma IVA filed by petitioners, the capacity of the petitioner remains unchanged during the injury period and POI. Production and capacity utilization have increased substantially during the POI to 106 and 103 respectively as compared to 100 during the base year 2014-15. Thus, imports from subject goods are not at all causing injury to the domestic industry.
- z) During 2017-2018, many large producers started to install new production lines with a view to replace imported wire rods with local production. First, a 240ktpy Contirod line at Hindalco's Birla Copper unit, was started in March 2018 and has already resulted in a 39% surge in Hindalco's wire rod output to 110kt in the March to September 2018 period compared to 79kt in the same period of 2017. Second, another 240Kktpy Contirod line in

Halol, Gujarat state, was commissioned last December at Ryker Base Private, a joint venture between local Indian cable-maker Polycab Wires and trading house Trafigura. Meanwhile, a further 240ktpy capacity Contirod line was supposed to be started at Vedanta's Silvassa plant before the end of 2018, will be started before year-end.

- aa) With the new installed capacity, the Indian wire rod industry can bring on-stream of new wire rod capacity in 2018, far more than the existing size of the entire Indian market.
- bb) The Applicants are at optimum capacity utilization since last three years. In fact, Hindalco has been regularly outsourcing part of its Rod production from others, as they do not have the capacity to process their cathodes to Rod.
- cc) The combined installed capacity of Copper Wire Rods (Copper Rod) is 400,000 MT (Hindalco: 150,000 MT and Vedanta: 250,000 MT) per annum during the period of investigation. Hindalco has been regularly outsourcing significant quantity of "Copper Wire Rods" production due to exhaustion of its own capacity.
- dd) Petitioners have already announced projects of 240,000 MT which would lead to more than doubling of their existing capacities. Hindalco has already commissioned their new "Copper Wire Rods" capacity in Q1 of FY 2019 while Vedanta's project is expected to be commissioned soon (if not already commissioned).
- ee) The applicants are integrated custom smelters and use copper concentrate and unrefined copper (Blister Copper, Copper Anode & Copper Scrap) as their raw material. They enjoy almost ZERO effective rate of Customs Duty on their raw material imports. Both the applicants source their main inputs predominantly (Copper concentrate & Unrefined Copper) from FTA / PTA / LDCs countries.
- ff) The main focus of the applicants is on selling Copper Cathode and Copper Rod. Resultantly, more than 95% of the revenue of the applicants is from these two products only.
- gg) The sales volume of petitioners remains almost same during the POI as compared to the base year 2014-15. As shown above, the exports sales volume of the petitioners has increased tremendously from 100 during the base year 2014-15 to 1138 during the POI. It seems that the petitioner is focusing on exports only, that too by choice, not by chance, rather than focusing on selling the subject goods in the Indian market.
- hh) The sales volume of M/s Hindustan Copper Ltd. increased by 35 percent during the POI. Further, as per the claims of the Applicants, the sales volume of the Applicants during the POI has remained constant. The sales volume of petitioners remains almost same during the POI as compared to the base year 2014-15. As shown above, the exports sales volume of the petitioners has increased tremendously from 100 during the base year 2014-15 to 1138 during the POI.
- ii) Average stock should not be seen in isolation. Average stock alone has no meaning, it should be seen in relation with the sales or production. The petitioners have not provided the same.
- jj) Petitioners are consistently maintaining "NIL" inventory for Copper Wire Rod (Copper Rod) at the end of each quarter. Therefore, inventory is not the factor which is causing injury to petitioner industry.
- kk) There is sudden and substantial increase in cost of sales of the product under consideration. It appears that there are some other factors which are causing injury to the domestic industry and resulted in higher cost of sales.
- ll) Price undercutting does not provide the basis for determination and shall not be seen in isolation. It has to be seen in light of overall performance of the domestic industry, whether it is resulting into material injury to the Domestic Industry. In present case, the price undercutting from subject countries was negative during 2014-15 and 2015-16 and slightly positive during 2016-17 and POI. .
- mm) It is also essential to ensure that import price (using CIF Value) has to be calculated by adding handling charge and other primary customs duties to obtain the same level position before comparing it with domestic price.
- nn) Moreover, Indonesia's export to India only covers copper wire having a diameter from 2.6mm to 1.6mm which is different from copper rod produced by the Petitioners having a diameter more than 8mm. Copper wire experiences further drawing process from copper rods. As such, it is unfair and economically unjust to compare the domestic selling price of copper wire rods with the cost of imported copper wire.
- oo) There is no correlation between the price undercutting and PBIT. Price undercutting is almost in the same range during the injury period, however, the PBIT has come down substantially during the year 2016-17 and POI.
- pp) It seems that there are some other factors which are causing injury to the domestic industry. Such decline in PBIT might be result of variations in other products and not related to PUC.
- qq) Any reduction in EBITDA of Vedanta and Hindalco may be attributed to reduced TCRC (costlier inputs) from mines and increased Cost of Production. This has nothing to do with imports from the subject countries. The relevant portion of the Annual Report of Hindalco is reproduced below: "adverse concentrate market led to decline of benchmark TCRC value for second year in row...."
- rr) Number of employees declined during the injury period from 100 (2014-15) to 89 during POI, however, salaries and wages have increased substantially from 100 during the base year 2014-15 to 130 during the POI.
- ss) There is a breach in causal link between the subject imports and the petitioner's performance. It is imperative to conduct a detailed examination of the other possible factors that caused injury to the petitioner.
- tt) It is submitted that for the calculation of injury and causal link, the injurious effects of the subject imports must be segregated from other factors that cause injury pursuant to Article 15.5 of the SCM Agreement and Annexure I of the Anti-Subsidy Rules.
- uu) The petitioners have failed to mention that the imports of Continuous Cast Copper Wire Rod from other countries, which are directly competing with their product, are also causing injury to them.

Sl.No.	Country	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
1	U ARAB EMTS	40,031	69,195	71,067	63,854
2	RUSSIA	29,286	50,999	12,400	133
3	Others	10,945	13,979	25,587	16,829
	Total Import	80,262	134,173	109,054	80,817

- vv) Imports from UAE are substantially higher than any other country. The reason for such substantial increase in imports is that the major exports from UAE is done by FUJAIKRAH GOLD, a company owned by Vedanta Group, one of petitioners. The website of Fujairah Gold depicts that:

“Fujairah Gold FZC operates a Precious Metal Refinery and a Continuous Cast Copper Rod Plant strategically located at Fujairah Free Zone II, Fujairah, United Arab Emirates. Fujairah Gold FZC is a part of Vedanta Resources Plc globally diversified natural resources company with interests in Zinc, Lead, Silver, Copper, Iron Ore, Aluminium, Power and Oil & Gas.”

- ww) It is clear that Fujairah Gold is involved in the production and export of the subject goods.
- xx) Major imports are being made by the Vedanta Group and that's the reason the same was not included in the subject countries despite having high share in imports.
- yy) The petitioners have deliberately left out UAE from the list of subject countries.
- zz) The inclusion of imports from UAE is important for the injury analysis, however the domestic industry has ignored the same altogether. The reasons for exclusion of UAE have not been listed in the petition.
- aaa) Imports from Russia have stopped due to policy change in their country. The imports from UAE in 2018-19 are expected to be around 75,000 MT which is higher than the subject countries' exports to India.
- bbb) It may be recalled that the Domestic Industry in its presentation before the Authority had clearly spelt out the reasons for their alleged drop in performance.
- ccc) It was argued that the genesis of the problems being faced by the domestic producers can be found in the Indo-ASEAN FTA. It was stated that the imports from the FTA countries increased as the customs duties came down. It was suggested that the Government of India should possibly take this as a case study to examine the serious negative effects of the FTA signed by the Government of India. Last but not the least, the Domestic Industry clearly admitted that the major and essential element of the alleged injury is the FTA.
- ddd) The Domestic Industry also argued before the Hon'ble Authority that the level of investments varies drastically depending upon where the product is situated in the production chain. It was also admitted that the pricing of “Copper Wire Rods” is dependent upon the LME prices of copper and there is huge fluctuation which could vary on a daily basis or even several times during the day. Therefore, it is not possible to develop a case of anti-subsidy for the Domestic Industry.
- eee) Without prejudice to our submission that the entire information/data in support of their claim of injury is misleading and irrelevant, it is submitted that the Domestic Industry has itself categorically admitted that the alleged injury is due to the other factors which are in no way connected with the alleged subsidization of the subject goods. That being the case, it is humbly requested that the Authority may terminate the investigation on this very ground alone.
- fff) Additionally, the applicants entered into agreements wherein the sales price was determined based on the current LME copper price and the goods were to be supplied in the future ('future contract').
- ggg) The aforesaid form of contracts i.e. forward contract and future contracts allows the parties to hedge risks. Under these contracts, a buyer who expects an increase in future price may purchase subject goods at the current prices and ensure the delivery of goods in the future. Accordingly, by entering into such agreements, the buyers shift the risk of an increase in future price to the seller (Applicants) at the cost of a marginal premium.
- hhh) Since the applicants have entered into future contracts, it is likely that the price of the subject goods is determined prior to the POI and the goods are delivered during the POI. Further, during the POI, the price of input materials has increased substantially (from USD 2.3/lb during 2016-17 to USD 3.2/lb during the POI) and therefore, it is likely that the Applicants had suffered because they were bound to sell subject goods at loss or below appropriate margins while honoring future contracts entered prior to POI. Under the aforesaid factual circumstances and in terms of Para 2 (1) to Annexure I of the CVD Rules, the Authority is requested to adjust the impact of forwarding contracts, futures contracts and other factors which have simultaneously impacted the economic parameters of the applicants.
- iii) The capacity installed remains unchanged during the entire injury period, however, capital employed has increased substantially from 100 during the base year 2014-15 to 121 during the POI.

H.3. Examination by the Authority

515. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry in this regard, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject countries.

516. Rule 13 of the Subsidy Rules deals with the principles governing the determination of injury which provides as follows:

13. Determination of injury-

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the casual link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if—

(i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and

(ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.

I. Volume Effect of subsidized imports and Impact on domestic Industry

i. Assessment of Demand

517. Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of all Indian producers and imports from all countries. It is seen that demand has increased over the injury period. The demand so assessed is as follows-

Sl.No.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
2	Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***
3	Imports from Subject Countries	MT	15,357	46,650	83,912	123,439
4	Import from Other Countries	MT	79,957	89,827	76,358	63,647
5	Total Demand	MT	***	***	***	***
	Trend		100	120	122	125

ii. Imports volumes and share of the imports from subject countries.

518. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under-

Sl.No.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	Subject countries					
a	Indonesia	MT	4,093	11,065	22,534	25,714
b	Malaysia	MT	10,841	27,473	32,137	46,328
c	Subsidized imports from Thailand	MT	***	***	***	***
c.1	Non-Subsidized imports from Thailand	MT	***	***	***	***
d	Vietnam	MT	20	4,015	16,096	32,035

2	Total subsidized imports from Subject countries	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	301	493	712
2.1	Total non-subsidized imports from Subject countries	MT	-	434	8144	14,162
3	Other Countries	MT	79,957	89,827	76,358	63,647
4	Total	MT	95,314	1,36,477	1,60,270	1,87,086

519. It is seen that:

- There has been a significant increase in the absolute volume of subsidized imports from subject countries by 612% in POI from the base year.
- The subsidized imports have increased sharply in relation to production of the domestic industry from ***% to ***%.
- The market share of subject imports has increased significantly, and the share of imports increased from ***% to ***% of demand of the country.

II. Price effect of subject imports and impact on domestic industry

520. With regard to the effect of subsidized imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

iii. Price Undercutting

521. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the investigation period. The price undercutting has been determined separately for each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole.

Sl.No.	Particulars	Unit	74081190	74081990	Weighted Average
1	Indonesia				
a	Landed Price	Rs/MT	-	4,38,937	4,38,937
b	Net Selling Price	Rs/MT	-	***	***
c	Price Undercutting	Rs/MT	-	***	***
d	Price Undercutting	%		***	***
	Range	%		0-5	0-5
2	Malaysia				
a	Landed Price	Rs/MT	4,35,641	4,52,487	4,52,449
b	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***
C	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
D	Price Undercutting	%	***	***	***
	Range	%	0-5	0-5	0-5
3	Thailand				
A	Landed Price	Rs/MT	-	4,39,784	4,39,784
b	Net Selling Price	Rs/MT	-	***	***
c	Price Undercutting	Rs/MT	-	***	***
d	Price Undercutting	%		***	***

Sl.No.	Particulars	Unit	74081190	74081990	Weighted Average
	Range	%		0-5	0-5
4	Vietnam				
a	Landed Price	Rs/MT	-	4,28,243	4,28,243
b	Net Selling Price	Rs/MT	-	***	***
c	Price Undercutting	Rs/MT	-	***	***
d	Price Undercutting	%		***	***
	Trend	%		5-10	5-10
5	Subject Countries as a whole				
a	Landed Price	Rs/MT	4,35,641	4,41,343	4,41,338
c	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
d	Price Undercutting	%	***	***	***
	Trend	%	0-5	0-5	0-5

522. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.

iv. Price Underselling/ Injury Margin

523. The Authority has worked out the non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed value of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling/ injury margin has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a whole.

524. It is noted from the table below that the price underselling/ injury margin is positive, indicating that the imports have entered the market at injurious prices.

525. The injury margin for cooperative producers/exporters are evaluated as under :-

Country	Producer	PCN	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
			USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
Indonesia	PT. Karya Sumiden Indonesia	P5	***	***	***	***	5-10%
	PT. Tembaga Mulia Semanan	P5	***	***	***	***	0-5%
	Others	P5	***	***	***	***	5-10%
Vietnam	All producers	P5	***	***	***	***	5-10%
Thailand	SEI Thai Electric Conductor Company Ltd	P5	***	***	***	***	0-5%
	Others	P5	***	***	***	***	5-10%
Malaysia	Metrod Malaysia Sdn Bhd			***	***	***	0-5%
	74081190	P3	***	***	***	***	0-5%
	74081990	P5	***	***	***	***	0-5%
	Panasonic Procurement Malaysia Sdn Bhd	P5	***	***	***	***	0-5%
	Metrod+ Panasonic			***	***	***	0-5%
	Others	P5	***	***	***	***	10-15%

526. The authority notes that in the disclosure statement inadvertently separate injury margin was given in the injury margin table above for CFT Vina Copper Co. Ltd. despite holding them as a non-cooperating party. The authority

has taken the corrective measure in the Final Findings. Since, no party in Vietnam has been treated as cooperating party, the authority has calculated the injury margin of all producers/exporters from Vietnam based on the total imports from Vietnam as per its consistent practice.

v. Price suppression and depression

527. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period.

Sl.No.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Cost of sales	Rs. /MT	***	***	***	***
2	Trend	<i>Indexed</i>	100	81	86	104
3	Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
4	Trend	<i>Indexed</i>	100	84	86	101
5	Landed Price	Rs./MT	***	***	***	***
6	Trend	<i>Indexed</i>	100	85	83	99

528. It is seen that both the selling price and cost of sales of the domestic industry have increased. However, the increase in the selling price is less than the increase in the cost of sales. It is further noted that the landed price of imports are below the selling price of the domestic industry. This shows that the imports are suppressing the prices of the domestic industry and are preventing the price increases, which otherwise would have occurred.

III. Economic parameters relating to the domestic industry

529. The Rules require that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

530. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization, domestic sales and export is as under:

Sl.No.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend		100	100	118	118
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend		100	106	99	106
3	Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Trend		100	104	80	87
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend		100	105	99	99
5	Export Sales	MT	***	***	***	***
	Trend		100	87	169	1039

531. The Authority notes that-

- a. The capacity utilization of the domestic industry has declined and significant capacity remained unutilized since 2016-17 onwards.

- b. The production of the domestic industry has increased over the injury period. The domestic sales of the domestic industry have declined whereas the exports of the domestic industry have increased considerably in the POI.

ii. Market Share

532. The market share of the domestic industry and other domestic producers over the injury period is as under:

Sl.No.	Market Share	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
	Range		30-40	30-40	20-30	20-30
2	Sale of Other Producers	%	***	***	***	***
	Range		40-50	40-50	40-50	30-40
3	Subsidized imports from Subject Countries	%	***	***	***	***
	Range		0-10	0-10	10-20	15-25
3.1	Non-Subsidized imports from Subject Countries		***	***	***	***
	Range		-	0-10	0-10	0-10
4	Other Countries	%	***	***	***	***
	Range		10-20	10-20	10-20	10-20
5	Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

533. It can be seen that the market share of the domestic industry and other domestic producers have declined in POI whereas share of subject countries' imports have increased. The share of imports from other countries have also declined.

iii. Profit or loss, cash profits and return on capital employed

534. The profit position of the domestic industry in terms of profit or loss, cash profits and return on investment was as under:

Sl.No.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
2	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>81</i>	<i>86</i>	<i>104</i>
3	Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
4	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>84</i>	<i>86</i>	<i>101</i>
5	Profit/(Loss)	Rs./MT	***	***	***	***
6	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>96</i>	<i>64</i>
7	Profit/(Loss)	Rs.Lacs	***	***	***	***
8	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>95</i>	<i>63</i>
9	PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
10	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>99</i>	<i>68</i>
11	Cash Profits	Rs.Lacs	***	***	***	***
12	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>96</i>	<i>66</i>
13	ROCE	%	***	***	***	***
14	<i>Trend</i>	<i>Range</i>	<i>25-35</i>	<i>30-40</i>	<i>25-35</i>	<i>15-25</i>

535. The Authority notes that:

- a. The profit of the domestic industry has come down over the injury period.
- b. Cash profits, PBIT and return on capital employed of the domestic industry have followed a similar trend.

iv. Inventories

536. The data relating to inventories of the subject goods is as follows-

Sl.No.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Average Stock	MT	***	***	***	***
2	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>443</i>	<i>325</i>	<i>461</i>

537. It is noted that the average inventories have increased over the period except some decline in 2016-17.

v. Employment, wages and productivity

538. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury period was as under:

Sl.No.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
2	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>111</i>	<i>119</i>
3	Employment	Nos	***	***	***	***
4	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>73</i>	<i>72</i>
5	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
6	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>100</i>	<i>106</i>
7	Productivity per employee	<i>Per No</i>	***	***	***	***
8	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>138</i>	<i>137</i>	<i>147</i>

539. It is seen that the number of employees has declined over the injury period with an increase in wages and the productivity per employee and per day.

vi. Growth

540. The trends of volume and profit parameters of the domestic industry showed as under-

Sl.No.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	Production	%	-	6%	-6%	6%
2	Domestic sales	%	-	5%	-6%	0%
3	Profit per unit	%	-	21%	-20%	-33%
4	Cash profit per unit	%	-	21%	-19%	-31%
5	Return on capital employed	%	-	19%	-23%	-36%

541. It is noted that there is positive growth in production of the domestic industry but, the domestic sales have declined. Growth in production has not resulted in growth in domestic sales and has resulted in increase of the export sales. The market share of the domestic industry has declined. The profits, cash profit and return on capital employed have also shown decline over the injury period.

vii. Factors affecting domestic prices

542. The Authority notes that the imports are undercutting the prices of the domestic industry. The market share of subject imports has increased over the period, whereas that of the domestic producers has declined. This shows that the imports are penetrating the market with low prices.

viii. Ability to raise capital investment

543. It is seen that the domestic industry has enhanced capacity for the subject goods over the period, making capital investment. However, despite increase in demand, the capacities are lying significantly underutilized.
544. It is noted that the volume parameters of the domestic industry have shown growth. However, there has been a deterioration in price parameters. The profits, cash profit and return on capital employed have also shown a significant decline over the injury period. The profitability of the domestic industry has declined over the injury period.

IV. Conclusions on Injury

545. The Authority notes that the imports have increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and have had a suppressing effect on the prices of the domestic industry. The price underselling is also positive. While the market share of subject imports has increased significantly, that of domestic producers has declined. The capacity utilisation of the domestic industry has declined. Even though performance of the domestic industry has improved in terms of production, domestic sales and capacity utilization have declined; it is seen that the domestic industry is suffering from underutilized capacities. Further, the profitability of the domestic industry has declined and its cash profits, PBIT and return on investment has followed the same trend. Accordingly, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

V. Causal Link

546. The Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

a. Volume and prices of imports from third countries

547. The imports from other countries are not significant enough to break the causal link between subsidized import from subject countries and injury to the domestic industry.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

548. The Authority notes that there is no contraction of demand. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement over the injury period. Further, there have been no changes in the pattern of consumption which could have caused injury to the domestic industry.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

549. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

d. Developments in technology

550. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

e. Export performance of the domestic industry

551. The injury information has been considered separately for domestic and exports, to the extent the same could be segregated.

f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

552. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.

VI. Conclusion on causal link

553. The authority notes as under:-

- a. The subsidized imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.
- b. Subsidized imports from subject countries are coming into India in substantial volumes.
- c. The imports are undercutting the prices of the domestic industry which have led to a decline in the selling price of the domestic industry as the imports are suppressing the prices of the domestic industry and prevented price increases, which otherwise would have occurred.
- d. There is decline in market share of domestic producers due to the positive price undercutting.
- e. Consequent impact of subsidized imports on the domestic industry have been significantly adverse in terms of reduced capacity utilisation, domestic sales, profitability, ROCE, etc.

554. The Authority therefore holds that there is causal link between the subsidization of the subject goods and the injury suffered by the domestic industry.

J. Post Disclosure comments

555. The Authority issued a disclosure statement on 21st October 2019 disclosing essential facts of the case and inviting comment from all the interested parties. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised had already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under:

Submission made by the domestic industry

The domestic industry reiterated its submissions stating that:

- The import data & domestic industry data completely pertain to copper wire under 7408. Copper wire rod is an industry terminology and wire rod are used as a terminology for rod in coil form falling under 7407 and are clearly beyond the scope of PUC. Petitioners did not include rod not in coil form within the scope of the present petition.
- Customs Tariff Act only uses wire and rod as terminologies, and wire has no restriction of diameter in it.
- Wire above or below 6mm, all are further drawn for the eventual end use requirement. It is eventually wire from 0.19 – 0.20mm which is the end product.
- Vedanta has not provided injury information as it has been considered ineligible on grounds of imports, but it is a matter of fact that Vedanta has also suffered injury.
- The domestic industry can meet full demand as the installed capacities for wire below 6mm are in the region of 11.33 lacs MT as against established demand of 6.6 lacs MT.
- Authority rightly determined that Alpha, DOVINA, CFT cannot be treated as co-operating producers/exporters and no individual subsidy margin should be determined for these parties.
- The producers in subject countries have benefited from subsidized cathode or wire above 8mm procured from Indonesia and subsidy margin is required to be determined for all the inputs procured by the producers in subject countries from Indonesia.
- Since preferential rules of origin do not apply to a CVD investigation, the producers have claimed that goods have been produced in Thailand, Vietnam or Malaysia even when inputs have been sourced from Indonesia. Further, these producers have even admitted that part production activity has happened in Indonesia. Producers in Indonesia are clearly benefited from the mining subsidies received in the input consumed by these producers. Thus, subsidy in the inputs procured from Indonesia is required to be captured and included in the subsidy in the product exported from Thailand, Vietnam and Malaysia.
- The questionnaire response of the GOV and producers/exporters of Vietnam should be rejected for suppression of facts that the producers have partly sourced cathode produced from domestic mining.
- With respect to Indonesian schemes, Authority is requested to consider that electricity is also being provided to these producers at less than adequate remuneration due to capping of selling price of coal and other measures applied by Government of Indonesia.
- The Authority has given separate margin for preferential lending in Indonesia under Program Nos. 2, 3, and 5, to other Indonesian producers/exporters but the same should be applied for both the responding producers/exporters of the subject goods as the lending rates are much lower to the prime lending rate.
- Under Program nos. 10, 11, 15, 17, 18, 19 of Indonesia, separate margin for income tax benefits are imposed on other Indonesian producers/exporters and same should be applied to both the responding companies as petitioners believe that both the responding producers/exporters are paying income tax at concessional rates.
- Program No. 14 of Indonesia i.e. 'Exemption of income tax on import' is all together a different subsidy scheme which should not be clubbed with import duty exemption. The scheme allows exemption on income tax of 2.5% under Article 14 of PMK 147/04.2011. The duty should be imposed separately to both the companies.
- Program No. 33 of Malaysia also constitutes countervailable subsidy.
- The Authority may kindly consider other authority findings and their margins to determine CVD margins in Malaysia, at least for non-cooperative producers.
- Malaysian scheme/program No. 16 i.e. 'Allowance for plants and machinery/Capital Allowance (CA)', the responding producer/exporter, Alpha Industries SDN BHD, Metrod OFHC and Metrod Malaysia have accepted availment of benefit. Schedule 3 of the ITA and P.U.(A) 52/2000 includes the allowance percentages for Plant and Machinery as 20% Initial allowance and 14% Annual allowance and provides a countervailable benefit in contrary to what the Authority has held.
- Malaysian scheme/Program No. 9 i.e. 'Pioneer Status' does not just provide income tax exemptions but also other incentives. The Authority should re-determine margins in residual category relying upon the other authority CVD margin.
- Thailand schemes/Program no. 13 and 14 are non-tax incentives provided by Board of investment (BOI) and companies with foreign ownership are eligible. Since STEC is foreign owned company and they met the criteria as

per BOI, hence they are eligible to avail benefit in addition to the tax incentives under these schemes. The Authority is requested to determine CVD margin under this scheme.

- STEC has acknowledged and the Authority has confirmed that STEC has incurred losses during the period of investigation. The Authority is requested to check the past records of the company. In a situation of consistent losses, it appears that the exporter's losses are being absorbed by some other entity. Thus, exports at losses and sales at losses implies existence of dumping. The Authority may kindly initiate suo moto anti-dumping investigation in respect of imports from Thailand. The same approach was adopted by the Authority in past.
- STEC is a subsidiary of Sumitomo Electric, Japan and is highly unlikely to be in losses unless they are selling transferring material on lower premiums/prices. Information shows that contrary to their claims of consistent losses since inception, the company has been in profits and the same are rising. Further, the company has sourced raw material from outside ASEAN as well.
- In Vietnam, the Authority should consider two programs (i) "Interest Rate Support Program under the SBV", on which the investigation was initiated by the Authority based on the information furnished by the petitioner, and (ii) "Import duty exemption for equipment and machinery to create fixed asset" as disclosed by the GOV in its questionnaire response. The scheme has been examined and quantified by the Authority in past. The Authority is requested to re-examine the scheme relying upon past finding and determine subsidy margin accordingly.
- The Authority has rightly determined that domestic industry has suffered material injury as a result of subsidized imports. Grossly underutilized production capacities for wire below 8mm despite significant demand, significant price undercutting and injury margin, collectively & cumulatively establish that the domestic industry has suffered injury.
- Subsidy duty may be imposed only on ad valorem basis expressed as % of CIF price because of (a) changes in LME on frequent basis, (b) existence of two PCNs, (c) CVD margins having been determined on ad valorem basis.

Views of other Interested Parties

The other interested parties have made following submissions:

- The Authority has proposed a different product under consideration in the Disclosure Statement, i.e. "Continuous Cast Copper Wire falling under tariff heading 7408 of the Customs Tariff", which is different from the PUC as defined in the initiation notice. The proposed scope of the product under consideration resulted in enlarging the scope of the investigation. The changes proposed in the product under considering resulting in enlarging its scope is without the authority of law.
- From the disclosure statement, the respondent is unable to ascertain the parties who have requested for change in the scope of the product under consideration. Incidentally, even the inspection of the public file as late as on 25.10.2019 does not indicate any such information.
- Metrod submits that its comments on the explanation given by the Authority in its letter dated 05 April 2019 to introduce PCN and other substantive comments have not been considered at all in the disclosure statement.
- "Copper Wire Rods" and "Copper Wires" are two completely different products and any attempt to suggest that the two terms can be used interchangeably, is bereft of any merit. It may also be noted that the CTH Codes for "Copper Wire Rods" and "Copper Wires" are different at the 4-digit level. While "Copper Wire Rods" fall under the CTH 7407, "Copper Wires" fall under CTH Code 7408. "Copper Wire" is a separate industry, none of the producers of "Copper Wires" are mentioned by the applicants in their application. This further proves and establishes beyond any doubt that "Copper Wire" is not included in the scope of the investigation.
- Copper Wires of thickness below 3MM was not produced by the petitioner industry during the POI and therefore, the same should be excluded from the scope of Product under Consideration.
- The exclusion of Sterlite from the purview of the Domestic Industry is contrary to the law and the well-established practices of the Authority.
- The Petitioner Industry has withheld the information about their relationship with UAE party in the non-confidential version of the petition.
- Hindustan Copper Ltd. has been left out despite the fact that their Price is benchmark rate for all Government procurement and majority of industry.
- The Authority has also not disclosed total production in India, the names of domestic producers whose production has been considered for determining total production and the percentage share of Hindalco in total domestic production and why such percentage share is considered as sufficient to command major proportion in total domestic production.
- There are many other manufacturers of the subject goods which have not been considered apart from the three producers such as Finolex Cables Ltd., TDT Copper Ltd., JMW, Omega Rolling Mills, Leebo Metals Pvt. Ltd., Gujarat Copper, Ramay Copper, TamradhatuUdyog, KC Metals, Coprod, COSMOS, Bhagyanagar Metals, Malhotra Industries and many others. The combined production of these companies is around 300,000 MT p.a., which is higher than the production of Hindalco under POI.

- The concept of double counting introduced by the Authority, is incorrect and needs reconsideration. When the applicants plead for imposition of duties on two different products at the same time, it makes logical and legal sense to consider only the downstream products for the purposes of standing as well as injury.
- Since the Authority is obliged to consider the impact of subsidized imports on the prices of the Copper Wire Producers, any analysis without considering the data/information of the Wire producers, would not only be illogical but also against the Rules.
- Production of Hindalco alone cannot be considered as sufficient for establishing the standing of the domestic industry.
- No comments can be offered on the Injury Parameters in the absence of clarity about PUC / Domestic Industry and Segregated Import data.
- The reduction in profits suffered by the Domestic Industry is on account of the incapability of the petitioner industry to provide Copper Wire to the Indian Consumers.
- Change in the demand pattern from Copper Rod to Copper Wire by the users of the subject goods has increased fixed costs and lowered profit margins.
- Reduction in the import duties from ASEAN countries under FTA is another cause for reduction in profitability.
- Vedanta has stopped its production due to strict pollution control norms and not imports.
- Since copper wire and copper rods are not internally comparable, clubbing them together for the purposes of assessing injury would not be commercially logical.
- The volume of imports from subject countries determined by the Authority is same as the volume of imports from subject countries provided in the petition. It is not possible that total imports of Copper Wire under tariff heading 7408 is same as total import of Copper rod, Copper Wire & Copper Strips imported under tariff headings 7407, 7408 & 7409 respectively. If there were no imports of Copper bars & rod or Copper strips from subject countries, domestic industry would not have requested inclusion of Copper Rod and Copper Strips within the scope of product under consideration for imposition of anti-dumping duty.
- If correct volume of imports of product under consideration is taken into account after excluding imports of copper rod under tariff heading 7407 and copper strips under tariff heading 7408, it would reflect lower volume of imports.
- Authority has determined that subsidy margin of STEC is de-minimis. This means that the exports of product under consideration by STEC are unsubsidized. Thus, while considering increase in subject imports and for assessment of material injury, the Authority is required to exclude exports of STEC from the total volume of exports.
- There continues to be a gap between the domestic demand and ability of the Petitioners to supply the product under consideration. Indeed, it may be seen that the increase in capacities of the Petitioners has not been able to keep up with the increase in demand.
- The price and cost of the Petitioners have moved largely in tandem with each other.
- Despite the landed price being below the selling price of the domestic industry, there was no price suppression or depression in the three years prior to the period of investigation. Indeed, the only year where there is a small gap between the cost and price of the Petitioners is in the period of investigation, where the increase in price was only 3 index points lesser than the increase in cost.
- Domestic industry has been successfully able to increase production over the injury period.
- While domestic sales have remained at the same level over the injury period, there is a substantial increase in export sales.
- The return on capital employed earned by the domestic industry appears to be in the prescribed range already i.e. 15-25%.
- Price undercutting margin for imports from Malaysia is 0-5% and the injury margin for imports from Malaysian cooperative exporters is also 0-5%.
- Prices of copper products worldwide tend to be pegged to the London Metal Exchange (LME) with an additional premium, which is usually negotiated. However, during the period of investigation, the LME price was in a very volatile range which is bound to have affected the domestic industry's performance.
- The impact of non-subject imports on the domestic industry must be considered and analysed separately.
- Imports from UAE, accounted for about 30% of the total imports into India. These imports were also entering India at comparable or lower prices as compared to import prices from the subject countries. Volume of Imports from UAE are higher than import from any of the subject countries taken individually.
- Domestic Industry's statement on accumulated inventories is factually incorrect as every quarter they reduce the inventory to NIL.
- Copper producers have excellent capacity utilization and very healthy EBITDA. Combined average EBITDA is INR 3242 Crore per year for the PUI.
- The reduction in EBITDA of Vedanta is mainly due to reduced TCRC from mines and increased Cost of Production.

Malaysia Subsidy Programs

- It has been submitted that Alpha's audited financial statement for FY 2017-18 show that it has not received any benefit under Program 1, 3, 4, 7, 8, 14, 24, 30, 34, and 35.
- Alpha does not have any financial arrangement with EXIM bank.
- In relation to the observation of the Authority relating to Program No. 12, it is submitted that Metrod is not eligible to take benefit under this scheme. It is important to highlight that the Accelerated Capital Allowance, which Metrod Malaysia Sdn. Bhd. has availed, is part of Program No. 16- Allowance for plant and machinery.
- The exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment has been availed by Metrod for refractories to be used in the new furnace as capital goods. It was also explained that the company requested for exemption from MIDA on the basis that imports of capital goods attract 0% import duty and, therefore, import duties should be exempt on refractories also. The company also requested the Authority that since exemption was granted in line with the policy of 0% import duty on capital goods, this scheme should not be considered as any benefit to the company or as a countervailable subsidy.
- Program 12 is available to all companies and the Inland Revenue Board applies objective criteria in granting the ACA. Thus, this program does not constitute a countervailable subsidy because it is not linked to export conditions, not specific in the manner required under the WTO agreement on subsidies and countervailing measures (SCM Agreement).
- Under Program 23, Alpha only received import duty exemption on machinery and equipment where such machinery and equipment were unavailable locally.
- It is submitted that Program 24 cannot be countervailable because the program involves exemption of import duties on the imported raw materials which are used in the production of export goods. Considering the exemption of import duties contained in the production of export goods as countervailable subsidy, would be in complete violation of the obligations under Paragraph (h) of Annex I of the ASCM and Annexure II Part 1 (h) of the CVD Rules.
- The alleged benefit under Program 35 ought to be adjusted only to the extent of the tax saved (24%) on the total profits earned by the exporter to arrive at the actual benefit. It appears that the calculation is based on the total amount of profit earned and not the tax saved.
- Alpha had been granted Pioneer status for a period of five years from 1 October 1987 to 30 September 1992. However, the pioneer status expired in 1992 and Alpha has not received any further pioneer status incentive subsequent to the expiry of the earlier incentive covering the period of investigation.
- Authority has not noted any evidence of receipt of subsidy programs by any producer/exporter from Malaysia.
- None of the companies under investigation has applied for or received any benefit from Programs 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34.
- Program 1 and 34 are only for Small and Medium Enterprises and the investigated producers are not eligible for this program.
- Program 11 is not linked to export conditions, not specific, and is generally available. Investigations by other Government Authorities have also determined that Program 11 is not specific in nature.
- The Authority has considered Program 16 – Allowance on Plants and Machineries (Capital Allowance) as a non-countervailable program. The provisions relating to depreciation were specifically explained and it was clarified that the scheme of depreciation works like any other depreciation elsewhere in the world. Both are depreciation related scheme which should be given the same treatment and shall not be considered as countervailable.
- Program 15 is not countervailable since it is not specific in nature. It is available to all companies such as resident and non-resident companies and unincorporated businesses such as sole proprietorships and partnerships. Export is not a criterion for granting IBA.
- Program 19 is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II, and III of the SCM Agreement.
- DGTR has erred in their interpretation of Article 2 of ASCM Agreement resulting a distorted consideration of this program specificity with regard to Programs 14, 23, and 24.
- All programs for which DGTR has relied on Adverse Inferences, were verified by the DGTR during on-spot verification held on 30 September 2019.
- The GOM has in its 2 November 2018 questionnaire response and its Supplementary Response provided first-hand information to the DGTR with respect to the programs and policies carried on by the GOM. This first-hand information should be used and relied upon without having to rely upon secondary information which may no longer be applicable.

Thailand Subsidy Programs

Program No. 2 is not limited to a certain enterprise, industry or the geographical area. There is no industry or market segment which is excluded from the scope of the program or not eligible to seek approval of the Board of Investment.

- With regard to Program No. 3, the income tax exemption under Investment Promotion Act is non-countervailable since the same is not limited to certain enterprise, sectors or geographical location. All enterprise, companies or sectors are eligible to receive benefit under this program. The Authority has countervailed this program on the presumption that the benefit was available to the producers who earned net profit during the POI. However, it is submitted that the company allowed to avail benefit under this program by the Board of Investment, may choose not to receive benefit under the program and such companies may forgo their right to claim benefit.
- The investigators accepted the submitted information pertaining to Program 5, provided during the verification, without having further questions or requesting additional documents.
- BOI has already explained in the verification meeting that Program No. 13 and 14 is not a subsidy program but rather a category of benefits under the new investment promotion scheme, which took effect on 1 January 2015, so it does not constitute a subsidy.
- With regard to Program No. 6, 7, 8, 9, and 10, the criteria for granting BOI investment promotion is NOT specific under the definition of Article 2 Specificity of the SCM Agreement. This is because investment promotion is granted not limited to company, industry, or area. The BOI also does not impose criteria that fall under Article 3 Prohibition of the SCM Agreement.

Indonesia Subsidy Programs

- The BZ program is not specific as it applies to all sectors of industry and region without limitation. BZ can also be an area of goods storage and this program applies to movement of goods within Bonded Zone, from Bonded Zone to free trade zone, to stock piling and export.
- Under strict monitoring, verification and regular audit, there will be no excess in using this program by any company within BZ including KSI.
- Even if the DGTR wants to calculate the subsidy margin for KSI under this program, it can only do so by referring to the interest factor as presented in its comments on disclosure:
- No legal basis for the DGTR to include export duty resulting in provision of raw material at less than adequate remuneration (LTAR) on copper concentrate as part of this investigation. The DGTR has never informed KSI on this program and the calculation made in the EF Disclosure remains unclear as KSI does not know wherefrom the figures have been derived. DGTR has failed to meet the burden of showing how this program results in the entrustment or direction to private entities to supply Indonesian producers of the product concerned with a financial contribution that confers a benefit.
- TMS is under KITE, not at all located in SEZ. The EF Disclosure mistakenly states in recital 430 quoted above that KITE also covers program on exemption of import duty for machinery. Article 2 of Minister Finance Regulation No. 254/PMK.04/2011 States
- "Exemption shall be provided on Import of goods and/or materials to be processed, assembled with, or installed on other goods for export purpose."
- The program, which on the import of raw material is subject to preferential customs duty, is not countervailable since (i) it has a strict verification process through the Customs Department; (ii) there is no excess in using the program; (iii) all imported materials are exported; and (iv) virtually all imports of copper cathodes by TMS were from FTA countries with 0% import duty.
- Export restraint on raw material copper ore and concentrate does not amount to a financial contribution in the form of provision of raw material at less than adequate remuneration. In US-Export Restraint, the WTO Panel observed that export restraint cannot constitute as government-entrusted or government-directed provision of goods and therefore does not constitute a financial contribution.
- Preferential Rate by EXIM Bank and Bank Mandiri have not been used by Indonesian producers participating in the investigation. EXIM Bank and Bank Mandiri are profit oriented financial institutions and they are not specific as the implementation of the programs is not limited to sector or region.
- SEZ is not countervailable as being in SEZ does not mean that the programs will automatically apply. The companies are required to apply separately for the programs.
- The VAT Exemption program was revoked and replaced by Government Regulation No. 81 of 2015. Under this, strategic industry covers various range of industries and is not limited to a particular region. This program is not specific.

Vietnam Subsidy Programs

- Under Program No. 1 and Program No. 3, reduction of corporate income tax is based on principles of "encouraged industries" and "encouraged geographical areas"
- There is a system in place for the General Department of Customs of Vietnam to monitor utilization of import duty exempt raw material in production of export goods as per Article 59 of Circular No. 38/2015/TT-BTC with regard to Program No. 2. This is a popular and widely used policy whereby Governments of other countries also

exempt/reimburse import duty on raw material for export production. Indian producers/exporters also enjoy benefits of such policy in India, which is known as Advance Licensing.

- Commercial Banks cannot be treated as government bodies. The Authority has made a false accusation of the nature of operation and loans given by Vietnamese commercial banks with partial or whole State-ownership, without providing any evidence.
- Financial guarantee provided by Vietin bank is a regular for-profit service by commercial banks all over the world.
- There are no pre-defined lists of eligible sectors or eligible regions for the Trade Promotion Program by GOV. Each year, the governmental body of the Program approves the programs for the year based on the proposals submitted by local authorities and associations. Therefore, the regions and the sectors eligible for promotion activities differ by year and are by no means "specific".
- No benefit has been received by any of the producers/exporters under investigation under Program 14 and 15.

Miscellaneous submissions on subsidy programs

- Due to certain developments it was unable to respond to the request for onsite verification. However, Alpha would like to request the Hon'ble Designated Authority to allow it to participate in the investigation as a cooperative producer, and prove that it has actually either (a) not availed; or (b) not benefitted from; any of the subsidies / programs examined by the Hon'ble Designated Authority
- TMS has fully cooperated with the DGTR by satisfactorily submitting its complete response to the DGTR followed by on-spot verification visit. TMS has indeed submitted all of its verification Exhibits from which the DGTR can use to determine which alleged programs were used, whether any used program is countervailable and if so, based on the available data to determine the subsidy margin.
- Authority has not disclosed the exact basis for determining subsidy margin for exports from Vietnam and only noted that subsidy margin has been determined based on facts available.
- The Authority has not taken into account the information regarding subsidy program provided by CFT Vina Copper and DOVINA while determining subsidy margin for all other exporters.
- The entire questionnaire response, especially the information regarding the use of specific subsidy programs and the amount of benefit availed by exporters from Vietnam should not be rejected if the information provided by the exporters was not complete or was not fully verified.
- Use of 'facts available' by the Authority under Rule 7(8) can be made to fill the gaps of missing information. It is also settled that such facts can include facts provided by interested party even if such facts do not provide for complete information.
- If majority of exports to India from the subject countries are made by cooperating exporters, then subsidy programs received by them are representative of subsidy programs received by all other exporters of the subject countries and such information should be used as facts available.
- The Public File does not contain any document which reflects that the Thai producers have availed income tax exemption or exemption of import duty on raw material. The input raw material used for production of subject goods is subject to NIL rate of duty which has been verified by the Authority during on-spot verification.
- In respect to the subsidy determination of all others rate for non-participating exporters, it is submitted that the methodology for computation of subsidy margin as well as the actual rate for "all other exporters" from Thailand cannot be claimed confidential.

K. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

556. The Authority notes that most of the submission made by interested parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The finding above ipso facto deal with these arguments of parties. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.

- As regards the submission concerning the widening of the scope of the product under consideration, the Authority notes that (i) "Copper bars, rods and profiles" are imported under tariff heading 7407 (ii) "Copper Wire" is imported under tariff heading 7408 and (iii) "Copper Plates, sheets and strip of a thickness exceeding 0.15 mm" are imported under tariff heading 7409. Product under consideration in the countervailing duty investigation is the product imported into India. Upon examination of the claims made by the interested parties and the import data obtained from DGCI&S, the Authority determined that the product under consideration in the present investigation is "Continuous Cast Copper Wire" falling under tariff heading 7408 of the Customs Tariff. The product under consideration includes Copper Wire of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm as well as 6 mm and below.
- At the stage of initiation of investigation, the product under consideration was defined as "Continuous Cast Copper Wire Rods", classifiable under Customs Subheading 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11, 7409.19. The Authority has in fact narrowed down the scope of product under consideration to include

only “Continuous Cast Copper Wire” falling under tariff heading 7408 and has not widened the scope of product under consideration.

- As regards the submission that the product under consideration contains two different products, the Authority notes that the product under consideration is only a single product namely “Continuous Cast Copper Wire”. Different cross-section dimensions of Continuous Cast Copper Wire do not result in different products.
- Authority has already responded to the claim concerning PCN methodology based on tariff code in the disclosure statement. As regards the submission that the PCN included products beyond the scope of product under consideration, the Authority notes that PCN based on tariff code was developed taking into account the entire scope of product under consideration suggested by the domestic industry at the stage of initiation of investigation and to ensure a fair comparison between different types/forms of the product. There is no rule that the PCN cannot be based on tariff codes. Interested party has not claimed that PCN based on tariff code has prejudiced their interest or has resulted in unfair comparison between the product under consideration and the like domestic product.
- As regards the submission that Copper Wires of below 3MM should be excluded because it is not produced by the domestic industry, the Authority notes that domestic industry produces copper wires of below 3MM and therefore the same cannot be excluded from the scope of product under consideration.
- Non-disclosure of information by M/s. Vedanta Industries (Sterlite Copper) of its related entity in the UAE does not affect the standing of the domestic industry because Vedanta Industries does not constitute part of the domestic industry.
- Other producers of “Continuous Cast Copper Wire” mentioned by interested parties are either importers of “Continuous Cast Copper Wire” or are buying “Continuous Cast Copper Wire” of higher cross-section diameter from the domestic industry to draw “Continuous Cast Copper Wire” into lower cross-sectional diameter. Inclusion of production of such domestic producers will result in double counting of total production in India.
- Unsubsidized import volume has been excluded by the Authority for determining total volume of subject imports and for assessment of material injury to the domestic industry.
- Authority has considered only the volume of imports of “Continuous Cast Copper Wire” falling under tariff heading 7408 and not included imports of “Copper Rod” and “Copper Strips” imported under tariff heading 7407 and tariff heading 7409 respectively in the injury analysis.
- Gap between demand and supply cannot be the reason for not recommending imposition of countervailing duty if the Authority finds that the imports of the product under consideration were subsidized and were causing material injury to the domestic industry.
- As regards the submission that injury is caused to the domestic industry due to imports from non-subject countries, Authority notes that even though import volume from non-subject countries are substantial but it is not significant enough to break the causal link between subsidized imports from subject countries and material injury to the domestic industry.

Claims concerning subsidization by the domestic industry

- The domestic industry has made a submission that the producers in Malaysia, Thailand and Vietnam are procuring inputs (copper cathode) from Indonesia and therefore the Indonesian subsidies are being passed through to the producers of subject goods in Malaysia, Thailand and Vietnam. The domestic industry has requested that while determining subsidy margin for Malaysia, Thailand and Vietnam, Indonesian subsidies passed through to the producers in these three countries should also be added. In this regard the Authority notes that the information submitted by the producers in Malaysia, Thailand Vietnam shows that majority of their input sourcing is from countries other than Indonesia.
- As regards the submission that subsidy margin should be determined for preferential lending for responding producers/exporters in Indonesia, the Authority notes that the Authority has verified the information provided by co-operating producers/exporters from Indonesia and no countervailable subsidy margin can be determined for preferential lending programs for the cooperating parties.
- As regards the submission that subsidy margin should be determined for Allowance on Plant and Machinery by Government of Malaysia and for Non-tax benefits granted by Government of Thailand, Authority notes that normal Allowance on Plant and Machinery programs do not provide for countervailable subsidy in accordance with Countervailing Duty Rules and the SCM Agreement. It is further noted that Authority has already determined subsidy margin for Accelerated Capital Allowance Program for all producers and exporters from Malaysia. Authority has also determined subsidy margin for all other producers/exporters from Thailand based on facts available for subsidy program providing non-tax incentives to producers/exporters in Thailand.
- As regards the submission that STEC is earning profits, the Authority notes that close scrutiny of the information provided by the domestic industry in the form of screenshots of third party website itself shows that STEC did not earn any profit during the calendar year 2017 and 2018.
- As regards the submission that if producers/exporters are non-co-operative, Authority must apply adverse facts available, the Authority notes that it has in fact applied adverse facts available against non-cooperative producers/exporters from subject countries.

Claims concerning Malaysian subsidy programs

- Authority has determined subsidy margin for Alpha Industries based on facts available and not based on claims made in their questionnaire response because Alpha Industries has not been considered as co-operating producer/exporter in the subject investigation.
- As regards the submission that exemption from import duty and sales tax on machinery by Government of Malaysia cannot be considered as countervailable because exemption granted was in line with policy of 0% duty on import of capital goods, the Authority notes that there is no legal basis for such argument under the Countervailing Duty Rules or under the SCM Agreement.
- As regards the countervailability of Program No. 12 concerning Accelerated Capital Allowance, Authority notes that Accelerated Capital Allowance is provided by Government of Malaysia to certain enterprises carrying out the promoted activity and therefore it cannot be clubbed with normal allowance/depreciation of plant and machinery available to all enterprises and duly fulfils the criteria of specificity.
- Metrod Malaysia did not disclose complete facts regarding the use of Accelerated Capital Allowance program even though it was specifically alleged by the domestic industry and information regarding the same was specifically requested in the questionnaire response. As part of the comments on disclosure, Metrod Malaysia has disclosed for the first time that Accelerated Capital Allowance was used by them and the corresponding amount of the benefit was incorporated in the total amount disclosed for Allowance on Plant and Machinery under Program No. 16. Authority notes that in the response filed by Government of Malaysia, the amount of benefit for Allowance of Plant and Machinery availed by Metrod Malaysia under Program No. 16 is provided in addition to the amount of benefit availed by Metrod Malaysia for Accelerated Capital Allowance under Program No. 12. Moreover, Authority notes that interested parties are required to provide complete information regarding the use of each of the subsidy programs for which specific information is requested in the questionnaire response. Authority is required to determine countervailability for each program specifically. Interested parties cannot cumulate different subsidy programs under one common category for the purpose of providing information.
- Authority further notes that Metrod Malaysia has incorrectly claimed that Accelerated Capital Allowance is available to all enterprises under the relevant rules and is therefore not specific. Rule 8.2.1 of the Rules of the Income Tax (Accelerated Capital Allowances) (Reinvestment of Eligible Projects) 2000 [P.U.(A) 506/2000] provides that such rules apply to qualifying plant expenditure incurred on the provision of plant or machinery for the purpose of a qualifying project in respect of promoted activity or promoted product. Rule 8.2.4 also says that the rules do not apply to company, which has been given Re-investment allowance. Thus, Authority confirms that the program is specific and does not provide for normal allowance/depreciation of plant and machinery and is not available to all enterprises. Thus, considering absence of full disclosure in the response filed by Metrod Malaysia and the inconsistency in the response filed by Metrod Malaysia and the Government of Malaysia in this regard, the Authority has not considered the information provided by Metrod Malaysia for determining benefit under Accelerated Capital Allowance.
- Metrod Group has wrongly stated that program no. 24 was countervailed by the Authority by stating that it involves exemption of import duties on the imported raw material used in the production of export goods. Authority has clearly noted in paragraph 253 of disclosure statement that the program No. 24 provides financial contribution in the form of revenue foregone and is also specific because it is limited to enterprise that use raw material that are not locally available.
- Authority has noted that Metrod Malaysia has received benefit in the form of exemption on import of raw material used in the production of export goods because Metrod Malaysia specifically admitted in its questionnaire response in Exhibit 14 that *“Grant of exemption of import duty on the raw material meant for export goods is covered under the exemption [of import duty on raw material]. No duty exemption under the scheme is available for goods which are imported for production of finished products destined for the domestic market.”* Authority had inadvertently noted in the disclosure statement this benefit availed by Metrod is a benefit under program no. 24. This does not change the admitted position that Metrod has availed this benefit and the same is countervailable. The Authority has now categorized this benefit availed by Metrod under “other program”.
- As regards the submission that export contingent exemption of import duty on raw material by the Government of Malaysia cannot be considered as countervailable subsidy because it is compliant with specific provision of Annex I of the SCM Agreement, the Authority notes that import of raw material for use in the production of exported goods cannot be considered as countervailable subsidy only if there is sufficient evidence to demonstrate that there is a verification mechanism to ensure that there is no excess remission have merely claimed existence of a mechanism and absence of excess remission without providing sufficient evidence or step by step explanation of such verification mechanism. Interested parties have not provided any instance of duty imposition by the Government on the company where it was unable to meet the export obligation. There is also no explanation by the exporter and especially by the Government of Malaysia to demonstrate how the amount of import quantity eligible for import duty exemption was fixed generally by the Government and especially in the case of raw material used for the production of product under consideration.

- The Authority has calculated subsidy margin for program granting exemption from income tax for Metrod Group based on the actual amount of benefit availed. Subsidy margin is based on the amount of tax saved on the total profits earned by the exporter to arrive at the actual benefit. Exporters from Malaysia have not objected to the correctness or legality of the methodology communicated to them and adopted by the Authority.

Claims concerning Thailand Subsidy Programs

- With regard to claim that subsidy programs provided by Government of Thailand are not specific, Authority notes that it has already provided sufficient explanation regarding specificity for each subsidy program.
- As regards the claim that programs No. 13 and 14 do not constitute countervailable subsidy, the Authority notes that Government of Thailand has not provided complete information regarding non-tax incentives under program no. 13 and why such non-tax incentives cannot be considered countervailable benefit.
- As regards the submission that export contingent exemption of import duty on raw material by the Government of Thailand cannot be considered as countervailable subsidy because it is compliant with specific provision of Annex I of the SCM Agreement, the Authority notes that import of raw material for use in the production of exported goods cannot be considered as countervailable subsidy if there is sufficient evidence to demonstrate that there is a verification mechanism to ensure that there is no excess remission. Government of Thailand has merely claimed existence of a mechanism and absence of excess remission without providing sufficient evidence or step by step explanation of such verification mechanism. There is also no explanation by the Government of Thailand to demonstrate how the amount of import quantity eligible for import duty exemption was fixed generally by the Government and especially in the case of raw material used for the production of product under consideration.
- The Authority further notes that no countervailing duty has been determined for cooperating producer/exporter from Thailand under the exemption of import duty on raw material imported for use in export production as the import duty on raw material imported by them was nil during the POI.

Claims concerning Indonesia Subsidy Programs

- With regard to the program concerning import duty exemption on import of raw material, the responding producer/exporter from Indonesia PT Tembaga Mulia Semanan (TMS) has raised two main issues (i) there was no excess remission of import duty on raw material because there is a strict monitoring mechanism and customs duty was paid by PT Tembaga Mulia Semanan on the short fall & (ii) even if subsidy margin is determined for this program, subsidy margin as a percentage of total turnover is negligible.
- In this regard, Authority notes that PT Tembaga Mulia Semanan did not respond fully to the questionnaire issued by the Authority, especially regarding the subsidy program concerning import duty exemption on import of raw material. PT Tembaga Mulia Semanan only stated that “this program does not confer material benefit to TMS as its vast majority of import of materials were from origin countries having FTA with Indonesia or ASEAN with zero import duty”. During verification, PT Tembaga Mulia Semanan acknowledged that there were in fact imports from non-ASEAN countries and benefit was received under this program in the form of duty exemption. Even during the verification visit, complete details of imports from non-ASEAN countries and the duty saved thereon was not provided. It was only subsequently that such details have been provided. Authority notes PT Tembaga Mulia Semanan did not provide complete information at the appropriate time and did not co-operate to the best of its ability.
- PT Tembaga Mulia Semanan has provided, as part of comments of disclosure statement, calculation of subsidy margin by calculating subsidy margin as a percentage of total turnover instead of total export turnover. Authority notes that subsidy margin calculated by PT Tembaga Mulia Semanan is not in accordance with Countervailing Duty Rules. In view of the above, Authority has determined subsidy margin for PT Tembaga based on facts available by relying on information provided by PT Karya Sumiden.
- As regards the submissions relating to the subsidy program concerning provisions of copper concentrate at less than adequate remuneration, the Authority notes that the same is a countervailable program in terms of SCM Agreement and the Countervailing Duty Rules. In fact, several countries have countervailed similar programs in the countervailing duty investigations conducted by them.

Claims concerning Vietnam Subsidy Programs

- As regards the submission that producers/exporters from Vietnam did not avail benefit for the subsidy programs for which countervailing duty has been determined by the Authority, the Authority notes that producers/exporters from Vietnam have not been treated as co-operating producers/exporters and therefore subsidy margin is determined for producers/exporters from Vietnam based on facts available.

L. CONCLUSIONS

557. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that

- i. The product under consideration has been exported to India from subject countries at subsidized prices except exports from M/s SEI Thai Electric Conductor Co. Ltd., Thailand.
- ii. The domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the product under consideration.
- iii. The material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS AND OTHER ISSUES

558. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

559. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization and create level playing field.

N. RECOMMENDATION

560. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including Government of Malaysia, Government of Thailand, Government of Indonesia and Government of Vietnam and adequate opportunity was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury and causal links in favour or against thereof. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

561. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury for a period of five (5) years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive countervailing duty as mentioned in Col No.7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of the subject goods from the subject countries.

DUTY TABLE

Sl. No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty amount as % of landed value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7408	Continuous Cast Copper Wire	Thailand	Any country including Thailand	SEI Thai Electric Conductor Co. Ltd	NIL
2.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than producer mentioned in S. No. 1	3.46%
3.	-do-	-do-	Any country other than Thailand,	Thailand	Any	3.46%

			Indonesia, Malaysia and Vietnam			
4.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk	3.75%
5.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT. Karya Sumiden Indonesia	4.98%
6.			Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer other than producer mentioned in S. Nos. 4 & 5	7.94%
7.			Any country other than Thailand, Indonesia, Malaysia and Vietnam	Indonesia	Any	7.94%
8.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Metrod Malaysia Sdn Bhd	2.47%
9.			Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than producer mentioned in S. No. 8	10.27%
10.			Any country other than Thailand, Indonesia, Malaysia and Vietnam	Malaysia	Any	10.27%
11.			Vietnam	Any country including Vietnam	Any	7.13%
12.			Any country other than Thailand, Indonesia, Malaysia and Vietnam	Vietnam	Any	7.13%

562. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

563. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Special Secy. & Designated Authority